# LOK SABHA DEBATES

(Third Session)



(Vol. XI contains Nos. 21-30)

# LOK SABHA SECRETARIAT NEW DELHI

Price: Rs. 1.00

#### CONTENTS

# No. 26-Monday, December 18, 1967/Agrahayana 27, 1889 (Saka)

	Columns
Oral Answers to Questions—	
*Starred Questions Nos. 721, 723 to 725.	7675–7705
Short Notice Question No. 15	7 <b>7</b> 05–11
Written Answers to Questions-	
Starred Questions Nos. 722, 726 to 729, 731, 732, 734 to	
744, 747 to 750.	7711-24
Unstarred Questions Nos. 4662, to 4665, 4667 to 4685, 4687, 4689 to 4719, 4721 to 4733, 4736 to 4745, 4747 to 4751, 4753 to 4761, 4763, 4764, 4767 to 4798,	
4798A, 4798B, 4798C, 4798D, 4798E, 4798F	7724-7805
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
Distribution of Posters in Assam saying "Assam for	
Assamese"	7805-09
Question of Privilege	7810-21
Papers Laid on the Table .	7821-22
Message from Rajya Sabha .	7822-23
Essential Commodities (Amendment) Bill—	
Report of Select Committee	7823
Unlawful Activities (Prevention) Bill	7824-7 <b>92</b> 6
Motion to consider, as reported by Joint Committee	
Shri Y. B. Chavan .	7824 <b>-792</b> 6
	7824–26
Shri K. M. Koushik Shri Krishna Kumar Chatterji	7827-34
•	7834–37
Shri Atal Bihari Vajpayee	7837-45
Shri Ahmed Aga	7845-59
Shri V. Krishnamoorthi	7860-63
Shri Prem Chand Verma	7863-66
Shri Sarjoo Pandey	7867–72
Shri Amiyanath Bose	7872-75
Shri R. Barua	787 <b>5</b> –77

<sup>•</sup>The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

										COLUMNS
	Shri G	eorge Fern	andes							7877-84
	Shri Vi	kram Cha	nd Ma	hajan						78 <b>84</b> -87
	Shri Viswanatha Menon									7887-91
	Shri D	. C. Sharm	a							7891 <del>-9</del> 5
	Shri K	. Lakkapp	а.							<b>7895-9</b> 8
	Shri Si	taram Kes	ri .							7899-7902
	Shri Sv	vell .								7902-06
	Shri Si	neo Narain	٠.							7906-11
	Shri T	enneti Visv	vanath	ıam						7911-16
	Shri H	em Raj								7916-20
	Shri O	nkar Lal B	ohra							7920-24
	Shri R	andhir Sin	gh							7924-26
Half-a	n-Hour	Discussion	n Re.	Supply	of	river v	water	s to V	<b>Ve</b> st	
Pak	istan									<b>7926–2</b> 8
Shr	i Bal Ra	i Madhok								7926-28

#### LOK SABHA

Monday, December 18, 1967/Agrahayana 27, 1889 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भूतपूर्व नरेशों की निजी बैलियां समाप्त करने के बारे में सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त का वक्तव्य

\*721. श्री शशि भूषण बाजपेयी : क्या वैदेशिक-कार्य यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या उनका ध्यान सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त के इस वक्तव्य की भीर दिलाया गया है कि निजी पैलियां तथा नरेशों के विशेषाधिकार समाप्त कर देने से भारत में पूंजी लगानें वाले विदेशी मित्रों के रवैये पर प्रतिकृल प्रभाव पढ़ेगा;
- (स) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है :
- (ग) क्या भारतीय राजदूतों को हमारी भ्रान्तरिक नीतियों के सम्बन्ध में ऐसे विवादा-स्पद मामले उठाने की धनुमति दी जाती है; ग्रीर
- (घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैवेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (बी व० रा० नगत): (क) से (व). सरकार ने 'एजेंसे फांस प्रेसे' की रिपोर्ट पूरी वेली है। इस सारी रिपोर्ट को पढ़नें के बाद, और सम्बद्ध अधिकारी ने सफाई में जो उत्तर दिया है, उसे देखते हुए यह पता चलता है कि उसनें इतनी अखरने वारी बात नहीं कही थी जितनी कि वह अबिवेकपूर्ण थी। फिर भी, इस अधिकारी को समुचित चेतावनी दे दी गई है और कह दिया गया है कि वह ऐसे सार्व-जनिक वक्तव्य न दें जिन्हें भारत सरकार की नीतियों और विचाराधीन कार्रवाइयों की आसोचना समझे जाने की जरासी भी गुंजाइश हो।

श्री शशि मूबण बाजपेयी: किसी राजा का पुत्र या किसी बैंकर का लड़का या किसी होई र का लड़का या किसी होई र का लड़का राजदूत बन जाए धौर उसके बाद यह कहे कि प्रियी पर्स धगर हिन्दुस्तान में सत्म हो जायेंगा तो इंटरनेशनल रिलेशंज खराब हो जायेंगे या यह कहे कि धगर बैंक नेशनालइज हो जायेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जायेंगे तो इसकी धनुमित धाप किस प्रकार दे सकेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है?

श्री ब॰ रा॰ भगत: जैसे कहा है मैंनें घपने उत्तर में उनको चेताबनी दी गई कि ऐसी बार्ते वह सार्वजनिक रूप से न कहा करें ...

श्री शिव नारायण : कह दी है उन्होंने ।

श्री ब० रा० भगत: कह वी है तनी तो चेताबनी दी गई है भौर धगर न कही होती [तो चेतावनी क्यों देने की जरूरत पड़ती। सरकारी मुलाजिमों के लिए कुछ नियम भी बने हुए हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं या सरकार जिन नीतियों पर धमल करने जा रही है उनके बारे में वे टिप्पणी न करें। ऐसे बक्तव्य न वें जिन से राजनीतिक

प्रतिक्रिया की भाशंका हो। उनकी इन मामलों में व्यक्तिगत राय कुछ भी हो सकती है भीर उसको रखनें के लिए वे स्वतन्त्र हैं। राजाका पुत्र हो चाहेवह उसकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो सकती है लेकिन सार्वजनिक रूप से या भाषिकारिक रूप से वे भपनी राय नहीं दे सकते हैं या दलल नहीं दे सकते हैं।

SHRI R. K. SINHA: It is seen that at times our representatives abroad, because of a sense of duty, have to come out with certain statements. That is one thing. But sometimes our representatives cross certain prescribed limits and this brings into controversy our national and international policies. Will the Government, therefore, lay down a code of conduct for al. employees abroad that they should not cross certain limits in giving out statements to the press?

SHRI B. R. BHAGAT: There is a code of conduct, Sir.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: मंत्री महोदय ने प्रपने उत्तर में कहा है कि हमारे सिंगापुर स्थित हाई किमश्नर के द्वारा जो सफाई दी गई है उसको देखते हुए सरकार कोई श्रीर कार्रवाई करना धावश्यक नहीं समझती है। जहां तक हमारे इन हाई किमश्नर का सबाल है वह एक कायदे के ध्रादमी मालूम होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा मौका था जिस पर उन्हें इस तरह का वक्तव्य देना पड़ा धौर उन्होंने धपनी सफाई में क्या कहा है? क्या उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने धपने व्यक्तिगत विचार प्रकट किये हैं या सरकार की नीति को प्रभावित करमें के लिए उन्होंने वक्तव्य दिया है?

श्री ब०रा० भगतः उन्होंने प्रेस के लोगों से कुछ बातचीत की । कोई वक्तव्य ऐसा नहीं दिया लेकिन बातचीत की ग्रीर उन्होंने बातचीत के दौरान यह कहा भी कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन वह बात खनी ग्रस्तवारों में। इसलिए उनको यह करना नहीं चाहिये था कि सरकार की जो नीतियां हैं उनके बारे में वह व्यक्तिगत राय दें भ्रीर उन बातों की चर्चा प्रेस में हो । इस वास्ते उनको चेतावनी दी है कि श्राइंदा कोई ऐसी बात न किया करें।

श्री मनु माई पटेल: जो बयान उन्होंने दिया है वह जो हमारी बुनियादी नीति है उसके खिलाफ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको चेताबनी देना काफी था, हमारी सावरेनटी है उस पर हमला हो तो क्या चेताबनी देना काफी है?

श्री ब० रा० भगतः यह अधिकारी पुरानें हैं। बीस साल से फारेन सर्विस में हैं। उनका भच्छा रिकार्ड अभी तक रहा है। यह एक ऐसी बात हुई है कि जिस के लिए यह उचित समझा गया कि उनको चेतावनी दी जाए भौर श्रागे से वह इस तरह की बात न कहें।

SHRI SWELL: Sir, very often our representatives abroad are subjected to questions about the affairs in the country about which perhaps the Government has not taken any decision. What do the Government expect these people to do under those circumstances? Are they expected to keep silent like wood and stone or are they expected to explain the policy of the country to those people?

SHRI B. R. BHAGAT: They are expected to explain the policy of the country, not to keep silent, if they are asked specifically. Even if certain decisions are not taken they can explain why decisions are not taken and not say anything for or against it.

SHRI D. C. SHARMA: Evidently the High Commissioner has functioned more as a price of some State—I do not know to which State he belongs—than as the High Commissioner of the sovereign democratic republic of India which pursues certain policies in the national field and also in the international field. In the light of this, may I know what kind of warning has been given to him? There are so many types of warning. There is warning, displeasure, suspension and dismissal. What kind of warning has been given to him? I think that a warning is absolutely inadequate for the criticiam that he has offered of the poli-

cies of the Indian Government, and such as person I do not think deserves to be our High Commissioner anywhere.

SHRI B. R. BHAGAT: He has been warned that he has been expressing personal views in his official capacity.

SHRI C. C. DESAI: I think the function of a High Commissioner is to communicate Government here and to the country also what the reaction on broad policies is in the foreign countries. What is wrong in his telling to the Government and to the country here that by pursuit of this policy the confidence in the Government's would be shaken in the foreign credit countries? Secondly, where is the objection? Why is this an act of indiscretion when similar statements are being made by the very gentleman sitting next to the hon. Minister, when the same thing has been done by Shri Gaikwad, Minister of Health in the Gujarat Government and when the same thing is done by Shri Karan Singh? Where is the indiscretion on the part of this particular person.

SHRI B. R. BHAGAT: The hon. Member has been a very distinguished High Commissioner.....(Interruption).

MR. SPEAKER: Order, order. I think the hon. Minister must reply and not any other hon. Member.

SHRI B. R. BHAGAT: The hon. Member has been a very distinguished High Commissioner himself, and I think more than anyone else he realises the distinction between communicating a personal view publicly and a communication with the Government. He cannot compare it with an opinion expressed by a political personality. I think that also he realises. He has been a very distinguished civil servant also. A civil servant has certain obligations. A person in politics, whether he occupies an important position or not, is free to express his view.

SHRI INDRAJIT GUPTA: The hon. Minister has stated that it is the duty of our foreign envoys to explain or interpret our policy abroad. Now, may I know whether his attention has been drawn to a new report this morning which quotes our charge d'affaires in Washington, Shri Banerjee, as having stated that border settlement with

China is an impossibility. Now, however intrasigent and hostile the present Chinese attitude may be, I would like to know whether it is government's policy that border settlement with China is an impossible question?

MR. SPEAKER: This question relates to Singapore.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Part (c) of the question is whether our envoys are allowed to raise controversial points. I want to know whether his attention has been drawn to this and, if so, the reaction of the government—is this going to be our declared policy.

SHRI B. R. BHAGAT: That report has appeared this morning. Certainly, the hon. Member cannot expect the government to comment on this without a clarification from the person as to what he has actually stated.

SHRI INDRAJIT GUPTA: But is it our declared policy that a peaceful settlement of the border question with China is an impossibility?

SHRI B. R. BHAGAT: As far as the policy of the Government of India is concerned, it is well-known and it has been stated many times. But the hon. Member is asking for information on the statement made by the charge d' affaires.

SHRI ANANTRAO PATIL: May I know from the hon. Minister whether it will be useful or not to conduct refresher courses for our envoys before they are appointed?

SHRI B. R. BHAGAT: It is done. Whenever a person joins the Foreign Office he is given a very thorough training.

बी मध लिसयं : हमारे संविधान में 1950 में कई बातें मम्जूर की गईं। जैसे माननीय सदस्य, श्री देसाई मौर लोवो प्रमु जैसे लोगों के लिए प्रमुच्छेद 314 रखा गया। उसी तरह राजा-महाराजामों के लिए मी कुछ उपबन्ध किये गये। मैं सरकार से इस बात का खुलासा चाहता हूं कि जब इस तरह की बात राजवूतों के द्वारा कही जाती है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि विदेशियों को उकसाया जा रहा है कि वे यहाँ पर चूंजी

न लगायें: यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय इस् राजदूत को यह सलाह देंगे कि वह तत्काल इस्तीफा देदें? हो सकता है कि हमारे राजा-महाराजा उन को लोक सभा का चनाव लड़ने के लिए टिकट दे दें, वह चुनाव लडें भौर फिर भपना काम करें। जब मेरे प्रस्ताव के सिद्धान्त को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, तो भव यह सरकारी नीति हो गई है कि कि राजा-महाराजा के निजी कोषों को समाप्त कर दिया जाये । ऐसी हालत में किसी भी सरकारी कर्मचारी को-भौर राजदत भी सरकारी कर्मचारी होता है-सरकारी नीति के विरुद्ध बोलने या काम करने की छट नहीं होनी चाहिए। वह भपने पद से इस्तीफा दे दें, चुनाव सड़ें भीर फिर लोक सभा में वह भ्रपनी बात रखें।

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): It is hardly a question.

SHRI PILOO MODY: I would like to know first of all whether the government has taken any final decision in the matter of privy purses and privileges or the effect that it would have on the flow of foreign capital in this country. If they have not taken any posture on that question, then I would like to know from the hon. Minister what would have been his reply to a question such as the one put to the High Commissioner in Singapore?

SHRIMATI INDIRA GANDHI: The government has not taken a final decision. As hon. Members are aware, the Home Minister was to discuss the implementation of the resolution passed by the All India Congress Committee with the Princes.

श्री मधुलिमये : सरकार ने प्रिंसिपल तो मान लिया है। क्या श्राप इससे भी भाग रही हैं?

SHRI PILOO MODY: In that case, what was the reply that he could have given?

MR. SPEAKER: The same reply could have been given.

AN HON. MEMBER: He should have kept quiet.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI: In view of the deplorable conduct on the part of the High Commissioner in Singapore and also the discussions here, may I know from the hon. Prime Minister whether the government will recall him and replace him?

MR. SPEAKER: That was exactly the question asked by Shri Limaye. It is becoming repetitive.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI: The Prime Minister is getting up to answer. Mere warning is not sufficient. I want to know whether he will be recalled.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I think 'deplorable' is a rather strong word. As the Minister said, the High Commissioner has committed an indiscretion and he has been duly warned. We certainly hope that our Ambassadors will not make unnecessary statements.

#### TIBETAN REFUGEES

\*723. SHRI M. R. MASANI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether the attention of Government has been drawn to a report in the Times, London of the 2nd September, 1967 carrying an interview with Mr. Keith Satterthweite, voluntary worker with Tibetan refuges in India, who claimed that he had been forced out from the Tibetan craft community with which he was working by the Indian officials as part of a general policy of hindering and stopping voluntary work by foreign nationals among Tibetan refugees;
- (b) whether the above facts are correct; and
- (c) whether it is a fact that Government have initiated a general policy of stopping work by foreign nationals among Tibetan refugees in this country and, if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Mr. Keith Satterthwaite, a farm worker from England, was reported to

be guiding the Tibetan craft community in Dalhousie in farm production. The cultivavable area available with this community being small, his services were not considered necessary, and he was informally advised to stop working with them. As the area is neither 'restricted' nor closed to foreigners, he could have stayed on if he had wished to do so. We approve only of Specialists and Technicians working with Tibetan refugees and 27 such foreign nationals are currently assisting them in rehabilitation.

SHRI M. R. MASANI: Mr. Speaker, Sir, if it was only a matter of informal advice and the liberty to stay on, there would have been no occasion for this gentleman to tell his sad story to the British public. But I may quote from what he has said in the Times that it went well beyond that.

"In May, the local district Commissioner summoned Lama Khamtral Rinpoche, the community's head, to ask why he had volunteers there. He had to tell us that we were supposed to go. When they learnt that we were not going to leave, they applied pressure on the Tibetan group by not issuing ration cards for cheap rice and wheat flour . . . .

SHRI PILOO MODY: Shame, shame!

SHRI M. R. MASANI: He further savs:

"But then an official came to Dalhousie and asked Lama Rinpoche why we still had not gone. We realised that if we did not go, they would put on more pressure. We moved to a private cottage....."

Therefore, they left. Does the hon. Minister think that this kind of thing should happen in this free and democratic country and this sort of bullying be permitted?

SHRI B. R. BHAGAT: It is true that he has said like this. But about the pressure and more so about the ration cards, that is not true. All those who wanted ration cards had been given ration cards and even those who were not on ration cards because they depended upon ration supplied through some contributions, through voluntary societies, due to drought and other situation in the country, were given ration cards. His point that the pressure was applied through denial of ration cards to these people is not correct.

SHRI M. R. MASANI: Is the hon. Minister aware of what Mr. Keith Satterthwaite has alleged when he was asked why this happened?

#### He says 1

"The Indian Government's attitude is that the refugees are not working enough. They did not want volunteer workers because the Tibetans would not become self-supporting...."

Is this Government's policy?

SHRI B. R. BHAGAT: No, Sir.

SHRI D. N. PATODIA: May I know whether it is a fact that the Indian Government wanted only specialised type of volunteers and not of ordinary type? If that be the case, may I know whether the statement of this gentleman is correct when he says:

"I know of several cases personally"he told at Dharamsala where the Dalai Lama is actually in residence-"a Swiss doctor with mobile dispensary was told to stop work among the Tibetans although he could work for the Indians."

#### SHRI M. R. MASANI: Shame !

SHRI D. N. PATODIA: That is the reason for this discrimination and why was a specialised person like a doctor, prevented from doing his job?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL **AFFAIRS** (SHRIMATI INDIRA GANDHI): We will look into it.

SHRI B. R. BHAGAT: I do not know about this. We have the list of specialists wholare working in which there are doctors, nurses, teachers and others. But I have just got the information that this doctor is still there.

SHRI D. N. PATODIA: The Minister says, he does not know it. He must have read the report.

MR. SPEAKER: His latest report is that he is still there.

SHRI M. R. MASANI: I am glad the Prime Minister has said that she will look into it. This is the hole purpose of this question to see that these things do not happen.

श्री श्रो० प्र० स्थानी: श्रध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की जानकारी में यह बात श्राई है कि जो बाहर के लोग वहां काम कर रहे हैं वह तिस्वती सरणार्थियों के बहुत से बच्चों को विदेशों में ले गए हैं श्रीर वहां उन का धर्म परिवर्तन भी उन्होंने किया है ? क्या ऐसी भी रिपोर्ट सरकार के पास है कि जो विदेशी वहां कार्य कर रहे हैं उन्होंने तिस्वतियों का धर्म परिवर्तन किया है श्रीर उन के इंस्टीट्यूशन में श्रनिवार्य रूप से ईसाइयत की शिक्षा दी जाती है ?

बी ब॰ रा॰ भगत: कुछ यह बात सही है कि कुछ देशों में जैसे स्विटजरलैंड ने कुछ बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रवन्ध किया है। अब यह धर्म परिवर्तन की बात का तो मुझे पता नहीं।

SHRI JYOTIRMOY BASU: Is the Government aware of the fact that Dalai Lama, in the name of resettlement of Tibetan refugees, is trying to make extensive purchases of tea estates and things like that in the border areas, specially in the Kangra valley and whether it is a fact that funds for this purpose are coming from western capitalist countries, and if so, what steps Government propose to take to prevent such things from happening? (Interruptions)

SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH: If so, how to get from eastern capitalist countries also?

MR. SPEAKER: Is that a rider to it!

SHRI B. R. BHAGAT: I want notice to answer this question.

भी जार्ज कर्नेन्द्रीख: प्रध्यक्ष महोदय, यह जो तिम्बती घरणार्थी हिन्दुस्तान में हैं क्या सरकार की ऐसी कोई भी योजना है कि जिस से किसी दिन इन घरणार्थियों को प्रपने देख बापस जाने में मदद हो जाय घौर उस वृष्टि से सरकार कोई भी ऐसी नीति प्रपना रही है या कोई भी कार्यक्रम घपने हाथ में

ले रही है जिस से कि यह चीज बहुत ही जल्दी कामयाब हो जाय?

श्री ब० रा० भगत: यह तो अपनी मर्जी से यहां आये हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उन को बसाने की . . . . (ध्यवधान) . . . . आप सुनिए तो । अब यह वापस जायें या नहीं, यह भी उनकी मर्जी है। हमारी कोई नीति नहीं है कि उन को वापस भेजा जाय ।

भी जाजं फर्नेन्डीख: ग्रध्यक्ष महोदय, वह मेरा प्रदन नहीं समझ सके हैं। वह अपनी मर्जी से नहीं भाये हैं। भन्तर्राष्ट्रीय घटनाभ्रों ने जो उन के ऊपर मुसीबत पैदा की उस की बजह से वह भाये हैं। उस में कुछ तो भ्राप की सरकार की भी गलती रही है। ग्रब 20 वर्षों के बाद ग्रसलियत को छिपाने से तो कोई **फायदा** नहीं है। मेरे प्रश्न का मतलब समझ लीजिए। राजनैतिक परिस्थितियों के कारण वह यहां श्राये हैं भीर श्राज तिब्बत का इस्तेमाल चीन ने वहां ग्रपनी फौजी ताकत को बढ़ा कर हिन्दुस्तान को खतरे में डालने के लिए किया है। तो क्या ऐसी कोई नीति सरकार की है है कि यह तिब्बती भ्रपने घर वापस जायें, भ्रपने देश को ग्रपने काबु में लें श्रौर जिस से हिन्दुस्तान पर जो भाज चीन का सतरा है वह भी दूर हो भीर इन की भी मदद हो?

श्री वर्ण्यातः माननीय सदस्य को ग्रच्छी तरहमालूम है कि सवालों के समय नीति पर बहस नहीं की जाती।

श्री जार्जफर्ने बीखः बहस मैं नहीं कर रहा हूं। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं भीर नीति के मामले में ही तो प्रश्न होते हैं श्रीर काहे के मामले में होते हैं?

MR, SPEAKER: He may please resumehis seat. We have got the Foreign Affairsdebate also.

श्री बं रा० भगत : उन्होंने नीति का जहां तक सवाल किया में फिर भी दोहराना बाहता हूं कि झगर ऐसी स्थित हुई भी कि जब बह बहां वापस जायेंगे तो यह उन की मर्जी पर निर्भर होगा ....

Oral Answers

श्री जार्ज कर्नेन्डीच : ग्राप से कुछ नहीं होगा । ब्रध्यक्ष महोदय , यह अपने आप चीजें नहीं होती हैं। सरकार को कुछ करना होता है। यह स्रोगक्या कर रहे हैं ? बस उन को रोटी खिनाने का काम कर रहे हैं भौर कुछ नहीं .... (व्यवधान) कुछ तो नीति बनावे उस के बारे में।

श्री प्रेम चन्द वर्माः अध्यक्ष महोदय, में जानना चाहता हूं कि इस वक्त तक कितने तिब्बती मरणार्थी हिन्द्स्तान में हैं? जिस इलाके से में आता हं जैसे धर्मशाला का जिक किया है कांगड़े में, वहां पर काफी तिब्बती है। तो क्या सरकार को मालुम है कि उन तिब्बती शरणार्थियों के साथ ....

MR. SPEAKER: That does not arise out of this question. This is about some voluntary worker and all that.

भी प्रेम चन्द वर्मा : उन तिव्बती शरणायियों के साथ कम्यनिस्ट पार्टी के सरगर्म लोगों ने सम्बन्ध बनाया हुआ है और वह जो लोग वहां से तिब्बती शरणार्थी के रूप में आये हैं उनमें चीन के कुछ एजेंट भी हैं जो यहां से सब खबरें वहां भेजते हैं और जो कुछ भी बातें वहां होती हैं वह चीन के रेडियो से बाडकास्ट होती हैं, तो क्या सरकार ने इस सिलसिले में कोई जांच की है ? अगर की है तो उस का कुछ विवरण बतायेंगे ?

श्री ब॰ रा॰ भगत : अभी तक हमारे यहां कुल 51 हजार तिब्बत से शरणार्थी आये हैं जिन में अधिकांश तो शरू में आये ये और कुछ अभी आते हैं। जहां तक उन में चीनी एजेंट या दूसरी पार्टी से सम्बन्ध रखने वालों का सवाल है जब वह आते हैं तो हम यह अच्छी तरह छानबीन कर लेते हैं कि उन में कोई चीनी एजेंट न हो या उन का राजनीतिक दलों के साथ सरोकार न हो बिलकुल । इसके बाद तब उन को बसाने के लिए या पनवास के लिए प्रबन्ध करते हैं ....

भी प्रेम चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कुछ केसेज पकडे गए हैं ...

भी ब॰ रा॰ भगत: उन को बापस भेज दिया गया ।

SHRI HEM BARUA: Because of the reception given by India to the Tibtan refugees, is it not a fact that China is at present pushing in more Tibetans into India, of whom some are specially Chinese spies? If so, may I know whether Government is trying to screen the new onrush of Tibetan refugees into India so that these spies may not percolate into our country?

SHRI B. R. BHAGAT: That is true. We are very careful. When we see that the influx of refugees that is coming if their number is more than just the trickle that is usually coming on account of hardhship, we go into it and very carefully screen them and it is a fact that about some of whom we had, doubts that they might be spics, we have been able to push them back.

श्री बलराज मधोक : क्या यह सत्य है कि जो तिब्बती रिफ्युजी भारत में आये हैं उन में से बहतों को उन क्षेत्रों में जहां वह अच्छी तरह बस सकते थे जहां की जलवाय उन के अनुकूल हैं वहां न बसा कर के उन को हम उन स्थानों पर भेज रहे हैं जहां की जलवायु उन को सूट नहीं करती और आहिस्ता आहिस्ता उन को समाप्त करती जा रही है ? इसके विपरीत लहाख और लाहौल स्पीती आदि उत्तरी भारत के अन्य क्षेत्रों में जहां वह बस सकते थे आसानी से और जहां उन के बसाने से हमें भी लाभ हो सकता है, उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लहाख में मैंने देखा कि 2 हजार तिम्बती आये हैं उन को बसाने का भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। तो क्या इस मामले पर भी सरकार रोशनी द्रालेगी?

भी ब० रा० भगत: लगभग 14 हजार आदमियों को तो हम बसा पाये हैं और जो बाद में आये हैं चूंकि जगह की कमी है और जगह से मतलब यह है कि बेती आदि की व्यवस्था हो तो उसकी कमी है, इसलिए एक बड़ा तबका है दस हजार के करीब, उनको हम मैसर स्टेट में जमीन तैयार करके वहां बसा रहे

हैं। अभी तक करीब 20 हजार जो शरणार्थी हैं जिन को बसाना बाकी है, उन के लिए जगह और इलाकों में खोज कर के और जमीन बगैरह तैयार करके बसाने की कोशिश की जा रही है।

श्री बलराज मधोक: अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा मा कि जहां बसाने की कोशिश कर रहे हैं वह उन के लिए सूटेबल नहीं है। तो उत्तर भारत में ही उन को बसाने की कोशिश करेंगे?

श्री ब० रा० भगत: मैंने जैसा बताया कि इन इसाकों में जैसी जमीन चाहिए और जो राज्य सरकारों से उस के लिए सुविधा चाहिए, वह नहीं मिल रही है। इसलिए मैसूर सरकार से बात की। वहां की सरकारों से बात कर के सब कुछ इंतजाम कर के तब उन को कहीं बसाया जाता है।

श्रीमती इन्विरा गांधी: जो लोग मैसूर में बसे हैं वह कुछ समय पहले मुझ से मिलने आये थे। उन्होंने तो कहा कि वह खुशी से वहां बसे इ।

चतुर्व पंचवर्षीय योजना + \*724. भी राम चरण: भी भोगेन्द्रझा: भी रवि राय:

स्वा प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या योजना आयोग ने चतुर्य पंच-वर्षीय योजना अप्रैल, 1969 से आरम्भ करने का निर्णय किया है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) क्यासरकार को पहले ही विश्व बैंक तथा अमरीकी सरकार से इस बारे में सुझाव मिल गए वे?

वेदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी व० रा० भगत): (क) और (ख). इस विषय में 6 दिसम्बर, 1967 को सभा की मेज पर रखेगये विवरण की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

Oral Answers

## (ग) जी, नहीं।

श्री राम चरच : जैसा कि मंत्री जी ने बताया है चौथी पंचवर्षीय योजना उस आघार पर है जो कि 1969 में चालू होगी तो एक तो यह तीसरी योजना बजाय पंच वर्षीय योजना के सप्त वर्षीय योजना हो जायगी और दूसरे यह है कि दो साल का जो समय यह है इस में जितना स्टाफ है, वह खाली बैठा हुआ है, उन के पास कोई योजना नहीं है प्लानिंग किमशन में अनेकों कर्मचारियों को मुफ्त की तनख्वाह दी जा रही है हालांकि उन के पास काम नहीं है और वह एक-एक फाइल को लेकर 6-6 महीने बैठे रहते हैं मसलन् रिसर्च बाफि ससंवहां पर बिलकुल सरप्तस हैं तो उन को अगर रिट्रैंच कर दिया जाय तो सरकार को कि तन धन की बचत हो सकती है?

श्री ब॰ रा॰ मगत: यह बात गलत है कि उन के पास काम नहीं है। इस की पहले ही छान बीन की गई थी और आवक्यकता से अधिक आदमी उनको दिये नहीं गये हैं।

श्री राम चरण: वहां पर काफी सरप्लस आदमी हैं और जैसा मैंने कहा एक-एक आदमी 6-6 महीने फाइल लिये बैठा रहता है और अगर मंत्री चाहें तो ऐसे कमंचारियों के नाम भी मैं उन को बतला सकता हूं?

श्री व० रा० भगत: अगर नाम बतलायेंगे तो मैं इस बारे में देखूंगा।

श्री राम चरण: रिसर्च आफिसस के काम के बारे में क्या आप ने कोई स्टडी ग्रुप कायम किया है जो कि इस की जांच करे?

श्री ब ० रा० भगत: में वही तो कह रहा या कि कुछ दिन पहले ही इस बात पर काफी छानबीन की गई यी कि प्लानिंग किमशन के स्टाफ में कितने आदमी हैं, कितने आदमियों की जरूरत है। बाकी जहां तक बौर्या पंच-

7692

वर्षीय योजना का सावल है वह योजना सन् 69 से मुख् होगी लेकिन यह कहना कि अभी उन को काम नहीं है यह ठीक बात नहीं है। जैसा कि बतलाया गया या अभी वार्षिक योजना बन रही है, इस साल की बनी है और अभी भी राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है इस-लिए योजना कोई समाप्त नहीं हुई है, योजना का कार्य चल रहा है और इसलिए जैसा कि माननीय सदस्य समझते हैं उस में लोगों के बेकार बैठने का सवाल नहीं होता है।

श्री सरख पाण्डेय : अभी जो वक्तव्य दिया गया है उस में यह कहा गया है कि यह लड़ाई के कारण और अन्न की कमी के कारण हमारी आर्थिक स्विति पर बहुत बोझ पड़ा और उस से योजना के काम में देरी हुई, पिछली लड़ाई के दौरान जो सरकार ने कर लगाये और उसकी वजह से जो पैसा मिला वह भी गया और योजनाएं भी काटी गयीं तो मैं जानना चाहता हं कि आखिर लडाई में कितना रूपमा बर्च हुवा जिसकी कि वहज से हमारी मोजना के ऊपर बुरा प्रभाव पढ़ रहा है ?

भी ब॰ रा॰ भगतः सडाई में जो कुछ खर्चा हुआ उस की अलग से तफसील मेरे पास नहीं है लेकिन डिफेंस बजट अगर देखेंगे तो उस से अनुमान सगा सकते हैं कि यह सब से बड़ी बात कि लड़ाई के कारण असर पड़ा वह यह है और जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा कि सारे उन देशों ने जो हमें विदेशी मुद्रा की सहायता करते ये वह सहायता करनी उन्होंने रोक दी, उन्होंने कर्जा बगैरह, ऐक्सटरनल लोन बगैरह सब रोक दिया और इस सदन में भी यह बात उठी थी कि हम इस योजना को ऐसा रूप दें कि हमारी सरकार को बाहर के देशों का सहारा लेने के लिए इंतजार न करना पढ़े। इस दृष्टि से योजना को नया रूप देने की बात चली और उस पर उस दिष्ट से विचार करने की आवश्यकता पढी और उस की वजह से उस के ऊपर असर पड़ा।

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR: May I know whether the pace of progress of the country has slowed down since the publication of the Draft Fourth Five Year Plan? May I also know whether while formulating the Fourth Five Year Plan beginning from 1969, the priorities and allocations would not be seriously disturbed?

SHRIB. R. BHAGAT: The slowing down has been due to the factors indicated in the statement made here earlier.

भी स्वतंत्र सिंह कोठारी : माननीय प्रधान मन्त्री ने अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि रिसोर्सेज के हिसाब से वह प्लान को आगे बढाएंगी। तो मेरा कहना यह है कि यदि सरकारी उद्योग धंधे ठीक से और कुशलता-पूर्वक चलें, तो उन से सरकार को प्लान के लिये रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकेंगे। तो पब्लिक सैक्टर के उद्योग धंधों की क्षमता बढाने के लिये मंत्री महोदय या सरकार ने क्या विकार किया है, क्या कदम अभी तक उस ने उठाये हैं या उठाने के बारे में सोच रहे है?

भी ब॰ रा॰ भगत : सब से बढ़ी बात यह है कि जो पंजी लगी हुई है और धंधे हैं वह ठीक से चलें। रिससैशन की बजह से कई दिक्कतें हो गयी थीं । अब सरकार द्वारा को तिश की जा रही है कि उन दिक्कतों को दूर करके उद्योग धंधों को कुशलतापुर्वक चलाया जाये तभी और पूंजी वापिस आयेगी।

SHRI G. S. REDDY: Have all the State plans been received by the Centre?

SHRIB. R. BHAGAT: The time schedule has been ready, and the consultation will go on till the end of this month, and by the end of this month, the State Plans are going to be finalised.

भी भीषन्य गोयल: में यह जानना चाहता हं कि तुतीय पंचवर्षीय योजना के पूर्ण होने के बाद बेकारों की संख्या का क्या अनुमान लगाया गया है और इस चौथी योजना का प्रारूप तैयार करते समय हम ने इस बात की क्या योजना की है कि यह बेकारों की संख्या किसीन किसी माला में कुछ कम की जाये ?

भी ब० रा० भवतः अभी इस के लिए सूचना मिलने की जरूरत है क्योंकि यह तफसील की बात है।

श्री प्रकाशबीर शास्त्री: मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने आगामी पंचवर्षीय योजनाओं के सम्बन्ध में यह कहा था कि हमें ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए जिन योजनाओं का रिटर्न जल्दी हम को मिल सके तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करते समय क्या सरकार उस को नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है और दूसरी बात यह कि जिलों में जो छोटी-छोटी योजनाओं का क्या भविष्य रहेगा?

श्री ब० रा० भगत: चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करते हुए उस में इस बात को स्वीकार किया गया था कि अब जो नई योजना बनेगी उस में इन बातों पर खास जोर दिया जायेगा।

भी प्रकासवीर शास्त्री: जिलों की योजना भी कुछ है?

भी ब॰ रा॰ भगत : जी हां, जिलों की भी योजना है, डिस्ट्रिक्ट प्लांस उस के लिए हैं।

श्री महाराज सिंह भारती: तीसरी योजना के समाप्त होने के बाद जो तीसरी योजना के लक्ष्यों की पूर्त्ति नहीं हो पाई थी और इस बीच में यह चौथी योजना शुरू हो गई तो हम को यह कई साल जो अभी मिले हैं तो क्या इन सालों में उस तीसरी योजना के बकाया लक्ष्यों की पर्ति हो जायेगी?

दूसरे जो चौथी योजना हम बनाने जा रहे हैं और जो अब तक बहस चसती रही है कि कितने की बने और कितने ही न बने, यह सब चसता रहता है तो मैं जानना चाहता हूं कि पुरानी जो एक रूपरेखा आई थी चौथी योजना की, चौथी योजना उन्हीं रूपरेखाओं के हिसाब से होगी या उस को बिसकुल नये सिरे से और नये ढंग से बनाया जा रहा है ? श्री ब० रा० भगत: तीसरी योजना के लक्ष्यों की पूर्णि में जो कमी रह गयी थी उस के लिए यह सब से पहला कर्लब्य होता है आगे की योजना का कि उन किमयों के पूरा करने के क्या उपाव किये जायें।

Oral Answers

श्री महाराज सिंह भारती: चौषी योजना नहीं बल्कि उस के पहले जो यह दो, तीन साल रहते हैं उन में तीसरी योजना के बकाया लक्ष्यों की पूर्त्ति होगी या नहीं?

भी ब० रा० भगतः उन की पूर्ति करना पहला कर्तव्य होता है। ग्रनाज के उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति में जो कमी रह गयी थी उस भोर सब से पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके लक्ष्य में जो कमी रह गयी है वह पूरी हो। बाकी बहाँ तक योजना के प्रारूप का सवाल है उस में 30 हजार 5 सौ करोड़ रुपये की योजना थी लेकिन भव चूंकि परिस्थित बदल गयी है, प्लानिंग कमिशन भी बदल गया है इसलिए श्रव नये रूप से इस पर सोचा जायेगा कि उसका क्या रूप होगा लेकिन उसे इस समय बतलाना कठिन है।

भी बै० ना० कुरील: अभी तक जो योज-नाएं चलती रही हैं उन में केवल साधन युक्त लोगों को ही लाभ हुआ है तो जो योजना बनेगी उसमें क्या इस बात का भी ध्यान रसा जायेगा कि जो साधनहीन लोग देश में हैं उन को भी लाभ पहुंचे ?

श्री ब० रा० भगतः यह बहुत जरूरी चीज है भौर इस पर भवश्य ध्यान दिया जायेगा।

SHRI S. KUNDU: Sometime ago the Prime Minister made a statement in the House setting out the reasons why the Fourth Plan has been shelved. In that she mentioned the Prkistani aggressicn, dreught etc. The point is that instead of the Fourth Plan, we are now having three yearly plans. Are Government sure that in future also such calamities as drought or aggression will not be there? Therefore, is that the real reason for shelving the Plan? Is it not a fact that

Oral Answers

the entire onus for the shelving of the Plan lies on the Congress Party for their indecision and inaction, that they could not decide upon what would be the policy behind the Plan and therefore to the detriment of the entire country's interests the Plan was shelved?

SHRI B. R. BHAGAT: It is not true to say that the Plan was shelved. The Prime Minister did not say that in her statement. What was said was that because of aggression the external resources were affected due to stoppage of aid and because of the drought the internal resources were vitally affected. These completely threw the entire resources aspect of the Plan out of gear. Therefore, the Plan has not been shelved nor postponed, but a new strategy of development has been evolved through annual plans. We are in a period of consolidation so that we may preserve and protect.....(laughter). The hon. Member may laugh, but facts cannot be ignored...

SHRI S. KUNDU: We had a figure of Rs. 21,000 crores....

SHRI B. R. BHAGAT: I am answering the hon. Member. What is being attempted is to....

SHRI PILOO MODY: Find excuses.

SHRI B. R. BHAGAT : ...preserve and protect what has been achieved so that when the Fourth Plan is launched, we are able to make up the loss and go forward on the expected rate of growth.

SHRI PILOO MODY: Will they at least have the cost of the champagne bottle with which to launch it?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : भ्रपने सीमित साघनों को घ्यान में रखते हुए तथा सूरका व सन्न उत्पादन की योजनामों को प्राथमिकता देते हए<del>--- क्</del>या सरकार ऐसा प्रयत्न करेगी कि इनके लिये उचित साधन उपलब्ध हो सकें ? इन के लिये समाज कल्याण की जो बहुत सी योजनायें चल रही हैं, उनमें से कुछ काट कर क्या सरकार उन पर पुनः विचार करेगी तथा खाद्यान्न में धारम निर्भरता लाने के लिये क्या सरकार इनके लिये ग्राधिक मात्रा में साधन उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी ?

श्री ब० रा० भगत: इन सारी बातों पर प्सानिंग कमीशन जरूर विचार करेगी।

SHRI N. K. SOMANI: Of late, there has been a tendency on the part of the Government of India to discuss and decide matters of vital importance outside this Parliament. When the decision to postpone the fourth plan was taken. Parliament was not consulted nor was a chance given to us to discuss it and take a decision. Another instance, which is of recent origin, was the way in which agricultural income-tax was decided upon outside the House. May I know why the Government is strengthening this tendency?

SHRI B. R. BHAGAT: Nothing new has been done.

AN HON. MEMBER: This is an old habit 1

SHRI B. R. BHAGAT : The Plan has not been postponed, and whatever decision is taken by the National Development Council always comes to the House. As far as agricultural income-tax is concerned, no decision has been taken. It is being studied, and when it is necessary to ask the authority of the House, the Government will come forward. So, nothing new has been done.

श्री महाराज सिंह भारती : यह प्लान का चौथा बच्चा तीन साल बाद पैदा होगा---भ्राप कहते हैं कुछ, नया नहीं हुन्ना।

श्री रणधीर सिंह: क्या श्रगली योजना में शहर के बजाये देहात पर ज्यादा जोर होगा. इंडस्टीज के बजाये एग्रीकल्चर पर ज्यादा एम्फेसिस डाला जायेगा. देहात में इसैक्टिफिकेशन, रूरल हाउमिंग भीर एग्री-कल्चर पर ज्यादा से ज्यादा रुपया सर्च किया जायेगा और जितना रूपया इन कामों के लिये पहले, दूसरे भीर तीसरे प्लान के लिये दिवा गया है, उस से दुगना रुपया एलोकेट किया जायेगा ?

श्री ब० रा० भगतः देहात का जरूर स्थान किया जायेगा । माननीय सदस्य के विचार हम प्लानिंग कमीशन को भेज देंगे।

SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH

SHRI HEM BARUA: Should a Member come to Parliament with a foreign cap?

MR. SPEAKER: They have presented to you and me also when we went there.

SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH: It is as much Indian as the Haryana turban and other caps on the other side.

MR. SPEAKER: Each one of us who went to Nepal has got it.

SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH: In the last seven or ten years there have been studied comments about planning in this country and also there have been comments that planning has not been as realistic as it should be, that planning has to be based on physical targets rather than monetary or financial targets. So, would the Government now make a very dispassionate and objective study instead of taking shelter under droughts, aggression etc., and look at the plan de novo, in a fresh way, and plan in a realistic way so that we achieve the desired results?

shrib. R. Bhagat: If by "realistic" is meant that needs have to be married with resources or means, that was done, because when the plan of Rs. 21,500 crores was drawn up, an estimate of the resources was also made with which the national minimum results could be achieved.

भी शिव नारायण : मध्यक्ष महोदय, हर प्रदन के ऊपर हमारे दल को, कांग्रेस पार्टी को गालियां दी जाती हैं तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि—माइ० सी० एस० के लोगों के बनाये हुए प्लान के भाषार पर नहीं, बल्कि हम को प्रेक्टिकली बतायें कि जब चौथी पंच वर्षीय योजना पूरी करेंगे तो उत्तर प्रेश को जिसे पिसले तीन प्लानों में नैगलैक्ट किया गया है, उस की पूर्ति करेंगे या नहीं?

SHRI PILOO MODY: Sir, I object to any Congressman trying now to shift the blame on to the ICS. (Interruption). Finally, after they have run out of all excuses, now he wants to blame it on the ICS.

भी शिव नारायण : हम वस्वई से नहीं स्नाते हैं, हमारे यहां स्लैक मनी नहीं है। भी वर्षा भगतः यह पार्टीका प्लान नहीं है, यह प्लानुपालियामेंटका बनाया हुन्ना है।

भी शिव नारायण: प्रध्यक्ष महोवय, हमें जबाब नहीं मिला । पिछली तीन योजनाम्रों में उत्तर प्रदेश को टोटली नैगसैक्ट किया गया है, उस को पूरा करेंगे या नहीं?

अध्यक्ष महोदय: जवाब दिया है, भाई।

श्री शिव नारावणः ग्रध्यक्ष महोदय, हम भी इस हाउस को रिप्रजेन्ट करते हैं, जनता हम से पूछती है ? हमें साफ जबाब मिलना चाहिये।

श्री ब॰ रा॰ भगत: उत्तर प्रदेश या दूसरे जितनें भी पिछड़े हुए प्रदेश हैं, उन पर पूरा भ्यान दिया जायेगा।

SHRI INDRAJIT GUPTA: In the statement which the hon. Prime Minister made on the 8th December, listing the reasons according to her, why it has become necessary to have this sort of Plan post ponement or holiday, may I know why there is no mention in it at all of the devaluation of the rupee? Is it because they think that it will not have any effect? Secondly, in view of the fact that our planning has been dangerously overdependent on foreign aid, has the Minister's attention been drawn to yesterday's news that the United States Congress has decided to cut down foreign aid drastically, to what they call, on all-time low, and in view of this, does he still think that they will be able to start this fourth Plan again from 1969?

SHRI B. R. BHAGAT: Devaluation is not the reason for postponening the Plan because it does not in any way affect the resources position. That is the answer for the first part. As for the over-dependence on foreign loans, the strategy of our Plan is to progressively reduce the quantum of foreign aid that is necessary for development and growth. But even there, (Interruption), it is much less than in any other developing economy. What was there by way of aid, even that relates to the crucial period. The percentage may be as low as 10 percent or even less. But it is

enough because it goes to a very vital sector of the economy, and stoppage of this aid dislocates the entire Plan as such. That is the reason.

SHRI S. R. DAMANI: While welcoming the postponement of the Plan to 1969, I want to know whether the targets fixed in the draft Plan will be altered or be maintained, and whether consideration will be given to the public sector projects which are running with reduced capacity, whether they will get preference.

SHRIB. R. BHAGAT: The new Planning Commission is giving an entirely new look to this and it will come to its own conclusion about the target, the resources and the priorities.

भारत सेवक समाज को मनुदान

\*725. बा॰ सूर्य प्रकाश पुरी: श्री रामावतार शर्मा: श्री शिव कुमार शाली: श्री राम गोपाल शालवाले:

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने भारत सेवक समाज को किसी न किसी रूप में अनुदान देने का निष्चय किया है हालांकि लोक लेखा समिति ने इस संगठन की हाल में ब्रालोचना की है;
- (स) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि कुछ सम्बन्धित व्यक्ति इस समाज के लेन-देन सम्बन्धी मामलों को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं; भौर
- (ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में जांच करने का है ?

THE DEPUTY MINISTER (DR. SAROJINI MAHISHI): (a) No grant has been released to the Samaj since November 1966. Government have not yet taken any decision about future releases and are considering the latest report of the Public Accounts Committee received last month.

- (b) No such complaint or allegation has come to notice.
  - (c) Does not arise.

बा॰ सूर्य प्रकास पूरी: प्रध्यक्ष महोदय, भारत सेवक समाज की स्थापना पं॰ जवाहर लाल नेहरू ने जिस उद्देश्य से की थी, उस से हट कर वह प्रस्य कांग्रेसी समाज सेवी संस्थाओं के सवृश्य हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार का भनुदान मारत सेवक समाज को मिसता रहा है, उसी प्रकार का भनुदान प्रस्य भौर कितनी संस्थाओं को केन्द्र की भौर से मिसता रहा है। दूसरे—ऐसे कितने राज्य हैं, जिन्होंने भारत सेवक समाज को, जो भनुदान वह पहले दिया करते थे वह बन्द कर दिया है? तीसरे—क्या भारत सेवक समाज ने पी॰ ए॰ सी॰ की रिपोर्ट पर सभी तक प्रपनी टिप्पणी दी है या नहीं?

DR. SAROJINI MAHISHI: It is a wrong impression that undesirable people are associated with the Bharat Sewak Samaj. The objective of the Samaj is very laudable, i.e. to provide employment to the people and to create voluntary services. Therefore, it is a wrong impression to think that undesirable people and matters are associated with this institution. Secondly, I require notice as to how many States have stopped giving aid to the Bharat Sewak Samaj.

Thirdly, he asked which other organisations similar to Bharat Sewak Samaj are receiving grant. The impression carried by the hon. Member is wrong, that all institutions which have got laudable objectives and which are meant for constructive work are receiving some aid.

डा० सूर्य प्रकाश प्रदी: मेरे प्रक्त का एक भाग यह भी था कि पी० ए० सी० की रिपोर्ट के ऊपर भारत सेवक समाज ने अपनी टिप्पणी की है अथवानहीं की है?

DR. SAROJINI MAHISHI: The 34th Report of the PAC (Third Lok Sabha) and 9th Report of the PAC (Fourth Lok Sabha) deal with use of funds given to Bharat Sewak Samaj. The Department of Expenditure in the Finance Ministry has set up an enquiry committee to go into all these matters whether the funds given to this institution were properly utilised and a report is awaited.

डा॰ सूर्य प्रकाश पुरी : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ विदेशी संस्थाओं ने भारत सेवक समाज को पिछले दो क्वों में काफी बड़ी राशि सहायता कार्यों पर कवं करने के लिए दी ह ? क्या यह सच नहीं है कि एक स्पेशल एकाउंट यहां कनाट प्लेस में ब्रिडलेज बैंक में सोला गया है जिस में डेढ़ लाल रुपया बिहार के सूला पीड़तों के लिए जो इनको मिला था वह भी जमा कराया गया है और यह जो सब राशि है उसका जो ब्याज होता है उस में से कर्म-चारियों के वेतन दिये जाते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी विदेशी संस्थायें हैं जिन्होंने भारत सेवक समाज को सहायता दी है, रुपये के रूप में ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इम्बिरा गांधी) : इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। इसको हम देखेंगे।

डा० सूर्य प्रकाश पुरी: कैयोलिक मिशन ने दी है मदद या नहीं दी है ?

श्री शिव कुमार शास्त्री: लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन क्या था ? धनुमान तो श्रापने नहीं दिये हैं, लेकिन क्या ऋण के रूप में श्रापने कुछ सहायता दी है ?

DR. SAROJINI MAHISHI: The 34th Report and the 9th Report of the PAC have been placed on the Table of the House.

SHRI S. K. TAPURIAH: She has not understood the question. The question was entirely different.

MR. SPEAKER: He may kindly repeat the question.

भी शिव कुमार शास्त्री: अनुदान तो आपने नहीं दिये हैं भारत सेवक समाज को लेकिन ऋण के रूप में कुछ राशि क्या दी है या नहीं दी है?

DR. SAROJINI MAHISHI: No loans are given in recent times.

श्री राम गोपाल शालवाले : कांग्रेस पार्टी ने घपने कुछ बेकार लोगों को काम पर लगाने के लिए भारत सेवक समाज की क्या स्थापना नहीं की थी ? इसके अनुसार · · · ·

श्री शिव नारायण : उनको भी, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप चैक करें। क्या कह रहे हैं?

श्री राम गोपाल शासवाले: कांग्रेस पार्टी ने अपने कुछ बेकार तथा श्रनुपयोगी लोगों को काम पर लगाने के लिए क्या भारत सेवक समाज की स्थापना नहीं की श्रीर भारत सेवक समाज द्वारा क्या देश का करोड़ों रुपया बरबाद नहीं किया गया है। श्रीर हर प्रकार का श्रष्टाचार उसके श्रन्दर नहीं हैं? देश के करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं? इसको देखते हुए इस प्रकार से इस संस्था पर रुपया खर्च करना क्या उनके साथ श्रन्याय करना नहीं है? मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार क्या भारत सेवक समाज के कार्यालयों को बन्द करने का विचार करेगी?

श्रीमती इन्दिरा गांधी: इनके प्रश्न का जो शुरू का हिस्सा था वह विस्कुल गलत या। यह राजनीतिक संस्या नहीं है भौर इस में अनेक ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के हैं ही नहीं। कांग्रेस वालों को भी यही इससे शिकायत रही है। (इंटरफांज)

MR. SPEAKER: Order, order. I am on my legs. The hon. Member must sit down now. Allegations have been made and she has denied them flatly. She has said that it is not only Congresamen but others are also there. I cannot allow any debate here. It is Question Hour and the hon. Member cannot ask any more questions on this now.

बी राम् गोपाल शालवाले : : कुछ कांग्रेसी <sup>र</sup> हैं या नहीं हैं ? क्या इनको बन्द करने का विचार भाग कर रहे हैं? इसका जवाब नहीं मिला है । मैंने . . . .

MR. SPEAKER: He must resume his scat. I cannot allow him to put further questions on this. He cannot get up and ask questions as and when he likes.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: Is it a fact that the Government has issued an order to State Governments and the organisations under them that they should dispense with tenders and give contracts to Bharat Sewak Samaj organisation and that they should advance money to them for executing the work; if so, is it also not a fact that due to this order the Thirupathi Devasthanam, Tirupathi, has given several lakhs of rupees to Bharat Sewak Samaj and without executing any work they have swallowed the money?

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I have no information about this.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: May I know whether the Government will take the trouble of enquiring into the allcgations about funds and see whether they are being properly utilised, whether there are properly audited accounts and all that? May I know whether Government is satisfied that this organisation has got properly audited accounts of money spent and that the funds are properly utilised by this organisation?

DR. SAROJINI MAHISHI: I have already replied to that question. The Department of Expenditure in the Ministry of Finance is going to set up an Inquiry Committee to go into this matter and see whether the funds are utilised properly and in a constructive way.

भी प्रकाशबीर शास्त्री: वित्त मंत्रालय तो न सही लेकिन क्या प्रधान मंत्री के सविवालय ने इस बात की जानकारी ली है कि केन्द्रीय सरकार के भीर इसरे कुछ मंत्रासकों से जैसे समाज कल्याम विभाग है या भीर दूसरे हैं, उन से भारत सेक्क समाज ने पब्लिक एकांडटस कमेटी की रिपोर्ट धानें के बाद किसी प्रकार

का कोई अनुदान या ऋण आदि लिये हैं? इसके प्रतिरिक्त भारत सेवक समाज ने जो बड़े-बड़े करोड़ों रुपये के ठेके ले रखे थे उनके सम्बन्ध में भी क्या वित्त मंत्रालय जानकारी ले रहा है कि वहां पैसे का सदूपयोग हो रहा है ग्रयवा नहीं ?

भी बलराज मधोक : भीर ठेके पूरे नहीं होते हैं।

DR. SAROJINI MAHISHI: Certainly. the Department of Expenditure in the Ministry of Finance, when they appoint an Inquiry Committee, will look into this matter. As far as the first part of the question is concerned, as regards grants from Social Welfare Board, Health Ministry and | others, they are meant for welfare and amenities services. These matters also will be looked into by them and they are being looked into .

SHRI S. C. SAMANTA: Is it not a fact that during the Third Five Year Plan the Information and Broadcasting Ministry set up an Inquiry Committee about the working and giving of grants to this organisation; if so, may I know whether the recommendations of this Committee have been implemented up till now?

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I have no knowledge of this .

SHRI JYOTIRMOY BASU: May I know how much money has been given by Government to this Samaj during the last five years and how much land and buildings in total and in different States has been given to them by Government?

DR. SAROJINI MAHISHI: Sir, I would require notice to answer this question.

SHRI GADILINGANA GOWD: Sir, similar allegations have been made about this Bharat Sewak Samaj during the last twelve or thirteen years. May I know when this report is expected to be submitted?

SHRIMATI INDIRA GANDHI: We do not know about the enquiry.

SHRI GADILINGANA GOWD: What is the answer?

MR. SPEAKER: No enquiry.

SHRI R. K. SINHA: Is it not a fact that the grants and assistance given to Bharat Sevak Samaj are also available to other social organisations in India, and, therefore, the grants given to BSS are not of a discriminatory character? Secondly, is it not a fact that every new grant to BSS is subject to performance and, therefore, sanctioned only on presentation of last year's accounts; and the demand for consolidated accounts, as made by the Public Accounts Committee, is a new one and, therefore, there has been no lanse on the part of BSS? Also, will the Government of India enquire whether members of the Communist Party and the RSS were also active workers of the BSS, because according to my information it is 80?

MR. SPEAKER: There is no question which the Minister can answer.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: It is true that grants are given to other organisations also. Now people are focusing attention on this particular question because something has gone wrong with this aspect of the work of BSS. But we should not lose sight of the good work done by BSS in many parts of the country.

SHORT NOTICE QUESTION राज्यों को स्पिरिट की सप्लाई

S.N.Q. 15. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया स्पिरिट का पिछला कोटा नवम्बर, 1967 में समाप्त हो गया था;
- (ल) क्या यह भी सब है कि विभिन्न राज्यों को स्पिरिट का नया कोटा श्रभी तक नहीं दिया गया है; श्रौर
- (ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं:?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH): (a) to (c). The Central Government does not supply any quota of spirit (alcohol) as such,

to the States. In order to ensure proper and equitable distribution of alcohol for industrial purposes on all India basis, the Central Government plays the role of a coordinating agency in that alcohol declared surplus to their requirements by certain States is allocated to other States which cannot meet their requirements from the production within their States. The inter-State allocations of alcohol are made subject to availability and constitute direct transactions between the supplying and the receiving States. A meeting with the representatives of the States which may have surplus alcohol to spare is scheduled to be held in Delhi on the 22nd December, 1967, for the purpose of assessing the surpluses available for inter-State allocations. The meeting is usually held some time after the commencement of the sugar season in November, when estimates of production of alcohol become available. The meeting this year could not be held carlier as the concerned States were not in a position to furnish estimates of Meanwhile to meet the production. urgent demands of Delhi State, the surplus States have ben requested to make small supplies as an ad hoc arrangement pending finalization of inter-State allocations.

भी रघुवीर सिंह सास्त्री: मंत्री महोदय ने बताया है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के लिये कोटा निर्धारित नहीं करती है, प्रिप्तु वह केवल समन्वय एजेन्सी के तौर पर काम करती है। क्या यह ठीक है कि राज्यों को उस की प्रावश्यकता से प्रिष्ठिक कोटा मिल जाता है और कुछ राज्यों को उन की प्रावश्यकता से कम, जिस का परिणाम यह होता है कि जिन राज्यों को प्रिष्ठिक कोटा मिलता है, उस के ब्यापारी स्पिरिट को दूसरे राज्यों में ऊने दामों पर बेचते हैं और उस की चोरबाजारी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस भेदभाव को और स्पिरिट में होने वाली चोर-बाजारी को समाप्त करने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

SHRI RAGHU RAMAIAH: The role of the Central Government has already been stated by me. There is no question of any statutory allocation. It co-ordinates and it advises the surplus States to

allocate a certain quantity to a deficit State. Thereafter it becomes a transaction between the two States. If in that there is a lacuna, either some State does not supply or some State gets an over-supply, it is a matter which has to be looked into. But it is a matter entirely between the two States.

भी रखबीर सिंह शास्त्री: मंत्री महोदय ने यह भी बताया है कि श्रागामी 22 दिसम्बर को वह इस सम्बन्ध में राज्यों के प्रतिनिधियों की एक बैठक कर रहे हैं। पीछे 12 दिसम्बर को इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने बताया था कि इस वर्ष शीरे श्रौर शगर का उत्पादन कम होने के कारण स्पिरिट का उत्पादन भीर भी कम होने की सम्भावना है श्रीर यह कि कुछ राज्य सरकारें पीने की शराब पैदा करने की श्रोर ज्यादा घ्यान देतीं हैं, क्योंकि उससे उनको ज्यादा रेवेन्य प्राप्त होता है। मैं यह जानना चाहता हं कि क्या मंत्री महोदय 22 दिसम्बर की मीटिंग में राज्यों के मंत्रियों या प्रतिनिधियों को इस बात के लिए पर्स्वेड कर सकेंगे कि पीने की शराब पैदा करने में कमी की जाये . . . .

SHRI HEM BARUA: Why?

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : ....श्रीर उस के स्थान पर स्पिरिट का उत्पादन ज्यादा किया जाये, क्योंकि स्पिरिट पेस्टीसाइड इंडस्ट्री में काम श्राती है, हास्पिटल्स में काम श्राती है श्रीर मानवीय दृष्टिकोण से उसका श्रीषक उपयोग होता है।

SHRI RAGHU RAMAIAH: Last August there was a meeting of the various Excise Ministers from the various States and they wanted a certain priority to be given to the potable alcohol. That has been given but we are constantly emphasizing on the various States the need for utilising it for industrial purposes.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTER-JI: The hon. Minister has aid that they are only serving the co-ordinating purpose. Is he aware of the scarcity that is prevailing in Calcutta and other urban areas which has been creating difficulties because spirit is often used for medical purposes? Will he make it possible through his coordinating efforts that the supply is regular?

SHRI RAGHU RAMAIAH: We are fully aware that alcohol is required for drugs and pharmaceuticals, let alone for polyethylene and synthetic rubber purposes. Last year we did import some alcohol and the question of import of alcohol in the future also is not ruled out.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि स्पिरिट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स लिये जा रहे हैं श्रीर क्या उसका कुछ इम्पोर्ट या भायात भी किया जायेगा।

SHR1 RAGHU RAMAIAH: The increase in the output of alcohol depends on the increase in sugar production.

भी स्वतन्त्र सिंह कोठारी: माननीय मंत्री मेरे प्रश्न को समझे नहीं हैं। मैंने यह भी पूछा है कि इम्पोर्ट के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है?

MR. SPEAKER: He has answered it previously. That was exactly what was asked, that is, about imports. You did not hear the answer then.

भी बिभूति मिश्रः क्या मंत्री महोदय को पता है कि छोग्ना से स्पिरिट बनती हैं; छोग्ना स्टेट सरकारों के हाथ में रहता है भीर जब गन्ना पेरने का दूसरा सीजन माता है, तो वे सरकारें छोग्ना को ठेकेदारों को रिलीज करती हैं, जिस का नतीजा यह होता है कि बहुत सा खोजा बहु जाता है और उसकी स्पिरिट नहीं बन पाती है? छोग्ना का दाम किसानों को चार प्राने मन मिलता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार छोग्ना के उत्पादन पर प्रपना प्रशासन भौर नियन्त्रण रखेगी, ताकि पहिले से ही छोग्ना को स्पिरिट बनाने के लिए कारखानेदारों को दे दिया जाये, उस से ज्यादा स्पिरिट बन सके भौर उस में कमी न हो।

SHRI RAGHU RAMAIAH: The whole object of the meeting which is scheduled to be held at some time towards the end of this month, as I have already indicated, is to regulate all these things.

श्री मत्युंजय प्रसाद: मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले साल कितनी स्पिरिट विदेशों को भेजी गई श्रीर क्या इस समय स्पिरिट का बहुत बड़ा स्टाक बाहर भेजने के लिए कलकत्ता में रखा हुया है।

SHRI RAGHU RAMAIAH: I am afraid, it is a question of import not of export. Last year we imported 41,883 tonnes of alcohol.

भी महाराज सिंह भारती: मैं मंत्री महोदय का घ्यान पिछले सप्ताह के योजना ग्रखबार की ग्रोर खींचना चाहता हूं। उसके सम्पादकीय लेख में कहा गया है कि—वह किसी ऐसे वैसे ग्रादमी का लेख नहीं है, बिल्क सरकारी ग्रादमी का लेख है—इस मुल्क में गन्ने की खेती की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उस की जगह भनाज पैदा किया जाये भीर चीनी बाहर से मंगाई जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने यह नीति ग्रपना ली है कि गन्ने की खेती खत्म की जाये। यदि हां, तो क्या वह स्पिरिट को बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट करने की सोच रही है?

SHRI RAGHU RAMAIAH: I should imagine that is primarily a question for the Food Minister to consider as to how much sugar they want and how much food they want.

भी महाराज सिंह भारती: योजना सरकारी मलवार है भौर उस के सम्पादकीय लेख में यह बात कही गई है।

SHRI MANUBHAI PATEL: The basic material for the manufacture of spirit is molasses. Mahuwa also is used as a basic material but that is not so cheap. From certain sugar factories these molasses are being exported to other countries. Has it come to the notice of the Government; is so, what steps is the Government talking in that regard?

SHRI RAGHU RAMAIAH: Export has been completely stopped with effect from 25th May, 1967 and 17th July, 1967 respectively in the case of Alcohol and Molasses.

SHRI SONAVANE: What steps are being taken to see that spirit is not diverted for drinking purposes by the drink addicts?

SHRI RAGHU RAMAIAH: We can only appeal to the States to be vigilant in this matter.

श्री तुलसीदास आधवः कहीं कहीं यह मोलेसेस फैंक दिया जाता है नदियों में श्रीर जमीन में श्रीर इसकी दुर्गंघ सब जगह झाती है। तो इस मोलैसेस का पूरी तरह उपयोग करने के लिए कोई इंतजाम सरकार ने किया है?

SHRI RAGHU RAMAIAH: Proper storage of molasses is one of the steps constantly before this all-India conference.

SHRI SRINIBAS MISRA: Does the Government think of giving some incentive for the production of alcohol so that production can be encouraged and by that process there will be a swith-over from tari for drinking purposes?

SHRI RAGHU RAMAIAH: I am afraid, industrial alcohol can be got only through molasses. Of course, there is a scheme in Bombay whereby they want to produce it out of ethylene which will reduce the demand for alchohal for the production of polyethylene etc. but that is still to come.

SHRI D. C. SHARMA: According to the statement made by the hon. Minister, even the essential services such as the hospital services, which are serving humanity, are being starved of the supply of spirit. In view of this background that even the hospital services do not get the required quantity of spirit for helping the patients, will the Government think that instead of cc-ordinating the activities of the State Governments and bringing about some kind of a consensus among them, they will try to import more spirit so that these essential services continue to run and that there may be the necessity of a change of policy even though you say, Sir, that a change of policy is not to be discussed during the question Hour?

SHRI RAGHU RAMAIAH: As I said last year too we imported some alcohol and whatever our requirements are to the extent that import is necessary we shall certainly do so.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: From the answers given it seems to me that there is a competition between those who are addicted to drink and those who want to manufacture alcohol out of molasses. Is it not therefore, in the interest of reducing this competition that people should be allowed to produce their own alcohol in their own houses for drinking purposes?

#### WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

EVACUATION OF TIBETAN BORDER VILLAGES
BY THE CHINESE

\*722. SHRI YAJNA DATT SHARMA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Chinese across the border in Tibet! are evacuating villages 7 to 10 miles from the border in the Central sector:
- (b) whether unwanted Tibetan civilians are being encouraged to flee to India; and
- (c) if so, the steps taken by Government to screen all Tibetan refugges entering India to detect any Chinese saboteurs entering India in the garb of refugees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT): (a) Government have no information to support this statement.

- (b) Some Tibetan refugees are fleeing to India as a result of religious persecution or similar reasons.
- (c) All Tibetan refugees entering India are carefully interrogated and screened to detect and prevent infiltration of subversive elements. This information was given in answer to Starred Question No. 1348 on the 24th July, 1967.

#### INDIAN STATISTICAL INSTITUTE

\*726. SHRI R. S. VIDYARTHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1032 on the 10th July, 1967 and state:

- (a) whether any decision has since been taken on the recommendations of the Review Committee of the Indian Statistical Institute; and
  - (b) if so, the details thereof?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

#### MANGLA DAM

- \*727. SHRI HEM BARUA: Will the Miniser of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that Government have contributed Rs. 130 crores towards the construction of the Mangla Dam by Pakistan; and
- (b) if so, whether the political aspect of the problem was taken into consideration while making this contribution?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT): (a) No. Sir.

- (b) Does not arise.
- U. S. EMBASSY OFFICIALS CORRESPONDING WITH STATE GOVERNMENTS

•728, SHRIA. K. GOPALAN: SHRI GANESH GHOSH: SHRI UMANATH: SHRI P. GOPALAN:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the officials of U.S. Embassy are writing directly to the State Governments ignoring his Ministry;
- (b) if so, whether the Chief Secretary, Jammu & Kashmir Government has forwarded a letter from one U.S. Embassy official asking the State Government to give facilities to some Embassy officials visiting Kashmir;
- (c) whether Government have taken up this matter with the U.S. Embassy; and
  - (d) if so, the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT): (a) Senior diplomatic officers of the U.S. and other Embassics have at times written directly to State Governments in connection with intended visits of their Deplomatic Officers, particularly when these are undertaken at short notice.

- (b) Yes, Sir.
- (c) and (d). Government have not taken up this matter with the U.S. Embassy as there is no objection to foreign missions corresponding directly with State Governments on routine matters. However, foreign Missions in Delhi have been informed that we would welcome such intimation to be given to the Ministry of External Affairs whenever Members of the Mission intend to visit the States on official or semi-official business.

RECRUITMENT ON LINGUISTIC BASIS

\*729. SHRI D. N. PATODIA: Will the
Minister of INFORMATION AND
BROADCASTING be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Government have decided to make recruitment for ministerial staff on linguistic basis;
  - (b) if so, the reasons therefor; and
- (c) the manner in which this change would lead to greater efficiency in the working of the A.I.R. Stations?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): (a) to (c). No, Sir, but there is a proposal to restrict transfers and promotions of Clerk Grade II, Clerk Grade I, Storekeepers, Head Clerks, and Accountants to a particular State. This may indirectly lead, to some extent, to appointments being restricted to particular language-knowing people but under the rules this is not so. The reasons are purely administrative economy and keeping up efficiency.

## विवेशों से भारत मूलक लोगों का स्ववेश लौटना

\*731. श्री मोलहू प्रसाद : क्या बैदेशिक-कार्य मंत्री ७ नवम्बर, १६६६ के तारांकित प्रकृत संख्या १४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की बढ़ती हुई जन-

संख्या हैं को देखते हुए बर्मा तथा है पूर्वी अफ्रीका के देशों में बसे भारत मूलक लोगों को स्बदेश लौटने से रोकने के लिए प्रतिकारात्मक कार्य-वाही करने का सरकार का विचार है।

- (स) क्या सरकार स्वदेश लौटने वाले भारतीयों को पूरी सहायता दे रही है ताकि वह ग्रपने पहले रहन सहन के स्तर पर पहुंच सकें; ग्रौर
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वैदेशिक-कार्य मंत्रासय में राज्य-मंत्री (श्रीव०रा०भगत) (क) सरकार का मत है कि भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रश्न को विदेशों से भारत लौटने वाले श्रयवा देश प्रत्यावर्तित होने वाले भारतीय मूल के लोगों के प्रश्न से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

(ख) और (ग). देश प्रत्यार्वात्यों के पूनर्वांस को सुविधाजनक बनाने के लिए और भारत में उनके जीवन-यापन का स्तर समुचित कंचा उठाने में उनकी सहायता करने के निए कदम उठाए जाते हैं।

RUMANIA'S REACTION TO NON-PROLIFERA-TION TREATY

\*732. SHRI MADHU LIMAYE: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether Government's attention has been drawn to the Rumanian comment/ memorandum on the Draft non-proilferation treaty:
- (b) the main points of this comment/ memorandum;
- (c) whether Government agree with all or any of these points if so, which; and
- (d) whether Government propose to cooperate with Rumania and other powers in countering U.S.—U.S.S.R. pressure?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT): (a) Yes, Siz.

- (b) A statement is placed on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT—2040/67].
- (c) The Government generally agree with the above-mentioned points.
- (d) There has been no such pressure. The question of countering it does not arise.

#### DIVERSION BARRAGE ON BURI TEESTA

- •734. SHRI S. C. SAMANTA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 289 on the 5th June, 1967 and state:
- (a) whether the detailed information on the construction of a diversion barrage on the Buri Teesta has since been received from our Mission in East Pakistan and also from the West Bengal Government; and
  - (b) if so, the contents thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT):(a) and(b). Neither the Government of West Bengal nor our Mission in Dacca have been able to provide detailed information on this subject.

#### USE OF ATOMIC ENERGY

# \*735. SHRI A.B. VAJPAYEE;" SHRI JAGANNATH RAO JOSHI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) whether the achievements of the Atomic Energy Commission in India so far have directly been made use of for increasing agricultural production and industrial development for increasing power generation capacity, for raising people's health standard or for strengthening the defence arrangements; and
- (b) if so, the details and the results thereof?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). A statement giving the required information is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT—2041/67].

#### DECENTRALIBATION OF ALL-INDIA RADIO

#### \*736. SHRI HIMATSINGKA: SHRI YASHPAL SINGH:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

- (a) whether Government have accepted the recommendations of the Chanda Committee with regard to the decentralisation of All India Radio; and
- (b) if so, the action taken thereon particularly regard to a closer link between the State administrations and regional radio stations?

# THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): (a) Yes, Sir.

(b) Decentralisation of authority and func tions is a continuous process. Some steps have already been taken in this direction. The Stations of All India Radio have now greater freedom in the matter of programme planning and presentation. Their talks and Drama Schedules etc. have no longer to be approved by the Headquarters. It is not obligatory now for Stations to relay Central Programmes except broadcasts by the President and Prime Minister and the national news bulletins. The Heads of Stations have been delegated administrative powers to appoint staff artists upto a certain limit. and administrative powers The financial delegated to Station Directors are reviewed periodically and enhanced whenever necessary.

As regard the establishment of a closer link between the regional Radio Stations and the State Administrations, measures to ensure more active participation of State Governments in the work of the various Stations of AIR are under consideration of Government.

#### ENQUIRY ABOUT ATROCITIES ON BUDDHIST COMMUNITY IN EAST PARISTAN

#### •737. SHRI D. C. SHARMA: SHRI SAMAR GUHA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to refer to the reply

given to Starred Question No. 1026 on the 10th July, 1967 and state;

- (a) the result of the enquiry made into the alleged atrocities committed on the Buddhist community in Chittagong in East Pakistan; and
  - (b) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT): (1) It has already been stated in answer to the Lok Sabhs Starred Question No., 1026, dated 10th July, 1967 that the Government had enquired into the incident involving an attack on members of the Buddhist community in Cox's B121r, Sub-division of the Chittagong District in East Pakistan, and had reason to believe that newspaper reports were correct. No further enquiry was considered necessary.

(b) As the House will appreciate, and as Government have stated before, the question of safeguarding the rights of minorities in Pakistan is the responsibility of the Government of Pakistan. However, from time to time the Government of India have represented to the Pakistan Government against the harassment of minorities in Pakistan, and have reminded them of their obligations in this regard under the Nehru-Liaquat Pact.

#### उत्पादन लक्ष्य

\*738. भी रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के लिए निर्घारित किये गये विभिन्न उत्पादन लक्ष्य पूरे हुए हैं; भ्रौर
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं:?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख). चालू योजना वर्ष ३१ मार्च, १६६८ को जा कर समाप्त होगी। अतः साफ जाहिर है कि फिलहाल स्थिति को बताना सम्भव नहीं।

#### RADIO CEYLON

•739. SHRI SHIVA CHANDRA HA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Radio Ceylon with continuous film songs operates from India:
  - (b) if so, the reason therefor;
- (c) whether Government plan to have such continuous national songs, dramas, etc. from A.I.R. Station in India; and
- (d) if so, when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): (a) No, Sir.

- (b) Does not arise.
- (c) All India Radio already have a service of a variety programme of songs, dramas etc. called Vividh Bharati, which is broadcast from two Short-Wave transmitters at Bombay and Madras as well as from 26 other Vividh Bharati Centres with low-power transmitters.
  - (d) Does not arise.

CORPORATION FOR ALL INDIA RADIO

\*740. SHRI SHRI CHAND GOEL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state the progress so far made to set up an autonomous corporation for the All India Radio?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): The proposal regarding conversion of All India Radio into an autonomous corporation is under active examination but till the decision is taken, it is difficult to give out the details of the progress made in this regard.

#### CEASEFIRE IN NAGALAND

•741. SHRI NITIRAJ SINGH CHAU-DHARY: Will the MINISTER OF EXTER-NAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to continue to extend the ceasefire period in Nagaland uniteterally, white hostile Nagas continue to violate it; and

#### (b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B.R. BHAGAT): (a) and (b). In furtherance of their objective of seeking a a peaceful solution, Government have been extending the period of the Suspension of Operations from time to time. This policy has been explained in the House on various occasions. Attention is invited to replies to Starred Question No. 445 dated the 12th June, 1967 and No. 285 dated 27th November, 1967.

In Nagaland, there has been no major violation of the arrangement. However, there have been a few viiolations in certain parts of Manipur which have been effectively dealt with by the State Government and the security forces.

#### CONFERENCE OF STATION DIRECTORS OF ALL INDIA RADIO

•742. SHRI CHANDRA SEKHAR
SINGH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be
pleased to state:

- (a) the subjects discussed at the conference of Station Directors of All India Radio held recently in New Delhi; and
  - (b) the decision taken thereon?

THE MINISTER OF INPORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): (a) The conference of Station Directors discussed a variety of subjects relating to the day-to-day running of radio stations in respect of programme, technical and administrative matters, of which the more important were:

- Co-ordination with State Governments in the programmes of local Radio Station;
- Principles for scrutiny of scripts of intending broadcastor's;
- Need to broacast more discussions on current affairs reflecting different points of view;
- Recruitment of programme staff on linquistic basis;
- Projection of the national image of Gandhiji among younger generations;

- Strengthening of school and industrial broadcests;
- Fuller utilisation of commercial records and repeat broadcasts of important programmes;
- Devotional programmes;
- 9. Broadcast of Price Bulletins;
- Utilisation of existing technical facilities to the maximum possible advantage and evolving methods for quick communication between various news Units; and
- Ensuring the highetst technical quality in the programmes.
- (b) The suggestions made by the Conference will be examined for adoption, as far as possible.

#### DEVELOPMENT OF STATES

•743. SHRI S. KUNDU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) whether she is aware of the growing imbalance between the less developed States and developed States of India;
- (b) if so, the per capita income of the people of the different States and the total income (gross national income) of the different States with area and population, yearwise, from the beginning of the Pirst Plan, upto-to-date; and
- (c) the steps Government propose to take to square up the growing imbalance between the States?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EX-TERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI) (a) to (c). Reliable : statistical data are not available to estimate the of imbalances nature and quantum between less developed States and developed States. Historical, geographical and domographic factors have inevitably created imbalance and unevenness in economic and social development. There is also the problem of backward areas within States. All these facts are taken into account in determining Plan outlays, allocatin Central assistance and in locating Central industrial projects. Attempts will continue to be made to reduce disparities among States through successive Five-Year Plans/Annual Plans.

Uniform concepts, standards and methodology were not evolved during the First and Second Plan periods for computing per capita income of different States. However, for the Third Five-Year Plan period, certain data were collected and are contained in the reply given on November 10, 1966 to Unstarred Question No. 1069.

Information regarding the area and population for different States is available in the Census Reports and the published documents of the Central Statistical Organisation—Annual Statistical Handbooks of the Indian Union.

# Indian Internees in Pakistan Detention Camp

•744. SHRI HARDAYAL DEVGUN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Indian internees in the Pakistan Detention Camp are still rotting and according to Pakistan agencies, the Indian High Commission has refused to recognise 29 of the Internees as Indians and the travel documents to the remaining internees have not been issued; and
- (b) if so, the reasons therefor and the further action which Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B.R. BHAGAT): (a) and (b). According to our High Commission Pakistan, there are at present 152 internees in the Lahore Internment Camp who have been presented by the Government of Pakistan for repatriation as Indian nationals. Out of this number, 42 persons are not acceptable to us for repatriation to Indian as on enquiries they have not been found to be Indian nationals. Out of the remaining 110 internees in the Camp, 51 are either deaf and dumb or demented and their national status cannot be verified. The cases of the remaining 59 persons are under consideration of the State Governments concerned.

# राष्ट्रीय विकास परिवद की बैठक

\*747. श्री रामावतार शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन के मुख्य मंत्रियों ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की मन्तिम बैठक में भाग लिया था:
- (स) क्या बैठक में देश में ग्राधिक संकट दूर करने के उपायों पर भी विचार किया नया था; ग्रौर
- (ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वर्देशिक-कार्य मंत्री (क्षीमती इन्दिरा गांधी): (क) बैठक में आन्ध्र प्रदेश गुजरात, जम्मू तथा कशमीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान ग्रीर उत्तर प्रदेश राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भाग लिया, इसके ग्रातिरिक्त शेष राज्यों ग्रीर संघ शासित क्षेत्रों के मंत्रियों या श्रन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ख) और (ग) वर्ष 1968-69 की की वार्षिक योजना की पृष्टभूमि और नीति सम्बन्धी पेचीदिगियों पर विचार-विनिमय करते, समय, परिषद् ने चालू वर्ष की आर्थिक प्रवृत्तियों पर भी विचार किया । बैठक में जो मुख्य निर्णय लिये गये वे दिनांक 11 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 584 के उत्तर में सभा की मेज पर रखे गये विवरण में दिए जा चुके हैं ।

INDO-U.A.R. PROJECT FOR MANUFACTUR-ING HF-24 JETS

•748. SHRI INDRAJIT GUPTA: SHRI DHIRESWAR KALITA: SHRI HIMATSINGKA:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state;

- (a) whether it has been decided to give up the Indo U. A. R. project for building a supersonic fighter aircraft;
  - (b) if so, the reasons therefor; and
- (c) the implications of the decision for the fututre of the HF-24 aircraft;

THE MINISTER OF STATE DEFENCE PRODUCTION IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA):
(a) No, Sir. Flight development trials of the E-300 engines installed in an HF-24 airframe are still in progress in U.A.R. The question of manufacture of the aircraft in collaboration with U.A.R. will arise only after the successfull completion of the flight trials.

(b) and (c) : Do not arise.

# RADIO PEACE AND PROGRESS AND RADIO MOSCOW

•749. SHRI KAMESHWAR SINGH: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether Government's attention has been drawn towards the recent criticism by the Radio Peace and Progress and Radio Moscow regarding the Madhya Pradesh Government; and
- (b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B.R. BHAGAT): (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India are taking up the matter with the Soviet authorities.

# CONTRACT WITH A.I.R. STAFF ARTISTES \*750. SHRI S. M. BANERJEE: SHRI GEORGE FERNANDES: SHRI RAMAVATAR SHASTRI:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

- (a) whether a new long-term contract is sought to be introduced for the All India Radio staff artistes;
  - (b) if so, the terms thereof;
- (c) whether the staff artistes individually and through their Guild have protested against the introduction of this new contract; and
- (d) if so, the steps Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): (a) and (b) Orders to replace the existing system of five year contract by a letter of appointment extending their ser-

vices upto the age of 55 years, which may further be extended upto 58 years and, in very special cases upto 60 years, have already] been issued. A copy of the form of letter of appointment is laid on the table of the House. [Placed in Library See No. LT—2042/67].

(c) and (d): Oral representations have been received from individual Staff Artist and Staff Artists Association. The All India Radio Broadcasters and Telecasters Guild has sent a representation in writing objecting to certain provisions contained in the new contract. These objections are being examined.

### सवाई माधो पुर (राजस्थान) का विकास

4662. श्री मीठा लाल मीना : क्या प्रधान मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि राजस्थान के सवाई माघोपुर जिले को पिछड़ा हुमा क्षेत्र घोषित किया गया है; ग्रीर
- (स) चालू वर्षं में उस जिले के मिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराणि नियत की गई है और वह राशि किन किन मदों पर सर्च की जायेगी?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरागांधी): (क) जी, हां।

(स) साधनों की बंदिश होने के कारण, इस जिले के तेजी से विकास के लिए राज्य की वार्षिक योजना 1967-68 में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया जासका।

#### DEFENCE CONTRACTS

4663. SHRI BABURAO PATEL: Will the MINISTER OF DEFENCE be pleased to state:

- (a) the number and amount of contracts directly given or caused to be given by the former State Minister of Defence, Shri B.R. Bhagat; and
- (b) the particulars of the proceeding followed in giving the above contracts?

(Rs.

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA): (a) Nil.

- (b) Does not arise.
- P. M. SECRETARIAT'S PUBLICATIONS 4664. SHRI BABURAO PATEL: Will

the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) the number and names of periodicals published by the Prime Minister's Secretariat and the nature of periodicals with names of those who write and edit them;
- (b) the number of copies of each periodical printed, either weekly or monthly as the case may be, the actual number of copies sent free and the persons and places where they are distributed;
- (c) the cost for publishing the periodicals annually and the recurring expenditure incurred for this purpose;
- (d) the amount realized from the sale of of copies of the different periodicals annually;
- (e) the purpose for which this literature is published and the measure of purpose it has served so far; and
- (f) if the periodicals are a losing concern, whether Government propose to close them down and if not, the reasons therefor?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRAGANDHI): (a) The Prime Minister's Secretariat does not publish any periodical.

(b) to (f). Do not arise.

GUJARAT'S SCHEME FOR INCLUSION IN THE FOURTH PLAN

4665. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) whether Gujarat Government have submitted their schemes for inclusion in the Fourth Plan;
  - (b) if so, the main features thereof;
- (c) the estimated amount to be spent;and
- (d) the proposals for raising the funds for the schemes to be included in the Plan?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIARS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) Sir, the Gujarat Government had submitted their schemes for inclusion in the Fourth Plan as envisaged earlier.

(b) and (c). The main provisions as merged after discussions with the State Government are:—

crores)
86 · 41
202 · 33
22 .00
41 ·10
73 -54
20 -62

TOTAL: 446.00

(d) The draft Fourth Plan outlay of Rs. 446 crores as indicated above was to be financed as under:

(Rs. crores)

Central Assistance 165

State Resources 281

TOTAL 446

INVESTMENTS IN PUBLIC SECTOR PROJECTS

4667. SHRI S. R. DAMANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) whether the question of increasing investment in public sector projects in the third year of the Fourth Five-Year Plan is under consideration;
  - (b) if so, the details thereof; and
- (c) whether the Planning Commission has concurred with the suggestion?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) to (c). The Planning Commission is currently engaged in discussions with the State Governments and the Central Ministries regarding the Annual Plan for 1968-69. The financial provisions will be based on the assessed requirements of each

project and the availability of resources. A definite indication of the possible investment in public sector projects will emerge only after these discussions are over.

#### RESORT TO FIRING IN NAGALAND

4668. SHRI NITIRAJ SINGH CHAU-DHARY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state the number of times firing was resorted to during the ceasefires firing was resorted to during the ceasefire persons killed and wounded as a result of such firings.

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): A statement showing details of exchange of fire between our Security Forces and underground Nagas since 6th September 1964 to 30th October, 1967 in Nagaland is placed on the Table of the House. [Placed in Library Sce. No. LT—2043 67].

# SCHOLARSHIPS TO CADETS OF INDIAN MILITARY ACADEMY

4669. SHRI M. MEGHACHANDRA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

- (a) whether the student cadets studying in the Rashtriya Indian Military Academy, Dehra Dun are paid some scholarships by their respective State Governments; and
- (b) if so, the names of State Governments and Union Territories which pay such scholarships and the amount per head per annum?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE) (SHRI L. N. MISHRA): (a) Yes.

(b) The names of State Governments and Union Territories which pay such scholarships and the amount per head per annum is given in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library See. No. LT—2044/67]. SCHOLARSHIPS TO CADETS OF INDIAN MILITARY ACADEMY FROM MANIPUR

4670. SHRI M. MEGHACHANDRA I Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

- (a) the number of student cadets sent by Manipur Government now studying in the Rashtriya Indian Military Academy, Dehradun;
- (b) whether the Government of Manipur has awarded some scholarships to their student cadets; and
  - (c) if not, the reason for the dealay?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA): (a) 13.

- (b) No.
- (c) Does not arise.

# मंत्रियों के व्यक्तिगत .जीवन से सम्बन्धित घटनाओं को आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में शामिल करने से सम्बन्धित सिद्धान्त

4671 श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में मंत्रियों के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित घटनाओं को शामिल करने के लिये कोई निर्देशक सिद्धान्त हैं; और
- (खा) यदि हां, तो उनकी मुख्य बात क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के॰ के॰ शाह) : (क) जी, हां।

(ख) चयन इस आधार पर किया जाता है कि समाचार बुलेटिन बिगेष के लिए उप-लब्ध कुल समाचारों के संदर्भ में प्रत्येक समाचार का समाचार के रूप में सापेक्ष महत्व क्या है।

# डलहोजी में तिस्वती शरणार्थियों का पुनर्वास

4672. श्री शशि भूषण वाजपेयी : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे • कि :

- (क) तिब्बती शरणार्थियों को मसूरी से हटा कर डलहीजी ले जाने के क्या कारण हैं;
- (बा) दलाई लामा को मसूरी से उलहौजी भेजने के क्या कारण हैं। और
- (ग) तिब्बती शरणाधियों के लिए सरकार ने अब क्या योजना बनाई हैं?

प्रवान मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तिब्बती शरणार्थी मसुरी में बराबर रह रहे हैं।

- (ब) 1960 में दलाई लामा धर्मशाला चले पए बे; उलहीजी में नहीं। यह इसलिए किया गया कि धर्मशाला शांतिपूर्ण स्थान था और इस प्रकार उसे ध्यान-मनन आदि के जिए अधिक उपयुक्त समझा गया। मकान के लिए और अच्छी सुविधाएं देने पर भी विचार किया गया।
- (ग) लगभग 4000 तिब्बती शरणाधियों को जमीन देकर बसा दिया गया है। लगभग 5000 तिब्बती शरणाधियों को बसाने के लिए मैसूर राज्य के मुंडगोड नामक स्थान में एक नई कृषि बस्ती स्थापित कर दी गई है।

परम पावन दलाई लामा द्वारा संगठित तिब्बती औद्योगिक पुनर्वास सोसायटी के पास 5000 तिब्बती शरणाधियों को फिर से बसाने का कार्यक्रम है; इनमें से लगभग 1000 शरणाधीं हिमाचल प्रदेश में विभिन्न प्रामोजनाओं पर भेज दिए गए हैं।

फिलहाल जमीन की कमी के कारण हमें पुनर्वास के काम में कठिनाइयां पेश आ रही हैं लेकिन उसे खरीदने और उपयोग में लाने की कोशिशों की जा रही हैं।

शिक्षा और चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के बारे में आवश्यक प्रबन्ध भी कर दिए गए हैं।

QUASI-PERMANENT OFFICIALS IN M.E.S.

4673. SHRI Y.A. PRASAD: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that in M.E.S., there is a large number of cases where quasi-permanent officials are, contrary to the rules, required to await their turn for over 10 years before they are made permanent
  - (b) if so, the reasons therefor; and
- (c) whether Government propose to lay on the table statement showing separately particulars of cases where permanency of certain officials has been delayed for over 3 years, over 10 years and 15 years?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH): (a) and (b), No, Sir, Cases where permanency has been delayed for over 10 years are rare.

(c) Information is being collected and a statement will be laid on the Table of the House in due course.

#### M.E.S. ENGINEERS

4674. SHRI Y. A. PRASAD: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

- (a) whether a considerable number of Engineers without degree or diploma employed in the Military Engineering Service represents those who have risen from clerical cadre, and
- (b) whether, in view of the fact that qualified engineers are now available in large numbers, the entry to the engineering cadre from clerical cadre has been stopped?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L.N. MISHRA): (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

#### DEVELOPMENT OF BACKWARD AREAS IN HIMACHAL PRADESH

4675. SHRI PREM CHAND VERMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) whether any areas in Himachal Pradesh have been recognised as backward areas:
- (b) if so, the amount likely to be spent thereon;
- (c) whether any recommendations have been received from the Himachal Pradesh Government for declaring certain other areas as backward areas; and
  - (d) if so, the nature thereof?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) No, Sir.

- (b) Does not arise.
- (c) No. Sir.
- (d) Does not arise.

## अजमेर में उसमें माग लेने के लिये पाकिस्तान से यावी

4676. श्री **भॉकर लाल बेरवा**: क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के यात्रियों ने हाल में राजस्थान के अजमेर में हुए उर्स में भी भाग लिया था।
  - (ख) यदि हां, तो कितने लोगों ने
- (ग) क्या उन्हें सरकार द्वारा विजा दिवे गये थे ;
- (घ) क्या यह भी सच है कि उन में से बहुत लोगों को सीमा पर गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वे पाकिस्तान से लाये सामान को बेच कर अपने साथ भारतीय सामान ले जा रहे थे; और
- (ङ) यदि हां, तो किनने व्यक्तियों का सामान पकड़ा गया था ?

# प्रवान मंत्री, अनु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वेदेशिक-कार्य मंत्री (बीमती इन्दिरा गांची ): (क) जी हां।

- (**ख**) 134 I
- (ग) जी हां।
- (घ) जी नहीं।
- (इ.) प्रष्न नहीं उठता ।

## कोहिमा में नागा सम्मेलन

# 4677. भी रघुवीर सिंह सास्त्री : भी शिव कुमार शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह **बताने की** कृपा करेंगे कि :

- (क) क्यायह सच है कि छिपे नागाओं ने 5 दिसंबर को कोहिमा में एक सम्मेक्सन कियाथा;
- (ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई पूर्व सूचना मिली थी; और
- (क) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में **सरकार** ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री , अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री, तथा बैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्बिरा गांधी) : (क) नागालैण्ड वैस्टिस्क चर्च कौंमिल ने यह सम्मेलन बुलाया था। उन्होंने 77 लोगों के पास निमंत्रण भेजा था, जिनमें कुछ छिपे नागा भी थे।

(ख) और (ग) : सरकार के पास प्रस्तावित बैठक के बारे में सूचना थी और बह ऐसी किन्हीं भी कोशियों का स्वागत करती है जो उस क्षेत्र में स्थायी गांति और स्विरता ला सकें।

SALE OF PRESIDENT AYUB KHAN'S BOOK ENTITLED 'FRIENDS NOT MASTERS'

4678. SHRI D. C. SHARMA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether book sellers in Delhi have gone back on their previous decision to boycott President Ayub Khan' book 'Friends not Masters'; and (b) if so, the reaction of Government on the sale of the book in India?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) The Government have seen press reports to this effect.

(b) The House has already been informed of the Government of India's decision to permit the import and sale of this book in In dia.

CARS WITH U.S. EMBASSY

4679. SHRI UMANATH: SHRI E. K.NAYANAR: SHRI P. GOPALAN: SHRI JYOTIRMOY BASU:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the U.S. Embassy has got more cars than the sanctioned number;
- (b) whether Government propose to look into the matter; and
  - (c) if so, when?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) No, Sir. Government have not fixed a ceiling in respect of the number of cars which a foreign Embassy or Mission may possess. Cars are being imported by them in accordance with their actual requirements, based on the strength of the Mission.

(b) and (c). Do not arise.

POLITICAL ASYLUM TO DR. DHARMA TEJA 4680. SHRI S. M. BANERJEE: SHRI KAMESHWAR SINGH: SHRI M. SUDARSANAM:

Will the Minister of EXTENRAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether any final reply has been received from the Government of Costa Rica with regard to the question of granting political asylum to Dr. Dharam Taja; and
- (b) if so, the nature thereof and the reaction of Government thereto?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATINDIRA GANDHI): (a) The decision of the Costa Rican Government is awaited.

(b) The question does not arise.

MINISTRY FOR SCHEDULED CASTS AND SCHEDULED TRIBES AT THE CENTRE AND IN THE STATES

4681 SHRI YASHPAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) whether a deputation of the All-India Federation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes met the Home Minister and demanded setting up of separate Ministeries at the Centre and in the States to look after the welfare of backward classes; and
- (b) if so, the reaction of Government thereto?

THE PRIME MINISTER, MINISTER ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTENRAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). No deputation as such has met the Home Minister. However, suggestions to set up a separate Ministry at the Centre and in the States to look after the welfare of Backard Classes have been received from time to time. Such an arrangement has not been found necessary at the Centre, as there is already in the charge of a Cabinet Minister a Department of Social welfare which deals with matters relating to the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes.

#### आर्थिक विकास

4682. श्री मोलहू प्रसाद : क्या प्रधान मन्त्री 10 अस्मत, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8772 के उत्तर के संस्वन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वीची पंचवर्षीय योजना में देश में विशेष रूप से अल्प विकसित क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों के बराबर लाने के लिये उनके आर्थिक विकासकी की गति को तेज करने के प्रस्तावों को कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया गया है?

प्रधान नंती, अणु शक्ति मंती, योजना मंती तथा वैदेशिक-कार्य मंती (भीमती इन्दिरा षांधी): राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना की स्यय-व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देते समय, अल्प-विकसित क्षेत्रों के तेजी से विकास के लिए व्यय-व्यवस्थाओं के व्यौरे का भी निर्णय किया जायेगा। इस सम्बन्ध में दिनांक 11 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रशन संख्या 6398 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

ALLEGED FRAUD BY INDIAN FILM PRODUCERS IN LEAGUE WITH CEYLON BROADCASTING CORPORATION

4683. SHRI D. N. PATODIA:
SHRI Y. A. PRASAD:
SHRI N. K. SANGHI:
SHRI K. P. SINGH DEO:
SHRI CHENGALRAYA NAIDU:
SHRI SHRI CHAND GOEL:
SHRI KANWAR LAL GUPTA:
SHRI C. K. CHAKRAPANI:
SHRI K. ANIRUDHAN:
SHRI HIMATSINGKA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that some Indian film producers and advertising agencies in league with the Commercial Services of the Ceylon Broadcasting Corporation have defrauded Government of several lakhs of rupees;
  - (b) if so, the details thereof; and
- (c) the steps taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): (a) to (c). The attention of the Government has been drawn to reports appearing in the Ceylonese and the Indian press and necessary investigations are being made.

STATE PLANOUTLAY OF RAJASTHAN

4684. SHRI D. N. PATODIA: SHRI ONKAR LAL BERWA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to State:

(a) whether it is a fact that the Planning

- Commission has been approached by the Government of Rajasthan explaining difficulties to maintain the State Plan outlays and seeking increased assistances from the Centre;
- (b) whether it is also a fact that due to inadequate resources, the Rajasthan government have been unable to finance important projects which are essential for food production; and
- (c) the nature of recommendations made by the Planning Commission in this regard and Governments reaction thereto?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI) (a) to (c). The Government of India have received a representation from Rajasthan regarding its financial difficulties which are at present under examination in the Ministry of Finance.

#### M.I.G. FACTORIES

4685. SHRI RANDHIR SINGH: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state.

- (a) the total expenditure incurred on M.I.G. Factories so far; and
  - (b) the total capacity of the factories?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA):
(a) The total expenditure incurred on M.I.G factories upto 31-3-67 is Rs. 25-18 crores.

(b) It will not be in public interest to disclose the capacity of the MIG factories.

LAUNCHING OF ROCKET "ROHINI"

4687. SHRI SRINIVAS MISRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that an all India made rocket "Rohini" has been launched from the launching site at Thumba;
- (b) if so, whether the rocket had any foreign components; and

(c) whether it was manufacutred with the collaboration of foreign engineers, or it was purely the achievement of Indian engineer?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) Yes, Sir.

- (b) No, Sir.
- (c) The rocket was designed and developed by Indian Engineers at the Space Science and Technology Centre, Trivandrum.

# भीरंगाबाद का सैनिक क्लर्क प्रशिक्षण स्कूल

4689 श्री प्रकाशवीर सास्त्री : श्री रामावतार शर्मा : डा० सूर्य प्रकाश पुरी : श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के सैनिक क्लक प्रशिक्षण स्कूल में एजूकशन (शिक्षा) हवलदार के पद वाले हिन्दी भाषी स्नातक अध्यापकों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के लिए बाध्य किया जाता है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि जो अध्यापक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने से इंकार करते हैं अथवा पढ़ा नहीं सकते हैं, उन्हें कोर्ट मार्गल करने के बाद पीटा जाता है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि जिन अध्या-पकों को बुरी तरह पीटा गया था, उन्हें पूना के सनिक अस्पताल में भर्ती किया गया था तथा उनमें से कुछ अध्यापकों को नौकरी से हटा दिया गया था; और
- (घ) यदि हा, तो इस संबंध में सरकार का क्या कायवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रासय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (भी ल० ना० निभ्र) : (क) जी नहीं।

- (खा) जी नहीं।
- (ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

## लमडेंग (आसाम) में सैनिक बैरक

4690. श्री ओ०प्र० स्यागी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (ग) क्या यह सच है कि लमडेंग (आसाम) में सरकार द्वारा निर्मित सैनिक बैरकें पानी और बिजली की व्यवस्था न होने के कारण अप्रयुक्त पड़ी हैं;
- (ख) यदि हां, तो इन बैरिकों को बनाने से पहल पानी और बिजली की सप्लाई की व्यवस्थान की जाने के क्या कारण थे; और
- (ग) क्या इस असावधानी के लिए मरकार का विचार किन्ही संबंधित अधि-कारियों को उत्तरदायी ठहराने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (भी स्वर्ण सिह): (क) एक जे॰ सी॰ ओ॰ और 5 अवर-श्रेणी सैनिकों के लिए 40980 रुपये के अनुमानित खर्च पर स्वीकार की गई एक बैरक सितम्बर 1967 में सम्पूर्ण की गई थी, और धारण किए जाने से पहले उसमें पानी की सप्लाई और बिजली का कनेक्शन प्रतीक्षित है ।

(ख) तथा (ग). पानी और बिजली की सप्लाई नाथं फरण्टियर रेलवे से प्राप्त की जानी है, और उनके साथ मामले का सितम्बर 1966 से अनुसरण किया जा रहा है, वर्तमान सकेत ऐसे हैं कि पानी की सप्लाई चालू मास के दौरान सम्पूर्ण हो जाएगी, और बिजली की सप्लाई मार्च 1968 में बिलम्ब के कारण जानने के लिए इन्क्वायरी की जा रही हैं।

# विदेशों के साथ पत्र-ब्यवहार

4691. श्री मोलह प्रसाद : क्या बैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि अन्य देश भारत सरकार क साथ अपनी भाषा में ही पत्र व्यवहार करत हैं।
- (स) क्या यह भी सच है कि सरकार ऐसे सभी पत्नों का उत्तर अंग्रेजी में भेजती हैं;
- (ग) यदि हां, तो क्या भविष्य में एस पत्नों के उत्तर हिन्दी में देने का सरकार का विचार है; और
- (घ) यदि नहीं, तो उसके क्याकारण

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी ): (क) चीन, फांस और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ को छोडकर अन्य सभी विदेशी सरकारें भारत सरकार के साथ अंग्रेजी में पत्न-व्यवहार करती हैं। चीन, फ्रांस और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ अपनी-अपनी भाषाओं में पत्न व्यवहार करते हैं लेकिन अपने पत्नों के साथ अग्रेजी अनुवाद लगा देते हैं । कुछ सरकारें, जैसे अर्जन्तीना, ब्राजील, बोलिबिया, चिली, कोलम्बिया, क्यूबा, मैक्सिको, पनामा, पराग्वे, पेरू, उरम्बे और बेनीजुला की सरकारें भी, अपने देशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ अपनी-अपनी भाषाओं में पत्र-व्यवहार करती हैं और साथ में अंग्रेजी अनुवाद लगा देती हैं, लेकिन इन देशों के भारत-स्थित मिशन भारत सरकार के साथ अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार करते हैं।

(खा) जी हां। लेकिन प्रत्यय-पत्न (लैंटर आफ़ कीडेंस) और प्रत्याबाहन-पत्न (लैटर आफ रिकाल) जैसे औपचारिक पत्र हिन्दी में भजे जाते हैं और उनके साथ अंग्रेजी अनुवाद होता है।

(ग) और (घ). विदेशी सरकारों के साथ निकट भविष्य में हिन्दी पत्राचार करना संभव न होगा क्योंकि (1) ऐसे कर्मचारियों को कमी है जो अपने को आसानी से ठीक-ठीक हिन्दो में अभिव्यक्त कर सकें और (2) प्राप्तकर्तादश की भाषा में अनुवाद करके भेजना इसलिए कठिन है कि विदेशों में हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान नहीं है।

## हिन्दी स्टेनोग्राफर

4692 श्री मोलह प्रसाद : क्या बैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि

- (क) उनके मंत्रालय में हिन्दी स्टेनोग्राफरों के कितने पद हैं।
- (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित पद कितने हें:
- (ग) क्या सभी अरक्षित पदों पर अनुसुचित जातियों तथा अनुसुचित आदिम जातियों के सस्दस्य कार्य कर रहे हैं, और
  - (घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

प्रधान मन्त्री, अण शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा बैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (घ). इस मंत्रालय में हिन्दो स्टैनोग्राफरों के तीन स्वीकृत पद हैं, जिन पर भरती या तो रोजगार कार्यालय के जरिए की गई है या भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों के जरिए । इरादा यह या कि अनुसचित जाति और अनुस्चित आदिम जाति के उम्मीदवारों को बरीयता दो जाये लिकन चुंकि ऐसे किसी व्यक्ति ने आवदन-पत्र नहीं भेजा, इसलिए उन्हें लेना सम्भव नहीं हुआ ।

RIVER CRAFTS SHIPS SEIZED BY PAKISTAN DURING 1965 INDO-PAK CONFLICT

4693 SHRI MADHU LIMAYE: Will the Minister of EXTENRAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have made any estimate of the value of river crafts/ships

are awaited.

seized by Pakistan (in the East) in the Indo-Pak. conflict of 1965;

- (b) whether Government are aware that these crafts are being auctioned by the Pakistan Government:
- (c) whether any compensation has been demanded and recived by India; and
- (d) whether India seized any Pakistani crafts?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY. MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) Yes, Sir. Rs. 6,73,30,656 (Rupees six crores seventy three lakhs thirty thousand six hundred and fifty six) at predevaluation rates, is the estimated value of the 184 Indian vessels of different types seized by Pakistan.

- (b) and (c), There have been reports that these Indian vessels/crafts have been or are being auctioned or given away to private parties. The Government, in a note to the Pakistan Government, protested against such moves, reserving their right to claim full compensation for the loss/damage to all Indian properties/assets. The Government have repeatedly proposed to the Government of Pakistan to hold discussions for the return of these properties and assets. The question of demanding any compensation would arise when Pakistan agrees to such discussion.
- (d) Three Pakistani ships were seized by us. Two of these have been exchanged with two of our ships seized by Pakistan. The possibility of the exchange of the remaining Indian ship with a Pakistani ship detained in India is being explored. India also seized one Pakistani flat.

## RELEASE OF SHRI MOHAN LAXMAN RANADE

4694. SHRI MADHU LIMAYE: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have sought the good offices of the Holy See, the Pope in securing the release of Mohan Laxman Ranade and Dr. Mascarenhas, now in the Portuguese capativity; (b) if so, the results of this mediation?
THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b), In September last year Government approached the Holy See through the Papal Internunciature in New Delhi for their good offices in securing the release from Portuguese custody, on humanitarian grounds, of Mohan Laxman Ranade. These efforts are still continuing and results

Dr. Telo Mascarenhas, a resident of Goa, had declared himself as an Indian National. The Portuguese Government, however, continue to regard him as a Portuguese citizen and are not prepared to entertain any external intervention on his behalf We have, nevertheless, taken up his case also with the Holy See.

AID GIVEN BY INDIA TO FOREIGN COUNTRIES

4695. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) the total aid given by India to foreign countries during the last 3 years, countrywise:
- (b) the main consideration for giving aid to these countries; and
- (c) the reasons for giving aid to others when we are short of funds?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) A statement showing aid given by India to the foreign countries under various assistance programmes during the last three years is placed on the Table of the House. [Placed in Library See No. LT-2045/67.]

(b) and (c). It has been our belief, which we have also expressed in appropriate international forums and elsewhere, that there must be much greater cooperation amongst developing countries in different fields. One form of such cooperation is for those countries having reached comparatively advanced stages of industrial, technological and scientific development to share their know-how, expertise and facilities with others. The magnitude of such assistance is,

however, small and in the view of Government the fact that we are ourselves in receipt of foreign assistance or are short of funds, should not stand in the way of mutually advantageous cooperation amongst developing countries.

### गांवों में आयोजन

4696. श्री ओ० प्र० स्यागी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार को पता है कि गांवों में सफाई की व्यवस्था खराब होने तथा गांवों में आयोजन न किये जाने के कारण, पढ़ें लिखे लोग वहां बसना पसन्द नहीं करते;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गांवों का योजनाबद्ध विकास करने के लिये कोई योजना बनाई है, और
- (ग) यदि हां, तो उसका क्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांघी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या LT-2046/67]

#### CORONATION OF SHAH OF IRAN

4697. SHRI BABURAO PATEL: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state the name and designation of the person who represented India at the Coronation of the Shah of Iran and the nature of the presents given to him on behalf of our country?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Shri K. V. Padmanabhan, Ambassador of India in Tehran, represented the Government of India at the Coronation of the Shah of Iran. This was in accordance with the practice followed by all other countries with a few exceptions.

The following presents were given to the Shah of Iran on behalf of the Government of India on the occasion of his Coronation:

- (a) one silver replica of the Qutab Minar
- (b) Brocade material
- (c) One gold enamel replica of a horse set with diamonds.
  - (d) Banaras gold brocade.

PROMOTION OF MECHANICS IN A.I.R.
4698. SHRI S. M. BANERJEE:
SHRI SRADHAKAR SUPAKAR:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

- (a) the reasons for not promoting qualified and trained mechanics of A.I.R. as Engineering Assistants on large scale;
- (b) the reasons for fixing a limited quota of five per cent for departmental promotions in this cadre and;
- (c) whether it is a fact that vacant posts against departmental quota are being filled up from outside?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH). (a) There are two grades of Mechanic in All India Radio—one in the scale of pay of Rs. 130-5-175-EB-6-205 and the other designated as Senior Mechanic in the scale of pay of Rs. 150-5-175 6-205-EB-7-240. The post of Senior Mechanic is wholly a promotion post from the lower grade of Mechanic.

According to the Recruitment Rules prescribed for the post of Engineering Assistant in the scale of pay of Rs. 210-10-290-15-220-EB-15-425-EB-15-470, 95% of the posts are filled in by direct recruitment and only 5% of the posts are filled in by promotion from the grades of Senior Mechanic, Radio Technician and Technical Supervisor. It is, therefore, not possible to promote Senior Mechanics etc. to the grade of Engineering Assistant, more than what is permissible in the Recruitment Rules.

(b) The duties of Engineering Assistant in All India Radio need a thorough knowledge of the fundamental principles of General physics and electronics. The Mechanics and Senior Mechanics, due to their limited general education, are generally not suitable for the post of Engineering Assistant. However, in order to provide incentive and promotion opportunities to the brighter Senior Mechanics etc., 5% of the posts in the grade of Engineering Assistants have been made available to them. The whole question, however is being examined to ensure to them their fair share in promotions.

(c) No. Sir.

#### PROMOTION OF ENGINEERING ASSISTANTS

#### 4699. SHRI S. M. BANERJEE: SHRI SRADHAKAR SUPAKAR:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to

- (a) the steps taken to fill up the vacant posts of Engineering Assistants against five per cent quota departmently:
- (b) whether any representations have been received in this regard; and
  - (c) if so, the action taken thereon?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): (a) Since the introduction of the grade of Engineering Assistant (previously known as Shift Assistant) in 1956, 60 departmental employees have been promoted to the posts of Engineering Assistant in A.I.R. in the departmental quota against the vacancies available to them upto June, 1966. The last batch was appointed in the period January-July, 1967.

- (b) Yes, Sir.
- (c) The filling up of the vacancies in the grade of Engineering Assistant available in the departmental quota after June 1966 is under consideration.

#### CLOTHING AND LEATHER ORDNANCE FACTORIES

4700. SHRI S. M. BANERJEE: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that production in some of the Ordnance Factories, especially in Clothing and Leather factories, has come to a stand still because of no work; and (b) if so, the steps taken by Government to provide more work to the Ordnance Factories?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA): (a) and (b). No, Sir. As the bulk of the deficiencies in clothing was met in 1963 and 1964, the requirements of the Services for subsequent years are considerably less and so there has been reduction in the workload in the Clothing Factories. To keep the capacity in these Factories utilized, efforts have been and are still being made to obtain orders from other Central and State Government Departments and Public Sector Undertakings. Diversification of production activities has been planned and orders for items of production like tents and durries have also been secured.

NAGA REPRESENTATIVES GOING TO LONDON TO MEET Mr. PHIZO

4701. SHRI HEM BARUA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that two representatives of the Naga Federal Government have recently left for London to meet Mr. Phizo.
- (b) if so, the reasons for this constant communication of Naga rebels with Mr. Phizo; and
- (c) whether these representatives are expected to submit any report to Government?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) Two representatives of the Underground Nagas visited U.K. during May-June, 1967. Government of India allowed them passport and foreign exchange facilities. This information was conveyed to the House in reply to Starred question Nos. 1 dated 22-5-1967 and 585 dated 19-6-1967. No approach for further consultations with Phizo has been made to Government by the Underground Nagas.

(b) and (c). Do not arise.

JEEPS SUPPLIED TO PRESIDENT OF SO-CALLED NAGA FEDERAL GOVERNMENT

4702. SHRI HEM BARUA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that some time back, the President of the so-called Naga Pederal Government was allowed two jeeps from the Nagaland Government quota; and
- (b) if so, whether any assurance was sought and obtained to the effect that the jeeps would not be used for purpose of hostile activities?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDINA GANDHI): (a) State Government of Nagaland has informed us that there is no truth in the report.

(b) does not arise.

### स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के भाषणों के रिकाडों पर रायलटी

7403. श्री कंबर लाल गुप्त: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा तैयार किये गये और कम्पनियों को दिये गये स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के भाषणों और ववतब्यों आदि की कुछ रिकार्ड करने वाली कम्पनियों द्वारा ध्वनि रिकार्ड कम्पनियों जाने के लिये सरकार उन रिकार्ड कम्पनियों से रायलटी लेती है; और
- (ख) यदि हां, तो कितनी रायलटी ली जाती हैं ; तथा श्री जवाहरलाल नेहरू के निवन के पश्चात् किन किन कम्पनियों से रायल्टी ली गई तथा कितनी कितनी रायल्टी जी गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० साह): (क) बामोफोन कम्पनी माफ़ इंडिया सिमिटड, कलकत्ता ने ज्यादा समय बजने बासा एक ऐसा रिकार्ड बनाया है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषणों के उद्धरण और उनकी बहिन द्वारा पढ़ा गया उनका इन्छा-पत्र और वसीयतनामा हैं। इस रिकार्ड की बिकी से होने वाली जाय पर रायल्टी भ्रदायगी सम्बन्धी करार को भ्रभी भ्रतिम रूप नहीं दिया गया है। भ्रतः इस बारे में सरकार को भ्रभी तक कोई रायल्टी नहीं मिली है।

### (स) सवाल नहीं उठता ।

DOCUMENTARY ON VEDIC RECITATIONS

4704. SHRIMATI TARA SAPRE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

- (a) whether a documentary on Vedic Recitations was taken at the time of the Centenary Functions of Vedmurti S.D. Satawalekar at Bombay; and
- (b) whether Government propose to sell copies of the documentary to Nations, where Sanskrit literature is studied with a view to earn foreign exchange?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

DEFENCE PACT BETWEEN IRAN AND PAKISTAN

4705. SHRI A. B. VAJPAYEE:
SHRI JAGANNATH RAO JOSHI:
SHRI YAJNA DATT SHARMA:

Will the Minister of EXTERNAL AFF-AIRS be pleased to state:

- (a) whether Government have any authentic information about the conclusion of a secret defence pact between Iran and Pakistan;
- (b) whether Government have ascertained from Iran about the existence of any such pact; and
  - (c) if so, the details thereof?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). Government have no such authentic information.

(c) Does not arise.

चूमिहीन भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि (का आवंटन

4706. श्री राम सिंह अयरवाल : श्री निहाल सिंह :

क्यारका मंत्रीयह बताने की क्रुपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार देश में भूमिहीन भूतपूर्व सैनिकों को खेती के लिए खेती वाली भूमि, ट्रैक्टर तथा हल एवं पशु खरीदने के लिए 8०० रुपये का मनुम्रहात मनुदान दिया करती थी, भौर
- (स) क्या सरकार ने भव यह सहायता देना बन्द कर दिया है भौर यदि हां तो इसके क्या कारण हैं?

प्रसिरका मंत्रालय में (प्रतिरका उत्पादन)
राज्य मंत्री (श्री ल० वा० मिश्र): (क)
द्वितीय विश्वयुद्ध के शीघ्र ही पश्चात् भिन्न
राज्य सरकारों की सलाह के साथ भूतपूर्व
सैनिकों के लिए भूमि कालोनियों की संस्थापना
की एक योजना तैयार की गई थी;
इस के झन्तर्गत भूमि उद्धरण धौर उसके
विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न
पैमानों पर विसीय सहायता दी गई थी।

(स) उस पुरानी योजना के प्रन्तगंत प्रव मृतपूर्व सैनिकों के लिए कोई कालोनियां संस्थापित नहीं की जा रहीं। किसी नई भूमि कालोनी के सम्बन्ध में, कि जो किसी नई योजना के प्रन्तगंत संस्थापित की जाए; केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ऐसी वित्तीय सहायता के लिए प्रव प्रव साधन प्राप्य हैं, प्रधांत् पंचवर्षीय योजनाम्रों के प्रन्तगंत मधिक प्रनाज उगाम्रों प्रभियान के लिए कृषि उद्देगों के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को उपलब्ध की गई राशि, भूतपूर्व सैनिकों के पुर्नीनर्माण भौर पुनरावास के लिए स्थापित की गई विश्वेष निषि, इत्यादि।

## सेना के पेंशन प्राप्त मृत कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन

4707. भी राम सिंह अयरवाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सेना के पेंशन प्राप्त किसी मृत कर्मचारी की विषवा को पेंशन देने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और
- (क्ष) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है? प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० निश्च): (क) तथा (क्ष). वर्तमान् नियमों के धनुसार, सेवा-विमुक्ति पेन्शन या निर्योग्यता पेन्शन प्राप्त प्राप्त कर के 1-1-1964 या उसके पश्चात् रिटायर होने वाले सैनिक पेन्शनर के मरने पर उसकी विधवा धाजीवन या पुनर्विवाह तक, कुटुम्ब पेंशन पाने की धरिक कारिणी है।

#### PAK. MILITARY AIRPORT IN KASHMIR

4708. SHRI HIMATSINGKA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1074 on the 20th November, 1967 and state:

- (a) whether Government have since taken any steps to ascertain whether a military airport is being constructed in the part of Kashmir which has been handed over by Pakistan to China; and
- (b) if so, Government's latest information in this regard?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). The usual vigilance is being maintained. Government have so far no reports to indicate that any military air port has been constructed in the part of Kashmi illegally coded by Pakistan to China.

## प्रतिरक्षा प्रयोगशाला को कानपुर से ग्वालियर स्थानान्तरण

4709. श्री महाराज सिंह भारती: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि:

- (क) प्रतिरक्षा प्रयोगशाला को कानपुर से ग्वालियर स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं;
- (स) क्या कानपुर से ग्वालियर ले आई गई प्रयोगशाला को मूमि न मिलने के कारण काम करने में कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, भौर
- (ग) यदि हां, तो वे कठिनाइयां क्या हैं भौर उन पर काबू पाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंद्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंद्री (श्री ल॰ ना॰ मिश्र): (क) पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस रिसचं लेबारेटरी (मैटींयल्ज), कानपुर के कार्यकलाप में वृद्धि हुई है। चूकि कानपुर की वर्तमान लेबारेटरी बहुत संकुलित हो गई है, भीर भ्रतिरक्त सुविधाओं के लिए भ्रावश्यक स्थान प्राप्य नहीं कर सकती, कई रिसचं भीर डिवनपमेंट डिवीजन खालियर भन्तरित कर दिए गए हैं कि जहां भवन प्राप्य हैं।

- (स) ग्वालियर में काफी मूमि प्राप्त है। भ्रेबारेटरी के भवनों का प्रसार करने संबंधी एक प्रस्ताव में प्रगति की जा रही है।
  - (ग) प्रधन नहीं उठता ।

सौलिड स्टेंट फिजिक्स लेबोरेंटरी दिल्ली

- 4710. श्री महाराज सिंह भारती : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) सोलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी, दिल्ली की स्थापना के बाद इस प्रयोगशाला में कितनी परियोजनायें मारंम की गई भौर कितनी परियोजनामों में सफलता मिली;

- (स) क्या किसी परियोजना के धन्तर्गत जत्पादन हुन्ना है भौर क्या जत्पादित वस्तु जवानों के हाथ में पहुंची है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; भीर
- (घ) स्थिति सुधारनें के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिष्म) : (क) 19 प्रायोजनाएं 1965 में इस सेवारेटरी को सौंपी गई थीं । इनमें से 4 प्रायोजनाओं के संबंध में विकास कार्य सम्पूर्ण किया जा चुका है।

(स) से (घ) चार प्रायोजनाधों में से कि जिन में विकास प्रावस्था सम्पूर्ण हो चुकी है, एक मद के लिए पाइलाट उत्पादन संयन्त्र के लिए सुविधाओं का निर्माण किया गया है। लेबारेटरी द्वारा हस्तगत की गई प्रायोजनाएं अधिकतम 'फावंढं लुक' किस्म की हैं, और सेवाओं को लिए आवश्यक मांबी साजसामान के संघटकों के तौर पर प्रयोग उपलब्ध करेंगी। लेबोरेटरी को सौंपा गया कार्य सन्तोषपूर्वक प्रगतिशील है, और निरन्तर समीका धाषीन।

हिषयारों सम्बन्धी अनुसन्धान और विकास

- 4711. श्री महाराज सिंह भारती: क्या रक्ता मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:
- (क) हिषयारों के बारे में धनुसन्धान तथा विकास संबंधी ऐसी कितनी समितियां तथा उप समितियां हैं, जिनमें गैरसरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि लिए गए हैं;
- (स) इन समितियों में उन्हें सिय जाने के क्या कारण ये तथा उन्हें क्या घषिकार दियेगये हैं; भीर
- (ग) सुरक्षा के दृष्टिकोण से गोपनीयदा
   बनाये रखनें के लिये क्या कार्यवाही की गई
   है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) धार्मीमेंट के लिए पैनल में, जो धायुधों के धनुसंघान भीर विकास से संबंधित है, निजी क्षेत्र से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हैं। तदिप धन्य क्षेत्रों, जैसे कि इलक्ट्रानिक्स, एरोनाटिक्स, नेवल रिसर्च, मैटीरियल्ज, मटलर्जी इत्यादि के लिए पेनल एडवाईजरी कमेटियों में विश्वविद्यालयों, सांईटिफिक इन्स्टीच्युशनों धौर उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हैं।

(स) उपरोक्त पेनल्ज/एडवाईजरी कमेटियों में रक्षा मंत्रालय से बाहर के प्रति-निषि उन विषयों में उनके विशेष ज्ञान के कारण शामिल किए गए हैं। झार० एण्ड डी० पैनलों/ कमेटियों में निजी क्षेत्र से प्रतिनिधियों के भी शामिल किए जाने की सिफारिश की है।

श्चार० एण्ड डी० पैनल /कमेटिएं सलाहकार संस्थाएं हैं, श्रीर वह डिफेंस रिसर्च एंड डिवेनपमेंट के संबंधित क्षेत्रों से सम्बन्ध रखनें वाली विभिन्न समस्याभों के बारे में विशेषकता पूर्ण सलाह देती है।

(ग) ऐसे प्रतिनिधि बड़ी सावधानी से चुने जाते हैं। जब उनकी नियुक्ति की जाती है आफीशल सीक्षेट्स एक्ट का उडरण उन सभी को भेजा जाता है, श्रीर उन्हें एक घोषणा पर हस्ताक्षर देने होते हैं, कि वह आफीशल सीक्षेट्स एक्ट का पालन करेंगे।

#### IMPORT OF FOREIGN FILMS

4712. DR. RANEN SEN: Will the the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5875 on the 17th July, 1967 and state:

- (a) whether Government have since reviewed the existing arrangements for importing foreign films into India; and
  - (b) if so, the decision taken thereon?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): (a) and (b). The question of

renewal of arrangements with U.S.A. for import of films is presently under negotiation. The exhibition of films as might be imported under the new agreement, will be subject to certification by the Central Board of Film Censors in accordance with the provisions of the Indian Cinematograph Act, 1952 and the rules made thereunder.

## RECOGNITION OF GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

- 4713. DR. RANEN SEN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:
- (a) whether the West German Chancellor, Dr. Keisinger had made a statement in Delhi that recognition of German Democratic Republic will be considered as an unfriendly act; and
  - (b) if so, Government's reaction thereto?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). A remark to this effect was made by Chancellor Keisinger at his press conference in New Delhi on 21st November, 1967.

The position of the Government of India is that they have full diplomatic relations only with the Federal Republic of Germany.

#### AMMUNITION DEPOTS

4714. SHRI YASHPAL SINGH: Will the MINITSER OF DEFENCE be pleased to state:

- (a) whether person employed in the various ammunition depots have put forward any demands for betterment of their working conditions;
  - (b) if so, the details thereof; and
- (c) the action proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA):

(a) No specific representation has been received.

(b) and (c). Do. net arise.

#### TERMINAL BALLISTICS RESEARCH LABO-RATORY AT BALASORE (ORISSA)

4715. SHRI S. KUNDU: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

- (a) whether the Board of Officers constituted for the purpose of location of a site for Terminal Ballistics Research Laboratory recommended Chandipore (on Sea) at Balasore, Orissa, where a Proof and Exeperimental establishment is located at present; and
- (b) if so, Government's reaction thereto?

  THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N.
- MISHRA): (a) No, Sir.
  (b) Does not arise.

### सेवा-निवृत्त प्रतिरक्षा वर्मचारियों को रोजगार दिलाना

4716. श्री निहाल सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने भ्रनेक प्रतिरक्षा कर्मचारियों का पेंशन पर सेवा-निवृत्त हो जाने भ्रथवा सेवा-मुक्त हो जाने के बाद ट्रक, ट्रैक्टर भ्रथवा स्कृटर दिये हैं;
- (स) क्या यह भी सच है कि यह सुविधा केवल ग्रधिकारियों को ही दी जाती है, सैनिकों को नहीं;
- (ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं भौर
- (घ) पिछले पांच वर्षों में श्रीक्षकारियों भीर सैनिकों को पृथक-पृथक कितनी ऐसी गाड़ियां श्रादि दी गई?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उल्पा-दन) राज्य मंत्री (श्रील० ना० मिश्र): (क) जी हां।

- (स्त) जी नहीं। सुविषाएं ग्रवर श्रेणी को भी प्राप्य हैं।
  - (ग) प्रश्न नहीं उठता।
- (भ) सेवामों के भीर मृतपूर्व सैनिक सेविवर्ग को गाड़ियां भलाट करने का काम रक्षा मंत्रालय

को 1965 से ही केवल मिल की गई घलाटमेंट के विस्तार ने एमबेसेडर कारें/टेक्सीएं	
भ्रफसर .	3
भवर श्रेणी	1
कुल जोड़ .	4
(तीन पहिए वाले) टेम्पो	
भफसर	4
मवरश्रेणी	1
441441	
कुल जोड़	5
टी० एम० वी० चेंसिस	
श्रफसर .	14
भवरश्रेणी .	3
सहकारी समितिएं	6
वहमारा वानावड	
कुल जोड़	23
आटोरिक्शा (तीन पहिए व	क्षी)
भफसर	, एक भीनहीं
भवर श्रेणी	64
सहकारी समितिएं	6
46311.1 4141114	
कुस जोड़	70
50 हार्स पावर के इसी ट्रक्ट	
मफसर	18
भवरश्रेणी.	2
<b>74.441</b> .	
मुल जोड़	20
14 हार्स पावर के क्सी ट्रॅक्टर	
प्रकसर	57
भवरश्रेणी.	139
कुम जोड़	196

#### AD HOC APPOINTMENTS IN CENTRAL INFORMATION SERVICE

#### 4717. SHRI NIHAL SINGH: SHRI Y. S. KUSHWAH:

Written Answers

Will the Minister INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state;

- (a) whether it is a fact that a number of officers in the Central Information Service appointed or promoted against purely ad hoc posts in the ex-cadre service have been and are being given regular appointments in the posts they are holding on ad hoc basis after the completion of certain years of service; and
- (b) if so, the steps taken to curb this practice?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): (a) No, Sir. However, since the constitution of the Central Information Service on March 1, 1960, five officers have been given regular appointments in the excadre posts to which they were initially sent on deputation. These posts were regular in character and not of an ad hoc nature. The absorption was made by the concerned Appointing authorities in accordance with their recruitment rules.

(b) Does not arise.

#### AD HOC APPOINTMENT IN MINISTRY

4718. SHRI NIHAL SINGH: SHRI Y. S. KUSHWAH:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that a number of Class I and II posts in the ex-cadre services of his Ministry are filled upon ad hoc basis from among the Central Information Service personnel;
  - (b) if so, the details thereof;
- (c) the number of cases in which the vacancies have not been referred to Union Public Service Commission so far; and
- (d) the steps take to expedite the filling up of these vacancies through Union Public Service: Commission ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH) (a): Yes, Sir.

(b) The following posts under the Ministry of Information and Broadcasting are at present filled by Central Information Service Officers on an ad hoc basis:—

Exhibition Officer, 1 post (Class I)
Directorate of
Advertising and
Visual Publicity,
New Delhi.

Inspector of Exhi- 5 posts (Class I) bitions, Directorate of Advertising and Visual Publicity, New, Delhi.

Extension Officer, 1 post (Class II All India Radio, Gazetted). Calicut.

- (c) Non of the above posts has beenreferred to the Union Public Service Commission for recruitment, so far.
- (d) The recruitment rules for the above posts are being framed. As soon as the rules are finalised in consultation with the Union Public Service Commission and notified, the vacancies will be filled in accordance with those rules.

BOYCOT BY CHINESE EMBASSY IN KATHMANDU OF FUNCTIONS ARRANGED BY NEPALESE GOVT-IN HONOUR. OF SHRI MORARJI DESAI

- 4719. SHRI D. C. SHARMA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:
- (a) whether the Chinese Embassy in Kathmandu boycotted all the functions arranged by the Nepalese Government for Shri Morarji Desai; and
- (b) if so, the reaction of Government thereto?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). The Government of India are not aware whether the absence of a Chinese Embassy representative at the functions was deliberate or accidental. The matter, however, is not of primary incern of the Government of India as they were not the hosts.

#### RESIGNATION OF SCIENTISTS?

- 4721. SHRI PREM CHAND VERMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that a large number of scientists have resigned from the Department of Atomic Energy and there is great discontentment among others; and
- (b) if so, the nature of their grievances and how these are intended to be removed?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

NASIK DIVISION OF HINDUSTAN AERONAU-TICS LTD.

- 4722. SHRI K. N. PANDEY: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that the Nasik Division of the Hindustan Aeronautics Limited had advertised certain temporary posts of Russian Interpreters in May, 1967:
- (b) whether it is also a fact that the candidates who appeared for interview for the said post on the 10th October, 1967 have not been paid the railway fares as mentioned in the interview letters so far inspite of several requests; and
- (c) if so, the reasons therefor and the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA):
(a) to (c). The Recruitment rules of Hindustan Aeronautics Limited provide for the payment of railway fares to the candidates appearing for interviews on production of cash receipts. Hindustan Aeronautics Limited have confirmed that payments have been made in all cases where cash receipts have been given by the candidates.

#### CANADIAN REACTOR

4723. SHRI SAMAR GUHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Canadian Reactor now

- operating in India is a special patent made for India; and
- (b) if not, whether the maximum capacity for nuclear charge for such a reactor is known to Canada and for that matter is likely to be known to other countries of the World including Pakistan and China also ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) The reactor is similar to the one in Chalk River, Ontario, Canada, except for certain changes which have been made to suit local conditions.

(b) The maximum fuel loading for such a reactor is known to Canada. We have no information as to which other countries are aware of the particulars.

#### EXPENDITURE ON NUCLEAR POWER STATIONS

- 4724. SHRI SAMAR GUHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:
- (a) the estimated costs for buying and constructing (separately for each item) the proposed Indian Nuclear Power Stations;
- (b) the estimated capacities for producing electricity by he proposed Nuclear Power Stations and the estimated costs for production of power by these power stations annually;
- (c) the estimated costs in terms of foreign and Indian currencies that will be required for construction and buying of nuclear charges from foreign countries initially and then annually;
- (d) whether Government have calculated costs for constructions of thermal power stations of similar capacities and also the cost of crude oil or coal that would have required annually for such power stations; and
- (e) if so, the comparative cost figures for construction and production of power by the nuclear and thermal power stations and what are the comparative advantages for nuclear power stations over thermal power stations?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) to (e). A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Libary. See No LT-2047/67].

## PERSONS OF INDIAN ORIGIN IN AFRICAN COUNTRIES

4725. SHRI YAJNA DATT SHARMA: Wil the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) the number of persons of Indian origin living at present in the African countries; and
- (b) the number of such persons who have so far been granted citizenship of the countries of their residence?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) There are approximately 900,000 persons of Indian origin in Africa including South Africa.

(b) Our present information is that the following have taken up local citizenship of the countries concerned:—

South Africa 500,000 (all persons of Indian origin in South Africa hold local citizenship).

 Kenya
 39,000 (appx.)

 Tanzania
 35,000 (appx.)

 Uganda
 44,000 (appx.)

 Zambia
 150 (appx.)

 Malawi
 100 (appx.)

## EXPANSION OF SMALL INDIAN LANGUAGES Newspapers

4726. SHRI YAJNA DATT SHARMA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

- (a) whother some difficulties in the expansion of the Indian Languages Newspapers on account of (i) shortage of newsprint, (ii) restrictions imposed on import of printing machines, and (iii) foreign exchange have been brought to the notice of Government; and
- (b) if so, the steps taken by Government to remove these difficulties?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): (a) Yes. Individual language papers as well as the ILNA have brought these impediements and difficulties to the notice of Government. The Government, on their own have also proceeded systematically to act up to the recommendations of the Diwakar Committee in this regard.

(b) The newsprint policy of the Government for 1967-68 was designed specifically to help language papers and resulted in relieving the shortage of newsprint in their favour. Import of printing machines, specially from rupee sources, is being allowed to newspapers, including language papers, for replacement and expansion to the extent possible. Out of 111 applications for licences of total value of about Rs. 263 lakhs, licences to 56 languages papers of the value of about Rs.94 lakhs were issued during 1966-67.

### अमरीका को उपहार में दिया गया हाची का अच्छा

4727. श्री हुकम चन्व कछवाय: क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने स्रमरीका को हाथी के दो बच्चे उपहार में दिये हैं:
- (ख) यदि हां, तो उन्हें भ्रमरीका भेजने पर कितना धन व्यय किया गया है;
- (ग) क्या ध्रमरीका सरकार ने भी पिछले दो वर्षों में भारत को ऐसे ही उपहार मेजे थे; धौर
  - (घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्विरा गांधी) : (क) जी हां । मियामी चिड़ियाघर के घधिकारियों की प्रार्थना पर भारत सरकार ने धमरीका में मियामी चिड़ियाघर को हाथी के बच्चे मेंट किए थे।

- (ग) भारत सरकार ने इस उपहार पर 6,000 रुपये सर्चे किए। यह राशि हाथियों की लायत है और भारतकर्ता चिड़ियाघर के अधिकारियों ने उनके यातायात का सर्चे बहुन किया था।
- (ग) भौर (घ). हमें इस बात की जान-कारी नहीं है कि पिछले दो सालों में भ्रमरीका की सरकार ने भारत को ऐसा ही कोई उपहार दिया।

## विदेशों में भारत मुलक व्यक्ति

4728. श्री हुकम चन्द कछवाय: क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री ३ जुलाई, 1967 के भतारांकित प्रश्न संस्था 4329 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विदेशों में भारत मूलक, व्यक्तियों के बारे में सूचना इस बीच इकट्ठी कर ली गई है;
- (स) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; भौर
- (ग) यदि हां, तो उसमें झौर कितना समय लगने की सम्भावना है?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी हाँ।

(स) भौर (ग). सुलभ सूचना देने वाला एक अयौरा सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। वेखिये संक्या L.T.—2048/67]।

पिंडियाला के निकट विमान दुर्घटना

4729. श्री हुकम चन्द कछवाय: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि अगस्त 1967 में पटियाला में सरकारी शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय के निकट एक विमान बुर्घटना में दो व्यक्ति भायल हो गये थे;
- (स) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे; और

(ग) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप जान श्रीर माल की कितनी हानि हुई ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उम्पा-दन) राज्य बन्त्री (श्रील०ना०निश्व): (क) जीहां।

- (स) दुर्धटना नीची उड़ान के कारण हुई ।
- (ग) कोई जन हानि नहीं हुई। विमान जो पंजाब सरकार से मांग कर लिया गया था, सर्वेथा विनष्ट हो गया था। तदपि उसका मालिकों द्वारा बीमा कराया गया था।

#### MANGLA DAM

4730. SHRI S. C. BESRA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the President of All-Indian Kashmir Refugees Committee has urged the Indian Government to raise the issue of compensation to the people of Pak,—occupied Kashmir, whose lands have been submerged by the Mangla Dam, with the Security Council as the Pakistan-held are alegally belonged to India; and
- (b) if so, the reaction of Government thereto?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) Government have seen press reports to this effect. However, no representation in this regard has been received.

(b) Does not arise.

TERRITORY UNDER PAR OCCUPATION ON TRIPURA-EAST-PAR. BORDER

4731. SHRI CHENGALRAYA NAIDU: SHRI MAYAVAN:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistan is still in occupation of five square miles, which it has illegally occupied on the head waters of the Fenny river on Tripura-East Paskistan border;

7766

(b) if so, the steps taken by Government to get back the territory from Pakistan?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF MINISTER OF PLANNING AND **EXTERNAL** AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) Yes, Sir.

(b) The Governmet are persisting in their efforts to regain this area through peaceful means. The demarcation on the Tripura Bast Pakistan border has recently been resumed. It is hoped that the outstanding border problems in this region would be resolved in the course of the demarcation process.

#### ROLE OF ARMY IN UNDERDEVELOPED COUNTRIES

- 4732. SHRI K. R. GANESH: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:
- (a) whether Government are aware of a study being made by the Massat Institute of Technology (USA) about the role of the army in under-developed countries;
- (b) whether the M. I. T. (U. S. A.) has prepared a complete card index of the Indian Army Officers;
- (c) if so, the sources of their information; and
- (d) the reaction of Government to this study and compilation of card indices of Indian Army Officers?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA): (a) to (d). Government have not seen the study referred to nor are they aware of the card index of Indian Army Officers stated have been prepared by the Massachussetts Institute of Technology.

### VIOLATION OF CEASE-FIRE BY PAKISTAN

- 4733. SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5062 on the 10th July, 1967 and
- (a) how may times Pakistan has since violated the cease-fire after the signing of the Tashkent Declaration; and
- (b) whether protests have been made against them to Pakistan and in the United Nations and if so, with what results?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : (a) The report received upto 13th December, 1967 indicate that 968 more violations of the Karachi Cease-fire Agreement of 1949 have been committed by Pakistan in J & K, thus bringing the total number of violations to 30.50 since the date of the Tashkent Declaration.

Written Answers

(b) Cease fire violation complaints have been lodged in all cases with UN Military Observers. Some serious violations have also been the subject of protest notes to Pakistan and subject for discussion between the Chief of the Army Staff, India, and C-in-C, Pakistan Army. At the meeting held in October 1967 at Rawalpindi, the two Army Chiefs once again agreed that local Commanders should resort to joint meetings at various levels through the good offices of offices of UN Observers to avoid misunderstandings leading to incidents.

#### NUCLEAR PLANTS IN BIHAR

- 4736. SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to
- (a) the specific requirements for selecting a site in India for starting a nuclear plant thereon;
- (b) whether Bihar meets those requirements;
- (c) if so, whether Government propose to start a nuclear plant in Bihar; an
- (d) how much nuclear raw material is taken annually out of Bihar and at what nuclear plants they are used in India?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF **PLANNING** AND MINISTER OF **EXTERNAL AFFAIRS** (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) The requiremets for selecting a site and establishing a nuclear power plant are mainly(i) adequate power potential in the region (ii) competitivesness with power from thermal stations, and (iii) suitability of site in regard to economic stability, availability of water, etc.

(b) and (c). The Atomic Energy Commission is currently reviewing the economic and technical feasibility of establishing atomic energy plants in various possible locations in the country. The question of establishing a auclear power station in Bihar will need to be examined on merits.

(d) The large scale supply of the Jaduguda concentrates has not yet commenced.

RECOGNITION OF COUNTRIES BY INDIA 4737. SHRI RABI RAY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) the names of countries in the world which have been both recognised and given diplomatic recognition by India; and
- (b) the countries which are only recognised but not given diplomatic recognition?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). A Statement is laid on the Table of the House. Placed in Library. See No. LT—2049/67.]

#### News about Late Dr. Ram Manohar Lohia's Illness

4738. SHRI RABI RAY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

- (a) whether the All India Radio was giving news about the illness of the late Dr. Ram Manohar Lohia while he was being treated in Willingdon Hospital, New Delhi before his death;
- (b) if so, how many bulletins were circulated; and
- (c) the dates on which they were circulated and the contents of those bulletins?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) About 50 different bulletins in English, Hindi and other Indian languages between October 2 and 11, 1967 carried the news about Dr. Lohia's illness. The medical bulletins issued by doctors and reports of important leaders calling at the Willingdon Hospital to enquire about Dr. Lohia's health

## PAKISTAN'S REFUSAL TO GIVE TRANSIT VISAS TO TWO INDIAN STUDENTS

- 4739. SHRI YASHPAL SINGH: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state |
- (a) whether Pakistan has refused transit visas to the two Indian students who are going on a world mission tour on a scooter:

- (b) if so, on what grounds; and
- (c) whether the matter has been taken up with the Pakistan Government?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) Yes, Sir

- (b) We understand that the current regulations of the Government of Pakistan do not permit the grant of visas to Indian nationals for travel by road through Pakistan.
- (c) The question of grant of travel facilities by road to Indian nationals on a reciprocal basis has been taken up with the Government of Pakistan on several occasions but the latter have not agreed to this so far.

#### NIGHT FIGHTERS AND MOBILE RADARS

4740. SHRI KANWAR LAL, GUPTA I
Will the Minister of DEFENCE be pleased
to state:

- (a) whether Government have purchased or acquired night fighters and mobile radars during the last one year;
  - (b) if so, the number thereof; and
- (c) the steps Government propose to take to acquire more night fighters or mobile radars?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH): (a) to (c). It will not be in the public interest to disclose any such information.

## पाकिस्तान सरकार द्वारा अनुसूचित कातियों तथा पिछड़े वर्गों के कोगों के साथ दुर्व्यवहार है

4742. श्री निहाल सिंह : स्या वैवेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'हिन्दुस्तान' के 25 नवम्बर, 1967 के अंक में छपी यह सबर सही है कि प्रधान मंत्री से यह प्रार्थना की गई है कि पाकिस्तान में अनुसूचित जातियों तचा पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों के साथ हो रहे दुब्यंबहार को व्यान में रसते हुए एक प्रतिनिधि-मंडल भेजा जाए: और (ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): जी हां।

(स) सरकार इस प्रस्ताव को व्यवहायंनहीं समझती।

किसानों के लिये नई प्रसारण योजना 4742. श्री शशि भूषण बामपेयी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार गांगों में किसानों तथा देहाती लोगों के लाभार्य कोई प्रसारण योजना तैयार कर रही है : ग्रीर
- (स) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) जी,हां।

(क) कृषि सम्बन्धी मामलों पर किसानों को सामयिक सूचना और सलाह देनें के लिये आकाशवाणी ने खाद्य भीर कृषि मंत्रालय के परामर्श से भपने विभिन्न केन्द्रों में 16 फार्म और गृह यूनिटें स्थापित की हैं। इन केन्द्रों से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उनमें सधन खेती के तरीकों के बारे में भी धावश्यक जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम खेती और उनकी समस्याओं के बारे में होते हैं और अब प्रगतिशील किसानों की बड़ी संख्या इन प्रसारणों में भाग ले रही है।

## तिम्बत के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता

4743. श्री शशि भूषण बाजपेयी : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिब्बत के शरणार्थियों को पूर्णतः भारतीय नागरिकता दे दी गई है; और (स) तिम्बत के ऐसे शरणाधियों की संस्था क्या है ओ भारत झाने के बाद फिर वापस तिम्बत चले गये हैं?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वंदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती न्दिरा गांधी) : (क) ग्रभी कोई मामला विचार के लिए सामने नहीं श्राया है।

(ख) ठीक-ठीक संख्या मालूम नहीं है। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है।

## DONATION OF SPECTACLES BY WEST GERMANY

4744. SHRI HARDAYAL DEVGUN: SHRI P. VISWAMBHARAN: SHRIMATI TARA SAPRE: SHRI N. K. SOMANI:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that 2 lakh spectacles have been donated by some associations in West Germany for Indians but no arrangements have so far been made to bring the articles to India; and
- (b) if so, when the donated goods will be brought to India?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). An Association of Opticians in the Federal Republic of Germany donated to India spectacle frames and lenses to the value of 2 Million D. Marks. These are being brought by an Indian Naval ship, expected to reach Bombay shortly.

## तिज्ञत की सीमा पर व्यापारियों की गिरफ्तारी

4745. डा॰ सूर्य प्रकाश पुरी : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठ व्यापारियों को, ओ तिब्बत की सीमा पर व्यापार करते थे, चीन द्वारा तिब्बत पर कन्जा किये जाने पर गिरफ्तर कर लिया गया था और उन्हें हाल में छोड़ दिया गया है;

- (स) क्यायह भी सच है कि उन्हें वहां पर पुनः व्यापार शुरू करने में भारी कठि-नाइयों का सामना करना पढ रहा है; और
- (ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, बोजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (भीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (ग). सरकार ने इस भाशय की प्रेस रिपोर्ट देख ली हैं। सदन को मालूम है कि मारत सरकर ने 15 दिसम्बर 1662 को जारी की गई भ्रपनी भ्रष्टिसूचना नं० 15/4/61-ई० भाई० के द्वारा चीन के तिन्दत क्षेत्र के साथ व्यापार पर रोक लगा दी है। संवद्ध तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

RENTS IN KANPUR CANTONMENT BOARD 4747. SHRI A. DIPA:

SHRI MANIBHAI J. PATEL:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the rents of private residential houses within the jurisdiction of Kanpur Cantonment Board, Kanpur have been raised recently;
- (b) if so, whether any instructions have been issued to the Kanpur Cantonment Board for curbing and fixing limit over the rents; and
  - (c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA): (a) The rent of private houses in Cantonments in U. P., including Kanpur Cantonment, is regulated by the provisions of the U. P. Cantonments (Control of Rents and Eviction) Act, 1952, and the Cantonment Board has not jurisdiction over the same. Under the provisions of this Act, the rent payable for any accommodation shall ordinarily be such as may be agreed upon between the landlord and the tenant. In the case of a dispute between the landlord and the tenant regarding the reasonable rent, it is the jurisdiction of the court of the Munsif or the court of Civil Judge to fix the same.

- (b) Does not arise.
- (c) Does not arise

#### NON-PROLIFERATION TREATIES

4748. SHRI NITIRAJ SINGH CHAU-DHARY: Will the Minister of EXTER-NAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether the non-proliferation treaties are expected to have within themselves the balance of mutual responsibilities and obligations for nuclear and non-nuclear powers;
- (b) if so, whether India expects to have a guarantee against China's threat of I. C. B. Ms.;
- (c) whether India has received such guarantees; and
- (d) the steps Government propose to take to meet the nuclear attack by China?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) The General Assembly in its resolution No. 2028(XX) has stated that the Treaty should embody an acceptable balance of mutual responsibilities and obligations on the nuclear and non-nuclear powers.

(b) to (d). The sponsors of the Treaty, viz- the U. S. A., and the U. S. S. R. have stated that assurances concerning the security of non-nuclear countries against nuclear attacks should be provided for not within the Treaty itself but within the framework of the U. N. Charter. They are holding discussions to this end.

#### NAVAL PORT AT ETTIKULLAM

4749. SHRI P. GOPALAN:
SHRI A. K. GOPALAN:
SHRI C. K. CHAKRAPANI:
SHRIMATI SUSEELA
GOPALAN:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

- (a) whether Government propose to construct a protected Naval Port at Ettikullam Cannanore District in view of the fact that there is a natural port site at Ettikullam; and
  - (b) if so, by what time?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

#### ALGERIA-INDIA COLLABORATION

4750. DR. RANEN SEN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether Algeria has sought Indian collaboration for setting up joint ventures in that country;
- (b) if so, the type of joint ventures proposed to be set up ;
  - (c) whether any steps have already been taken in this direction; and
    - (d) if so, the details thereof?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EX-(SHRIMATI **AFFAIRS** TERNAL INDIRA GANDHI): (a) to (d). During the course of discussions held in October, 1967 between the Government of India and a trade delegation from Algeria, the Algerian delegation had shown interest in setting up of factories in Algeria for the production of bicycles, motor-cycles, diesel engines and tractors with Indian collaboration. Experts from India are expected to visit Algeria early next year with a view to examining the feasibility of such ventures.

#### ALLOCATION FOR WEST BENGAL

4751. SHRI B. K. DASCHOWDHURY; Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) Whether the plan allocations for West Bengal for 1968-69 have been fixed; and
- (b) if so, what is the total amount and what is the share of the centre and the State?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

#### प्रावेशिक सेना

4753. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक सेना में लगभग 8,500 पद खाली पड़े हैं;

- (स) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; भौर
- (ग) पादेशिक सेना को सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रति रक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) प्रादेशिक सेना में (सभी श्रेणियों में) लगभग 7840 की कमी विद्यमान है।

- (ख) इस कमी के मुख्य कारण हैं :--
  - (1) प्रादेशिक सेना समग्र समय के लिये वृत्तिक प्राप्य नहीं करती; भौर
- (2) मालिक भ्रपने कर्मचारियों को प्रावेशिक सेना में प्रशिक्षण के लिए सदा छोड़ने भीर भ्रापाती स्थितियों में उनके समंगीकरण के वाबजूद भी, उन के पदोन्नति के पक्षों भीर उपलब्धियों को सुरक्षित रखने को राजी नहीं होते।
- (ग) सरकार मालिकों को भ्रपने कर्म-चारियों को प्रादेशिक सेना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए अनुरोध करती रहती है। सेवा की शतों और स्थितियों में सुधार करके तथा प्रशिक्षण सुविधाओं को युक्तिसंगत बनाते हुए प्रादेशिक सेना को भ्रषिक भ्राकर्षक भी बनाया जा रहा है।

ISSUE OF DIPLOMATIC PASSPORTS

4754. SHRI J. H. PATEL: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether Government propose to lay on the Table of the House a defining the categories of people who are allowed to travel abroad on diplomatic passports:
- (b) whether wives/relations/P. As., of Ambassadors, Ministers and Government officials of the Secretarial rank are issued diplomatic passports during their travel abroad;

- (c) whether Government have reserved to themselves the discretion to make an exception to the normal practice in this regard; and
  - (d) if so, the results thereof?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) Under item III in Part I of Schedule II/of the Passports Rules 1967, already laid on the Table of the House, a diplomatic passport is issued to the following categories of persons:—

- Officers of the Indian Foreign Service.
- (2) A person having diplomatic status either because of the nature of his foreign mission or because of the position he holds;
- (3) Following members of the family of an officer or a person referred to in item (1) or item (2) above when travelling with or joining such officer or person at Government expense:—

Wife or official hostess, as the case may be, husband, son and daughter.

A statement indicating the categories of persons who are ordinarily given diplomatic passports is placed on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT—2050/67.

- (b) Near relations namely, wives or husbands, sons and daughters, of Ambassadors, Ministers/(diplomatic), officers of the Indian Foreign Service, and other officers of diplomatic rank posted in the Indian Missions abroad are entitled to diplomatic passports for the period of their mission and return to India. PAs and officials of similar rank are not ordinarily eligible for diplomatic passports, unless they have to discharge diplomatic functions abroad e.g. couriers etc.
- (c) and (d). Government have discretion to issue a diplomatic passport to a person other than those specified in the categories mentioned in answer to (a) above when the issue of such passport is considered necessary in view of the position he holds or the importance of the mission on which he is proceeding abroad. This power to grant

diplomatic passports is not exercised arbitrarily but is regulated in accordance with the rules framed under the Act.

#### PRIME MINISTER'S TOUR OF TAMILNAD

#### 4755. SHRI MURASOLI MARAN: SHRI SEZHIYAN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) the expenditure incurred by Government for the Prime Minister's tour of Tamilnad during January-February, 1967;
- (b) the amount incurred by Government in respect of the public meetings organised by the Congress party and addressed by the Prime Minister at various places in Tamilnad; and
- (c) the sources and the accounts under which the above expenses were met?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) As permissible under the rules, Prime Minister travelled in an AIR FORCE plane. The prescribed charges due from her for these journeys were deposited into Government account. The other expenditure incurred by the Central Government was towards payment of TA and DA of the Personal and Security staff accompanying the Prime Minister. This amounted to about Rs. 300-00 (Rupees three hundred only).

(b) and (c). No expenditure was incurred by the Central Government on the meetings,

### अफ्रीकी देश छोड़ने वाले भारतीय व्यापारी

- 4756. श्री ओ० प्र० त्यागी: क्या वैदेशिक-कार्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या सरकार को इस बात की जान-कारी है कि बहुत से घनी भारतीय व्यापारी जो परिस्थितियों से विवस होकर अफीकी देश छोड़ रहे हैं, इंगमैंड तथा अन्य पश्चिमी देशों में बस रहे हैं और वहां अपनी पूंजी क्या रहे हैं;

- (ख) यदि हां, तो क्या उनके भारत लौटने के लिए सरकार ने कोई प्रयत्न किये हैं; भौर
- (ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार को कहां तक सफलता मिली है?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैवेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) हाल ही म भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति धपने निवास के देशों को छोड़कर दूसरे देशों को गए हैं, प्रमुख रूप से कीनिया से यूनाइटेड किंगडम के लिए। हमारी सूचना के धनुसार इनकी संख्या इतनी नहीं है जितनी कि कुछ धखवारों को देखने से लगती है। उनकी संपत्ति के बारे में कुछ भी मालुम नहीं है।

- (ख) जी नहीं। लेकिन, अगर भारतीय मूल के व्यक्ति भारत में बसना चाहते हैं तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंश्र हैं। भारत सरकार उन्हें भीर उनके परिवारों को सीमाशुल्क श्रीर श्रायात संबंधी कुछ रियायतें भी देती है ताकि यहां फिर से बसने में उन्हें सुविधा मिल सके।
  - (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## PUBLIC SECTOR CORPORATIONS UNDER DEFENCE MINISTRY

4757. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

- (a) the firms of Auditors of Chartered Accountants which are conducting the audit of Public Sector or autonomous corporations established under this Ministry since their establishment, and
- (b) how much amount has been paid to them as fee upto 1966?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA):

(a) and (b). The Information is furnished in the statement laid on the Table of the House [Placed in Library. See No. LT—2051/67].

## AUDIT OF PUBLIC UNDERTAKINGS UNDER I & B MINISTRY

4758. SHRI ARJUN SINGH
BHADORIA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be
pleased to state:

- (a) whether any firms of Auditors or Chartered Accountants are conducting the audit of all the public sector or autonomous corporations established under Ministry since their establishment; and
- (b) how much amount has been paid to them as fee upto 1966?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): (a) and (b). The Film Finance Corporation Ltd., Bombay is the only Government undertaking functioning under this Ministry. Besides the Children's Film Society, India and the India Institute of Mass Communication have been set up under the Societies Registration Act, 1860, and the Council of India under the Press Council Act, 1965. Excepting the accounts of the Press Council of India, which are audited by the Comptroller and Auditor General of India, those of the other three organisations are audited by firms of Chartered Accountants. The fees paid to the Auditors are as follows:-

Amount	Period for whic paid		
of fee			
paid	From	To	

#### Rs.

- (1) The Film 8,400 1960-61 1966-67 Finance Corporation Ltd., Bombay.
- (2) The Chil- 10,250 1955-56 1966-67 dren's Film Society, India, Bombay.
- (3) The Indian 500 in 1966
  Institute of
  Mass Communication,
  New Delhi
  (set up in
  August, 1965).

#### SAINIK SCHOOLS IN WEST BENGAL

- 4759. SHRI B. K. DAS CHOWDHURY: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:
- (a) the number of Sainik Schools in West Bengel with locations thereof;
- (b) the number of students receiving education therein; and
- (c) the annual expenditure incurred theron?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA):

- (a) One, at Purulia.
- (b) 280.
- (c) Estimated expenditure for the year 1967 is Rs. 4.13,348/-

#### DEVELOPMENT OF ROCKETS

4760. SHRI ONKAR LAL BERWA: Will the PRIME MINISTER be pleased to

- (a) whether it is a fact that a Rocket with a new type of Nose-cone was fired at Thumba; and
- (b) if so, whether there is any proposal for the deployment of these rockets for deference purposes?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) Yes Sir. Recently a Judi rocket was fired with a dart which was completely made in India.

(b) No. Sir.

## ARTISTES IN SONG AND DRAMA DIVISION

4761. SHRI M. MEGHACHANDRA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

- (a) the total number of artistes, Statewise, recruited by the Song and Drama Division in the year 1967;
- (b) the minimum and maximum pay scale for the artistes so recruited;
- (a) whether it is a fact that the artistes are facing grave difficulties in getting residential accommodation at Delhi; and

(d) if so, the arrangements being made to provide the artistes with residential accommodation?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): (a) 277 artists as follows:—

1. Assam				31
2. Manipur and	Tripu	ıra		43
3. Bihar .				26
4. Jammu and K	ashn	nir		18
<ol><li>Haryana</li></ol>				7
6. Uttar Pradesh	1			72
7. Himachal Pra	desh			34
8. Punjab .				12
9. Delhi .				10
10. Maharashtra				1
11. Kerala				5
12. West Bengal				7
13. Rajasthan				5
14. Andhra Prade	sh			1
15. Gujarat				2
16. Madhya Prade	sh			3
			_	
				277

(b) 1. Actors and Actres			215—440
2. Dancers .	300	•	215-440
	•	•	
3. Singers	:	•	215-400
4. Instrumentalists (S		•	215-400
<ol><li>Instrumentalists (James 1)</li></ol>	r.)	•	133—265
<ol><li>Stage Decorator</li></ol>		•	215-400
<ol><li>Make up man-cum</li></ol>	-Dre	sser	210-320
8. Stage Assistants			133-195
9. Instructor .			Consoli-
			dated
			Fee Rs.
			200.00
			p.m.
10. Performer			Consoli-
10. 10		•	dated
			Fee Rs.
			150·00
			p.m.
<ol><li>Training Assistant</li></ol>			Consoli-
			dated
			Fee Rs.
			100.00
			p.m.

(c) and (d). The artists on a regular pay scale are eligible for Government accommodation from the general pool like other Government employees. Those who are unable to secure such accommodation get house rent allowance as admissible under the rules.

#### MILITARY LANDS MANUAL

4763. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

- (a) whether there is a Military Lands Manual, as modified upto 1944, of the Government of India containing the various laws and regulations governing land policy in cantonment areas;
- (b) whether the laws and regulations in the said Manual concern the rights and titles of civilians resident in and owning property in a cantonment; and
- (c) whether it is a fact that sale of this Manual is not being made to the general public and if so, the reasons therefor?

#### THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Military Lands Manual is intended to be a guide to the procudure to be adopted in regard to the administration of military lands both inside and outside the Cantonment and also to their acquisition and relinquishment for Central Government purposes. The notes contained in the manual supplement in no way over-ride the provisions of the statutory rules and regulations or the terms of any grant. The publication is essentially meant as a guide to the officials connected with the administration of the military lands and accordingly the sale of the publication is not made to the general public. The laws and the statutory rules and regulations are, however, published in the official Gazette.

#### TRANSFER OF PROPERTY IN CANTONMENT AREAS

4764. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that when-ever any transfer of property taken place in a Cantonment area from a private person to another, the Military Estates Officers insist on the transferee signing an acknowledgement deed admitting Government's title over the land; and
- (b) if so, the reasons for getting such an acknowledgement deed ?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA): (a) and (b). No, Sir. This is not insisted upon in every case. Admission deed is required to be executed only in the case of grants made under General Order by the Governor General in Council No. 179 dated 12th September, 1836.

Condition 6 of the said Order stipulates that a transferee of a site held under the terms of this Grant shall also subscribe to the conditions of the Grant.

## ढाका में भारतीय दूतावास

4767. डा॰ सुर्य प्रकाश पुरी : स्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बतानें की कृपा करेंने कि:

- (क) क्या यह सच है कि क्षाका में भारतीय दूतावास में कार्य कर रहे कर्मचारियों के निवास के लिय उचित प्रबन्ध नहीं है ;
- (स) क्या यह भी सच है कि वहां टूटे फूट मकानों में भारतीय कर्मचारी रहते है: ग्रीर
- (ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) भीर (ख). सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ भारत-ग्रास्थानी कर्मचा-रियों के लिए रहनें की जगह की व्यवस्था करना है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि इन कर्मचारियों को रहनें के लिये जो मकान बिए गए हैं वे भ्रपर्याप्त हैं भ्रयवा टुटी-फूटी धवस्था में हैं।

## (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

#### CONSTRUCTION OF DAMS BY PAKISTAN

4768. SHRI D. N. PATODIA: SHRI N. K. SANGHI: SHRI Y. A. PRASAD: SHRI D. N. DEB :

Will the Minister of EXTERNAL AF-FAIRS be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that Pakistan is constructing bunds and embankments at different places on Manu, Dhalau, Gomti, Khauri and Muhurim rivers, which is likely to result in widespread floods in Tripura as a result of blockade of passage of water in these rivers;
- (b) whether Government have taken up this matter with the Pakistan Government; and
- (c) if so, the reaction of the Government of Pakistan thereto ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER EXTERNAL **AFFAIRS** (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Pakistan Government's response has not been encouraging. Either they have denied the existence of such constructions' or have justified them on the plea that these were vital for Pakistan. Joint enquiries by the Engineers of the two countries have been held in some cases, but no satisfactory results have been obtained so far.

#### SETTLEMENT OF KASHMIR DISPUTE

4769. SHRI D. N. PATODIA : SHRI Y. A. PRASAD: SHRI D. N. DEB : SHRI R. R. SINGH DEO:

Will the Minister of EXTERNAL AF-FAIRS be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that according to the news appearing in the Pakistani Press, West Germany favoured the settlement of Kashmir dispute on the principles of justice and self-determination:
- (b) whether Government have checked up the veracity of this Press statement; and
  - (c) if so, the findings thereof?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EX-TERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) to (c). The position has been explained in this House in the statement made by the Prime Minister on December 8, 1967 in connection with a Calling Attention Notice.

## विदेशों से छात्रवृत्तियां तथा निमंत्रण

4770 श्री ओंकार लाल बोहरा : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या भारतीय विद्यार्थियों को विदेशी सरकारों द्वारा पेश की जानें वाली खात्रवत्तियों को स्वीकार करनें के लिये उनके मंत्रालय की मनुमति नहीं लेनी होती है।
- (ख) यदि हां, तो भारतीय नागरिक होनें के नाते क्या वे विदेशी सरकारों से सहायता ले सकते हैं; भौर
- (ग) क्या विदेशों के विभिन्न केन्द्रीय संगठनों से देश को मिलने बाले निमंत्रणों के सम्बन्ध में भी उनके मंत्रालय की धनु-मित लेनी अपेक्षित नहीं है और यदि हां, तो यह बात कहां तक उचित है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वेदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्बिरा गांधी): (क) ग्रीर (ख). विदेशी सरकारों द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्तियों पर सम्बद्ध मंत्रालय विदेश मंत्रालय के परामर्श से विभार करते हैं भौर तब वे चुनाव के भाभार पर भारतीय छात्रों को दी जाती हैं। सरकारी कर्मचारियों की स्वीकृति विभागीय विनियमों द्वारा संचालित होती है।

(ग) भारत-स्थित विदेशी मिशनों को समय समय पर यह सलाह दी गई है कि वे घपनी (सरकारों, संगठनों भौर संस्थानों की भोर से जो भी नियंत्रण दें वे सब विदेश मंत्रालय के जरिय दिए जाने चाहिए।

## DEFENCE EQUIPMENT MANUFACTURED IN ORDNANCE FACTORIES

4771. SHRI S. S. KOTHARI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

- (a) the value of defence equipment manufactured by Ordnance Factories and public undertakings;
- (b) whether it is a fact that India is selfsufficient in light artillery;
- (c) how the semi-automatic rifle, developed in the ordnance factories compares with similar weapon manufactured abroad; and
- (d) whether there is any proposal to export such rifles?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA) (a) The value of Defence equipment delivered to the Armed Forces from Ordinance Factories, Departmental Undertakings and Public Sector Undertakings in 1966-67 was approximately Rs. 150 crores.

- (b) Yes, Sir.
- (c) The performance of the Indian semiautomatic rifle compares favourably with similar weapons manufactured abroad.
- (d) It would not be in public interest to give any details in this regard.

महापुरुषों के जीवन के बारे में फ़िल्में 4772. श्री ऑकार लाल बोहरा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बतानें की कुपा करेंगे कि :

- (क) क्या भारत के महापुरुषों के जीवन पर तथा उनके सन्देंश का प्रचार करनें के लियें जिन्होंनें राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा दी है, फिल्में बनानें के प्रस्ताव पर फिल्म डिवीजन विचार कर रहा है; सौर
- (का) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के o के o बाह): (क) भीर (स). एक विवरण सभा पटल पर रसा जाता है। [पुस्तकासय में रसा गया। देखिये संस्था LT 2052/67]।

## हिन्दी की फ़िल्में

4773. श्री ऑकार लाल बोहरा : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

- (क) किन राज्यों में हिन्दी भाषा की अधिक फिल्में बनती हैं; भौर
- (स) किन राज्यों में सब से मधिक लोग उन फिल्मों को देखते हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) महाराष्ट्र ग्रीर मद्रास ।

(ख) इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देना कठिन हैं, परन्तु यदि पक्के सिनेंमाघरों और उनमें कितनी सीटें हैं, इन की संख्या के स्नाधार पर चला जाए, तो यह समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र, स्नांध्र प्रदेश, मद्रास, केरल, पिष्चम बंगाल और मध्य प्रदेश में लोग बड़ी संख्या में सौर बार बार हिन्दी फिल्में देखते हैं। इस घारणा का स्नाधार यह है कि प्रादेशिक फिल्में झपनी कीमत पूरी करना भी मुश्किल पाती हैं।

## छोटे समाचार पत्रों को प्रोत्साहन

4774. श्री ओंकार लाल बोहरा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने छोटें घौर प्रादे-शिक भाषा समाचार-पत्रों की वित्तीय स्थिति सुधारनें के उद्देश्य से उन्हें विज्ञापनों भादि की भ्रषिक सुविधायें देनें की कोई योजना बनाई है; भौर
- (स) क्या छोटे विशेषकर प्रादेशिक भाषा समाचार-पत्रों की समस्याम्रों का मध्ययन करने तथा उन्हें दूर करने के सुझाव देने के लिए एक समिति बनाने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (भी के के गाह): (क) उपलब्ध धन राशि के भन्दर भन्दर, छोटे भीर प्रादेशिक भाषाओं के समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन देनें की मात्रा बढ़ानें का पूरा प्रयस्न किया जा रहा है। सरकारी विज्ञापनों के लिए छोटे भौर भारतीय भाषाधों के समाचार-पत्रों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की सरकार की नीति के कार्यान्वियन के बारे में विज्ञापन भौर दृश्य प्रचार निदेशालय को सलाह देनें के लिये एक समिति बनाई गई है जिसमें इण्डियन लैग्वेज न्युज पेपर्स एसो-सियेशन के प्रधान भी शामिल हैं। इस समिति की पहली बैठक 8 नवम्बर, 1967 को हुई

(ख) छोटे समाचार-पत्रों की जांच समिति भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों सहित छोटे समाचार-पत्रों की समस्याधीं का ग्रध्ययन किया है। इसके लिय एक भौर समिति स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

### कृषिजन्य आय पर आयकर

### 4775. श्री रामावतार शास्त्री : श्री गुणानन्द ठाकुर:

क्या प्रधान मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की पिछली बैठक में राज्यों में लगान की बजाय कृषि जन्य ग्राय पर ग्रायकर लगानें से सम्ब-न्धित विषयों पर विचार किया गया था:
- (ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया था तथा किन किन राज्यों के मस्य मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था तथा किन-किन राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इस का विरोध किया था: और
- (ग) विरोध करने वाले मुख्य मंत्रियों ने इसका विरोध करने के क्या कारण बताये थे?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तया वैवेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में ग्रामीण क्षेत्र से राजस्व बढ़ाने के अन्य उपायों के साथ साथ, कृषिजन्य आय-

कर को सामान्य आयंकर के साथ मिलाने के योजना आयोग के सुझाव पर भी विचार किया गया या। यह निश्चय किया गया कि ग्रामीण श्रेत्र से अतिरिक्त साधनों के जटाने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग की एक समिति का गठन करे।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

#### BOMBING AND FIRING RANGE AT TILPAT (HARYANA)

4776. SHRI D. C. SHARMA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the land acquired by his Ministry for setting up Bombing and Firing Range at Tilpat (Haryana) for the Indian Air Force is not being used for the purpose;
- (b) whether it is also a fact that it has been leased out to cultivators to whom it originally belonged and is being used for cultivation and other agricultural purposes now;
- (c) whether it is further a fact that some land belonging to the farmers of the adjoining villages has been forcibly cultivated by Air Force authorities and the farmers are harassed; and
- (d) if so, the action taken or proposed to be taken against the officers responsible for it ?

THE MINISTER OF STATE (DEF-ENCE PRODUCTION) IN THE MINIS-TRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA): (a) No, Sir.

- (b) No., Sir.
- (c) No, Sir.
- (d) Does not arise.

#### कवि संसाधनों सम्बन्धी उप-समिति

4777. श्री बेबराव पाटिल : स्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने 2 और 3 दिस्मबर, 1967 को हुई अपनी बैठक में कृषि संसाधनों सम्बन्धी एक उप-समिति गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस उप-सिमिति की नियुक्ति कब तक हो जायेगी और इस प्रस्तावित उप-सिमिति के निर्देश पद क्या होंगे ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री: (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) राट्रीय विकास परिषद् ने अपनी 1 और 2 दिसम्बर, 1967 को हुई बैठक में निश्चय किया कि ग्रामीण क्षेत्रों से अतिरिक्त साधनों को जुटाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये योजना आयोग एक समिति गठित करे।

(ख) सिमिति के गठन और विचारणीय विषयों के बारे में व्यौरा तैयार किया जा रहा है।

PROFITS OF HINDUSTAN AERONAUTICS
4778, SHRI M. MEGHACHANDRA:
Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Hindustan Aeronautics Ltd. has been able to increase its earnings in its sales and is also earning increasing profits;
- (b) if so, the progress in its sales and profit during the years 1964-65, 1965-66 and 1966-67; and
- (c) the saving in foreign exchange made by the increase in its sales during the above period?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) The sales during the years 1964-65 to 1966-67 and profits earned are as follows:

1964-65 1965-66 1966-67

(Rupees in lakhs)

Sales . 1340·91 1646·33 2857·87 Net Profit . 103·75 121·98 129·24

### CONVENTIONAL T. V. STATIONS

4779. SHRI M. MEGHACHANDRA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

- (a) whether under a Satellite Communication Pilot Project experiment under the auspices of UNESCO, more conventional television stations are being set up in the country;
- (b) if so, the details thereof and the expenditure involved; and
- (c) whether all the components of the TV sets will be manufactured in India?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): (a) to (c). A UNESCO Mission was in India during the period November 17 to December 8, 1967 to examine the feasibility of a pilot project on the use of Satellite communic ation. The Mission was assisted by a counter-part team nominated by the Government of India. The report of the Mission has not yet been received. It will be possible to decide whether all the components will be manufactured in India after receipt of the report.

## पेकिंग रेडियो द्वारा भारतीय फिल्मी कलाकारों का प्रचार

4780. श्री यशपाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) एशियाई फिल्म समारोह में भाग लेने वाले फिल्मी कलाकारों के नाम क्या हैं तथा यहां पर कौन कौन सी फिल्में भेजी गई थीं।
- (ख) क्या सरकार को पता है कि कुछ महीने पूर्व पेकिंग रेडियो द्वारा एशियाई फिल्मी समारोह में भाग लेने वाले कुछ भारतीय फिल्मी कलाकारों के बारे में प्रन्वार किया गया था;
- (ग) क्या यह सच है कि फिल्म "यादें" के निदेशक श्री सुनील दत्त ने पेकिंग रेडियो से इस प्रचार का प्रवन्ध कराया था; और
  - (घ) क्या सरकार उसके विरुद्ध कोई कार्य-बाडी कर रही है ?

<sup>(</sup>c) The information is being compiled and will be pleaced on the Table of the House.

सुचना और प्रसारण मंत्री (भी के० के शाह) : (क) एक विवरण जिसमें एशियाई फिल्म समारोह फन्कफर्ट में भाग लेने वाले फिल्मी कलाकारों तथा फिल्मों के नाम दिये गये हैं, सभा पटल पर रखा गया है। पुस्तकालय में रखा गया। वेचिये संख्या एल० टी०-2053/67]।

- (ख) और (ग). जी, हमारी जानकारी में नहीं।
  - (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

SUPPLY OF TINNED MEAT TO ARMY BY ESSEX FARM, DEIHI

4781. SHRI K. RAMANI : SHRI GANESH GHOSH: SHRI UMANATH: SHRI K. M. ABRAHAM:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

- (a) whether Government have received any representation regarding the slaughtering of pregnant goats by Essex Farm, Delhi, who are supplying tinned meat to Army:
- (b) if so, whether it is a fact that due to the slaughtering of pregnant goats, there is discontentment amongst the workers and a large number of workers have been dismissed:
- (c) whether Government have investigated into the matter; and
- (d) if so, the result thereof and the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA): (a) Yes, Sir. A Member of this House has represented in the matter.

(b) to (d). Inquiry in the matter reveals that Army Veterinary Officer conducts ante-mortem and post-mortem examination, and it is not correct that pregnant goats are slaughtered for supply of tinned meat to the Army. However, Government is not aware that there is discontent amongst the workers due to the slaughtering of pregnant goats.

विकलांग सैनिकों को उद्योगों में नौकी देना

4782. श्री ऑकार लाल बेरवा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने विकलांग सैनिकों को उद्योगों में नौकरियों देने की एक योजना तैयार की है; और
- (ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (भी ल० ना० मिथ) : (क) तथा (ख). जी हां। उनके लिये उनकी शिक्षा योग्यताओं, अन्भव और अवशिष्ट क्षमता के अनुसार, हो सके तो उनके ही राज्य /जिला में, साधारण मेडिकल मानदंडों में छुट देते हुए, सरकारी विभागों, राजकीय क्षेत्र के उपक्रमों और निजी फर्मों में उपयुक्त असैनिक रोजगार ढूंढ़ने के यत्न किए जाते हैं। काम दिलाऊ कार्यालयों द्वारा पूर किए जाने वाले तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी स्थानों में नियक्ति के लिये नियोग्य मृतपूर्व सेवा सेविवर्ग को ततीय वर्ग की प्राथमिकता में भारी प्राथमिकता दी जाती है। कामदिलाऊ कार्यालयों द्वारा पुर किए जाने वाले तृतीय श्रेणी स्थानों के लिए शिक्षा योग्यताओं में छूट भी दी जाती है। उन व्यक्तियों के लिए जो शिक्षा योग्यता के अभाव के कारण असैनिक रोजगार के लिए सीघे लिए जाने के योग्य नहीं समझे जाते. व्यावसायिकः प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण उन्हें औ-द्योगिक फर्मों में रोजगार प्राप्त करने में सहायता देते हैं, या अपना रोजगार शरू करने में।

## बुरबेलखन्ड के लिए रेडियो स्टेशन

4783. श्री राम सिंह अयरवाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश

के बुंदेलखण्ड क्षेत्र में अभी तक कोई रेडियो स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है;

- (बा) संस्कृति, कला और शिल्प, भाषा तथा साहित्य के बारे में इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इस में निकट में भविष्य में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

## सूचना झौर प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). नौथी पंच वर्षीय योजना के मसौदों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के लिये एक अलग रेडियों केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है। वास्तविक स्थान का निर्णय तकनिकी और कार्यक्रमों को तैयार करने में उस की उपयुक्तता को ध्यान में रख कर किया जाये। यह प्रोजेक्ट अपेक्षित साधनों और विदेशी मुद्रा के उपलब्ध होने पर कार्यन्वित किया जाएगा।

#### SCHOLARSHIPS IN SAINIK SCHOOLS

4784. SHRIB. K. DASCHOWDHURY: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

- (a) the schemes of various State Governments, Union territories and Central Government for grant of scholarships to the boys who qualify for admission in the Sainik Schools;
- (b) whether any proposal is under consideration to increase the amount of scholarships in view of the rise in prices since the institution of the scholarships;
- (c) the number of students who qualify for admission, but do not join the school/ leave the schools after joining it for some time due to financial stringency of their parents; and

(d) whether there is any proposal to increase the existing income ceilings for the purpose of grant of scholarships due to high cost of living?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA) (a) A statement giving details of the scholarship schemes instituted by the State Governments and the Ministries of Home Affairs and Defence for education in the Sainik Scholols is laid on the Table of the House, [Placed in Library. See No. LT-2054/67.]

- (b) There is a proposal before the Board of Governors, Sainik Schools Society to increase the fees to be charged in the Sainik Schools. If approved by them, this will require a consequent increase in the amounts of the scholarships.
- (c) No statistics are available. The scheme of scholarships has been devised in order to obviate such cases.
  - (d) No.

### जहां भारत मूलक लोग बसे हुए हैं उन बेशों से सम्बन्ध

4785. श्री शिव चरण लाल : क्या वैवेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के साथ, जहां भारत मूलक लोग बसे हुए हैं, घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा बैवेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): भारत सरकार उन सभी देशों में अपने राजनियक और दूसरे प्रतिनिधि रखती है जहां भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, और इन मिशनों के माध्यम से तथा अन्य उपयुक्त तरीकों से इन देशों के साथ और वहां रहने वाले भारतीय मूल के बोयों के साथ सम्बन्ध बनाए रखने और बढ़ाने की कोशिश करती है। भारत सरकार उन्हें हर तरह की सहायता देने की भी कोश्रिश करती है, विशेषकर आर्थिक, स्रीकिक और सांस्कृतिक खेलों में।

### ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग

4786. श्री शिवचरण लाल : न्या वैवेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

- (क) ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग में कितने अफसर तथा कर्मचारी कार्य कर रहे हें ;
- (ख) उनकी हिन्दी की योग्यता का व्यौराक्या है:
- (ख) क्या उच्चायुक्त को हिन्दी में लिखे गए पत्नो के उत्तर हिन्दी में नहीं दिए जाते, क्योंकि वहां हिन्दी जानने वाले कर्मचारी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं: और
- (घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्बरा गांधी): (क) 322।

- (ख) सचना इकटठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।
- (ग) जी नहीं । हाई कमिश्नर के नाम से हिन्दी में जो पत्र भेजे जाते हैं। उनका हिन्दी में उत्तर दिया जाता है।
- (घ) हिन्दी के उपयोग के बारे में भारत सरकार के निदेशों का बराबर पालन किया जाता है। हिन्दी कक्षाएं चलाई जा रही हैं ताकि ऐसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा सके जो हिन्दी में पत्र-व्यवहार कर सकते हों।

#### APARTHEID IN RHODESIA

4787. SHRI HIMATSINGKA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the report that the Rhodesian Minority Government is taking vigorous steps to enforce apartheid in Rhodesia;

- (b) if so, the steps, according to Government's information, being taken by the Smith regime in that direction; and
- (c) the steps Government are taking to make them refrain from taking such steps through the U.N. or otherwise ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EX-TERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) Yes, Sir.

- (b) Reports indicate that legislation enacted and contemplated by the illegal regime in Rhodesia aims at setting up machinery for the separate development of races in Southern Rhodesia on the pattern of the apartheid regime in South Africa.
- (c) Rhodesia being a British Colony, it is legally, morally, and constitutionally the responsibility of Britain to take steps to restrain the Smith regime from enforcing apartheid in that territory. India is cooperating with other like-minded countries in the United Nations and elswhere in all action aimed at bringing down the white minority regime and the installation of a representative Government in Zimbabawe, based on the will of the majority of the population.

#### ACCOUNTS-CUM-ADMINISTRATIVE OFFICER IN NATIONAL SAMPLE SURVEY

4788. SHRI RAM CHARAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to

- (a) whether it is a fact that a post of Accounts-cum-Administrative Officer is being created in the Directorate of National Sample Survey under the Department of Statistics:
- (b) whether the existing arrangements have been found satisfactory since the inception of this organisation; and
- (c) if so, the reasons for creating the post referred to at (a) above in the context of the present financial stringency ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EX-TERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). While the existing arrangements were satisfactory in the beginning, it has been felt for some time past that due to increase in the volume of work in the Directorate of National Sample-Survey, he arrangements for supervision of accounts and administration work should be strengthened. The extra expenditure involved is nominal.

#### MANUFACTURE OF RADAR AND MICROWAVE EQUIPMENTS

4789. SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

- (a) whether there is any proposal to set up a new unit for the manufacture of radar and Micro-wave equipments;
  - (b) if so, the details thereof:
  - (c) the estimated cost of the unit; and
  - (d) when the unit is likely to be set up?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA):

(a) Yes, Sir.

(b) to (d). The Bharat Electronics Limited, who have been entrusted with the planning of the new factory, have commenced the preparation of the Project Report. The details of the project, e.g. estimated cost, schedule of production, etc., would be available only on the receipt of the Project Report, which is expected by the middle of 1968.

#### MANUFACTURE OF TELEVISION SETS

4790. SHRI YOGENDRA SHARMA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 30 on the 14th November, 1967 and state :

- (a) the estimated production capacity of the firms given licences for the manufacture of Television Receiver sets;
- (b) when the production is likely to start; and
- (c) the estimated price of the television sets produced by these firms ?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) Two firms have been licensed for the

production of 10,000 television receiver sets each, per year.

- (b) By the middle of 1968.
- (c) Televison sets with 23" Screen are expected to be marketed at Rs. 1500/each and those with 19" Screen at Rs. 1350/- each.

CHINESE TROOPS CONCENTRATIONS ON NORTH SIKKIM BORDER

SHRI SAMAR GUHA: SHRI N. K. SOMANI: SHRI K. P. SINGH DEO :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that China is concentrating troops in unusual strength along the border areas of North Sikkim:
- (b) if so, what is the underlying objective of such Chinese build-up along the sensitive Indo-Chinese border areas ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) - (a) Although the Chinese continue to remain in strength along our northern borders and the borders of Sikkim with Tibet, there is no indication that in recent months there has been any significant increase in that strength on the North Sikkim border.

(b) Does not arise.

#### LOAN TO NEPAL

4792. SHRI NARENDRA SINGH MA-HIDA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

- (a) the total amount of loan given to the Nepalese Government since 1947:
- (b) the terms and conditions thereof: and
- (c) the purpose for which this amount has been utilised by the Government of Nepal ?

THE PRIME MINISTER. MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EX-TERNAL AFFAIRS(SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) Rupees one Crore.

(b) The loan is to be utilised for the establishment of industrial enterprises in Nepal, particuarly in the fields of jute. cement, paper, textile industries and such other industries which would be beneficial to Nepal. It carries interest at 3% and is repayable over a period of 15 years.

(c) Being utilised for industrial development.

### बिहार के सिये धन का मियतन

4793. श्री भोगेन्द्र साः क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 के लिये बिहार सम्बन्धी योजनाओं के लिये 75 करोड़ 43 लाख रुपये की राशि नियत करने का प्रस्ताव था;
- (ख) क्या यह भी सच है कि उक्त राक्षि को अब घटा कर 70 करोड़ 41 लाख रुपये कर दिया गया है; और
- (ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और यदि नहीं तो इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) राज्य सरकार ने अपनी वर्ष 1968-69 की योजना के लिये 75 करोड़ 43 लाख रुपये की व्यय-व्यवस्था का प्रस्ताव किया है।

- (ख) राज्य की वार्षिक योजना 1968-69 के प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं।
  - (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## OPENING CEREMONY ON MANGLA DAM

4794. SHRI SRADHAKAR SUPAKAR: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that at the time of the opening ceremony of the Mangla Dam, the contribution of buge sums of money by India was not mentioned in the report: and
- (b) whether the Indian national Flag was not flown along with the flags of other nations at the above ceremony?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF

PLANNING AND MINISTER OF EX-TERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). Yes, Sir. The Indian Flag was not flown at the opening ceremony. Flags of only those countries who had contributed to the construction of the Mangla Dam were flown at the ceremony, and we were not one of these.

## REPATRIATION OF INDIANS DETAINED IN BURMA

4795. SHRI S. C. SAMANTA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) the further progress made in the matter of securing the release and repatriation of the Indians detained by the Burmese Government for the so-called economic offences; and
- (b) the facilities afforded to them by our Embassy in Rangoon?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). Two more persons have been released very recently bringing the total released from jail to 56 persons so far. The Embassy is pursuing with the Burmese authorities the release of the remaining 23 persons still under detention. The Embassy interviews the detenus and brings any difficulties mentioned by them to the notice of the Burmese authorities for remedy.

## RESUMPTION OF TALKS WITH NAOAS

4796. SHRI K. P. SINGH DEO: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether the leaders of the underground Nagas have offered some fresh conditions for the resumption of talks with Government on the Naga problem;
- (b) if so, the main features thereof;
  - (c) Government's reaction thereto ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) Government of India have not been approached in the matter, by the Underground Nagas.

(b) and (c). Do not arise.

#### AO AND SEMA TRIBAL COUNCILS

#### 4797. SHRI YAJNA DATT SHARMA : SHRI HEM BARUA :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that Ao and Sema Tribal Councils have passed resolutions asking all-non-Nagas running shops or doing business under the licence of local Nagas to quit the Nagaland area within six months;
  - (b) if so, the details thereof; and
- (c) the steps taken by Government for the security of non-Nagas who are doing business in Nagaland?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) to (c). State Government of Nagaland have informed us that they (the State Government) have set up a committee to examine the matter. The State Government has also informed the Tribal Council/Councils concerned not to take any precipitate action.

PASSAGE OF ISRAELI SHIPS THROUGH THE SUEZ CANAL

4798. SHRI BEDABRATA BARUA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether Government have taken any steps to resolve the situation arising out of the stand taken by the U.A.R. Government not to allow Israeli ships to pass through the Suez Canal; and
  - (b) if so, the outcome thereof?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). Israeli ships bave

never been permitted to pass through the Suez Canal and the present situation in West Asia does not owe its origin to the denial of passage to Israeli navigation through the Suez Canal.

It may be mentioned that since the very beginning of the West Asian crisis, India has in cooperation with other countries, continued to make strenuous efforts at the United Nations and elsewhere to assist in the finding of an acceptable solution which would bring about peace and stability in the area on a lasting basis. After prolonged consultations among members of the Security Council, a draft Resolution sponsored by U. K. was passed unanimously on November 22, 1967.

#### PRICE OF TRANSISTOR RADIO SETS

4798-A. SHRI S. C. SAMANTA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

- (a) the efforts being made to bring down the cost of the transistor radio so as to place it within the reach of general public; and
- (b) the price of the single band low cost transistor radio at present ?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA):
(a) It has been decided that 75% of the new capacity being licensed for manufacture of radio receivers, whether valve type or transistor type, is to be used for the production of low cost radio receivers. Components constitute the major portion of the cost of radio receivers. Therefore steps are being taken to get these manufactured at cheaper prices.

(b) The prices at which single band low cost transister radios are being sold vary from firm to firm. One of the sets is being sold in Super Bazar for Rs. 85/-.

#### APPRISING M.Ps. WITH DEVELOP-MENT PROGRAMMES

4798-B. SHRI K. LAKKAPPA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any instructions were issued to the State Governments stating that Members of Parliament ahould be apprised of agricultural and other development programmes during their non-Session period;

- (b) if so, whether any reports have been called for as to how far the officers and the State Governments have followed these instructions; and
- (c) if not, whether Government would take steps to see that the respective constituency programmes are apprised to the M.Ps.?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) The Ministry of Agriculture, Department of Community Development, wrote to State Governments requesting them to afford facilities to M.Ps. to visit Development Blocks and see the working of agricultural and connected programmes. No other general letter on the subject has been issued.

(b) and (c). No special reports were called for by the Agriculture Ministry. It is assumed that the State Governments provided M.Ps. with appropriate facilities.

#### ESTABLISHMENT OF A COMPUTER CORPORATION WITH U. S. ASSISTANCE

4798-C. SHRI K. P. SINGH DEO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) whether Government propose to set up a Computer Corporation in India with the assistance of an American firm;
  - (b) if so, the details thereof; and
- (c) the benefits likely to be derived by setting up such a Corporation?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) Ten computer systems are being located in different parts of the country. A proposal to bring the activities of these computer systems under a corporation run by Government is under consideration. No assistance from any

American firm in the setting up of the proposed corporation as such is contemplated.

(b) and (c). No detail have been worked out yet.

#### PAK INFILTRATORS

## 4798-D. SHRI R. R. SINGH DEO: SHRI BEDABRATA BARUA:

Will the Minister of EXTERNAL AF-FAIRS be pleased to state:

- (a) whether Government have sent a protest note to the Government of Pakistan against their policy of sending the infiltrators into Assam; and
  - (b) if so, the reaction of the Government of Pakistan in this matter?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) Several notes have been sent to the High Commission of Pakistan urging them to prevent such infiltration.

(b) Pakistan Government have repeatedly denied the charge, alleging in turn, that the infiltrators are Indian nationals evicted from India and whom the authorities in Pakistan are obliged to send back.

# SETTING UP OF ILMENITE ORE PROCESSING PLANT IN KERALA

4798-E. SHRI A. K. GOPALAN:
SHRI C. K. CHAKRAPANI:
SHRIMATI SUSEELA
GOPALAN:
SHRI P. GOPALAN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

- (a) whether there is any proposal to set up an ilmenite ore processing plant in Kerala to make use of the rich ilmenite deposits in that State;
  - (b) If so, the details thereof; and
  - (c) if not, the reasons therefor ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). Indian Rare Earths Limited, a public sector undertaking under

the administrative control of the Department of Atemic Energy, has finalised plans for setting up a processing plant at Chavara near Quilon (Kerala), to produce the following minerals in the quantities indicated against each:

	•	٠ ،	r	Metric tonnes/ annum
Ilmenite	<u> </u>			100,000
Rutile				5,850
Zircon				7,000
Monazite				585
Sillimanite				4,100

The estimated fresh outlay on this plant is approximately Rs. 160 lakhs.

(c) Does not arise.

#### विल्ली विकास प्राधिकार

4798-F श्री रघुवीर सिंह शास्त्री: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विकास प्राधिकार को किस कारण से स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन लाया जा रहा है?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वंदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में विषय हस्तान्तरण जब कभी प्रशासकीय सुविधा के हित में आवश्यक होता है, तो किया जाता है। जहां तक दिल्ली विकास प्राधिकार का सम्बन्ध है, यह मामला अभी विचाराधीन है।

#### 12.14 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

DISTRIBUTION OF POSTERS IN ASSAM SAYING 'ASSAM FOR ASSAMESE'

MR. SPEAKER: Shri Daschowdhury.

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati): On a point of order, Sir.

MR. SPEAKER: How can a point of order arise when there is no subject at all before us. Is it about the calling attention?

MR. SPEAKER: You cannot question that on the floor of the House. You have no right to question it on the floor of the House. Nothing will be taken down. You may have your satisfaction.

#### SHRI DHIRESWAR KALITA: \*\*\*

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) :\*\*

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch Behar): Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:—

Distribution of posters in Assam saying "Assam for Assamese".

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): Mr. speaker. Sir, the state Government have informed us that some posters, mostly in Assamese, but a few in English also started appearing from middle July to middle August. 1967 containing slogans like "Stop Exploitation "Assam for Assamese" and of Assam", "Down with Federal Plan" etc. A leaflet entitled "Ahvan" was also found in circulation in Nowgong town exhorting the Assamese people to launch a peaceful agitation against exploitation by the non-Assamese people. In early November, 1967 a printed handbill addressed to students was found in limited circulation in Gauhati. It emphasized the theme of "Assam for Assamese" and asked the students to fight for the legitimate right of local people to get preferential treatment in both public and private employment. Enquiries made by the State Government disclose that a number of miscellaneous groups that have recently sprung up are circulating pamphlets and posters. No established political party or organisation is reported to be responsible for these posters. The State Government are making further inquiries in the matter. The Central Government are in close touch with the State Government regarding these developments.

<sup>\*\*</sup>Not recorded.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY: Sir, it has been stated by the hon. Minister that no established organisation has any connection with this. So far, we have come across the cases of the Shiv Sena and Hindi Sena. Here, you find another Sena, that is, Lachet Sena, in Assam. With your permission, I would like to quote from Indian Express, Delhi Edition, of 21st September, 1967:

"The 'Assam for the Assamese' movement is gaining strength in this frontier State of India. A Lachet Sena on the pattern of Shiv Sena is being organised in Assam.

Reports received in the State capital from all over Assam indicate that the sponsors of the move have intensified their poster campaign during the last few days..... posters asking the Assamese to unite to 'free Assam' have appeared in all important towns of Assam."

These posters pose a serious problem to India today. This is simply furthering a cause of disintegration movement in India. Not only that. This has caused wide-spread insecurity and nervousness in the minds of the people, non-Assamese speaking people. May I know from the hon. Minister whether the Government propose to make a thorough probe and investigation through C. B. I. to find out the origin and the real intention of the Lachet Sena and this poster-campaign in Assam?

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli): Including Shiv Sena.

M.R. SPEAKER: Don't bring Shiv Sena at every stage.

SHRI Y. B. CHAVAN: I do not deny the seriousness of the problem that these Senas have raised. But as far as developments in Assam are concerned, I am sure, the Assam Government is aware of it and they are making certain probes and enquiries into the matter. As I said, we are also in close touch with them.

श्री रचुवीर सिंह शास्त्री (वागपत): जैसा कि माननीय गृह मंत्री महोदय ने कहा है यह समस्या बहुत गंभीर है और कुछ संस्थाएं व कुछ व्यक्ति अपने दलगत स्वार्यों को राष्ट्र के ऊपर रख कर देश में प्रान्तीयता, भाषावाद

और पृथक्करण की भावना का जो विष है उसे जनमानस में भर रहे हैं। यह नई-नई सेनाएं बन रही हैं और कुछ सेनाओं के विषय में तो समाचार पत्नों से यह भी ज्ञात हुआ है कि वह खुनी क्रांति और हिथयारों की टेनिंग की बात भी करने लगे हैं। इस का यह भी परिणाम हो सकता है कि किन्हीं दो ऐसी सेनाओं में संघर्ष हो जाय और देश के सामने एक विचित्र स्थिति पैदा हो जाय । विशेष रूप से क्योंकि आसाम हमारी सीमा का प्रान्त है इसलिए सुरक्षाकी दृष्टि से उस का विशेष महत्व है, मैं गृह मंत्री महोदय से पछना चाहता हं कि क्या ऐसी तो बात नहीं है कि कुछ विदेशी एजेंटों का इस मामले में हाथ हो. य। आसाम के पूनर्गठन का जो मामला चल रहा है उस का तो कोई इस में हाथ नहीं है? हम विदेशों में तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात कर रहे हैं परन्तु अपने यहां एक प्रान्त **और दूसरे** के बीच में ही सह-अस्तित्व नहीं रख सकते। तो यह गंभीर स्थिति इस समय पैदा हो यई है। ऐसी स्थिति में मैं यह भी प्रश्न करना चाहता हं कि क्या प्रिवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट जो है, इस प्रकार से सीमा प्रान्त और देश की सूरक्षा को दृष्टि में रखते हुए उस के माध्यम से कार्यवाही करने में सरकार की कोई दिक्कत है ? और क्या सरकार राज्य-सरकारों को इस सम्बन्ध में निश्चित निर्देश देगी कि वे प्रभावशाली कदम उठायें, जिससे कि इस प्रकार की जो गीतिविधियां हैं, उन पर रोक लगे और उन को बढावा न मिले ?

SHRI RUPNATH BRAHMA (Kokrajhar): I am sorry, Sir, I could not follow the Home Minister. I wanted to know....

MR. SPEAKER: He may please sit down. He has no right to ask anything. This is call-attention. Call-attention is a thing where only persons who have given notice to ask questions have a right to get up and ask a question. Almost every day he gets up; probably he does not know. He has no right to ask a question unless his name is there printed. . . . . . (Interruptions)

Assamese" Posters (C.A.)

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): These observations should be circulated among all Congress members.

MR. SPEAKER: I have not allowed them.

THE HON. MINISTER

SHRIY. B. CHAVAN: The hon. Member if I have understood him rightly, wanted to emphasize the seriousness of the problem. I have already answered that certainly we do agree that these tendencies are a serious threat and there is no doubt about it. I am sure the State Government is quite aware of it and if any preventive actions are necessary. I have no doubt they will not hesitate to take them.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai): Here is the Home Minister who has not been able to apprehend anybody. This might be the handiwork of pro-Chinese or pro-Pakistani elements. There are anti-Assamese elements. May I tell him that Assamese are the most exploited citizens in India? (Interruptions)

MR. SPEAKER: He may please resume his seat.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY: May I ask another question?

MR. SPEAKER: It is not permitted.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY: It is very important, Sir......

MR. SPEAKER: May be, it is very very important; it is not permitted.

May I tell my hon. friends who have raised something as a point of order, to write to me first? My request to them is that they may write to me; if there is anything wrong somewhere, I may correct myself and do something, but they should write to me. If they raise it on the floor of the House, I will not be able to understand it. Therefore, whether it is Mr. Basu or any other friend, I will request them to write to me; if there is anything wrong, I will certainly correct it; I will even send for him and talk to him also.

MR. MADHU LIMAYE.

12<sup>.</sup> 23 hrs.

#### QUESTION OF PRIVILEGE

श्री मधु लिमये : (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस में मुझे खुशी नहीं है। जब मंत्रियों के खिलाफ़ या दूसरे ऐसे बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ उठाता हूं, तो उस में मुझ को जरूर मजा आता है, लेकिन आज मैं केवल अपना फर्ज अदा करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले जब भाषा विधेयक पर यहां मतदान हो रहा था, तो इस सदन में एक ऐसी घटना घटी. जिसको मेरे ख्याल में इस सदन का कोई भी सदस्य अच्छा नहीं समझेगा। आपने भी उस के बारे में कहा है कि अच्छा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, घटना यह हुई कि जब विभाजन के लिये लावो साफ़ की गई थी और दरवाजे बन्द कर दिये गये थे तो इस सदन के माननीय सदस्य श्री कानतन नायर ने बाहर जानने की कोशिश की । जब उन्होंने दरवाजे बन्द पाये, तो उन्होंने उसको लात मारकर खोलने की कोशिश **की** , जिसमें बाहर के दरवाजे के तीन शीशे ट्ट गये । जो लाबी-एस्सिटेंट बाहर खड़ा था, वह बच गया, नहीं तो वे शीशे उस को लगनेवाले थे ।

अब यह कहा जाता है कि मतदान के बाद क्या दरवाजे नहीं खुलने चाहिये थे? इस के बारे में मैं जानता हूं कि हर एक सवाल पर जब मत विभाजन होता है, तो उसके बाद आप भाषा देते हैं कि—लावीज शुडवी क्लीय हैं उस के बाद दो मिनट तक घन्टी बजती है, जिनको आना होता है, वे आ जाते हैं और फिर दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं। मैं यह मानता हूं कि हर विभाजन के बाद दरवाजे खुलने चाहिये ताकि बाहर जो लोग हैं, उन को आने का मौका मिले। लेकिन अध्यक्ष महोदय, लाबीज क्लियर करने की जो इस में ध्यवस्था दी गई है—उस का अर्थ हम लोगों को

समझ सेना चाहिये । इस से सम्बन्धित नियम 367(3) यह है कि-"If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged, he shall order that the Lobby be cleared." इस का उद्देश्य यह है कि जो बाहर सदस्य हैं, उन को पता लग जाय कि मत-विभाजन होने जा रहा है और वे अन्दर आ सकें। इस का यह भी अर्थ है कि अगर कोई गैर सदस्य सदन में है या लावी में है, तो वह अन्दर न घुस सके, उन को बाहर जाने के लिये मौका दिया जाय। इस में ऐसा नहीं है कि जो सदन का सदस्य है उस को बाहर जाने का कोई बुनियादी अधिकार है। वह इस सदन में या बाहर बैठ कर अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल न करना चाहे तो न करे। इस नियम के अर्धान जो सदस्य बाहर हैं, उन को अन्दर आने का अधिकार है। जो गैर सदस्य हैं उन को बाहर जाने के सिये कहा जाता है। लेकिन यह कहना कि हर सवाल के बाद दरवाजे खुलने चाहियें-मेरी इस सम्बन्ध में बही राय है, इस से मेरा मत-भेद नहीं है, दरवाजे जरूर खलने चाहियें। ऐसी स्थिति में यदि माननीय सदस्य की राय में दरवाजे नहीं खुले थे तो आप क्षेत्राकर कह सकते थे और मैं ऐसा समझता हं कि आप ऐसा नहीं कहते कि दरवाजे नहीं खुलेंगे। चेरियन साहब ने जब कहा था तो आपने हां कहा या । यह काम बहत ही अनचित है।

इस सदन के मैं दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। एक दफ़ा आपको याद होया—उस समय आप अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन मंत्री थे—राष्ट्रपति जी। का अभिभाषण हो रहा था और हमारे दल के सदस्यों ने कहा—राष्ट्रपति जी, किसी भारतीय भाषा में बोलिये। उन्होंने यह नहीं कहा कि हिन्दी में बोलें, उन्होंने कहा था—तेलगू में बोलें, तिमल में बोलें, आठवें परिशिष्ट में जो भाषायें हैं, उन भारतीय भाषाओं का आदर करें। राष्ट्रपति जी ने जब नहीं माना, तो उन्होंने समा स्थाग किया, तब उस घटना को लेकर इस सदन में एक विशेष कमेटी कायम की

गई और उस के सामने हमारे दल के सदस्यों का मामला लाया गया और उस के बारे में उनकी जो राय थीं, वह सदन के सामने रखी गई। दूसरी घटना—दो-र्तान दिन पहले, शुक्रवार, की घटना है, जब लखनऊ विश्वविद्यालय के एक युवक ने इस प्रेक्षक दीर्घा से शृद पर्षे फेंके, नारे वगैरह लगाय । उस पर बाद में एक प्रस्ताव यहां आया, मैं तो उस बार यहां नहीं था, लेकिन इस सदन ने एक बिलकुल असाधारण कार्यवाही कर के उस के साथ सख्त व्यवहार किया और प्रस्ताव रखा, और मेरा ख्याल है, पहली बार इस लोक सभा ने किसी गैरसदस्य को जेल की सजा दी। उस के मामले को विशेषाधिकार समिति के पास नहीं भेजा, सीधा उस को जेल भेज दिया।

पिछले दो-तीन सालों में दक्षिण में हिन्दी विरोधी आन्दोलन हए--मैं जानता हूं कि वहां के छात्रों के मन में यह डर था कि उन के कपर हिन्दी लादी जा रही है--वहां पर तोड फोड, मारपीट और जलाने का काम हुआ, उसी तरह से आज उत्तर भारत के छात्रों के मन में यह डर है कि अंग्रेजी उन पर लादी जा रही है--इस लिये वहां भी ये सब काम हए । हम इस तरह की घटनाओं को अच्छा नहीं समझते, लेकिन शान्तिपूर्ण सिविल-ना-फर्मानी को हम अच्छा समझते हैं। तोड-फोड, मारपीट, जलाने की बात को मैं अच्छा नहीं समझता, लेकिन हमारे इस सदन के सदस्य ही अगर तोड-फ़ोड का काम करने लगें, तो फिर वे तो शवक हैं, उन को यह सदन कैंसे दोष दे सकता है, उन के मन में तो ढर है कि उन के ऊपर कोई। भाषा थोपी जा रही है। दक्षिणवालों के मन में डर है कि हिन्दी थोपी जा रही है, उत्तरवासों के मन में डर है कि अंग्रेजी थोपी जा रही है इस लिये यवक ऐसे काम कर सकते हैं. यदापि मैं इस को अच्छा नहीं मान सकता। लेकिन र्याद हमारे सदन के सदस्य ऐसा काम करने लगें तो उस के लिये हम को कुछ व्यवस्था करर्नः पडेर्गः ।

# [बी मधु लिमये]

मैं कोई लम्बा भाषण नहीं करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं तो मेज पालियामेंटरी प्रैक्टिनैज से मैं आप के सामने एक उद्धरण रख सकता है। उस के 120 पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है:

"Other acts besides words spoken or writings published, reflecting upon either House or its proceedings, which, though they do not tend directly to obstruct or impede either House in the performance of its functions yet have a tendency to produce this result indirectly by bringing such House into odium, contempt or ridicule or by lowering its authority may constitute contempts."

आ गे और एक कानून दिया है उस में से मैं एक वाक्य पढ़ता हूं:

"disorderly conduct within the precints of either House while such House is sitting."

अब यह सदन की कक्षा में आता है या नहीं तो इस के बारे में फैसले हो चके हैं। हमारी जो लौबी बाहर है वह सदन में आती है। इसी तरीके की एक और मिसाल है लेकिन मैं उसे उध्त करके सदन का समय नहीं लेना चाहता हुं मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हुं कि सम्माननीय सदस्य एक अर्से से तरह तरह की बातें इस सदन में कह रहे हैं। मैं उस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हुं क्योंकि वाणी स्वातंत्रय में वह कह सकते हैं कि मझे अधिकार है। लेकिन इस तरीके का व्यवहार जो उन के द्वारा किया गया है उस की मैं आलोचना करता हं और आप से प्रार्थना करता हूं कि आम मुझे इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का प्रस्ताव करने के लिए अनमति दें।

SHRI V. KRISHNAMOORTHI (Cuddalore): May I make one submission?....

MR SPEAKER: Now, I would like to hear Shri N. Sreekantan Nair who is the person concerned. Why does Shri V. Krishnamoorthi want to get up and speak? He is present here in this House, and let us hear him.

SHRI N.SREEKANTAN NAIR (Quilon): I am giving a personal explanation under rule 357..—

श्री मधु सिमये: अघ्यक्ष महोदय, यह कैसे हो सकता है, मैं आप से पूछता हूं। मैं व्यवस्था का प्रमन उठा रहा हूं। इस वक्त 357 में कार्यवाही नहीं चल रही है। मेरे भाषण के जवाब में वह बोल सकते हैं लेकिन 357 में नहीं इसके बारे में मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं।

SHRI N. SREEKANTAN NAIR: I am on my legs now. How can be get up?.....

श्री मधु लिमये : मैं अध्यक्ष से व्यवस्था चाह रहा हूं।

MR. SPEAKER: I have called shri N. Sreekantan Nair.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli): We shall obey only the Speaker. It is not Shri Madhu Limaye who is to dictate every thing to this House. Shri N. Sreekantan Nair knows that he has to obey the Speaker only.

श्री मधु लिमये: देखिये मुझे सकत ऐत-राज है इस बारे में। मैंने आप से अपील की है मैंने आप के ऊपर कोई चीज लादने की कोशिश नहीं की है।

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण ) : हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे । यह भी कोई तरीका है ।

MR. SPEAKER: Order, order. Let there be no controversy about it now.

श्री मधु सिमये: मुझे जो नायर साहब ने अभी कहा उस पर सख्त ऐतराज है। क्या में ने आप को डिक्टेट करने की कोशिश की है? मैं ने तो केवल व्यवस्था का सवाल उठाया है।

भी जार्ज करने न्डीच: हम इसे कभी बर्दाणत नहीं करेंगे। यह इन्होंने क्या कहा है श्री मधु लिंमयं के बारे में ? यह भी कोई तरीका है ? जो कुछ उन्हें कहना हो यह स्पीकर को कहें।

SHRI NAMBIAR: We shall respect the Speaker only who is the authority so far as this House is concerned. But every now and then we find that Shri Madhu Limaye and Shri George Fernanades getting up and trying to dictate to us. They think that by shouting they can do so......(Interruptions)

MR. SPEAKER: I want to hear Shri N. Sreekantan Nair only. The others may resume their seats.

SHRI NAMBIAR: Shri N. Sreekantan Nair will only obey your orders, and not those of Shri Madhu Limaye or Shri George Fernandes. You have called upon Shri N. Sreekantan Nair and he should be allowed to speak.

MR. SPEAKER: Let not hon. Members heat into it. Let us verify the facts.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI: Before hear him, I want to make a submissi-

MR. SPEAKER]: I want to verify the facts first. How can the hon. Member say the facts about him?

SHRI V. KRISHNAMOORTHI: I want to point out that you have already disposed of this matter.

SHRI S. K. SAMBANDHAN (Tiruttani): You have already disposed of it.

MR. SPEAKER: Whether I have disposed of it or not is for me to say and not for the hon. Member.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI: I am opposing the motion.

MR. SPEAKER: He may oppose it later. I have not placed it before the House yet.

I have not disposed of it yet. All that I know of was what happened in the House only; Shri N. Sreekantan Nair came in and shouted 'the doors are not open', and he shouted in such a way that I was really nervous that something criminal had happened, and I immediately asked them to open the door. I accept that much. I did not know anything beyond that while

I was in the Chair. There is no point in the hon. Member's saying that I have disposed of it. He wanted the doors to be opened, and immediately I said that the doors would be opened. Beyond this, I did not know what had happened: I was in the Chair continuously the other day for nearly two and a half hours, and I did know what had happened earlier. Therefore, to say that I have disposed of it is not correct. I had disposed of it only to this extent that I had asked them to open the doors, and nothing more than that. As to whether the glass was broken how many doors were damaged, what happened to the staff and so on, I am not aware of these things, and I do not want to give my opinions or say anything about them here. If Shri N. Sreekantan Nair had done anything, he himself will explain now, I do not want other groups or parties to mport politics into it. Shri N. Sreekantan Nair is here present in the House. I would like him to say what he wants on the question of facts only, not on the question of rules and all that. We have been taking notice of disorderly scenes now. Whatever the rules may be, let not Shri N. Sreekantan Nair worry about it; let him now give us the facts in regard to what had happened according to him. That is all I want now, and nothing more.

Shri N. SREEKANTAN NAIR: As certain allegations have also been made and reflections cast on me, I have to reply.

MR. SPEAKER: He may reply, but not under some other rule, Do not worry about the rules. I take care of the rules.

#### SHRI S. K. SAMBANDHAN rose—

SHRI N. SREEKANTAN NAIR: The Deputy Secretary of the Lok Sabha served on me a notice at dead of night on Saturday, 16th December 1967, demanding a reply by 10·30 a.m. on Monday, 18th December 1967. As Sunday is a holiday, the time-limit laid down is unfair and unreasonable even on a routine matter. On a very serious allegation levelled against me of violating the privileges of Parliament, I have not been given even the opportunity to refer to the official records. Yet, as the allegation has been made on the floor of this House, I ask your permission to

[Shri N. Sreekantan Nair]

Question of

make a personal explanation under rule 357 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha.

On Saturday, after polls were taken on amendments Nos.102-118 to the Languages Bill, I felt disgusted and wanted to get out and breath fresh air. I found the doors of the Lok Sabha lobby locked, even after the announcement of the results of the division and at the time when the hon. Member, Shri Surendranath Dwivedy, was pleading to get his amendment No. 132 accepted. I explained to the Watch and Ward Officer that the result had been announced and that he had to open the door. He replied that he had orders not to open the door. I told him nobody had a right to keep me as a prisoner in a locked room. Yet he refused to open the door.

So I came back and told you:

"Sir, in between voting I have got a right to go out. Why should they lock it ?"

You then said:

"If anybody wants to go out, he may go out. The doors may be opened. Nobody can be prevented".

When I went back, I still found the doors closed. So, I knocked the door. Then another officer came and let me out.

I had no altercation with the Watch and Ward staff whose predicament I could very well appreciate and sympathise with. But I was also not prepared to concede to anybody, including you, the hon. Speaker, the right to restrain me within locked doors when no Division is being recorded in the House. The proceedings of the House would substantiate the fact that I attempted to go out only between Divisions.

As to Shri Prakash Vir Shastri, he cannot understand or appreciate the emotional upsurge of a freedom fighter when the future and the unity of the country is in danger.

So far as Shri Madhu Limaye and Shri Yadav are concerned ....

MR. SPEAKER: They have explained their point.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR: No. Sir. I must explain.

So far as Shri Madhu Limaye and Shri Yaday are concerned, they are the lucky beneficiaries of the milch-cow of the postindependence socialist movement which volunteers like me have nourished with our sweat and blood under the great leadership of Shri Jaya Prakash Narain, Shri Atchut Patwardhan, Shri Asoka Mehta and the late lamented Dr. Lohia.

As one who has been penalised for his patriotism for about 6 years of the cream of his youth in the prisons of a princely State in sub-human conditions, I am not frightened of the prospect of a few days or months or even of years in a Congress prison in Free India for fighting for the equality of the people of the non-Hindi States with those of Hindi States . . . .

MR. SPEAKER: No. no. Nobody wants to imprison him.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR .... Therefore, I still maintain that the restriction imposed on my movements was illegal.

As regards the point made by Shri Limaye that the doors would be opened only to let members in, not to let them out, that is a one-way traffic which no one can accept. Of course he understands only one-way traffic. Some people may be frightened by him, but I am not afraid of him. I have got as much right here as Shri Madhu Limaye. If I do not abuse my rights, it is because I have got more self-respect, not because of anything else.

On the question which he raised of disorderly conduct, you know which party in both Houses indulges in that conduct . . .

SHRI NAMBIAR : We are suffering because of that.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR: I may lose my temper on only very fundamental matters like the language issue. But I am one of the disciplined members of this House. But on this issue we are agitated; on this issue the entire non-Hindi people are agitated and we will fight.

#### SOME HON. MEMBERS rose-

MR. SPEAKER: I am not calling anybody on this issue now. The motion has been made, and he has replied. If you are allowed, all the 500 members will have to be allowed.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI: His eyes are open only now, his eyes were not open when Mr. Kachwai burnt the language Bill. (Interruptions)

MR. SPEAKER: This has nothing to do with language.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI: Because he is a South Indian, this motion has been brought by Mr. Limaye.

SHRI S. K. SAMBANDHAN: I want a clarification.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash):
Because he has opposed Hindi, Mr. Limaye
has chosen to bring this motion. We know
how these people behave and how this
party behaves.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI: I crave your indulgence for only one or two minutes.

MR. SPEAKER: I do not want any discussion on this. Nothing will be taken down.

••

SHRI HEM BARUA (Mangaldai): May I request Mr. Limaye, through you, to withdraw the motion, because tempers are frayed in the House.

MR. SPEAKER: He can himself say that.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI: Merely because he is from Kerala, this House should not be used as an instrument to condemn a man from the south. (Interruption)

# श्री मधुलिमये: हम भी दक्षिण के हैं।

MR. SPFAKER: May I request all of you to sit down? (Interruptions) What is all this? For nothing you are making so much noise. (Interruptions) Will you kindly sit down, or all of you want to continue like this?

SHRI NAMBIAR: The records show who misbehaves.

MR. SPEAKER: Mr. Sreekantan Nair has given a statement. What he has to say, he has to say. Why should others be excited? Nothing has been done new. I think you want to be excited, you are not excited I know, you try to be excited; there is no reason but you want to be excited and you are not able to get excited.

SHRI M. R. MASANI (Rajkot): Sir, I am very sorry that the Leader of the House is not here at this moment to guide the House in this matter. What has just happened is extremely distressing. What should be considered on merits is beccming a continuation of a linguistic dispute which has nothing to do with us just now. That matter is closed.

Shri Madhu Limaye has brought a motion. The hon. Member, Sri Shri Sreekantan Nair, evidently got excited the other day and did something which I am sure he himself is not happy about now. apart from the point whether he should or should not have been stopped from leaving the House, I am sure he will appreciate that breaking the glass and using violence is not what is expected of an hon. Member of the House-a breach of dignity of this august body. I think the best thing would be if Mr. Sreekantan Nair, as a good Member of Parliament, gets up and tells you that he regrets his action, that he lost his temper because of provocation. In that case, Mr. Madhu Limaye should withdraw the breach of privilege motion.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR: I am not a renegade and I do not retract anything.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH):
Sir, the seriousness of the matter is there.

What we have heard from Mr. Sreekantan Nair and the points that he made out ere perhaps enough to drop this matter. I therefore suggest that the matter may be dropped.

भी मधु लिमये: मसानी साहब की बात को उन्होंने नहीं माना है। इसलिये वापसी

<sup>\*\*</sup>Not recorded.

## [बी मधु लिमये]

की विनती मैं नहीं मानता। आपका नापदंड क्या है यह मैं जानना चाहता हूं। मैं अपने प्रस्ताव के लिये इजाजत मांगता हूं। अगर पर्चित लोग खड़े होंगे तो मेरा मामला जाएगा।

SHRI HEM BARUA: Dr. Ram Subhag Singh said that the matter may be dropped.

MR. SPEAKER: Yes; it is true that the Minister said it and Mr Masani also said so. But it is not my job to force anybody to drop or not to drop anything. Now that Mr Limaye's motion is before the House, I request....

श्री मधुलिनये: सब समझ गया हूं मैं राम सुभग सिंह जी। मैं इजाजत मांगता हूं।

बी अटल बिहारी बाजपेयी (बलरामपुर) : इससे पहले कि आप यह प्रस्ताव सदन के सामने रखें अच्छा होता अगर माननीय प्रदृश्य श्री श्रीकान्नतन नायर ने खेद प्रकट कर लिया होता । मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप हमें थोड़ा मौका और दें उनसे बातचीत करने के लिए और मेरा ख्याल है कि वह तैयार हो जाएंगे अपने आचरण पर खेद प्रकट करने के लिए।

MR. SPEAKER: Then we will take it up tomorrow. I do not think we should get excited on this matter. Tomorrow let us take up this matter, so that tempers may cool down and let us not speak with these feelings now. Shri Sreekantan Nair may also speak and friends from the South may speak. We shall take up this matter tomorrow.

#### 12,48 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE
STATEMENT PE DOCUMENTARY FILMS
AND NEWSREELS

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): I beg to lay on the Table a statement showing decisions taken on seventy-nine recommendations of the Committee on Broadcasting and Information Media

on Documentary Films and Newsreels. [Placed in Library. See No. LT-2035/67].

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): Sir, I just wanted to make one submission. In spite of the assurances given by the Speaker in the last two sessions that the Hazari report should be taken up it is being postponed.

MR. SPEAKER: Order, order. Nothing will be raised here. I did not allow anything to be raised by Shri Vajpayee. At the Business Advisory Committee, the Minister is there. The Congress Members were also there. It is not myself alone. Business Advisory Committee means half a dozen Congress Members also. All of them consider the points and take a decision. If you want to write to the Business Advisory Committee again, you might do so. But nothing can be raised here now.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: In spite of the assurance, if the discussion of the Hazari report is dropped for two sessions consecutively, it will create a bad impression in the country about the House.

MR. SPEAKER: Order, order.

#### 12.484 hrs.

#### MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:—

"I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha. at its sitting held on the 15th December, 1967 has passed the enclosed motion referring the Delhi Rent Control (Amendment), Bill, 1964, by Shri M. P. Bhargava, M.P., to a Joint Committee of the Houses and to request that the concurrence of the Lok Sabha in the said motion and the names of the Members of the Lok Sabha to be appointed to the said Joint Committee may be communicated to this House.

#### MOTION

"That the Bill further to amend the Delhi Rent Control Act, 1958, be refer red to a Joint Committee of the Houses consisting of 30 members; 10 members from this House, namely:—

- 1. Shri Vimalkumar M. Chordia
- 2. Shri D. P. Karmarkar
- 3. Shri Santokh Singh
- 4. Shri Lokanath Misra
- 5. Shri P. C. Mitra
- 6. Shri Jagat Narain
- 7. Shri G. D. Tapase
- 8. Shri Bhawani Prasad Tiwari
- 9. Kumari Shanta Vasisht
- 10. Shri M. P. Bhargava, and 20 members from the Lok Sabha;

that in order to constitute a meeting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee:

that in other respects, the Rules of Procedure of this House relating to Select Committees shall apply with such variations and modifications as the Chairman may make;

that the Committee shall make a report to this House by the 30th September, 1968; and

that this House recommends to the Lok Sabha that the Lok Sabha do join in the said Joint Committee and communicate to this House the names of members to be appointed by the Lok Sabha to the Joint Committee."

12.50 hrs.

ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL

REPORT OF SELECT COMMITTEE

श्री विमूति मिश्र (मोतीहारी): अत्या-वस्यक वस्तु अधिनियम, 1965, में आगे संशोधन करने तथा अत्यावस्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1964, को अग्रेतर अविध क लिए जारी रखने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन मैं पेश करता हैं।

#### 12.501 hrs

# UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) BILL

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): I beg to move:

"That the Bill to provide for the more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for matters connected therewith, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."

The House is aware that the Unlawful Activities Bill was referred to Joint Select Committee in the last session of this House. Considerable discussion has already taken place regarding the general principles of the Bill. I had explain the main considerations which had guided us in bringing forward this measure while replying to the general debate that had taken place in the House at the time of its reference to the Select Committee, I would not like to repeat what I said on that occasion. It however, clear that we have certain problems-it is no good shutting our eyes to them-and a democratic, constitutional way has to be found to deal with them. It is with this object that this Bill was brought forward.

It has been thoroughly scrutinized by the Select Committee which also had the benefit of hearing the Attorney General on the constitutionality of the Bill, about which several members had raised doubts. It is clear from the evidence that the Bill is in accordance with the constitutional provisions and places only reasonable restrictions on the freedom of speech and expression right to assemble peacably and without arms and right to form associations or unions. The Select Committee have made, a number of changes in the Bill. I would like to refer only to the important changes as the report of the Select Committee is already with the Honourable Members.

#### 12.52 hrs.

#### [MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

Honourable Members will notice that the first important change made in the Bill is in clause 2 of the Bill. The Select Committee felt that instead of defining unlawful activity separately in relation to sovereignty and integrity of India, as had been done

#### [Shri Y. B: Chavan]

in the Bill presented before this House, it would be better to follow the phraseology used in the Constitution (Sixteenth Amendment), Act, 1963. Sub-clause (f) of clause 2 has been amended accordingly. Certain drafting changes have also been made in clause 2 to bring out clearly the intention behind the Bill.

The next significant change is in clause 4. The Bill did not envisage any time limit within which the tribunal had to decide the matter placed before it, although it had been indicated that the tribunal will decide the reference as expeditiously as possible. The Select Committee have now fixed a maximum period of six months from the date of issue of a notification under clause 3(1). within which the tribunal must decide the reference.

The Select Committee have also materially changed clause 5 of the Bill. Previously the Bill had provided that the tribunal will consist of a chairman and two other members to be appointed by the Central Government. Government had moved an amendment to provide that the Chairman of the tribunal will be a sitting judge of the High Court. The Select Committee felt that in order to inspire confidence of the public in the tribunal, and also to facilitate disposal of business the tribunal should consist of a sitting judge of a High Court. Therefore now it will be a one-member tribunal consisting of a sitting judge of a High Court. This is an important modification and would effectively allay approhensions and fears of a section of the House that the clause as it originally stood could be used to pack the tribunal.

The Select Committee have made another change of great significance. Proviso to clause 6(1) had conferred powers on the Central Government to extend the period of operation of the notification confirmed by the tribunal from time to time by any period not exceeding one year at a time. Even at an earlier stage when I had looked into the Bill. I had given notice of an amendment to provide that in no case will a notification declaring an association unlawful remain in force for more than 3 vears. The Select Committee have, however. gone further and have deleted the proviso altogether. This means that the maximum

period for which an association can be declared unlawful will be two years from the date on which the notification becomes effective.

The Committee have made certain changes in clauses 7 & 8 to mitigate any conceivable hardships that may be caused in the implementation of the provisions of this Bill. They have also reduced the punishment provided for in clauses 10, 12 and 13.

Sir, you will recall that I had, while replying to the general debate on the Bill, pointed out that the Bill was necessary because there were divisive forces in India and effective measures were necesary to counter them. It is not a party matter because the unity and integrity of India is an ideal to which all parties subscribe. At the same time I am under no illusion that a mere legal action would provide an enduring solution.

But other methods, political and educational have to be strengthened by legislative action. I shall be very happy indeed if the powers under this Bill are not used, and groups and individuals try to solve the grave problems facing us in a manner that is conducive to maintaining the integrity and unity of this great country. I commend the Bill as reported by the Select Committee for acceptance of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill to provide for the more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for matters connected therewith, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."

There are some amendments to Motion for consideration.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : (Balrampur) : Sir, I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th February, 1968." (37)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): Sir, I beg to move:

"This House is of opinion that the unlawful Activities (Prevention) Bill, 1967, be referred to the President for obtaining the opinion of the Supreme Court under article 143 of the Consti-

tution on the question of constitutional validity of the Bill." (75)

SHRI P. RAMAMURTI (Madurai) : Sir, I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st March, 1968." (78)

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the first day of the next session." (117)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Other amendments to this motion are barred because similar amendments have been moved. Now, these amendments and the original motion are before the House. We have 7 hours in all out of which a maximum of five hours we can provide for general discussion and two hours for clause-by-clause consideration.

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, I have one submission.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Business Advisory Committee has taken a decision after a good deal of deliberation.

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, I was in the Business Advisory Committee and you were not. In the Business Advisory Committee we demanded eight hours and we were told that always you have one hour in your sleeves and so it was decided to put down 7 hours. I only request you, Sir. to make it eight hours and allot 6 hours for the general discussion because, many of us have sent minutes of dissent.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is true that the discretion of one hour is there and I can give half-an-hour there and half-an-hour here. But at this stage of the general discussion I am not going to use that discretion. Only five hours are there for general discussion.

#### 13.00 hrs.

SHRI K. M. KOUSHIK (Chanda): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have had the privilege of going through both the old Bill and also the new Bill that is before the House. Though the hon. Home Minister has said that there is a lot of change made in the new Bill that is before the House

I think, Sir, basically there is absolutely no difference between the old and the new. At this stage I am reminded of our pre-independence days when the Britishers were actual y bringing forward such repressive mea es as we have in this Bill.

7828

We can recollect that even at that time, as a matter of fact, we were not allowed to speak about what is going on with regard to the second world war. Even in the hotels there used to be big placards saying "please keep your mouth shut."

MR. DEPUTY-SPEAKER: He may continue his speech after the lunch hour.

13-01 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the chair]

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVEN-TION) BILL—contd.

SHRI K. M. KOUSHIK: Mr. Deputy-Speaker, Sir, going through the several clauses in the Bill I am reminded of the pre-independence days when repressive measures were foisted against us by the Britishers to curb our spirit and enthusiasm during the national movement.

We can all recollect that in the days of Second World War, we could see that there were boards put up in every place, "keep your mouth shut and don't talk." To talk of what was going on in the world about the War, about the Germans' efforts as to what they have been doing and what they have been achieving and all that was considered to be a prejudicial act which was being punished under the Defence of India Rules. This was a sort of repressive measure which was being foisted on us in those days of pre-Independence. today, unfortunately, the same type of repressive measure is being foisted by our own people now. I can also say, at the time when the Britishers foisted such repressive measures against us, not only we but even the Benches on the others side were also with us in criticising, in hurling

#### [Shri K. M. Koushik]

hundreds of abuses, against the Britishers. Unfortunately, it has now fallen to the lot of Mr. Y. B. Chavan to foist this Bill on us. I say, on behalf of my Party, I cannot support this Bill for two reasons. firstly, that the Statement of Objects and Reasons, as contained in the Bill, does not show any exigency or necessity which impels the hon. Home Minister to get this Bill passed and, secondly, from the available records, it appears—I have no doubt about it-that it is unreasonable and it is against the spirit of the Constitution and the provisions of the Constitution. Therefore, on these two grounds, I submit that I cannot recommend the acceptance of this Bill as it is put before the House.

Now, if anybody examines the provisions of this Bill, it will be very clear that there are ruthless provisions. The executive has been given arbitrary powers of declaring an association unlawful. Not only that. Even without waiting for the confirmation of that order, namely, that a particular organisation is unlawful, the executive has been given powers, till the decision, to execute that order in the manner as laid down in the Bill. So, I personally feel, and my Party feels, that such an arbitrary power can only be exercised in certain exigencies and in certain impelling necessities. Here, we find from the Statement of Objects and Reasons, no justifying or impelling necessity or any exigency, which makes the hon. Home Minister to foist this Bill on us, we are told : "Please accept it": whether there is any such necessity or not, is a thing which, in my opinion, is wanting in this case. The Statement of Objects and Reasons does not show any such exigency. That is one thing. Secondly, the Statement of Objects and Reasons says that the National Integration Committee wanted such an Act to be framed. This recommendation cannot be divorced from the context and that is that at that time there was a section of the people in the south who wanted a Tamilnad for themscives. That was a sort of secession that they wanted. Therefore, the Committee recommended, in order to keep up the integrity and the sovereignty of India and the Unity of India as a whole, that such a provision was necessary. But now the formation of Tamilnad has been given up and,

in fact, that Party is actually ruling in Madras. So, my humble submission is that the reason given in the Statement of Objects and Reasons and the recommendations of the Committee are of no avail so far as this Bill is concerned when it is being put up for the acceptance of the House.

My second reason is that, as far as I am aware, no other country in the world has a parallel provision or a parallel Act as the one that is being put up before this House. So, I say that this is not a thing which could be lightly treated and which could be lightly accepted. If no other country in the world has made any provision of this type, there is no reason why such a provision should be enacted in our country.

The third thing that I would say is this. Even supposing that this law is enacted, I would feel that it will not benefit the country in any manner. Now there are the hill people in Assam wanting a separate State for themselves; the Nagaland is there; and the Mizo trouble is also there. I ask the hon. Home Minister whether the passing of this Bill by itself would put an end to these secessions, whether it will help to bring that unity which, we are apprehending, is not there today. This is a matter which I have very seriously thought of and I say that even if this Bill is passed, the matters will not improve. Therefore, such a legislation should not be embarked upon. This is my honest submission to this House.

Therefore, on all these counts—there is no exigency, there is no impelling necessity, there is no real benefit to accrue by the acceptance of this Bill. Hence, I humbly submit that this House should reject the Bill and should not accept it.

This Bill makes out three kinds of offences, namely, cession, secession and disruption—these are the three offences made out in this Bill. If really these are the offences and it is the desire of the Government to punish all those who advocate it, who advocate any act to bring about cession, secession or disruption of the country, then there are other ways of doing it. We have got a chapter on Sedition in the Penal Code. The offence of sedition could be enlarged. These are offences against the State and

these could be put into the Penal Code by an amendment of the Penal Code and it will be a law for all times to come and it could be dealt with in the ordinary tribunals existing in the country. There is no necessity for such a stringent provision. This provision is actually giving arbitrary powers, exemplary powers, unthought of powers to the executive to declare any organisation as unlawful and take further action to put the people behind the bars, and also to take other matters into their hands. This is one position which, I submit, could be easily achieved by an amendment of the Penal Code. Therefore, this drastic Bill or obnoxious Bill as I call it. with all apologies to our Home Minister. I say, is not necessary; it is not necessary that we should go through it and, as a matter of fact, accept it for any of the reasons which he has submitted before this House.

The next point that I would say is this. We have been, actually with great zeal, preserving the Fundamental Rights enshrined in the Constitution. I say that many of the provisions that have been incorporated in this Bill are absolutely unreasonable; they go against the principles of the Constitution and are, therefore, likely to be struck down as ultravires. Clause 3 reads thus:

- "(1) If the Central Government is of opinion that any association is, or has become, an unlawful association, it may, by notification in the Official Gazette, declare such association to be unlawful.
  - (2) Every such notification shall specify the grounds on which it is issued and such other particulars as the Central Government may consider necessary;

Provided that nothing in this subsection shall require the Central Government to disclose any fact which it considers to be against the public interest to disclose."

My humble submission is: if you simply disclose the grounds on which you declare in the notification that a particular organization is an unlawful organization, how is he to meet that charge before the Tribunal when he is called? If you do not disclose the facts to that organization, how is that

organization to defend itself against your contention that it is an unlawful organization? I am unable to understand. Therefore, unless both the grounds and the facts on which the grounds are based are put in the notification and supplied to the person or the organization to whom it pertains, he will be in midwaters and he will not be able to defend himself and he will not be able to put up a case before the Tribunal. Therefore, my humble submission is that this proviso to sub-clause (2) of Clause 3 runs counter to the fundamental principles and, therefore, it is likely that it will come in the way of the Act being declared as constitutional and it will be treated as unreasonable.

#### Now clause 3(3) reads:

"No such notification shall have effect until the Tribunal has by an order made under section 4, confirmed the declaration made therein and the order is published in the Official Gazette:

Provided that if the Central Government is of opinion that circumstances exist which render it necessary for that Government to declare an association to be unlawful with immediate effect, it may, for reasons to be stated in writing, direct that the notification shall, subject to any order that may be made under section 4, have effect from the date of its publication in the Official Gezette."

This is absolutely an arbitrary power given to the executive. When we have actually separated executive from the judiciary, now to give this arbitrary power to the executive is something which runs counter to the zeal we have shown in making our Constitution. So, I submit, Sir, that this position will have to be taken into account in finding out whether it is reasonable or unreasonable. To me it appears this is one of the grounds on which this Act may be declared or is likely to be declared as unreasonable and unconstitutional.

Then, in clause 9 we have got no right of appeal. Therefore, this Tribunal's decision will become final. So that is a thing which again will add tot he weight to declare this Bill when it becomes an Act as unreasonable.

# [Shri K. M. Koushik]

Again in Clause 4 the burden of proof has been cast on the person. A notice is issued to him, he goes to the Tribunal. There he is asked to show cause as to why the Association should not be declared unlawful. This is running counter to the canons of jurisprudence. It is for you, it is for the Government to show that the organization is an unlawful one. This is asking an innocent man to prove his innocence which is something absurd. The onus should actually lie on the prosecution, and as Clause 4 has been framed, in these cases the onus has been shifted on to the accused or the delinquent, viz., the organization, and this again is likely to come in the way of its being held a reasonable restriction.

Under clause 13(3) which is a major one . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. You have got a second speaker.

SHRI K. M. KOUSHIK: I will finish within two minutes.

Under clause 13(3) again Government and Government's nominees are entitled to bargain with regard to the territories. Now that is permissible. They are immunised whereas persons who want-in a democracy it is the people who actually mobilise public opinion-and show to the Government that this is the public opinion will be hauled up under this Act, a thing which is absolutely discriminatory and certainly this discrimination will entail this provision being struck down as ultra vires. Therefore, my submission is that this would be treated as unreasonable, and discriminatory and, therefore, the Bill should not be accepted.

Lastly, if one scrutinises the opinion of the Attorney-General, on which the Home Minister has relied so much, one would find that he has watered it down completely when he comes to the concluding part of his evidence when he says that he has not examined it from that angle of vision and so he is not able to say much. Therefore, we find that even the Attorney-General is not confident that the provisions of this Bill are not unreasonable and are not likely to be struck down as ultra vires.

Therefore, in these circumstances, my humble submission is that this Bill should not be accepted and other measures should be devised in order to rehieve the things intended to be achieved by this Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I call the next Member to speak, I would like to say that hon. Members from the Congress Benches should confine their remarks to just ten minutes each.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTER-JEE (Howrah): I must congratulate the hon. Home Minister on his having brought forward, in his patriotic zeal, a very important Bill before this House. It is all the more a happy thing for me that he had this Bill examined by a Joint Committee, on which I also happened to be a Member.

Before discussing this in the Select Committee, the Home Minister had the goodness to circulate a note on the necessity of this Bill, and in that note he has said that:

"Pursuant to the acceptance by Government of the unanimous recommendation of the Committee on National Integration and Regionalism appointed by the National Integration Council, the Constitution (Sixteenth) Amendment Act, 1963 was enacted empowering the Parliament to impose by law reasonable restrictions. The object of this Bill is to make powers available for dealing with activities directed against the integrity and sovereignty of India."

The great architect of our Constitution, Dr. Ambedkar, said in the Constituent Assembly:

"What the Draft Constitution has done is that instead of formulating fundamental rights in absolute terms and depending upon our Supreme Court to come to the rescue of Parliament by invoking the doctrine of police power, it permits the State directly to impose limitations upon the fundamental rights."

So, he has made it perfectly clear that the State may be required to put certain restrictions on fundamental rights for protecting the integrity and sovereignty of India. The National Integration Council which met on 20th September, 1961 issued out a statement and in that statement certain observations were made, and they are as follows:

"National integration cannot be built by brick and mortar, by chisel and hammer; it has to grow silently in the minds and hearts of men."

The statement further says:

"We are passing through a transition period, and all the periods of transition are periods of tragedy, tragedy because we have to give up something which we hold dear, but that pain has to be faced by us and we have to work actively in order to make this country into a truly civilised and democratic State."

So, certain restrictions have to be borne and tolerated by the people who want the integrity and sovereignty of the country to be preserved.

It is to be noted in this connection that even in America which is supposed to be a country where democratic ideas have been nurtured all through, the Supreme Court had passed a judgment to the effect that:

"The liberty of the individual to do as he pleases even in innocent matters is not absolute. It must yield to the common good."

Even in Japan and certain other countries where the security of the State has been in danger, certain enactments had to be passed to curtail the fundamental rights in the matter of association. So, it is not in India alone that this has been done. The Attorney-General who had the goodness to appear before the Joint Committee had a remarkable piece of advice to offer. This is what he said:

"But having regard to the fact that the Constitution was specifically amended so as to include sovereighty and integrity of India as matters which have to be preserved at all costs, and having regard to the situation which is not so satisfactory in some parts of the country in regard to this very matter, some kind of legislation of this nature was necessary, and if one is going to have legislation of this kind, then one might as well have it."

This was his considered view before the Joint Committee.

We have examined the necessity of this Bill from all points of view. I yield to none in my patriotic zeal to safeguard the rights and liberties of every individual belonging to this country, but I feel that conditions have now developed where there have been subversive activities endangering our security and sovereignty. Who does not know the inspiration of a foreign country like China behind the subversive activities indulged in by some political parties in this country with the aid of that country to achieve their objectives? It is not a new thing in our country that certain activities have been undertaken by some hostiles such as the Naga hostiles or the Mizo rebels to get trained in Chinese guerilla warfare tactics. Even the other day, we heard that Mizo hostiles are being trained in Pakistan in guerilla tactics for the purpose of applying those tactics in our country endangering our security. Have hon. Members on the other side who criticise the Bill ever given their thought to this aspect, to the danger to the sovereignty, and integrity of the country that these subversive activities constitute ?

Some hon. Members on the Committee have appended minutes of dissent to the Report of the Committee. I have very carefully gone through these notes of dissent which they in their wisdom have sent in. But what I find is that there have been repeated arguments on one and one point only, that this Bill was not necessary. But none has been able to establish that the provisions of the Bill are unnecessary for safeguarding the national integrity and security of our country.

Therefore, I feel thrt probably they have been motivated in doing so by some kind of fear complex that this Bill will be utilised against them in their lawful activities. Our Home Minister has made it perfectly clear that this Bill is not intended to limit the activities of any political association or to restrain it from carrying on its polltical activities in conformity with the laws of the land. It is only when this condition is infringed, that action will be called for. It is only to preserve and protect the integrity, security and sovereignty of

783**7** 

[Shri Krishna Kumar Chatterjee] the country that this Bill has been brought forward.

It is only natural for any patriotic individual to think in terms of national safety and national security. If anyone living in this country thinks that he has no responsibility on this score, I say it is better that he leaves this country. This Bill is concerned with only ensuring that a situation is not created whereby the interests of the country are jeopardised.

In this context, I strongly hold that this Bill should have been put on the statute back as it was drafted in 1966. hon, friend who preceded me was making the point that this bill is more stringent in its provisions than the original Bill of 1966. Probably he has not gone through That Bill is before me. There that Bill. the definition in clause 2 of 'unlawful association' is much stringent than in the Bill before us. We on this side feel that in the Bill before us many important things have been left, which ought not to have been left out. But probably the Home Minister thought that by leaving those things out, he might be able to secure unanimity in the acceptance of the Bill with no objection raised by members opposite. unfortunately, even though the members of the other side had every opportunity to express their opinions freely in the Select Committee, and no one was debarred from expressing his views in the strongest terms, there even then these notes of dissent have come. The opposition that is put forward to the Bill is rather regrettable.

We know full fell the dangers ahead. We were only in the recent past faced with aggression from a foreign country. Pakistan is still designing against us, and China has not given up her wrongful designs against us. I would, therefore, appeal to them to accept the Bill unanimously, so that we can go to the country and tell the people that this Bill is not to curtail their rights, but to safeguard their rights and the integrity and safety of the country.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलरामपुर): उपाध्यक्ष महोदय. मैं इस विघेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हं। संयुक्त प्रवर समिति के सदस्य के नाते मैंने तथा मेरे भन्य साथियों ने यह प्रयत्न किया था कि इस विघेयक का स्वरूप ऐसा बने, जिस से सरकार को दिये जाने वाले मधिकारों का दुरुपयोग न हो सके श्रीर संविधान द्वारा जो मूलभूत श्रविकार दिये गये हैं, उन की रक्षा की जा सके। लेकिन हमें इसमें सफलता नहीं मिली।

संयुक्त प्रवर समिति को एक गधा सौंपा गया था भौर समिति का काम था उस का घोड़ा बनाना। लेकिन परिणाम यह निकला है कि वह खच्चर बन गया है। ग्रब गृह मंत्रालय का भार ढोने के लिए तो खच्चर ठीक है, लेकिन ग्रगर गृह मंत्री यह समझते हैं कि वह खच्चर पर बैठ कर राष्ट्र की सर्वप्रभृता भीर अखंडता की लडाई लड लेंगे, तो मेरा उन के साथ विनम्त्र महाभेद है।

जिस परिस्थिति में यह विधेयक लाया गया है, उस को हमें स्मरण रखना होगा। मद्रास में एक पार्टी थी, जो भारत से पथक होने की बात करती थी। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद ने उस पृथकता की चुनौती को घ्यान में रख कर एक कमेटी बनाई थी सर सी० पी० राम-स्वामी प्रय्यर की प्रध्यक्षता में। गृह मंत्री महोदय का दावा है कि उस कमेटी की सिफ़ा-रिश के मनुसार यह विघेयक लाया जा रहा है। गृह मंत्रीभी यह स्वीकार करेंगे कि म्रब दक्षिण में इस तरह की राष्ट्रीय एकता के लिए चनौती विद्यमान नहीं है। जिस दल ने स्वतंत्र तामिलनाड का नारा लगाया था, उस ने ग्रपना वह विचार छोड़ दिया है। जनता के बहुमत के समर्थन से वह दल म्राज तमिलनाड में सत्तारुढ़ है। मन गृह मंत्री महोदय के सामने कौन सा संकट है, जिस के निवारण के लिए वह ये ग्रसाधारण ग्रधि-कार लेना चाहते हैं?

जहां तक बाग़ी नागाभों का सवाल है, जो भारत से पथक होना चाहते हैं, उन के साथ भारत सरकार बात वार्ता कर रही है। बागियों के साथ वार्ता हो रही है भीर संसद को कहा जा रहा है कि सरकार को ऐसे मिषकार दिये जायें, जिन के मन्तगंत ऐसे तत्वों के खिलाफ़ कार्यवाही हो सके। मगर हमारी सरकार वार्ता का दृष्टिकोण मपनाना चाहती है, तो इस प्रकार के प्रधिकार मांगने का कोई मर्थ नहीं है। स्पष्टतः ये मिषकार वागी नागामों के खिलाफ़ काम में नहीं भायेंगे, जिन के साथ वार्ता का दौर चल रहा है।

न ये मसाधारण मधिकार जम्मू-काश्मीर में उस वर्ग के खिलाफ काम भायेंगे, जो पाकिस्तान के साथ सांठ-गांठ कर रहा है भीर जो जम्मू काश्मीर की सांविधानिक स्थिति में परिवर्तन लाना चाहता है। ग्रभी-ग्रभी भारत सरकार ने मिर्जा ग्रफ़जल बेग पर लगाए हए प्रतिबन्ध हटा लिये हैं। उन प्रतिबन्धों के हटानें के बाद उन्होंनें श्रीनगर में जो भाषण दिया है, वह शेष भारत के साथ काश्मीर के सम्बन्धों को चुनौती देने वाला भाषण है। क्या वह भाषण और उस में उटाई गई मांगें देश की ग्रखंडता के लिए. देश की सर्वप्रभुता के लिए संकट नहीं है ? उसी संकट को ध्यान में रख कर उन्हें पकड़ा गया था, लेकिन माज भारत सरकार उन्हें छोड़ने की स्थिति तक ग्रागई है। शेख ब्रब्दल्ला पर लगे हुये प्रतिबन्ध भी ढीले कर दिये गये हैं भीर भगर कुछ ही दिनों में शेख साहब पूरी तरह से रिहा हो जायें, तो किसी को ताज्जब नहीं करना चाहिए।

ग्रगर यह बात उठने वाली है—ग्रीर उठ रही है कि भारत में काश्मीर का विलय ग्रन्तिम नहीं है, काश्मीर के सवाल को फिर से खोला जाये, उस पर पाकिस्तान, जम्मू-काश्मीर ग्रीर भारत के लोग मिल कर चर्चा करें, तो क्या इस विधेयक के पारित होने के बाद सरकार ऐसे तत्वों पर बन्धन लगाएगी? —ग्रीर ग्रगर बन्धन ही लगाना है, तो ग्राज बन्धन हटानें का क्या मतलब है? मैं बिना मुकदमा चलाए किसी को जेल में रखने के हक में नहीं हूं। व्यक्ति-स्वातंत्रय् का समादर होना चाहिए, लेकिन सरकार के दिमाग में जो विविधा है, उस की कथनी भौर करनी में जो धन्तर है, इस विधेयक को लाने के पीछे उस का जो मन्तव्य है, उस को समझने में में मसमर्थ रहा हूं—शायद यह सदन भी ग्रसमर्थ है।

कहा जाता है कि ग्रब ग्रापातकाल की स्थिति समाप्त हो रही है, केवल सीमा-प्रदेशों में वह स्थिति बनाए रखी जायेगी और शेष भारत में धब ग्राघारमृत ग्रधिकारों को उपभोग में लाने का, और अगर उन पर आक्रमण होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जाने का ग्रधिकार नागरिकों को वापस मिल जायेगा। लेकिन जिस समय ग्रापत्काल स्थिति थी ग्रीर सरकार को ग्रधिकार प्राप्त थे, उस समय सरकार ने कैसा भ्राचरण किया? क्या श्रीनगर में प्लैविसाइट फंट को गैर-कानुनी घोषित करने का ग्रिषिकार सरकार के पास नहीं है ? ग्रगर सरकार चाहे, तो क्या वह प्लेविसाइट फंट को गैर-कानुनी घोषित नहीं कर सकती? इस विघेयक के बिना भी वह ग्रिषिकार सरकार के पास ग्रापात्काल स्थिति के कारण है। लेकिन सरकार ने उस मधिकार का प्रयोग नहीं किया। फिर नये प्रविकार मांगने की क्या भावश्यकता है?

हमें डर है कि इन प्रधिकारों का दुर-पयोग होगा। गृह मंत्री महोदय का दिमाग किस मनमाने ढंग से काम करता है, उन्होंने इस का भी एक संकेत दो दिन पहले दिया। कांग्रेस के माननीय सदस्य ंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में पूछा था भौर गृह मंत्री महोदय ने कहा कि भार० एस० एस० सम सार्ट श्राफ पोलीटिकल शार्गनाइयेशन है—किसी तरह का राजनीतिक संगठन है, श्रौर हम ने केन्द्रीय सरकार के कर्मवारियों से कह दिया है कि वे उस में न जायें। में पूछना बाहता हं कि किसी भी संगठन को [श्री अटल बिहारी बाजपेयी] राजनीतिक घोषित करने का स्रधिकार सरकार को किसने दिया है।

श्री यशवन्त राव चह्नाणः वह इनहेरेंट है।

श्री अटल विहारी वाजपेयी: वाह ! उत्तराधिकार से प्राप्त है!

मंत्री महोदय कहते हैं कि सरकार को यह प्रिषकार है कि वह किसी भी संगठन को राजनीतिक घोषित कर दे थ्रौर भव सरकार यह अधिकार लेना चाहती है कि किसी भी संगठन को ग़ैर-कानूनी घोषित कर दे। एक अधिकार तो इनहेरेंट हैं थ्रौर दूसरा अधिकार वह संसद् से लेना चाहती है।

श्री यशवन्त राव चह्नाण: पोलीटिकल समझना ग्रलग बात है ग्रीर गैर-कानूनी डिक्लेयर करना ग्रलग—उस के लिए ट्रिब्यू-नल के सामनें जाना होगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेथी: सरकार दिब्यूनल के सामनें भी जाने के लिए तैयार नहीं है। सम्बद्ध धारा में यह प्रवाइजो दिया गया है कि बिना दिब्यूनल के सामने जाये तत्कालिक परिस्थिति को देख कर सरकार किसी संगठन को गैर-कानूनी घोषित कर सकती है।

श्री यशवन्त राव चह्नाणः लेकिन बाद में जाना तो पड़ेगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं उस पर बाद में भाऊंगा।

सरकार नें यह फ़ैसला किया है कि घार० एस० एस० किसी तरह का राजनीतिक दिल समझा जाये, लेकिन क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि देश के दो कोई हाई कोटों नें इस बारे में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ़ की गई कार्यवाही को रद्ध कर दिया है? उपाध्यक्ष महो-दय, क्या गृह मंत्री महोदय जानते हैं राजस्थान के हाईकोर्ट का फैसला ? हाईकोर्ट का

फैसला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांस्कृ-तिक संगठन है। उसमें भाग लेनें के कारण किसी कर्मचारी को निकाला नहीं जा सकता है। गृह मंत्री महोदय किस दिब्युनल की बात कर रहे हैं गृह मंत्री महोदय का दिमाग किस दिशा में काम कर रहा है? इस की मैं चर्चा कर रहा हं। देश की भ्रसंडता के लिए, देश की सर्वप्रभुता के लिए जो भी चुनौती है उस का दुढ़ता के साथ सामना होना चाहिए। लेकिन भ्रगर सरकार सामना नहीं कर पा रही है तो इसलिए नहीं कि उस के पास भविकार नहीं है। सामना इसलिए नहीं कर पा रही है कि सरकार में दम नहीं है। बैकबोन माफ बनाना एक श्रंग्रेजी की कहावत है। इस सर-कार की कमर जो है वह केले की तरह है। बागी नागाम्रों के साथ बातचीत, शेख म्रम्दुल्ला के साथ गुप्त बार्ता, मगर देश की सीमाधों के भीतर प्रपने विचारों के प्रनुसार जो भारत का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं उनके प्रति सरकार की श्रधिकारों का दुरुपयोग करनें की भेदभाव की नीति ग्राज स्पष्ट हो गई। इस विधेयक में कहा गया है कि धगर कोई देश के किसी भागको भारत से प्रखग करने का प्रयत्न करेगा कोई भारत से घलग होने की बात करेगा तो उस पर इस कानून को भापत्ति होगी और कोई ग्रगर भारत के किसी भाग को दूसरे को देने की बात करेगा तो यह भी भ्रापत्तिजनक होगा। लेकिन यह सरकार स्वयं भारत के भाग पड़ोसियों को दे रही है भौर इस के लिए संसद की सलाह लेना भी जरूरी नहीं है। सरकारी प्रधिकारी मंत्रियों से परामशं कर के या बिना परामर्श किए भारत की भूमि का दान कर सकते हैं, वह इस कानून के भ्रंतर्गत भ्रवैध नहीं होगा। ध्रव कहा जाता है कि भूमि मिलाना घगर सर्वप्रभुता की सीमा के अंतर्गत आता है तो ग्रपनी भूमि किसी को दे देना यह भी सर्व-प्रभुता का हिस्सा है। क्या सरकार इसके लिए यह व्यवस्था मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि ऐसे समझौते, ऐसे मन्तर्राष्ट्रीय समझौते जिन में भूमि देनी पड़ती है वह संसद

की सहमति के बिना कार्यान्वित नहीं होंगे ? लेकिन यह हमारे प्रधिकारियों को, मंत्रियों को छट देता है देश की सर्वप्रभुता, प्रखंदता के खिलाफ काम करने के लिए। मगर यदि कोई दल ऐसा काम करेगा तो उसे गैर-कानुनी घोषित किया जा सकता है। हम नहीं चाहते कोई दल ऐसा काम करे। लेकिन श्रीर सतारु दल का कोई व्यक्ति खडे हो कर यह कहे कि जो एक तिहाई भाग काश्मीर का पाकिस्तान के पास है वह पाकिस्तान को देकर हमें समझौता कर लेना चाहिए तो क्या वह इस विघेयक के मंतर्गत दंड का भागी होगा ? मैं चाहता हं कि गृह मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें। मैं प्रधान मंत्री नेंहरू की चर्चा नहीं करता। उन्होंनें एक बार सार्वजनिक रूप से यह भवसर दिया था लेकिन बाद में पाकिस्तान ने नहीं माना तो उन्होंनें बापस ले लिया। लेकिन भविष्य में इस तरह का कोई अवसर नहीं दिया जायगा, हम एक तिहाई काश्मीर पाकिस्तान को देकर उस पर से श्रपना दावा छोड कर समझौता करने के लिए मागे नहीं बढेंगे, क्या यह विधेयक इस दिशा में सरकार के हाथ पैर बांघता है? मेरे पास जो खबरें घा रही हैं वह बडी चिन्ता पैदा करने वाली हैं।दिल्ली में बैठे हुए शेख प्रव्दल्ला से कुछ गुप्त बातें हो रही हैं भौर गृह मंत्री महोदय को भी उन गुप्त बातों का पता नहीं है। भगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो शेख प्रब्दुल्ला श्रौर प्रधान मंत्री के बीच में कोई गप्त-पत्र-व्यवहार चल रहा है भीर उस पत्र-व्यवहार में शेल भन्दल्ला को कुछ भवसर दिये जा रहे हैं। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हं, इस चर्चा में भाग लेते हुए कि जम्म भीर काश्मीर को शेष भारत के साथ लाने की जो प्रक्रिया भव तक चल रही है उस प्रक्रिया के ग्रागे बढ़नें की गंजाइश है, मगर उस प्रक्रिया में किसी को पीछे नहीं लौटने दिया जायगा। किसी को घड़ी की सुई को पीछे चुमाने का घषिकार नहीं होगा। भारत की जनता यह यह स्वीकार नहीं करेंगी कि म्राप जम्मू भौर

काश्मीर की घाटी को प्रधिक स्वायसता दे कर सिक्किम या भूटान के उदाहरण के तौर पर शेख भन्दुल्ला के साथ किसी तरह का समझौता करें। भगर ऐसा समझौता किया गया तो क्या यह विधेयक सरकार को उस समझौता से रोकता है? नहीं रोकता।

गृह मंत्री महोदय ने भपनें भाषण में बांटने वाली शक्तियों की बात कही। उन्होंने कहा वह विषेयक साया जा रहा है बांटने बासी शक्तियों के खिलाफ। कोई मगर भारत का हिस्सा भारत से घलग करना चाहे. तो मैं समझ सकता हं। कोई घगर चीन या पाकि-स्तान या किसी तीसरे को देना चाहे तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन यह जो बांटने वाली शक्तियां हैं, प्रधान मंत्री और गृह मंत्री की करपना का जो राष्ट्रीय एकीकरण है उसमें खतरा डालती है यह बात हमारे दिमाग में संदेह पैदा करती है। राष्ट्रीय सर्वप्रभूता और राष्ट्रीय अखंडता इसकी अभी तक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हुई है। इसलिए हम ने संयुक्त प्रवर समिति में कहा या इंटीग्रिटी के आगे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जोड़ना चाहिए। लेकिन संविधान का हवाला दे कर यह प्रस्ताव नहीं माना गया । मैं कहना चाहता हं कि सेशन और सेशेसन को छोड़ कर जो भी चुनौती पैदा होती है उस से राज-नीतिक स्तर पर निपटना होगा। गृह मंत्री महोदय भी मानते हैं कि खाली कानून से ऐसी शक्तियों से निपटारा नहीं हो सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि फिर कानून में आप ऐसा अधिकार क्यों लेना चाहते हैं? यह विघेयक खाली सेशन और सेसेशन तक सीमित रहना चाहिए। देश की सर्वप्रभूता और अखंडता के लिए आपकी, कल्पना के अनुसार जो संकट पैदा होते हैं उन का निवारण आप राजनैतिक स्तर पर करिए। कोई मच्छर को मारने के लिए तौप नहीं चलाया करता है। देश में भाषावाद, प्रान्तवाद और छोटे छोटे स्वार्थ अपने सिर उठा रहे हैं। अगर हमें लोकतंत्र में विश्वास है, देश की

[भी बटल बिहारी वाजपेयी]

जनता में विश्वास है, जिस विश्वास की दोहाई राजभाषा विधेयक पर भाषण करते हुये वह दे रहे थे, वह लोक तंत्र में हमारा विश्वास, जनता में हमारी निष्ठा, इस प्रकार के पैदा होने वाले संकटों का निवारण करने में समर्थ होनी चाहिए। उस के लिए सरकार को मनमाने अधिकार लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर गह मंत्री इस विधेयक में और भी कुछ संशोधन करने को तैयार होंगे तब तो यह विधेयक हमें मान्य होगा अन्यथा, मैं यह मांग करूंगा कि यह विधेयक वापस लिया जाय हमारा दल इस विधेयक को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

भी अहमव भागा (बारामुला) : उपाध्यक्ष महोदय, में इस बिल का स्वागत करता हं क्योंकि कुछ ऐसी टेंडेंसी यहां बढ़ रही है, आज जिस इंटीग्रेशन की बात की जा रही है और अभी जो तकरीर हई उस में आनरेबल मेम्बर ने स्वीकार किया कि नागाल है का प्राबलम है, आसाम का प्राबलम है, और काश्मीर का भी जिक्र उन्होंने किया। तो जब इस बात को मानते हैं कि ऐसी टेंडेंसी है तो यह भी जरूरी है कि हम एक ऐसा कानून लागू करें जो हमारी सरकार को इस काबिल बनाये कि जब जरूरत हो तो इस कानन का इस्तेमाल करे। कोई कानन बैक्अम में तो नहीं बनता, खाली में तो नहीं बनाया जाता। उसके लिए एक प्रापर क्लाइमेट की भी जरूरत होती है। कोई एसी स्कीम हो, कोई ऐसा माहौल जिस में बह सब टेंडेंसीज जो कि डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसीज हैं जो मुल्क के टुकड़े करने की तरफ जा रही हैं, ऐसा माहील जब हो तो उस की रोकथाम भी होनी चाहिए। 1961 में जब नेशनल इंटीग्रेशन की कान्फरेंस बुलायी गई उस वक्त डाक्टर राधाकृष्णन बाइस प्रेसीडेंट थे, उन्होंने अपनी इफ्तताई तकरीर में कहा था: कि हिन्दस्तान में वह वक्त, वह दिन अच्छे थे, जब हिन्दुस्तान में गुडबिल थी, एक अण्डर-स्टैण्डिंग थी, एक दूसरे के लिये टालरेशन था। उन्होंने हवालां दिया था अशोक के जमाने का, उन्होंने हवाला दिया या चन्द्र गुप्त मौर्य के बक्त का, उन्होंने हवाला दिया-अकबर के वक्त का। उस के बाद चुंकि ये सुरत नहीं रहीं, इस लिये हिन्दुस्तान नीचे चला गया। उस के बाद सन 1962 में एक कान्सिल बनाई गई, जिसमें दो कमेटियां बनी, जिनके जिम्मे यह काम सौंपा गया-एक रिजनल इन्टीग्रेशन के बारे में थी और दूसरी नेशनल इन्टीग्रेशन और कम्यलिज्म के बारे में थी। जहां तक मझे मालुम है इन दोनों कमेटियों ने अपनी कोई सिफा-रिशात नहीं दीं। ऐसी हालत में मैं यह समझता हं, कि अलावा इस के कि यह कानून नाफ़िज किया जाय हम को एक ऐसे माहौल की जरूरत है, जिसमें लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिये अण्डरस्टैंडिंग और टालरेशन पैदा हो।

जनाब, मुझे पं० जवाहर लाल नेहरू का एक जमला याद आता है, जो उन्होंने, अगस्त, 1952 को इसी एवान में कहा था। उन्होंने कहा था----

"The strongest bonds that bind will not be of your army or even of the Constitution but bonds that are stronger than the Constitution and laws and army, bonds that bind by love and affection and understanding."

यह जुमला इसी एवान की डिबेट के बाल्युम 4, हिस्सा 2, कालम 3908 पर मौजूद है। आज कहा जाता है कि नागाओं के साथ बातचीत क्यों होती है ? बात इस लिये होती है कि वे हमारे भाई हैं, हम उन के साथ अण्डरस्टिंडिंग पैदा करना चाहते हैं। बात इस लिये भी जरूरी है कि हमें एक ऐसा माहौल तैयार करना है, जिसमें कि वे हम को अच्छी तरह से समझ सकें, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस में कामयाब न हों. तो

हमें इस कानून की भी जरूरत है। लेनकि इस के सिलसिले में पहले कोशिश जरूर होनी चाहिए।

इसी सिलसिले में में आपकी तबज्जह चन्द रोज हुए श्री कृपालानी जी के दो-तीन जुमलों की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने काम्मीर डिबेट के सिलसिले में यहां पर फर-माई थीं। में यह समझता हूं कि ऐसी प्रोबो-केटिब बातें नहीं होनी चाहियें, जिससे हमारी एकता, हमारी इन्टीमिटि में फर्क आये और लोगों को दुख पहुंचे। आप जानते हैं- कि हर शब्स के पास दिल होता है और जब ऐसी बातें कही जाती हैं, तो उसके दिल पर चोट लगती हैं—उन्होंने फरमाया था—

"One would be living in a dreamland if he said that there was no communalism in Kashmir. If there was no communalism, how could such a large number of infiltrators come there?"

सच्चाई यह है कि वह हकीकत से नाआश्नां हैं, वे जानते ही नहीं हैं कि किस्सा क्या है। दीन मुहम्मद हमारा ही आदमी था, जिसने सब से पहले हमें इनिफलट्टेटर्स के बारे में इत्तला दी कि इनफिलट्रेटर्स आ गये हैं। उन लोगों का यह इरादा था कि 9 अगस्त को जो जलुस शेख अब्दुल्ला की गिरफतारी का दिन मनाने के सिलसिले में निकलनेवाला था, उस में गड़-बड़ डालें। लेकिन चुकि 5 अगस्त को ही यह जाहिर हो गया कि वे आ गये हैं, लिहाजा उन्होंने खद वालन्टैरीली कहा कि हम ज्लूस नहीं निकालेंगे और इस तरह से इनफिलट्रेटर्स नंगे हो गये, एक्सपोज्ड हो गये और उस के बाद वे चले गये। इस लिये कृपालानी जी ने जो बात कही-उन को सही हालात की बाकफियत नहीं थी।

में इसी सिलसिले में एक और बात की भी आपको बाद दिलाना चाहता हूं—काश्मीर में सैकेड रेलिक की गुमगुदगी के सिलसिले में बहां का हिन्दु, वहां का सिख, वहां का मुसल-मान—सब एक साथ थे, आपने उन के इस

जज्बे को एप्रीशियेट नहीं किया। वे लोग सड़कों पर रहे, वरफवारी में एक साथ खड़े रहे---उस हिन्दू के, उस सिखों के, उस मुसल-मानों के इस जज्बे को एप्रीशियेट नहीं किया। उधर जब ढाका में कश्-तो-खन हवा, तो कलकत्ते ने उस का जवाब दिया, लेकिन हम सब एक साथ थे और हम ने तय किया था कि हम सब एक साथ चलेंगे। हम ने उस वक्त किस को पुकारा था, कृपालानी जी यहां पर मौजूद नहीं है, काश्मीर के लोगों ने उस वक्त किस को पुकारा? उन्होंने अफगानिस्तान को नहीं पुकारा, रूस को नहीं पुकारा, उन्होंने पाकिस्तान को नहीं पुकारा---उन्होंने शास्त्री जी को पुकारा । शास्त्री जी वहां आये और शास्त्री जी ने उस मामले को हल किया। मैं बड़ी सफाई से यह बात कहना चाहता हं । हमारे गरीब लोगों की नजर में, इन्तहा गरीब लोगों की नजर में आज शास्त्री जी से बहादुर ज्यादा कोई नहीं है, क्योंकि वह तनहा इन्सान साखों लोगों के मजमे में गया--जहां फीज काम नहीं कर सकती थी, वह अकेला जाता है और तमाम हालात पर काबू पाता है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने आज तक शास्त्री जी का स्टेच् काश्मीर में क्यों नहीं बनाया? इतने साल गुजरे गये लेकिन वहां के लोग शास्त्री जी को आज भी याद करते हैं। मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि शास्त्री जी का स्टेचू काश्मीर में जरूर होना चाहिये।

क्रपालानी जी ने दूसरी बात जो बयान की, उस से भी मुझे दुख पहुंचा, काश्मीर के लोगों को भी पहुंचा। उन्होंने कहा....

एक माननीय स्वस्य : हाजीपीर पर बनाइये।

श्री अहमद आगा: उन्होंने कहा कि मेख साहब और बरुगी साहब वहां के लोगों के नुमाइन्दे हैं। मैं समझता हूं कि वह हालात से नावाकिफ़ नहीं हैं, इस लिये कि वे दोनों बगैर इलैक्शन के चुने जाते रहे हैं उन्होंने कभी इलैक्शन नहीं लड़ा, लेकिन आज कल

# [श्री अहमद आगा]

जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, वह इलैक्शन से आये हैं। इस सिये में अर्ज करना चाहता हं कि इस तरह की बातें करने से पार्टी इन्टरेस्ट तो एडबान्स हो सकता है, मगर दूसरे मल्कों को हम क्या इम्प्रेशन देते हैं। हम पाकिस्तान को यह कहते हैं कि वहां कांग्रेस थोपी गई है। यह बात नहीं है--कांग्रेस वहां पर पहले से मकबूल थी, खुद बख्णी साहब के जमाने में भी मौजूद थी। मैं आपको बतलाना चाहता कि इस पिछले इलैक्शन से पहले जो इलैक्शन हुआ था--उस में मौहम्मद शकी क्रेशी का इलैक्शन हो रहा था, क्रेशी साहब लीड कर रहे थे. बराबर खबरें आ रही थीं यानी-कदम जर्मन का बढ़ता है, फतह इंग्लिश की होती है-लेकिन जब इलैंक्शन का रिजल्ट एनाउन्स हुआ, तो दूसरे साहब, जो उन के कैन्डीडेट ये जीत गये। उस वक्त तो उन्होंने एतराज नहीं किया, उस वक्त इलैक्शन कमीश्रन उनका अपना था इसलिए ठीक था. लेकिन आज ठीक नहीं है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हं कि अगर आज हिन्दस्तान के इलैक्शन कमीशन के होते हुए यह कहा जाय कि काश्मीर का इलैक्शन गलत है, तो में कहुंगा कि सारे हिन्दस्तान का इलैक्शन गलत है। होम मिनिस्टर साहब ने उस बात अपने जवाब में महज इतना ही कहा कि वह मामला अदालत में हैं। मैं यह कहता कि अगर वहां के रिटर्निंग आफिसरज के फैसलों के खिलाफ़ फैसला हो जाय, तो क्या बात है, बद्धशी साहब फिर इलैक्शन लड लें।। मगर इस तरह की बातें कर के गलतफहमी पैदा करना मनासिब बात नहीं है।

कृपालानी जी ने एक और बात उटाई---जिससे मुझे दुख हुआ। वह कहते हैं--

> "First-class administators should be sent to Kashmir. Kashmiri officials should be provided elsewhere."

लेकिन आप काश्मीरी आफिशियस्य को कहां रखते हैं। मुझे ज्यादा दुख इस लिये हुआ कि होम मिनिस्टर साहब ने उस का मौजूं जवाब नहीं दिया। उन्होंने सरसरी तौर पर कह दिया कि हां, ऐसा ही होता है। क्या काश्मीर का हिन्द, काश्मीर का सिख, काश्मीर का मुसलमान इस काबिल नहीं है कि वह अपनी रियासत में अपनी सरकार चला सके। आप यहां से अपने एडिमिनिस्टेटर्संस को भेजते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं देते हैं। दस सालों से हमारे प्रमोशन कोटा की 30 पोस्टें खाली पड़ी हैं, उन को फिल-अप कीजिये। वहां से आदमियों को यहां लाइये। अब यहां से आदमी वहां भेजते हैं और वहां से लोगों को यहां नहीं बुलाते हैं, इस से उन के अन्दर फस्ट्रेशन पैदा होता है। मैं आपको बताऊं कि हम ने हिन्दुस्तान के साथ इल्हाक क्यों किया---यह 1938 की बात है, हम अन्धेरे में भटक रहे थे, हमें उस वक्त पंडित जी ने रोशनी दिखाई, उन्होंने हम से कहा कि तुम्हारे दुख की असली दवा सोशलिज्म है-सोशलिज्म बाई डेमोक्रेटिक प्रासेस । उस वक्त सन 1938 में यह बात हमारी समझ में आ गई, हम ने कहा यह ठीक है और तब से हम ने हिन्दस्तान से इंस्पीरेशन सेनी शुरू की, गाइडेन्स लेनी शुरू की। जब हम लोग उधर नहीं गये, तब हम पर शक क्यों किया जाता है। हमने कब कहा कि काश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, उस पर हमारा क्लेम नहीं है। आज सिक्योरिटी कान्सिल में हमारा मुकदमा क्या है---हम को वह हिस्सा वापस दिलाया जाय। हमने कब कहा कि हम विदृष्टी कर रहे हैं। हम उस को जरूर लेंगे, जब भी मनासिब वक्त होगा, मनासिब हालत होंगे. हम उस को जरूर लेंगे। लेकिन आप यह क्यों कहते हैं कि आपने उस का ख्याल ही छोड़ दिया है, हम को शब्हे की नजर से देखने से नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। शुब्हा नहीं होना चाहिये, यकीन होना चाहिए, यकीन से ही बादमी आगे बढता है।

परमेश्वरी हिन्दू का कोई किस्सा नहीं था, वहां पर बीसियों लड़कियों ने शादियां की हैं——

दैरो हरम में फर्क क्या, हक वही झलक वही आइने मुखतलिफ सही, आइनागर तो एक है। वहां पर तो ऐसी कोई बात नहीं है। असली बात यह थी कि लोगों के दिलों में फ्रस्टेशन था। रिजनल इन्जीनियरिंग कालिज के लड़के निकलते हैं, पहला बैच निकला--एसिस्टेंट इन्जीनियर बना, दूसरा बैच निकला---ओवरसीयर बना, अब तीसरा बैच निकलेगा तो उसे सब-ओवरसीयर बनना पडेगा--यह हमारे साथ जुल्म है। हम जो हिन्दुस्तान का हिस्सा बने हैं, तो उन को यहां लाइये, पब्लिक सैकटर्स में जगहें हैं, वहां उन को काम दीजिये, ताकि उन को यह महसूस हो कि यह मुल्क मेरा है, में इस मुल्क को बिलॉंग करता हूं। वहां का हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उस को यह समझ घाना चाहिए कि कि हिन्दुस्तान मेरा है और मैं हिन्दुस्तान का हुं। उस को हिमालय के पहाड़ों के कविनों में षकेल दें धौर फिर उस से तवक्का करें कि वह कुछ नहीं करेगा---यह कैसे मुमकिन है। रिजनल कालेज में झगड़ा क्यों होता रहता है-इस लिए होता है क्योंकि उनको बेकारी सामने नजर भाती है। इसीलिए वह देख रहे हैं कि जो पिछले साल पास करके गए वह स्रोवरसियर बने। धव मैं पढ़ रहा हुं तो मैं सब ग्रोबरसियर बनुंगा भीर फिर जो मुझ से जूनियर हैं वह शायद मिस्त्री बनेंगे तो मेरा कहना है कि यह बड़ा जुल्म है।

#### 15 Hrs.

बाकी यह हमें समझ लेना चाहिए कि कि हम उसी वक्त भागे जा सकते हैं जब हम एक तरीक़े से उस इंटैग्नेटी को उस एकता को हम भ्रस्काज से भी पूरा करें। कोई प्रोबोकेशन न करें। जो कानून है उस को मैं वैसकम करता हूं सेकिन महुख कानून नाकाफ़ी है उस के लिए एक मुनासिब माहौल पैदा करने की भी खकरत है।

شرى احمد آغا (بارامولا) ـ ا بادهيكش مهودئر میں اس بل کا سواگت کرتا ھوں کیوں که کچھ ایسی ٹینڈینسی یہاں ہڑھ رھی ہے آج جس انٹیگریشن کی بات کی جا رہی ہے اور ابھی جو تقریر هوئی اس میں آنریبل ممبر نے سویکار کیا که ناگالینڈ کا پراہلم ہے آسام کا پرابلم ہے اور کشمیر کا بھی ذکر انہوں نے کیا ۔ تو جب اس بات کو مانتر ہیں کہ ایسی ٹینڈینسی ہے تو یه بھی ضروری ہے که هم ایک ایسا قانون لاگو کریں جو هماری سرکار کو اس قابل بتاوے کہ جب ضرورت هو تو اس قانون کا استعمال کرہے۔ کوئی قانون ویکٹوم میں تو نہیں بنتا خالی میں تو نہیں بنایا جاتا ۔ اس کے لئے ایک پراپر سکیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی ایسی سکیم هو کوئی ایسا ماحول جس میں وہ سب ٹینڈنسیز جوکہ ڈسریشنسٹ ٹینڈنسیز ہیں جو ملک کے ٹکڑے کرنر کی طرف جا رهی هیں ایسا ماحول جب هو تو اس کی روک تهام بھی هونی جاهئير ـ

ک کانفرینس بلائی گئی اس وقت ڈاکٹر رادھا کرشنن وائس پریسیڈینٹ تھے انہوں نے اپنی ابتدائی تقریر میں کہا تھا کہ هندوستان میں وہ وقت کلول تھی۔ ایک انڈر سٹینڈنگ تھی انہوں نے موالا دیا اشوک کے زمانے کا ۔ انہوں نے موالا دیا چدرگت موریہ کے وقت کا ۔ انہوں نے موالا دیا چندرگت موریہ کے وقت کا ۔ انہوں نے موالا دیا چندرگت

ایسا ماهول تیار کرنا ہے جس میں کہ وہ ہم کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں ۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم اس میں کامیاب نه هوں تو همیں اس کانون کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے سلسلے میں پہلے کوشش ضرور ھونی چاھئے ۔

اسی سلسلے میں میں آپ کی توجہ چند روز ہوئے شری کرپلانی جی کے دو تین جملوں کی طرف دلانا چاھتا ھوں جو انہوں نے کشمیر ڈبیٹ کے سلسلر میں یہاں پر فرمائی تھی۔ میں به سمجھتا ہوں که ایسی پرووکیٹو باتیں نہیں ہونی چاھیں جس میں هماری ایکتا ۔ هماری انٹیگریپٹی میں فرق آثیر اور لوگوں کو دکھ پہنچر ۔ آپ جانتر ہیں کہ ہر شخص کے پاس دل ہوتا ہے اور جب ایسی باتیں کہی جاتبی هیں تو اس کے دل پر چوٹ لگتبی ھے۔ انہوں نر فرمایا۔

"One would be living in a dreamland if he said that there was no communalism in Kashmir. If there was no communalism, how could such a large number of infiltrators come there?"

سچائی بہ ہے کہ وہ حقیقت سے ناآشنا هیں ۔ وہ جانتر هی نهیں هیں که قصه کیا ہے۔ دین محمد همارا هی آدمی تها جس نے سب سے پہلے همیں انفلٹریٹرس کے بارے میں اطلاع دی تھی که انفلٹریٹرز آ گئے ھیں۔ ان لوگوں کا یہ ارادہ تھا کہ و اکست کو جو جلوس شیخ ابدته کی گرفتاری کا دن منانر کے سلسلر میں نکلنر والا تھا۔ اس میں گربڑ ڈالیں۔ لیکن چونکه ه اگست کو هي په ظاهر هو گيا که

**آشری احمد آغا**م

آکبر کے وقت کا ۔ اس کے بعد حونکہ یه ٹینڈینسیز نہیں رهیں اس لئر ھندوستان نیجے چلا گیا۔ اس کے بعد سن ۱۹۹۲ میں ایک کاؤنسل بنائی گئی جس میں دو کمیٹیاں بنیں ۔ جن کے ذمہ یہ کام سونیا گیا ۔ ایک ریجنل انٹیکریشن کے بارے میں تھی اور دوسری نیشنل انٹیگریشن اور کمیونلزم کے بارے میں تھی ۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے ان دونوں کمیٹیوں نے اپنی کوئی سفارشات نہیں دیں ۔ ایسی هالت میں میں یه سمجهتا هوں که علاوه اس کے کہ یہ کانون نافظ کیا جائر ہم کو ایک ایسر ماهول کی ضرورت مے جس میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے انڈر سٹین**ڈنگ اور** ٹالریشن پیدا هو۔

جناب مجهر پنڈت جواهر لعل نہرو کا ایک جملہ یاد آتا ہے جو انہوں نے ے اگست ۱۹۵۲ کو اسی ايواں ميں كما تھا ـ

"The strongest bonds that bind will not be-of your army or even of the Constitution but bonds that are stronger than the Constitution and laws and army, bonds that by love and affection and understanding."

یه جمله اسی ایوان کی ڈبیٹ کے و الميم ۾ پيج ٢ کالم ٩٠٨ه پر موجود مے ۔ آج کہا جاتا مے که ن**اکاؤں** کے ساتھ بات حیت کیوں ہوتی ہے۔ بات اس لئے ہوتی ہے که وہ همارے بھائی ھیں۔ ھم ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہتر میں ۔ ہات اس لئے بھی ضروری ہے که هس، ایک

میں گیا۔ جہاں فوج کام نہیں کر
سکتی تھی۔ وہ اکیلا جاتا ہے اور
تمام حالات پر قابو پاتا ہے۔ میں
جاننا چاھتا ھوں کہ آپ نے آج تک
شاستری جی کا سٹیچو کشمیر میں کیوں
نہیں بنایا۔ اتنے سال گزر گئے لیکن
وھاں کے لوگ شاستری جی کو آج
بھی یاد کرتے ھیں۔

کرہلانی جی نے دوسری بات جو 
ہیان کیں اس سے بہی مجھے دکھ 
ہہنچا ۔ کشمیر کے لوگوں کو بھی 
ہہنچا ۔ انہوں نے کہا۔۔۔۔۔

ایک ماننیه سدسیه ـ حاجی پیر پر -----نائیم ـ

شری احمد آغا ۔ انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب اور بخشی صاحب وهاں کے لوگوں کے نمائندے هیں ـ میں سمجهتا ھوں کہ وہ حالات سے ناواقف ھیں۔ اسلئے که وہ دونوں بغیر ایلیکشن کے چئے جاتے رہے هیں ۔ انہوں نے کبھی ایلیکشن نہیں لڑا۔ لیکن آجکل جو چیف منسٹر هیں وہ ایلیکشن سے آثر **ھیں ۔ اسلئے میں عرض کرنا چاھتا** ھوں کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے پارٹی انٹریسٹ تو ایڈوانس ھو سکتا ہے مگر دوسرے ملکوں کو ہم کیا امپریشن دیتے هیں ـ هم پاکستان کو یه کمپتے هیں که وهاں کانگریس تھوپی گئی ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ کانگریس وهاں پر پہلے سے مقبول تھی ۔ خود بخشی صاحب کے زمانے میں بھی موجود تھی۔ میں آپ کو بتلاؤں اس ہجھلے الیکشن سے پہلے جو ایلیکشن هوا تها اس میں محمد شفی کریشی کا ایلیکشن هو رها تها۔ کریشی

وہ آئے ھیں لہذا انہوں نے خود کہا کہ ھم جلوس نہیں نکالینگے اور اس طرح سے انفلٹریٹرز ننگے ھو گئے ایکسپوزڈ ھو گئے اور اس کے بعد وہ چلے گئے ۔ اس لئے کرپلانی جی نے جو بات کہی انکو صعیع حالات سے واقفیت نہیں تھی ۔

میں اسی سلسلے میں ایک اور بات کی بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ۔ کشمیر میں سیکریڈ ریلک کی کشیدگی کے سلسلے میں وہاں کا ہندو۔ وہاں کا سکھ۔ وہاں کا مسلمان سب ایک ساتھ تھے۔ آپ نے ان کے جزبہ کو ایپریشیٹ نہیں کیا ۔ وہ لوگ سڑکوں پر رہے ۔ برفباری میں ایک ساتھ کھڑے رہے۔ اس ھندو کے اس سکھ کے اس مسلمان کے جزبہ کو ایبریشیٹ نہیں کیا۔ ادھر جب ڈھاکہ میں کشتو خون ہوا تو کلکتہ نے اس کا جواب دیا ۔ ليكن هم سب ايك ساته تهر اور هم نے طے کیا تھا کہ هم سب ایک ساتھ چلینگے۔ هم نے اس وقت کس کو پکارا تھا ۔ کرپلانی جی یہاں پر موجود نہیں ہیں ۔ کشمیر کے لوگوں نے اس وقت کس کو پکارا ۔ انہوں نے افغانستان کو نہیں پکارا ۔ روس کو نہیں پکارا ۔ انہوں نے پاکستان کو نہیں پکارا ۔ انہوں نے شاستری جي کو پکارا ـ شاستری جي وهاں آئے اور انہوں نے اس معاملے کو ھل کیا ۔ میں بڑی صفائی سے یہ بات کہنا چاھتا ھوں ۔ ھمارے غریب لوگوں کی نظر میں آج شاستری جی سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ تنها انسان لاکھوں لوگوں کے مجمد

Activities (Prevention) 7858

[شری احمد آغا]

صاحب لید کر رہے تھے ۔ برابر خبریں ا رهی تهیں ـ قدم جرس کا بڑھتا ہے قتر انگلش کی ہوتی ہے۔ لیکن حب أيليكشن كا رزك ايناؤنس هوا تو دوسرے صاحب جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے وہ جیت گئے ۔ اس وقت تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا ۔ اس وقت ایلیکشن كميشن ٹهيك تها ليكن آج ٹهيك نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاھنا ہوں کہ اگر آج ایلیکشن کمیشن به کم که کشمیر کا ابلیکشن غلط ہے تو میں کہونگا کہ سارے ہندوستان کا ایلیکشن محلط ہے۔ هوم منسٹر صاحب نے اس وقت اپنے جواب میں محض اتنا هی کمها که یه معامله عدالت میں ہے۔ میں یه کہتا ھوں کہ اگر وھاں کے رٹرننگ آفیسر کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو کیا بات ہے بخشی صاحب پھر ایلیکشن لڑ لیں۔ مگر اس قسم کی باتیں کرکے غلط فہمی پیدا کرنا مناسب بات نہیں ہے۔

کرپلانی ج نے ایک اور بات اٹھائی ۔ جس سے مجھے دکھ ھوا ہ وہ کہتر ہیں۔

"First-class administrators should be sent to Kashmir. Kashmiri officials should be provided elsewhere."

لیکن آپ کشمیری آفیشیلز کو کہاں رکھتے ھیں ۔ مجھے زیادہ شک اس لئے ہے کہ ہوم منسٹر صاحب نے اس کا موزوں جواب نہیں دیا ۔ انہوں نے سرسری طور پر کہہ دیا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا کشمیرکا هندو کشمیر کا مسلمان اس قابل نمیں

ہے کہ وہ اپنی ریاست میں اپنی سرکار چلا سکے ۔ آپ یہاں سے اپنے اید منسٹریٹرز کو بھیجتے ھیں لیکن ان کو موقع نہیں دہتے ہیں۔ دس سالوں سے ہمارے پرموشن کوٹے کی . ۳ پوسٹیں کھالی پڑی ہیں ان کو فل آپ کیجئے ۔ وہاں سے آدمیوں کو یہاں لائیے۔ جب یہاں سے آدمی وہاں بھیجتے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو بہاں نہیں بلاتے میں اس سے ان کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیوں کیا۔ یہ ۱۹۳۸ کی بات ہے ۔ هم اندهیرے میں بھٹک رہے تھے۔ همیں اس وقت پنٹت جی نے روشنی دکھلائی -انہوں نے هم سے کہا که تمہارے دکھ کی اصلی دوا سوشلزم ہے ۔ شوشلزم بائي ڏيمو کريڻک پروسس - اس وقت سن ۱۹۳۸ میں یه بات هماری سمجه میں آ گئی۔ هم نے کہا یه ٹھیک ھے اور ثب سے هم نے هندوستان سے انسپیریشن لینی شروع کی ـ گائڈینس لینی شروع کی۔ تب ہم لوگ ادھر نہیں گئے۔ پھر آج ہم پر شک کیوں کیا جاتا ہے۔ ہم نے کب کہا که کشمیر کا جو حصه پاکستان کے قبضه میں ہے اس پر همارا کلیم نهیں ھے۔ آج سکیورٹی کانسل میں همارا مقدمه کیا ہے۔ ہم کو وہ حصه واپس دلایا جائے۔ ہم نے کب کہا کہ ہم ودڈرا کر رہے ہیں۔ ہم اسکو ضرور لینگے ۔ جب بھی مناسب وقت ہوگا ۔ مناسب ہالات ہونگر ہم اس کو ضرور لینگر ـ لیکن آپ به کیوں کہتے هیں که آپ نے اس کا خیال کیوں

چھوڑ دیا ہے۔ ہم کو شبہہ کی نظر سے دیکھنے سے نتیجہ اچھا نہیں نکلیکا ۔ شبہہ نہیں ہونا چاھئے۔ یتین سے ہی آگے ہڑھتا ہے۔

پرمیشوری هندو کا کوئی قصه نهیں تھا۔ وهاں پر بیسیوں لڑکیوں نے شادیاں کی هیں۔

دیروحرم سیں فرق کیا ، حق وہی جھلک وہی

آئنے مختلف سہی، آئنا کر تو ایک ہے وهاں پر تو کوئی ایسی بات نہیں ھے۔ اصلی بات یہ تھی که لوگوں کے دلوں میں فرسٹریشن تھا۔ ریجنل کالج کے لڑکے نکلتے ہیں۔ پہلا بیچ نکلا انجینیر بنا ـ دوسرا بیچ نکلا اور سیئنر بنا۔ اب تیسرا بیچ نکلیگا تو اسے سب اورسیئر بننا پڑیگا ۔ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ ہم جو ہندوستان کا حصه بنر هيں تو ان كو يہاں لائير -پبلک سیکٹرز میں جگہیں ہیں ان کو کام دیجیئے تاکہ ان کو یہ معسوس ھو که یه ملک میرا ہے۔ میں اس ملک کو ہلونگ کرتا ھوں۔ وھاں کا هندو هو ـ سیلمان هو ـ سکه هو اس کو به سمجه آنا چاهیئر که هندوستان ميرا هے اور ميں هندوستان کا هوں ۔ اس کو هماليه کے پہاڑوں کے کوینوں میں دھکیل دیں اور پھر اس سے توقع کریں که وہ کچھ نہیں کریگا۔ یہ کیسر ممکن ہے۔ ريجنل كالبح ميں جهكڑہ كيوں هوا ـ اسلئر هوا که وه بیکار هیں ـ

اسی لئے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ

پچھلے سال پاس کرکے گئے اور وہ اوورسٹر بنے ۔ اب میں پڑھ رھا ھوں تو میں سباوورسٹر بنوں گا اور پھر جو مجھ سے جونئر ھیں وہ شاید منسٹر بنیکا تو میرا کہنا ہے کہ یہ بڑا جرم ہے ۔ ہاتی یہ ھیں سمجھ لینا چاھئے کہ ھم اس وقت آگے جا سکتے ھیں جب ھم ایک طریتے سے اس انٹیگریٹی کو اس ایکتا کو ھم الفاظ سے بھی پورا کریں ۔ کوئی پرووکھش نہ کریں ۔ کوئی پرووکھش نہ کریں ۔ کوئی برووکھش نہ کریں ۔ کوئی بھی بروا

SHRI V. KRISHNAMOORTHI (Cuddalore): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have given an amendment which reads:

"This House is of opinion that the Unlawful Activities (Prevention) Bill, 1967, be referred to the President for obtaining the opinion of the Supreme Court under article 143 of the Constitution on the question of constitutional validity of the Bill."

I would like to express my dissatisfaction on the effort made by the hon. Home Minister to bring about this Bill which is neither necessary nor timely.

As you know, Sir, the integration, the oneness of mind and thinking is very necessary now. When Pakistan committed an aggression or when China committed an aggression, we had managed the affairs of this country even without a measure like this. I want to ask the hon. Home Minister as to for what purpose he is bringing forward this Bill. What is the object of that? What is the present clear danger which exists in India now? The recommendations of the Integration Council dealt only with regard to the separation issue. As you know, we were the only Party who were demanding separation. We have already given it up and there is no necessity for the hon. Home Minister to bring about this Bill we do not even think of reviving or thinking in terms of separation now.

SHRI Y. B. CHAVAN: It is not meant for you. Why are you talking like that?

SHRI V. KRISHNAMOORTHI: Of Course, Mr. Y. B. Chavan is very very intelligent; he is very clever and he is the senior most Minister. He dissolved the West Bengal Government and he started thinking of Naxalbari and all that. I have a

#### [Shri V. Krishnamoorthi]

doubt in my mind. The word 'unlawful' defines that if anybody wants separation or if anybody speaks of separation or if any party advocates separation or if party says that a particular piece of land should be given either to China or to Pakistan or to any other country, it is an offence and the person has committed an offence and, if the party is committing an offence, the very party itself can be banned as per the provisions of the Bill. I ask the hon. Home Minister: What is the necessity now? Is there any Party in India which is demanding separation now? Let the hon. Minister answer that. He says that the D.M.K. Party has given it up. I am thankful to him because he has also agreed now. But I have got my own doubts. After all, the non-Congress Governments have become a prey to Mr. Y. B. Chavan and, in future, he may say that he has got his own piece of evidence that there is a man in the south, or some man in Madras, or some interested party, who claims for separation or the C.B.I. which is Mr. Chavan's bureau of investigation has got a piece of evidence that the Madras Government still insists or still believes or still advocates separation. He may say-I have got my doubts-I am doubtful-that he may do it in future or he may have such a motive.

Now I am coming to the point. In the interest of the country, suppose somebody says, "All right, let us negotiate with our neighbour, whether it is China or Pakistan; in the interest of the majority area or in the interest of the country, in order to maintain very good relations with the foreigners, the enemies who are on the border, let us sit together, rather talk together, let them take one or two villages, we should have friend-ship", is it an offence? If a party says like that, is that party to be banned? If a party says that we must at any cost preserve the integrity and territorial jurisdiction of India by mutual adjustment, is it an offence?

Further, I am charging the hon. Home Minister with this. They are saying that the territory of India extends to the whole of Kashmir also. Several thousands of square miles are now in Azad Kashmir, occupied Kashmir, from where my hon. friend, Mr. Aga, comes. What steps have the Government taken so far to get them back? For the past more than 20 years, the Pakistanis are illegally occupying those areas. What steps the Government have taken so far ? They have not at all taken any steps. If anybody says, if anybody in Kashmir or in any part of northern India says, "Why should we have quarrel with Pakistan? Why not we sit together, discuss it with Pakistan and settle this territory issue", is it an offence Before Mr. Nehru died, I remember, he had said that on the ceasefire line if Pakistan comes for an agreement, the

ceasefire line may be agreed upon by both the parties. I remember, he has mentioned that. If anybody says like 'that now, is it an offence? If anybody says that we must protect India's integrity and security by making friendship with those people, is it an offence? That is why, I say that this it not ment against those people. This is meant to be used against anti-Congress associations, whether it is Jan Sangh or SSP or DMK or even Swatantra. They want to perpetuate their power and that is why they are bringing this measure to eliminate the opposition parties in the States as well as here.

Another thing that I want to say is this. Mr. Daphtary, the Attorney-General of India, whom we had cross-examined, said that even innocuous speeches would come under the purview of this Bill. If I speak, in the interest of India, that these villages may be transferred to Pakistan for bringing about an amicable settlement, if I say that instead of spending thousands of crores of rupces on Defence every year and then going with a begging bowl to Russia and America, we can have friendship with Pakistan, we can have a friendly relation with our neighbour, instead of spending thousands of crores of rupees on Defence, we can sit together and talk together and settle this issue, is it an offence? Even those innocuous speeches, those innocent speeches, are punishable. That is why I am saying that this Bill offends article 19 (1 ) of the Constitution. This is unreasonable because the objection is not made clear, the scope of the Bill is not made clear. In the United States, freedom of speech and expression is not banned, it is banned only on certain occasions, where a speech or assembly or expression is in its very nature a clear danger to the very security of the American nation. If a man speaks, that is not taken notice of. Or if a Party says something in a trivial manner, it is not taken serious notice of, but when there is a clear and present danger to the very security of the country, it is only then that it is taken as an offence in the United States. We are deriving so much of federal principles, so much of democratic principles from the United States. I am appealing to the Home Minister: let us follow that example. This Bill is not meant for curtailing separation. issue. It is not meant for curtailing activities of persons who advocate cession. It is meant to suppress Opposition Parties. It is against Art. 19(1) of the Constitution and it is unreasonable. That is why I oppose this Bill and would plead that it must be sent to the President for obtaining the opinion of the Supreme Court about the constitutionality of this Bill.

With these words, Sir, I am opposing this Bill.

श्री प्रेमचन्द वर्मा (हमीरपुर): मैं भ्रापका श्राभारी हूं कि भ्रापने मुझे बोलने के लिए सयम दिया है। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुमा हूं।

विरोधी पक्ष द्वारा यह कहा गया है, डी॰ एम ० के ० के माननीय सदस्य द्वारा यह कहा गया है कि केवल डी० एम० के० पार्टी ही ऐसी पार्टी थी जो हिन्दूस्तान से मलग होने का नारा लगाती थी भ्रौर भ्रव चुंकि उस पार्टी ने यह नारा लगाना बन्द कर दिया है, ग्रपनी उस मांग को उठाना छोड़ दिया है, इस वास्ते इस बिल की म्रावश्यकता नहीं रह गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बात की क्या गारन्टी है कि कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों या वर्षों के बाद वह उस मांग को फिर उठाना शुरू नहीं कर देगी। डी० एम० के० की वह मांग या वह नारा ही हमारे सामने नहीं है. देश की दूसरी समस्याएं भी हमारे सामने हैं। देश की एकता का सवाल हमारे सामने है। एक ग्रोर नागा समस्या है दूसरी ग्रोर मिजो समस्या है भौर तीसरी भोर काश्मीर की समस्या है। इसके घलावा चीनी एजेंट भी हिन्दुस्तान में काफी सरगरम हैं। क्या भाप इसको नहीं जानते हैं कि भाज रैड गार्ड केरल में बनी हुई है, शिव सेना बम्बई में बनी हुई है, भौर हिन्दी सेना किसी दूसरी जगह बनी हुई है। न जाने कौन-कौन-सी सेनाएं बनी हुई हैं, फौजी भौर नीम फौजी जमायतें हिन्द्स्तान में बनती जा रही हैं। मैं समझता हुं कि माज इस संसद का, भाज हम लोगों का यही कर्तव्य है कि देश की एकता के बारे में सोचें, इस एकता को कायम रखने के लिए जो कुछ हो सकता

है करें, उन शक्तियों पर काबू पाएं जोकि देश के टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहती हैं, देश के संगठन को तोड़ना चाहती हैं, लोगों में सापस में नफरत पैदा कर रही हैं। इनके लिए मैं समझता हूं कि कोई न कोई कानून बनना चाहिए। साप देखें कि हिन्दुस्तान के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सौर पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सभी जगह गड़बड़ी चल रही है। कौन नहीं जानता है कि कुछ शक्तियां हमारे देश में ऐसी हैं, जोकि कानून में कमजोरियों के कारण से नाजायज फायदा उठाना चाहती हैं।

डी० एम० के० के बारे में मैं एक बात भौर कहना चाहता हं। हमने अभी-भ्रभी हिन्दी बिल पास किया है। भ्रभी से इस पार्टी ने बयान देने शुरू कर दिए हैं, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। कौन नहीं जानता कि इस पार्टीन हिन्दी के सावाल को लेकर इससे पहिले क्या कुछ, नहीं किया । वहां इसके लीडरों नें कहा था कि हम मिट्टी का तेल खिड़क कर भपने भापको जला देंगे। तशदुद ग्रामेज बयान इन्होंने दिए थे। मभी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के फायदे के लिए इस कानून को लाया जा रहा है। मैं इस एलीगेशन का खंडन करना चाहता है। मैं समझता हं कि कोई भी पार्टी हो हर पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह देश की एकता को बनाए रखे भौर जो पार्टी सरकार में है उसका तो यह भौर भी कर्तव्य है कि वह देखें कि देश में एकता बनी रहती है भौर भगर वह इस बात को नहीं देखती है तो मैं कहंगा कि वह भपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन नहीं करती हैं। जो सरकार है उसका यह पहला कर्तव्य है कि जनता के घन की, जनता की दौसत की, जनता की इज्जत की, जनता की जान की रक्षा वह करे। भाज हम देखते हैं कि न किसी की दौलत सुरक्षित है और न किसी की जॉन सुरक्षित है और न ही जायदाद और

[श्री प्रेम चन्द वर्मा ]

इंज्जत सुरक्षित है। ग्रापने जब बंगाल में श्री भ्रजय मुखर्जी की सरकार थी तो देखा ही था कि वहां क्या-क्या घटनाएं घटित हुई थीं। मैं एक घटना घापके सामने रखता हूं जोकि पालिमेंट के मेम्बरों के साथ घटित हुई थी कुछ मेम्बर पालामेंट के कलकत्ता गए थे। मैं भी उनमें से एक था। जब हम लोग जहाज में बैठे हुए थे तब कुछ लोगों ने उस जहाज को माग लगाने की धमकी दी थी और मैम्बरों को भी बीच में जला डालने की धमकी दी थी। मैं कल्पना तक नहीं कर सकता हूं कि मैम्बरों तक को इस तरह की घमकियां दी जा सकती हैं। ऐसी हालत बंगाल में पैदा हो चुकी थी। जो मैंम्बर उस वक्त बंगाल में गए थे वे जानते हैं कि किस तरह से उनकी जानें बची थीं। नागालैंड में जो कुछ हो रहा है, वह भी भापके सामने है। यही नहीं भाषा का सवाल जो हमने श्रभी हल किया है उसके ऊपर भी कुछ मोगों ने टिप्पणी करना शुरू कर दिया है।

मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए इस बिल को पास करना जरूरी है, मनीपुर,त्रिपुरा, ग्रसम, बंगाल तक जितनी भी हमारी सरहद जितनी भी हमारी सीमा है उस सीमा पर हमें ऐसे लोगों से वास्ता है जो विदेशों से मदद लेकर, पाकिस्तान भौर चीन से मदद लेकर भनेक प्रचार की बातें कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर रहे हैं, तोड़फोड़ का कोई मौका हो, उसको हाय से जाने नहीं देते हैं। यही नहीं, जब भी मौका मिलता है, ट्रेन उलट देते हैं, कारखानों को जला डालते हैं, हड़तालें करवाते हैं स्रौर तरह-तरह से हथकंडे इस्तेमाल में लाते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक इस तरह के ग्रनसर जो हैं इनको देश से हटा न दिया जाए तब तक इस कानून का होना घाव-इयक है। देश की एकता ग्रीर स्वतन्त्रता को अगर हमें कायम रखना है तो जरूरी है कि इस तरह की पावर्ज हमारे हाथ में हों। म्राज हमारे हां जनता की सरकार है भीर कानून व व्यव- स्या को बनाये रखना उसका पहला कर्त्तंब्य है। जनता की सरकार जो भी कानून लाती है जनता की भलाई के लिए लाती है। जनता की भलाई के काम ग्राना जनता की सरकार का पहला काम होता है। मेरी समझ में नहीं **भाता है किन्तु फिरके या कुछ जिम्मेदार** पार्टियां इसका क्यों विरोध कर रही हैं। मैं तो यह समझता हूं कि वे ऐसा इसलिए कर रही हैं कि उनका मन साफ नहीं है, उनका हृदय साफ नहीं है। एक कहावत है कि चोरी करने के लिए जब भ्रादमी जाता है तो भ्रपने साये से भी वह हरता है। भ्रगर भ्रापके मन में कोई पाप नहीं है तो भ्रापको इससे डरने की जरूरत नहीं है। ग्रगर भापके मन में यह विचार नहीं है कि अपने काम को आप तोड़ें, तोड़फोड़ की कार्रवाइयों में ग्राप हिस्सा लें देश में गड़बड़ी भ्राप पैदा करें तो इस विधेयक से श्रापको डरने की जरूरत नहीं है। तब धगर श्रीर भी कड़ा विघेयक लाया जाए तो उस विघेयक से भी भ्रापको क्या फर्क पड़ेगा? जो लोग पावर हासिल करने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए जनता की जो शक्ति 🕏 उसका गलत प्रयोग करेंगे उनको इससे डरने की जरूरत है, दूसरों को नहीं। सरकार की तरफ से जो कानून लाया गया है यह जनता की भलाई के लिए लाया गया है, देश की एकता को बनाये रखने के लिये लाया गया है, देश को मजबूत बनानें के लिये ग्रौर देश के ग्रन्दर जो गड़बड़ियां होती हैं, उनको रोकने के लिए न्नाया गया है। जब इन चीजों को खतरा पैदा होगा तब इस कानून को काम में लाया जाएगा। होम मिनिस्टर ने कहा है कि वह चाहते हैं इस कानून को ग्रमल में लाने की जरूरत न पड़े। लेकिन मैं समझता हूं कि यह देश में जो हालात पैदा होंगें, उस पर निर्भर करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसको इसी रूप में पास कर दिया जाए । सी सरकू पाच्डेय (गाजीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्मांग्य की बात है कि झाज इस सदन यह कानून झाया है। न तो इस कानून की कोई सांविधानिक झावश्यकता है, न नैतिक भौचित्य है भौर न ही देश की वर्तमान स्थिति को दृष्टि में रखते हुये इसकी कोई जरूरत है। मुझसे पहले एक कांग्रेसी वक्ता नें कहा कि इस कानून की जरूरत इसलिए पड़ी कि देश में ऐसे तत्व हैं, जो देश के टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कानून बना कर देश की एकता की रक्षा नहीं की जा सकती है। कानूनों से न भ्रपराध रोके जा सकते हैं भौर न देश की रक्षा हो सकती है।

15,20 hrs.

[SHRI C. K. BHATTACHARYYA in the chair.]

इस सदन में मंत्री महोदय के दल का बहुमत है, इसलिये भले ही वह इस कानून को पास कर लें, लेकिन जनता उसकी घज्जियां उड़ा कर फेंक देगी और कोई उस का समर्थन नहीं करेगा। अगर उनमें साहस था, तो उनको इस कानून की सांविघानिकता की जांच के लिये सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए थी और देश की जनता से भी पूछना चाहिए था।

बहुत से दंड-शास्त्रियों ने लिखा है कि एक जमाने में यूरोप के देशों में पाकेट-मारी के लिए फांसी दी जाती थी और सड़कों पर एलान होता था कि इस जुमें में फलां श्रादमी को फांसी दी जायेगी, लेकिन जब उस फांसी को देखने के लिए मजमे में जो लोग श्राते थे, उनमें ही जेबकटी होती थी। श्रगर यह सरकार श्रपनी नीतियों को नहीं बदलेगी श्रीर श्रगर देश का कोई भाग, या जनता का कोई वगं, उन नीतियों से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह देश से झलग होने की मांग करेगा। इसलिए सरकार को कानून बनाने के बजाय नागालैंड, काश्मीर श्रीर दक्षिण के कुछ लोगों की समस्याभों का समाधान ढंढना पडेगा। सवाल यह है कि क्या इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा। भ्रमी तो सरकार के पास यह
कानून नहीं है, लेकिन फिर भी उसने बंगाल
में क्या किया? कानूनों की मर्यादा को जितना
इस सरकार ने तोड़ा है, उतना दुनिया की किसी
सरकार ने नहीं तोड़ा है। बंगाल में गवर्नर
के जिरये जबर्दस्ती माइनारिटी पार्टी का राज्य
बना दिया गया। हरियाणा में भी इसो ढंग से
मंत्रि-मंडल को तोड़ा गया। दूसरे सूबों
में भी ऐसा करने की तैयारी की जा रही है।
इस सब के बावजूद मंत्री महोदय भाज सदन से
यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें भीर पावर दे दी
जाये, ताकि वह ऐसे लोगों को जेल में बन्द कर
दें, जो उनके राजनीतिक बिरोधी है। इस
बिल को लाने की भ्रीर कोई वजह नहीं है।

पिछली दफा प्रिवेटिव डिटेंशन एक्ट के सम्बन्ध में मंत्री महोदय नें कहा था कि उसका दुरुपयोग नहीं होगा । उसके अन्तर्गत कितने चोर-बाजारिये, बदमाश और असामाजिक तत्व पकड़े गये, उसका लेखा-जोखा नहीं है । लेकिन यह तथ्य है कि उसके अन्तर्गत वे लोग पकड़े गये, जो इस सरकार की नीतियों पर प्रहार करते थे । ये पावर्ज इसी लिए मांगी जा रही है कि जो व्यक्ति कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करें या वर्तमान असंतोष को दूर करने की मांग करें, उसको जेल में बन्द किया जा सके ।

यह कमाल की बात है कि इस कानून में यह भी कहा गया है कि झगर कोई झादमी लिख कर, बोल कर या सोच कर भी झपने विचार प्रकट करता है, तो उसको जेल में बद किया जा सकटा है। लेकिन प्रक्त यह है कि इसका फैसला कौन करेगा। चल्लाण साहब का कांस्टेबल, जिस को कुछ पता नहीं होता है। माननीय सदस्यों को भी ज्ञात होगा कि झगर कोई व्यक्ति कहता था, "बम महादेव", तो सी० झाई०डी० का सिपाही लिखता था, "बम मार दो"। मेरी एक मीटिंग के बारे में यह रिपोर्ट लिखी गई कि सरजू पाण्डेय ने कहा है कि पटवारियों की जान मार दो। वह

[श्री सरजू पाण्डेय]

सिपाही यह फैसला करेगा कि हमने क्या कहा भौर क्या नहीं कहा। मैं समझता हूं कि इससे बदतरीन कानून दुनिया में कहीं नहीं है। मंत्री महोदय को इसे वापस लेना चाहिए।

कांग्रेस पार्टी के लोग यह समझते हैं कि चुंकि वे सत्ता में हैं, इसलिए यह कानुन उनके विरुद्ध इस्तेमाल नहीं होगा । सरकार कहती है कि हम देश में एकता कायम करने के लिए इस कानून को ला रहे हैं। लेकिन जब यह सरकार पुंजीपतियों के इशारों पर चलेगी, वेश के लोगों के जानो-माल की रक्षा नहीं करेगी, जब देश में रहने वाले पांच करोड़ मुसलमान ग्रौर दूसरी कम्युनिटीज सिक्युर फील नहीं करेंगी, तब क्या इस कानून से देश की एकता कायम रह सकेगी ? नहीं। यह सरकार देश में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहती है कि लोग ऐसे कानुनों को टोड़ें। म्राखिर कानून की मंशा क्या है ? कानून की मंशा है जनता की रक्षा करना । जनता को किसी भी कानून पर कूर्बान नहीं किया जा सकता है। सरकार को इस तरह के कानून बना कर जनता को तंग करने की नीति छोड़ देनी चाहिए। यह सरकार हमेशा रूलिंग पार्टी के फायदे के लिए ग्रौर कांग्रेसियों की सत्ता को कायम रखने के लिए कानुन बनाती है।

जो भाषा सरकार के लोग बोलते हैं, जब हम लोग वही भाषा बोलते हैं, तो हमारे विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। सरकार के लोग कहते हैं कि सारा काश्मीर दूसरों को दे दो। लेकिन प्रगर दूसरे यह कहते हैं कि पाकिस्तान से सुलाह करो, तो कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के एजेन्ट हैं। प्रगर सरकार सारे मुल्क को दूसरों के हवाले कर दे, सी॰ प्राई०ए० का पैसा खाए, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन प्रगर कोई दूसरा घादमी इन बातों की घालोचना करता है, तो उसको इस कानून के धन्तर्गत बन्द कर दिया जायेग।

इस बिल में यह भी कहा गया है कि अगर सरकार चाहेगी, तो वह इस बात का कारण भी नहीं बतायेगी कि उसने किसी संस्था या किसी व्यक्ति को क्यों इल्लीगल करार देने के लिए नोटिफाई किया है। जब भी सरकार पब्लिक इन्ट्रेस्ट की बात कहती है, तो उसका हमेशा मतलब होता है सरकारी इन्ट्रेस्ट और इसी के अनुसार यह सरकार कार्य कर रही है।

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : जब रण में लोग पकड़े जाते हैं, तो क्या उसका कारण दिया जाता है ?

श्री स**० मो० बनर्जी**: माननीय सदस्य जाकर रण में चोरी करें, तो देखें, क्या होता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (ग्रलीपुर) : रण में ब्लैक-मार्केटिंग करने वालों को गोली से उड़ा दिया जाता है।

श्री सूरज पाण्डेय : ठीक यही सवाल से भी गोबिन्द सहाय ने किया था, जब कि वह उत्तर प्रदेश में मंत्री थे। मैं उस वक्त जेलखाने में बन्द था । उन्होंने मुझ से पूछा कि अगर आपका जेलखाना होगा, तो मेरे साथ क्या करेंगे। मैंने कहा कि हम आप को जेल में मलाई तो खिलायेंगे नहीं, हम गोली मार देंगे, लेकिन उसके लिए जन-समर्थन चाहिए । अगर कोई देश-द्रोही और गहार है. तो सरकार में हिम्मत चाहिए कि उसको जेल में बन्द कर दे, लेकिन जिन लोगों को यह सरकार गद्दार कह कर बन्द करना चाहती है अगर वह उनको बन्द करेगी, तो उसका आसन कावम नहीं रहेगा, देश की जनता उसको उठा कर फेंक देगी, क्योंकि इस सरकार को देश में समर्थन प्राप्त नहीं है। जहां तक रूस का सम्बन्ध है, वहां पर ब्लैक-मार्केटिंग और चोर-बाजारी का सवाल ही नहीं है। रूस में तो ऐंसी सरकार है, जिस ने बहुत पहले ही उन समस्याओं का समाधान कर लिया, जिन को यह सरकार अभी तक हल नहीं कर पाई है।

इस सरकार ने अभी भाषा का बिल पास किया है। क्या वह बता सकती है कि भाषा के बारे में उसकी नीति क्या है? इन बीस बरसों में वह कोई भाषा नीति निर्धारित नहीं कर पाई, कोई आर्थिक प्राग्राम नहीं दे सकी, गरीब जनता के सवालों को हल नहीं कर सकी. राष्ट्रीय सवालों को हल नहीं कर सकी। तो फिर वह देश में एकता कैसे कायम कर सकती है ? सरकार को इस काले और रही कानन को तुरन्त वापस ले लेना चाहिए। मैं कांग्रेस के सदस्यों से कहंगा कि वे भी इसी कानुन में बन्द होंगे, कम से कम श्री शिवनारायण तो जरूर बन्द होंगे। सवाल किसी पार्टी का नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गद्दारी करता है, तो सरकार उसको जरूर फांसी लगा दे, लेकिन एक वंग सा कानुन बना कर एकता की बात करना ठीक नहीं है।

अगर यह सरकार मिल-मालिकों के पक्ष में रहेगी, देश के लोगों के हित में काम नहीं करेगी और कोई भी नीति निर्धारित नहीं करेगी, तो वह देश में एकता कैसे कायम रख सकेगी? महाराष्ट्र में शिव सेना किस ने कायम कर रखीं है? बंगाल में अत्याचार कौन कर रहा है? अगर बंगाल की जनता वर्तमान शासन को पसन्द नहीं करती है, तो यह सरकार उसको फौज के बल पर कायम रखना चाहती है। इस स्थिति में जनता में असन्तोष रहेगा और जब लोगों में असन्तोष बढ़ता है, तो वे कानुनों की परवाह नहीं करते हैं।

श्री वाजपेयी ने कहा है कि मन्त्री महोदय खच्चर पर चढ़ गए हैं। हमारे यहां खेत को ठीक करने के लिए हेंगा होता है। एक आदमी हेंगा लेने के लिए गया और छः महीने के बाद लौटा, जब कि खेती का मौसम खत्म हो चुका था। में समझता हूं कि मन्त्री जी खच्चर पर भी सबार नहीं हैं। वह तो हेंगे पर सवार हैं जो इस वक्त आया है, जब कि उसकी कोई खरूरत नहीं है। इस से देश का कोई काम नहीं बनेगा। सरकार इस बिल को बापस ले और देश के लोगों में यह भावना उत्पन्न करे कि अपने व्यवहार, विचारों और नीतियों से कि देश की एकता कायम रहे। कानून के बल पर देश में एकता कायम नहीं रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

SHRI AMIYANATH BOSE (Arambagh): Mr. Chairman, Sir, as a person who opposed the Congress in the last election, and who does not wish today the Congress to continue in the Government, but also as a person who seeks to strengthen the integration of the country. I support this measure with some qualifications.—(Interruptions) I support this measure with certain qualifications which I shall state presently. Firstly...

SHRI S. M. BANERJEE: Netaji.

SHRI AMIYANATH BOSE: Mr. Banerjee, please do not talk of Netaji. It is you and the communist party who called Netaji a quisling and a traitor. (Interruption).

MR. CHAIRMAN · Will Mr. Amiyanath Bose kindly come nearer the mike? His speech is not audible to the reporters.

SHRI AMIYANATH BOSE: Mr. Chairman, Sir, I will deal firstly, with your permission, with the legal aspect of the problem. Firstly, is it a measure which is unconstitutional? I do not want to argue in detail the constitutional problems, because I am not arguing before a court of law, But an Assembly which determines the law should be told by a person who has some experience of legal affairs that this is not in any way unconstitutional. I fully endorse the opinion of the Attorney-General that reasonable restrictions are permissible under article 19 of our Constitution.

Secondly, the other very important point is, is there any law in force in India today which deals or can deal with forces of disruption in our country? Examine the Indian Penal Code carefully. There is no law which can effectively—(Interruption)—there is no law in our country which can

#### [Shri Amiya Nath Bose]

deal effectively with persons who are trying to secode or plead for secession of any part of our country. It is easy to say that you can bring a law of treason, but we have not yet got that law in our country. Therefore I say this law deals with two very important crimes : one is an attempt to secode from India and the other an attempt to cede a part of the country to a foreign country. The only thing that I will tell the Home Minister is this: there should be an appeal to a Bench of the high Court of the State concerned. Let us be quite frank. There today considerable corruption in our country, corruption which has affected the entire public life and the social fabric of our land. I will say this, as a person practising in the different courts of our country, that if there is any institution which till this day commands the universal respect of our country, it is the judiciary of our land. Therefore, I shall appeal to the Home Minister to introduce a measure into this Bill whereby an appeal to the high court concerned can be provided.

SHRI S. M. BANERJEE: He would not accept it.

SHRI AMIYANATH BOSE: I know Mr. Banerjee is anxious because I am now coming to the political aspect of the problem.

Let us be quite frank. We are living in a world where we must examine the inter national policy of certain countries which are contiguous to our lands. Let us examine the history of Pakistan. When I visited Badshah Khan in March this year, he told me something. He said, "you must always remember that Pakistan was born out of hatred for India and any concession to Pakistan of any kind will only increase Pakistan's desire to destroy your country." The principle we must follow regarding Pakistan is this: I shall repeat what Mr. Winston Churchill said about England, "What we have, we must hold". We have almost destroyed India. Mr. Chavan and the party he belongs to were primarily responsible for bringing about the partition of our country. Let us not destroy India further. Let us not give one inch of our land in Kashmir or anywhere else to Pakistan. Let us recover from China what we have lost.

It is necessary that we must tell the people of India—we shall hold every inch of the Indian soil. It is necessary that we must deal with Pakistan and China firmly because they are trying to subvert our country. Let us be quite frank. There are people in Bengal who have openly declared their allegiance to China.

#### SOME HON. MEMBERS: Shame.

SHRI AMIYANATH BOSE: I remind the House of the 2nd October incident, when Mr. Ajoy Mukherjee intended to resign. I carried on two month's election campaign along with Mr. Ajoy Mukherjee from the same constituency. He deafeated the Chief Minister, Mr. P. C. Sen and I defeated the Congress Finance Minister, Shri Sachin Choudhury from the constituency, except this that Ajoy Babu had a majority of 800 only whereas I had majority of 8,000 in the same Assembly constituency. From 17th to 21st October I toured my constituency, going from village to village. Let me tell you, the people there are suspecious of persons belonging to the Marxist Communist Party. I do not know whether officials the Marxist Communist Part is involved. I have no evidence-Certainly the CPI is not involved. (Inter-. rrtions). But there are persons inside the Marxist Communits Pary who were and are openly declaring their allegiance to China and the people of Arambagh, Goghat, Purusurah and Khankul, whom I contacted during those five days, detest these treacherous people of Bengal. At the same time, I warn Congressmen. There has not been and there today is not any pro-Congress feeling in Bengal. People of Bengal donot like the Congress. But, they hate those who want to become traitors to India. That. is the political position.

It is necessary that for integration, we must train the people to think in terms of India. To borrow a phrase from Netaji, we must drill them to think in terms of one nation.

At the same time, it is Netaji who said, in one of his famous speeches delivered in Germany during the war, on free India and her problems, that we must bring in laws so that we can deal with disruptors ruthlessly and with determination. Therefore, it is

necessary, while we have certainly to develop national consciousness, we have to develop national integration, that we must be ruthless with those who want to destroy the unity of India, we must be ruthless with those who want to see that a portion of India goes or who want to destroy or disrupt the unity of this country.

With these words, Sir, I say give the judiciary a higher position in the Bill. Let the confidence of the people be roused. Let an appeal be provided to the different High Courts and, if necessary, even to the Supreme Court of India. But it is necessary that laws are brought in which will bring those persons who want to subvert the unity and subvert the integrity of India to book. They must be punished severely. It is necessary that those laws must be brought in.

With these words and with these qualifications, Sir, I support the measure.

SHRI R. BARUA (Jorhat): Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Bill. At the very out set, I wish to point out that the Bill is very limited in scope. It only tries to deal with unlawful activities of a limited character, which are intended, or support any claim to bring about on any ground whatsoever the cession of a part of the territory of India or the secession of a part of the territory of India from the Union or which incites any individual or group of individuals to bring about such cession or secession. Therefore, I see no reason why so much anger should be expressed against the provisions of this Bill.

It may be said that this Bill was not necessary in view of the existing law of the country. But, as was already pointed out by Shri Amiyanath Bose, the existing provision of the law does not effectively deal with these secessionist and disruptive forces that are growing in this country. Today as you know, in some parts of India secessionist forces have come up. We have got the experience of it in Mizoland. In other places also there is a move to organise parties on a regional basis with an idea to secede from India. It is a dangerous trend and unless Government is fortified with adequate powers it may not be possible for the existing law to deal with these organisations or individuals. So long we were under the Defence of India Rules. It is not happy for

the country to always depend upon such rules. The sooner we get rid of it the better. Once the Defence of India Rules are abrogated there is nothing to deal with these forces. Therefore, it is in the fitness of things that this Bill has been brought forward.

The next argument brought forward is that it limits the fundamental rights as provided by the Constitution. As was rightly pointed out by the Attorney General, it is a reasonable restriction on the fundamental rights and it is within the competence of the State to formulate laws within that limited provision. Sir, disruption is one thing and secession from the Union of India is another thing.

Here the restriction is supposed to be on the right to secede from the country. This is a reasonable restriction and it in no way offends against the Constitution. Therefore, to say that the government has something to muzzle public opinion is wrong. Government want power to deal with a party or an individual who intends, or acts in a way, to give a part of the country to a foreign country by cutting it out completely from the Union of India. Therefore, it is absolutely within the reasonable restrictions mentioned in the Constitution itself.

The second argument that is normally flung is that the Government's notification comes first and the decision of the Tribunal next. It has been argued with some force: how is it that the government comes up with the notification, declaring a certain association to be unlawful, and then the case goes to the tribunal. When it is a question of the integrity and safety of the country, government cannot wait indefinitely, say for two, three or six months to declare an association unlawful, after getting the verdict of the tribunal. Even in normal cases we always find that the prosecution starts action first. Here it being a case affecting the integrity of the country, government should have the right to issue the notification first, as has been provided here.

The only objection can be that instead of giving the jurisdiction to the High Court, the government keeps to itself the right of declaring a certain High Court Judge to be the tribunal. It is up to the government to see whether, through the medium of

#### [Shri R. Barua]

the rules, it can be left to the High Court to provide two or three Judges to deal with the matter or they should themselves notify. As has been suggested in some circles, I would also prefer that the tribunal, instead of being constituted by a notification, there should be a provision whereby the High Court, of its own initiative, can sit in judgement of course within the rules prescribed here. If, however, no rule is made and it is absolutely left to the High Court, I am afraid the final judgement would not come within the six months period prescribed here and it will take a long time, as is now happening in the case of so many cases in the various High Courts. Therefore, the difficulty can be obviated only if some rule can be made to see that the High Court, while having jurisdiction to deal with the matter on its own, has to deliver the judgement within the time limit prescibed.

Lastly, I would submit that it will be wrong to presume that the Act is intended to fall upon certain political parties. apart from political parties there are other forces that are coming up. Therefore, it is in the fitness of things that government comes up with legislation, arming itself with sufficient powers to cope with any situation or contingency. After the improvements made by the Select Committee, I find there is very little objection to the provisions of the Bill. If we really mean business when we say that the Defence of India Rules should not be there in the country for a long time to come, in view of the conditions obtaining in the country it is very much necessary that Parliament provides the government with sufficient powers to deal with disruptive forces. With these words, I support the measure.

भी जार्ज फरनेन्डीख (बम्बई-दक्षिण): सभापित महोदय, जब इस कानून पर ज्वाएंट कमेटी में बहस चल रही थी तब ऐटार्नी जनरल दफ्तरी साहब ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह कहा था:

"This Bill is not perfectly constitutional.

I say it is constitutional."

दुर्भाग्य तो यह है कि यह दोनों वाक्यों का क्याफर्कवह करना चाहते हैं वह प्रश्न उन से नहीं पूछा गया लेकिन एक बता बिल्कुल साफ है कि इस मुल्क के सब से बड़े कानूनी अधिकारी इस सरकार को यह कहते हैं कि यह कानून परफैक्टली पूर्णतया तो कांस्टीट्यूशनल नहीं है वह सिर्फ कांस्टीट्यूशनल है।

दूसरी बात उन्हीं के साक्षरी में पेज 8 पर यह है:

"There was a time in the beginning when the fundamental rights were quite firm. Then came a period when they were eroded and gradually article 14 almost ceased to exist. Then again came a period when the fundamental rights were put up firmly and everything was properly tested. Perhaps we are again coming to a period when they will not be looked at as seriously as they used to be."

इस सब से एक बात बिल्कुल साफ है। कांग्रेस पार्टी विचारों की टक्कर में इस मुल्क में हार रही है और उसी के कारण यह दल अब ऐसे कानून की शरण लेना चाहता है जो इस मुल्क में प्रजातन्त्र को आहिस्ता-आहिस्ता खत्म कर दे। क्या लिखते हैं कानून में। बुनियादी तौर पर अनलाफुल एक्टिविटीज और अनलाफुल एसोसिएकन, दोनों का प्रश्न इस में आ जाता है। अनलाफुल एक्टिविटीज कौन सी? कोई भी एक्टिविटी

"which is intended, or supports any claim, to bring about on any ground whatsoever the cession of a part of the territory of India or the secession of a part of the territory of India."

और अनलाफुल एसोसिएशन कौन? इस-किस्म की कार्यवाही का समयंन करने वाली वह अनलाफुल एसोसिएशन। में चव्हाण साहब से पूछना चाहता हूं कि इस मुल्क में कौन से दल के पास यह अधिकार है इस वक्त कि हिन्दुस्तान की भूमि के किसी भी भाग को, किसी भी हिस्से को उठा कर दूसरे किसी भी मुल्क को देने का काम वह कर सकता है। मेरे दल के पास नहीं है। यहां अलग-असग अपोजीशन पार्टीज के दल हैं, उनके पास नहीं है। अगर किसी भी दल के पास अधिकार हैं तो वह वही दल हो सकता है जोकि सरकार में बैठता है और वह दल चव्हाण साहब का अपना दल है, कांग्रेस पार्टी है। कितनी चालाकी इन्होंने इस कानून में की है। दफा 13 में उनके लिए तो छूट दे दी गई है। सब -क्लास 3 आप देखें। इस में लिखा हुआ है:

"Nothing in this section shall apply to any treaty, agreement or convention entered into between the Government of India and the Government of any other country or to any negotiations therefore carried on by any person authorised in this behalf by the Government of India,"

कौन गवर्नमेंट आफ इंडिया? कांग्रेस पार्टी ही गवर्नमेंट आफ इंडिया है? इस वक्त। इसको कहने से काम नहीं चलेगा कि जो नौकर-शाह हैं, वे सरकार हैं। सरकार आपकी है, आपके दल की है। मतलब इतना ही होगा कि कांग्रेस पार्टी इस मुल्क के हिस्सों को दूसरे मुल्कों को दे सकती है। ऐसा करने की उसको छूट है। हमारे नेता मधु लिमये साहब ने ज्वायंट कमेटी के सामने जो तरमीम पेश की थी कि किसी भी नागरिक को यह अधिकार रहे कि अगर सरकार अथवा दूसरी कोई भी संस्था हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से को दूसरे मुल्क को देने का कार्य करती है तो उसके क्रपर कोई भी नागरिक मुकदमा चला सकता. है। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को इसका अधाकर रहना चाहिए। इस संशोधन को आपने तब कबूल नहीं किया था। अब तो वह संशोधन मेंने पेश किया है और मुझे देखना है कि आप उसको मानते हैं या. नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो इसका साफ मतलब होगा कि जो डर हम लोग इस सदन में और सदन के बाहर भी हमेशा व्यक्त करते हैं कि कांग्रेस दल को खत्म करने के लिए चूंकि विचारों की सड़ाई में आप हारे हैं और हार रहे हैं, इसलिए इस तरह के कानून को चाते हैं, उसका पूरा पूरा सबूत मिल जाएगा।

जब जब रोटी की बात यहां की जाती है और और यह कानून हमारे सामने पेश किया जाता है तो मैं गृह मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि वह एक या दो दलों के नाम तो लें, एक या दो संस्थाओं के नाम तो लें जिन के विरुद्ध वे इस कानून के भाषार पर तत्काल कोई कार्रकाई करने जा रहे हैं। भगर वे नाम नहीं बता सकते हैं तो यह कानून किस लिए?

पिछले कई महीनों से इस पर बहुस चली मा रही है, सदन की कमेटी भी इस के लिए बनी थी भौर मैं समझता हूं कि मुल्क का करोड़ों रुपया इस पर खर्च हुआ है वह बेस्ट है। यह कानून भापके सामनें जो सतरा है उससे बचाने के लिए ग्राप ला रहे हैं। इसकी कोई जरुरत नहीं है। डिफेंस आफ इप्डिया रुलज आप के पास हैं। वे बहुत खतरनाक हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट **भाष के** पास है। इंडियन पीनल कोड भ्रापके पास है, किमिनल प्रोसीजर कोड म्रापके पास है। जो भी कानून ग्राप चाहते हैं वे सब ग्रापके पास हैं। भ्रापको बताना चाहिए कि भ्रापकी नजर में इस वक्त ऐसी कौन सी संस्वाएं है जिन के लिए घाज जो कानून हमारे पास है वे पूरे नहीं उतरते हैं, उन से पूरा नहीं पड़ता है। भापको कारण बताने चाहिए इस कानून को लानें के भौर यह भी बताना चाहिए कि तत्काल इसकी ग्रापको किस के विरुद्ध ग्रमल में लाना है।

भगर भाप किसी दल का नाम नहीं बता सकते हैं तो मैं एक दल का नाम दे सकता हूं जिस के विरुद्ध कार्रवाई भाप कर सकते हैं भगर अप में हिम्मत हो तो उस दल का नाम है कांग्रेस पार्टी। चृंकि यह भाप की खुद की संस्था है इस वास्ते भाप सब से पहले इस कानून का प्रयोग भपनें खुद के खिलाफ़ कैसे कर सकते हैं? मैं भापको बताता हूं कि क्यों इसके विरुद्ध भमल में लाना चाहिए। मैं भापसे जानना चाहता हूं कि कौन सा दल है जिस नें हाजीपीर को

## [बी जार्ज फरनेन्डीज]

जोकि हमारा घपना एक देश का हिस्सा है, बापिस ले कर पाकिस्तान को दे दिया? मैं पूछना चाहता हं कि इसको वापिस नेने के लिए कितने हमारे जवान मारे गए? क्या आप इसको नहीं मानते कि पाकिस्तान के हाय में भाज जो काश्मीर का हिस्सा है वह भारत की भमि है घौर क्यों घापने उस हिस्से को पाकिस्तान को दिया, किन कारणों से दिया ? जब हमारे जवान वहां मर रहे थे उस वक्त भाप में से कितनें खत्म होने के लिए भीर मिट जाने के लिए तैयार थे? कच्छ के रन को श्राप लें। वह भारत की भिम है। उन्नीस साम तक किसी नें कोई प्रवन नहीं उठाया था इंग्निस्तान के प्रधान मन्त्री विलसन के कहने पर पाकिस्तान के साथ सौदा करने के लिए ग्राप क्यों तैयार हुए, क्यों घार्बिट्रेशन को घापने माना। साढ़े तीन हजार वर्ग मील भूमि में से ऐसा दिखाई पड़ता है कि दो ढाई हजार वर्ग मील हम लोगों के हाय से जाने वाली है। भाप लोगों के कारनामों की वजह से । क्या धाप तैयार हैं सजा भगतने के लिए? वक्हाण साहब को याद होना चाहिए कि जब चीन ने पहली बार आक्रमण किया था तब हमारे पहले प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने कहा था कि अपनी भूमि के बारे में और चव्हाण साहब को बह याद भी होगा कि---

Not a man lives there not a blade of grass grows there.

अपनी भूमि के बारे में आपके दल के सब से बड़े नेता के मुंह से ये शब्द निकले थे। किस को इस मुल्क की सावरेन्टी की चिन्ता है? क्या इस दल को है? इस दल ने इस मुल्क की सावरेन्टी की बात को कभी सोचा ही नहीं। अत्यन्त नम्प्रता के साथ में चव्हाण साहब से कहता हूं कि मेरे सामने तो एक ही दल है जिसके ऊपर आप इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं और वह आपका ही दल है। लेकिन आप में कभी भी हिम्मत नहीं हो सकती है कि इसके विरुद्ध आप इस कानून का प्रयोग करें।

इंटेग्नेशन बाले हिस्से पर आप आयें। इंटेन्नेशन बालीं बात पर आप आ जाएं। मुल्क की इंटेग्नेशन की क्या डेफ़ीनीशन है। 15 सम्बर बसे पर आपने कहा है:

"Integrity is oneness of the county, not honesty; integrity actually means oneness and undivided. Personally speaking, the term integrity is wider than territorial integrity."

नाख इस मुल्क की इंटैग्नेशन को खत्म करने वाला कौन-सा दल है? इसको भी मुझे युह-मन्त्री से सुनना है। में उन के इस दल का नाम चाहता हुं। कौन-सा दल तमिल-नाड में है, दक्षिण में है, महाराष्ट्र में है, उत्तरी हिन्दुस्तान में है। अगर आप किसी दल का नाम नहीं बता सकते हैं तो मैं घापको बताता हं। ग्रगर यहां भी किसी कसौटी को लगाना है तो पिछले बीस साल से घापकी जो ग्राविक नीतियां रही हैं, विकास सम्बन्धी जो नीतियां रही हैं उनको घाप लगाएं। उन नीतियों के कारण ही हिन्द्स्तान के ट्कड़े होनें जैसी परिस्थितियों का निर्माण हवा है। श्रापकी नीतियों की बजह से ही सबे सबे में धाज लडाईयां होती है, एक सुबे का घादमी दूसरे सुबे में नहीं जा सकता है। इसके कुछ कारण हैं। एक परसेंट खमीन है हिन्दुस्तान की केरल में। चार परसेंट हिन्दुस्तान की घाबादी केरल में बसती है। लेकिन दस परसेंट हिन्दुस्तान को निर्यात व्यापार से कमाई केरल से होती है। लेकिन घाप देखें कि केरल पर पहली पंचवर्षीय योजना में सौ रूपया में 37 वैसे ही घापने घौद्योगिक विकास के लिए लर्ज किए। दूसरी योजना में 87 पैसे सौ रुपए में सर्च किए। तीसरी योजना में 1 रुपया 87 पैसे 100 रुपएे में खर्च किए । यही हालत बिहार की है, यही हालत उड़ीसा की है, यही हालत दक्षिण की भीर मुल्क के दूसरे सूबों की है। जो विकास होता है यह कहां होता है? जो मैट्रोपालिटन सेंटर्स हैं, बम्बई है, कल-कत्ता है, दिल्ली है, मद्रास है, बंगजीर है या जो औद्योगिक केन्द्र हैं वहां पर आप मुल्क के विकास का सारा पैसा लगा देते हो । महाराष्ट

में 3 प्रतिसत औद्योगिक विकास की रकम लगी हुई है । करीव करीव इतनी ही बंगाल में लगी हुई है और बची हुई रकम बड़े-

बंगाल में लगी हुई है और बची हुई रकम बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों में लगा देते हैं। लेकिन देहातों के बारे में या उन सूबों के बारे में बहां पर लोग खिक खिनत से खान से नहीं लड़ पाते उन के बिकास के लिए बापने नहीं सोचा और नतीजा वह हो रहा है कि सूबे सूबे में बाब झगड़े हो रहे हैं और इन झगड़ों की चबह से मुल्क का इंटीग्रिटी पर खतरा ना बाता है जिस का जिक दफ्तरी लाहब ने किया है। इसलिए कार्य-वाही करनी हो तो अपने ही दल पर करनी होगी। और कोई दल इस इंटीग्रिटी वाले मामले में आ ही नहीं सकता है।

16 hrs.

एक ही आखिरी बात कह कर में खत्म करूंगा कि हमें आज गन में सचमुच यह डर है कि और इस कानून का विरोध करते हुए में यह डर व्यक्त कर देना चाहता हूं क्योंकि, कुछ सब्त भी हम लोगों के हाथों में है। हमें ऐसा डर लग रहा है अध्यक्ष महोदय कि आहिस्ता-आहिस्ता प्रजातन्त्र को बिल्कुल खत्म करने वाली बात हो रही है। पल्टन के साथ बातचीत कभी कभी चलती है यहां पर। विदेश तक में वाकर कांग्रेस दल के लोग बोल रहे हैं कि कुनार नंगलम साहब पर विश्वास नहीं है इसलिए चुप बैठे हैं, जरा एक बार इन को खत्म होने दीजिए फिर देखिए कि हम क्या करने वाले हैं ? विदेशों तक जाकर यह बातें हो रही हैं, बिरोधी दल के लोग नहीं बोल रहे हैं और यह बोलना तभी हो जाता है जब कपरी गृट के लोगों में कुछ बहस होती है और मैं चाहंगा कि जब इंटर पालियामेंट्री युनियन का अधिवेशन हुआ पाल्म-द-मेलोरा में, स्पेन में तो कांग्रेस पार्टी के कौन लोग वहां गए थे, उन की बह्वाण साहब जांच करें, उन में से किसी व्यक्ति ने बिदेश के किन व्यक्तियों के साथ इस पल्टनी कार्यवाही के बारे में बात-**बीत बलाबी ? इस की बांब करें, क्योंकि यह** बहुत यंभीर मामले होते जा रहे हैं।

इसलिए में कहना चाहता हूं कि जब हुकूमतशाही इस मुल्क में प्रचातंत्र को खत्म कर के एक दल की और वह भी उस दल की जो साम्राज्यवाद की समर्थक है, साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ हाथ मिला कर अपनी ही हुकूमत इस देश में चलाने के प्रधास में हो तो आज यह इशारा देना बहुत जरूरी है और खास तौर से चहुाण साहब जैसे लोगों को जैसा कि बिजियम पेन ने कहा था:

"As William Penn said," Democracy dies in the hearts of dexocrats before it dies in the hands of the dictator."

SHRI VIKRAM CHAND MAHA-JAN (Chamba) : The present Unlawful Activities (Prevention) Bill is the most timely legislation which could have been brought in the present circumstances which are prevalent in the country. The object of the Bill is to curb the activities which would lead to cession or secession or disruption of the country. Now the question is whether this Bill will suppress an expression of honest opinion or it will suppress an activity which would lead to cession or secession or disruption. One of the hon. members said that if anybody expresses an honest opinion that such and such a thing should be done, this Bill would suppress even that particular act. My submission is that the hon. Member has not carefully read the definition of 'unlawful activity'. The definition of 'unlawful activity' specifies that if anybody organizes an activity which leads to this particular act being a cession or secession or disruption or which incites the disruption of the country, that would be covered by the 'unlawful activity' but not the honest expression of an opinion or a sugges-

Then, they have said that it would infringe the Fundamental Rights as envisaged in article 19 of the Constitution.

Even Art. 19 of the Constitution says, you have a right to organize activity which is for the benefit of the country, you have freedom of association and freedom of expression. But the question is: does this freedom of expression include the freedom to organize activity which would lead to the disruption or secession of the country? Now it will

7886

## [Shri Vikram Chand Mahajan]

be a strange argument that you can use fundamental rights for the purpose of creating disruption in the country or inciting an activity which would lead to secession. Fundamental rights can only be used for the benefit and development of the country and not for the disintegration of the country. Therefore, the argument that it would be hit by Art. 19 of the Constitution seems to be due to an elementary lack of knowledge of Art. 19 of the Constitution and the Constitution of India. Constitution of India cannot be used for the purposes of disrupting the country and the object of this Bill is to prevent disruption of the country and not to suppress the legitimate grievances or legitimate opinion or expression of opinion within the country. Therefore, my submission is that this Bill is not hit by Art. 19 of the Constitution.

Then they have said that Cl. 3(3) of the Bill specifically gives power to the Government and the executive to declare any organization unlawful without getting the sanction of the Tribunal. Sir, there are always certain emergencies when one has to act without going through the normal procedure. For example, even under the Criminal Procedure Code, if a policeman apprehends a thief, immediately he has the power to detain him for a certain number of hours or a certain number of days without going to the court of law.

AN HON. MEMBER: How long can be detain him ?

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN: 24 hours in one case and two days in another case. Similarly, under the Criminal Procedure Code you can search the house of any particular person only with the sanction of the Magistrate. But there is an exception provided in Sec. 165 which says that you can search the house of a person in an emergency without taking the sanction of the Magistrate, but, subsequently you must go to the Magistrate and have it validated. Similarly, a provision is made under this Act that in an emergency you can take an action, but, subsequently you must go to the Tribunal and justify your action. Therefore, my submission is that it is protected by the Act, it is legal and it is not arbitrary as has been made out by some hon. Members.

Then another argument is put forth that there is no right to appeal and, therefore, it is arbitrary. My learned friend should carefully read the Constitution of India. Under the Constitution of India the decision of any Tribunal, whatever it is, is subject to the decision of the High Court under Art. 226 and no Act of any legislature can abrogate that right which is given under the Constitution. No Bill can abrogate that power given under the Constitution. My learned friend may kindly read the provision of Art. 226 of the Constitution.

Similarly, the Supreme Court has the power to hear appeal directly from any Tribunal even if the Bill has barred the right to go to a Court. What is barred is the right to go to a Civil Court under the Civil Procedure. Code, but not the right given under the Constitution to go to the High Court. My learned friends should read certain provisions of the Constitution before they say that the right is even barred under the Constitution. No power of any legislature can bar the right given under the Constitution to go to a court of law unless the Constitution itself is amended. Therefore, my submission is that the right of appeal is sufficiently safeguarded. Then some points have been made out....

KRISHNAMOORTHI: SHRI V. Whether the restriction is reasonable or not, kindly tell us ?

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN: Question raised is: whether the restrictions are reasonable or not. Once you give the power to the judiciary to examine a particular act, automatically you presume that the judiciary will act impartially and once it acts impartially and once the opinion of the judiciary is there.....

KRISHNAMOORTHY: SHRI But nothing prevents Perliament to discuss and judge whether it is reasonable or not.

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN: You have not followed what I have said. If you intentionally want to close your mind and keep on pursuing one line of thought, then, of course, you cannot follow. Once you give power to a judge to decide a case and he has to act judicially, you presume the impartiality of that judge. Once you assume that he will act impartially, the

arbitrariness goes. You can only act arbitrarily if you do not act judicially. Once you are acting judicially you cannot act arbitrarily, and rationality is there. This is my line of argument and thought.

Another argument has been put forward namely that Sheikh Abdullah was acting against the interest of the country but now he is being released and that by itself shows that Government are not acting in accordance with the spirit of the Bill. I would submit that in the Bill itself it is provided that one who indulges in unlawful activity will get a specific punishment, that is two years or three years or seven years but not perpetually. Sheikh Abdullah may have acted against the interests of the country but even under this Bill the punishment is for a certain number of years only. If he is let off now and he again acts against the interests of the country, he can again be put back in prison under the Bill. So, my submission is that the Bill is sufficiently comprehensive and it does not give arbitrary power to Government, and, therefore I support the Bill.

SHRI VISWANATHA MENON (Ernaculam): On behalf of my party I oppose this Bill. We have tabled two amendments; one seeks to refer the matter through the President to the Supreme Court under article 143, and the other seeks to have it circulated for eliciting opinion thereon. I shall now explain why we have given these two amendments.

The Joint Committee has examined this Bill only generally, and even the evidence of the Attorney-General does not give the sanction for the constitutional uprightness of this Bill. Moreover, there are some States with non-Congress Governments in power. The States have not been consulted about this particular Bill which is going to affect the entire nation.

If one reads the evidence of the Attorney-General, one would find it crystal clear that he is not convinced whether the restrictions sought to be imposed under this Bill are reasonable or not; he is still not sure about it. That point has been clearly brought out in the evidence when my leader Shri P. Ramamurti had put him the question. I would quote from the evidence in this con-

nection. The relevant portion is as follows:

"Shri P Ramamurti: But the Government in certain circumstances is authorised to do certain things. Therefore, in a democracy, people can certainly ask the Government to do a thing in a particular way. How is it unlawful?

Shri Daphthari : I agree. It did not strike me then.

So, I would like to emphasise that the Attorney General had to agree with my leader on that particular point in the course of his evidence. Since he was honest before the committee he had to agree that the restrictions sought to be imposed under this Bill were unreasonable.

Therefore, we have suggested that before we pass this illegal Bill, it is better that we refer the matter through the President to the Supreme Court under article 143 and also get the opinion of other eminent jurists in the country. But we find that somehow or other, Government want to pass it. I would like to know what the urgency is for passing this immediately.

Already my DMK friends have said that they have given up the idea of secession. Then why this Bill. ? Is it because a particular area of the country is trying to secode? If it is a question of dealing with the Naga hostiles or the Mizo hostiles, I do not think this Bill will help in solving that problem. Now in India two Prime Ministers are functioning, one Prime Minister of Underground Nagas and another Prime Minister here. Without solving that question politically, we are not going to have a solution of that problem at all and this Bill is not going to be useful for that, either to deal with the problem of Nagas or the problem of Mizos or any border problem.

#### 16.15 hrs.

## [MR. DEPUTY-SPEAKER in the chair]

On the question of the border problems, I want to make it clear that my Party's stand has always been to solve the problem by mutual discussion and settlement with Chiaa and with Pakistan.

AN HON. MEMBER: What about Naxalbari?

SHRI VISWANATHA MENON: I am coming to that.

[Shri Viswanatha Menon]

These problems should be settled on the basis of give and take. I want to make one thing clear. The question of getting back Azad Kashmir or Aksai Chin cannot be solved by means of this Bill. This Bill is not enough for that. Something more is needed. But of that there is no indication in this Bill.

Coming to the Bill itself, I want to draw the attention of the House to one particular point. Under the provisions of the Bill, when an association is unlawful, it is its bounden duty to come forward with evidence to refute the charge. This is a principle no body can understand. If an accused is put before the court, we know that it is the bounden duty of the prosecution to prove the charge. But here the prosecution has nothing to do, it has only to accuse a body of being unlawful and it is upon that body to prove the contrary.

Somehow or other they want to ban certain organisations by passing this Bill. I am sure Government are going to act immediately and efficiently so as to curb important opposition parties in this country. It may hit our Party. We do not mind, because we have worked in illegality and legality. This is nothing new for us. But it may affect other democratic parties as well. If they want to curb any party, they can use this weapon. Working against sovereignty is a vague term, working against integrity is another vague term. Any opposition party can be curbed by making use of this.

Here I want to draw your attention to what happened. When emergency was declared and DIR came into force, in 1964, we were all arrested in Kerala. For what? They were saying that we were working against the nation. But actually for what purpose? There was a mid-term election in the offing. Somehow the Congress Party wanted to keep us in jail and damage our reputation. But what happened? The elections were held. All the leaders who were put in jail were elected. Then they thought it better to release us.

Somehow or other the Government want to cling to power. I am sure that this Bill is going to hit West Bengal. I am sure they would put the Opposition leaders inside

jail somehow or other. If they are so sincere about their democratic principles, I challege them to have a mid-term election in West Bengal. Then we can see whether the actions taken by the UF Ministry were correct or not, were in the interest of the people or not. Let us put our trust in the people and let them decide. But for doing that, this Bill is not necessary. If they want to preach to the people against us, why don't they do it? We know their arguments because we know the background. In Kerala, during the election time, from every nook and corner, Shri Nanda and other leaders of the Congress Party spoke against us branding us as 'Chinese spies'. But the people elected me and other leaders of my party. We, the MPs from Kerala, belonging to our party were detenus in 1964-65-66. Why are they resorting to such tactics? Why not fight the issue politically? We are saying that you have to settle the border problem peacefully. Talk China, talk with Pakistan, that is our slogan. Even if this Bill is passed because of your brute majority, we will say so because we love the people of Inda. That is the only solution. If you want to solve it, you have to do it. You have to settle it today or tomorrow, you will be forced to do it. We will say that, we will preach that, and we are going to do that.

About this Bill, I have to say one thing more. The learned member was trying to impress us with the jurisdiction of the High Court and the Supreme Court. We know the scope of appellate jurisdiction, and we know the scope of writ jurisdiction Why not give this appellate jurisdiction to the court? Why not an appeal provision be included in this Bill as Mr. Amiyanath Bose suggested? Why not the proceedings in the tribunal be changed to that of a Sessions Court or High Court and have criminal proceedings ? Then difficulty will come. Under the Evidence Act it is not easy to prove anybody guilty. So, they will have their own man as tribunal, and everybody will be put up and convicted, they will be put for seven years in jail.

Putting people in jail will not solve any problem. If it could solve the problem, India would have been under the British even now. A number of persons were put in jail, were hanged, but what happened finally? India got its freedom. Just like that these repressive measures are not the solution. That I want to make clear and impress on my Congress friends.

This is not the solution for all these things. If you have got a political policy, go to the people, preach before the people, let us fight it out that way, without putting persons in jail.

Sheikh Abdullah has been put in jail for 13 or 14 years. Now, if he comes out, I assure you he will get a better reception than these Kashmiri Ministers, Mr. Qureshi or Mr. Karan Singh. He will be called by his old name the Lion of Kashmir.

Ideology cannot be crushed by repression. If your are against his ideas you propagate it. If you are aganist my opinion, propagate it, and let us face the electorate. You are not prepared to face the electorate of Bengal. If you face the electorate of Bengal, I challenge you, your Dr. P. C. Ghosh will lose his deposit. That is going to happen.

My humble submission to Mr. Chavan and the Government is that by this Bill you are not going to crush the democratic movement of this country. You may declare an organisation to be illegal. I became a communist in 1940 when the Communist Party was an illegal party, and afterwards it was declared illegal twice. you may declare it illegal hereafter also, we do not mind. In 1940 the Communist Party was a small thing. Now you know we have got some States at least.

With these words, I oppose this Bill.

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur): I have no end of sympathy for the Home Minister because he has already been under fire for nine days, and on account of this Bill he is again having to face the slings and arrows of the opposition.

But I want to say one thing to my opposition friends, and I say that in all sincerity, and I hope they will listen to me with as much attention as I listened to them. They are utterly mistaken if they think that this Bill is meant to curb the lawful activities of any party in this country. It is not a fetter that is being forged to be placed on the legs of any member of any party in this country.

This Bill is a kind of handshake offered to the parties; it is a kind of warm embrace of friendship offered to the opposition parties; it is a kind of friendly gesture to the opposition parties. What is all this about? It is not there to put down the legal and constitutional agitation or propaganda or the right of assembly or the right of preaching of any recognised party. It is only meant for those persons who, under the cover of some name or connotation, try to subvert the unity of India; try to make it possible for the foreigners to come here and grab our territory; make it possible forthose persons whose hearts are not with us-by saying "with us" I do not mean the Congress-to come and disrupt the integrity of this country. Therefore, I do not think any Member of any opposition party has to be afraid of this Bill. One great philosopher has said : "You have nothing to lose but your chains; workers of the world, unite : you have nothing to lose but your chains."

SHRI S. M. BANERJEE: You will be the gainers.'

SHRI D. C. SHARMA: I say to my Opposition friends, "Do not be afraid. You have nothing to lose by voting for this Bill." Because it is meant for the underground movement, the subterranean movement, for the people who talk one thing in public and say another thing when surrounded by the walls of a chamber; and they show their hands of friendship to the Home Minister but their hands are poisoned, and they bare their iron claws. This is meant for them. (Interruption).

Well, Mr. Banerjee is a good friend of mine. I can assure thim that while he may have some trouble at the hands of the Kanpur people he cannot have any trouble at the hands of the Home Minister. Are there not forces of disruption in Kashmir? An hon. Member spoke very highly of the people of Kashmir. I speak highly of the people of Jammu and Kashmir. I belong to Jammu and Kashmir. Pandit Jawaharlal Nehru could not buy an inch of land there but I can buy as much land there as I like if possible, because I tell you I am a citizen if Jammu and Kashmir. I have some stake there.

AN HON. MEMBER: How much land?

SHRI D. C. SHARMA: I will give you all that land. Do not bother about it. Sir. I was respectfully submitting: can any body deny there are forces in Jammu and Kashmir which are trying to disrupt the lawfully constituted government of any body I do not bother about the person who is the Chief Minister of that State. Are there not forces in the Punjab which are trying to see to it that Punjab also becomes another Kashmir or something like that ? They want that article 373 should be applied to Punjab as it applied to the State of Jammu and Kashmir at one time. Are there not forces in West Bengal? My friend was asking, why can't you fight an election ? My friend, we know the art of fighting an election; we know the art of winning the election.

We also know the art of lossing elections gracefully. But we do not talk, like that.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash): You also know the art of purchasing votes.

SHRI D. C. SHARMA: Nobody purchases anybody. But I know there are some agents of foreign Governments in this country who try to sabotage our country.

Here is West Bengal. What was the slogan there ?

आमार बार्डः तोमार बार्डः नक्लसबार्डः ।

Do the people of Naxalbari believe in the integrity of India? Have they any faith in the unity of India? Do they believe that India should remain one?

आमार नाम तोमार नाम वियटनःम । चीन के माओ को लाल सलाम ।।

Why are these slogans being shouted in West Bengal. It is because there are certain forces working in India at this time which try to undermine the India that has been built by the sacrifice of all of us, including the opposition members. We are all partners in the building of India. No-body can deny it.

I was very glad to hear the DMK member saying that they do not want to secede from India. But they may have another feeling tomorrow and a diffrent feeling the day after tomorrow about secession.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI Mr. Sharma also may say that Kashmir should go to Pakistan tomorrow.

श्री कमलनयन बजाज : पूरा हिन्दुस्तान पाकिस्तान में चला जाय तो कोई एतराज नहीं है।

SHRI V. KRISHNAMOORTHI: You are a capitalist and you want to rule the country by capitalism, (Interruptions)

SHRI KAMALNAYAN BAJAJ: We do not have extra terrtorial loyalties.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI: You are the agents of American capitalism.

SHRI KAMALNAYAN BAJAJ: I am not the agent of anybody. (Interruptions).

I have created wealth in the country and I am proud of it. Even if you want to do it, you cannot do it.

SHRI D. C. SHARMA: I agree that you have created wealth, but why don't you distribute it among the members of the opposition party and others also (I nterriptions)

Sir, politics is a game of change. It is not a game of unchanging loyalities, unchanging policies or unchanging programmes. I know that as long as Mr. Annadurai is Chief Minister of Madras, Madras is safe. I have no doubt about it. As long as Dr. P. C. Ghosh is there in West Bengal, West Bengal is safe. But we are surrounded on all sides by people who do not mean well to us. One of the minutes of dissent given by an hon, member from the south has made me say that there is need for a Bill of this kind. Otherwise, India will be torn into pieces. India will be a land of divided lovalties. disunited territories and a balkanised land. What has he said ? He has said that Mansarover is ours, Kailas is ours, Bara Hoti is ours, Longju is ours and other territories which are at present in the illegal possession of some other powers like the Chinese are ours. How can we get back those territories which my friend calls ours and which I also call ours. We can get back those territories only if we put the fear of God into the hearts of these who try to

sabvert us, who fan out all over the border, who make speeches, who distribute arms, who give away ill-gotten funds of other countries. What are the funds of the China Bank? Why dose not the Government lay on the Table of the House the accounts of the China Bank, who get funds of other countries and distribute them so that India does not remain India, India becomes a satellite of some other power, it becomes a territory of some other nation.

Sir, without going into the constitutional question, which has been answered by Mr. Daftary himself, without going into the other questions, I appeal to my hon. friends that this Bill is meant to help them and me, it is not meant to be some kind of a dagger at them, it is meant to be a kind of handshake with them and therefore they should all welcome it.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) 1 Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to oppose this Unlawful Activities (Prevention) Biff, 1967. After carefully giving through the provisions and also the notes of dissent given by hon. Members, and after going through the Report of the Joint Committee I have no hesitation to come to the conclusion that this Government can use this weapon to suppress the political activities of unarmed associations in this country which are in existence under the Constitution. Therefore, I would like to say that this Bill is most undemocratic and obnoxious and it has no semblance of any democratic virtue. As such this has to be thrown out on the ground that it is undemocratic and the provisions of the Bill do not attract the common sense of anybody in this country. It creates confusion and at can be utilised against the political parties and their activities at any time by a Home Minister like Shri Chavan. We have been carefully watching the behaviour of the Congress during the last twenty years. We have been seeing how far these provisions and their democratic values have been respected under this regime we know how this Government has taken vengeance when non-Congress governments have been installed by the people after this election.

We can also say that the constitutional powers have been abused and misused by the government, specially since Shri

Chavan has been holding this portfolio of Home Ministry and I warn this government that they must be prepared for and a coup against this government, if they rule this country like dictators, bringing in this kind of obnoxious legislation to suppress and oppress the democratic values and virtues in this country. Has this government got any moral courage to defend this Bill when they have misused the powers under the Constitution, making use of the office of Governors, to sabotage the non-Congress governments which were established and installed in power by the people during the 1967 elections? After observing the behaviour of the Congress Government for the last twenty years we have no hestitation in coming to the conclusion that this government is not for democracy and this government is not going to attach any values to democracy and the democratic principles.

Article 19 of the Constitution envisages freedom of association, freedom of trade and freedom of movement but, under the guise of this law, by the passing of this legislation, they want to take away all the rights guaranteed by the Constitution and impose restrictions in their place. Is it democracy? Harold Laski has said that in a democratic country any restriction by way of legislation is the negation of democracy. I would like to remind this government that this piece of legislation will definitely take away the rights guaranteed by article 19 of the Constitution. The freedom which has been envisaged in various walks of life by the Constitution in article 19 will be taken away by this Bill and the party in power will use these powers for political vengeance.

At the time of war, whether it be with Pakistan or China, we have witnessed how the people of this country stood as one and waged a war against the aggressors. It is the people who fought for freedom at the time of aggression. What were the Congress people doing? They were beggling in this country and all over the world because they have not produced any wealth in this country. They have not at all defended the Constitution properly.

Incidentally, I would like to mention here, because it is relevant, what is happening in my part of the country. It is a matter of Unlawful

[Shri K. Lakkappa]

shame how the Congress Government in Mysore abused the powers, made use of the police for committing atrocities, thereby creating a law and order problem, which has been under fire in the Mysore Assembly. Now the Chief Minister of Mysore has agreed for a judicial enquiry.

Today there was a newsitem in the papers that the Home Minister of Mysore has tendered his resignation.

What is the value, the moral value, this government is attaching to the provisions of the Constitution? Further, where is the necessity for bringing this legislation ? We have any number of laws on the subject. We have got sections 112 and 122 of the Indian Panel Code which provide ample power to check, the waging of war against India, unlawful activities in India, to suppress the atrocities committed in India. The police has wide powers, so also the military to take action to defend our country, our nation, to defend the honour of this country. Then, where is the necessary for bringing in this kind of obnoxious legislation ipso facto? The Attorney-General, Shri Dapthari, has clearly stated during the course of his evidence that we cannot say how far these restrictions are reasonable, so far as article 19 is concerned.

"Reasonable restriction" is a point to be argued on both sides. The Congress to remain in power for a long time can make use of "reasonable restrictions" and can exercise it over other political parties and they can remove any association which is in existence under the authority of law by calling it "unlawful activity." They can also sabotage the reasonable trade union movement in this country and thereby they can give a go-by to democracy. The Congress raj that we have observed for these 20 years is nugatory of democracy.

It has been said that the DMK pleads for Dravida Nad. What dose Shri Chavan plead for ? For Maharashtra. Shri Chavan, being the Home Minister, has no respect for democracy. He behaves in such a way that he wants to maintain the territorial integrity of Maharashtra. He wants to wage any war he likes because he is having power.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH):
That is not correct.

SHRI K. LAKKAPPA: See the way in this Government behaved in the Mysore-Maharashtra boundary dispute. And they say that they want to maintain the honour of this country, that they want to defend national integrity and territorial integrity. It is the military, the Indian jawans, who fought for freedom and for maintaining the integrity of India, not these Congress people. Even today if anybody or any association, even in the absence of this Bill, starts any activity against India, all the Indian people will fight against that.

Why is the hon. Home Minister afraid new? It is because he has now had an experience that at any moment the people can instal non-Congress governments throughout India. Therefore he wants to make use of this Bill so that all the democratic values and virtues would be given a go-by.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member's time is up.

SHRI K. LAKKAPPA: Just five minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your party's time is limited. Now you should conclude in half a minute.

SHR1 K. LAKKAPPA: Now, the executive authority is to declare an association unlawful. Let the Home Minister accept that before an executive authority declares that it is unlawful it will be referred to the High Court. Let there be a declaration from the High Court; let the highest judiciary in the country say that it is an unlawful activity. Before that he has no right to declare that it is unlawful. But this Government, which has got so much suspicion in its mind, wants to exercise and invoke this power to see that every lawful association is illegal.

Therefore my submission is that this Bill is obnoxious in nature and undemocratic in character and I would like to say that it be put in the cold storage even if it is passed or the Home Minister should withdraw the Bill.

बी सीताराम केसरी (कटिहार): उपा-ध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक इस हाउस में उपस्थित है उसके समर्थन में मैं भी कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हुं। आज जो मुल्क की अवस्था है और जो घटनायें इधर 5-6 महीनों में घटी हैं उन को महेनजर रखते हुये और जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं और विघटन-कारी तत्वों ने जो इस देश की अखंडता पर एक आभात किया है उसको महेनजर रखते हुये जो विधेयक हमारे गृह मंत्री जी ने उपस्थित किया है उसके पोछे एक औ चत्य है। अप एक बार बंगाल की ओर दुष्टिपात करें। नक्सल-बाड़ी में जो घटनायें घटी, हिन्द्स्तान के कुछ भागों में जो घटनायें घट रही हैं, अभी हमारे दोस्त ने कहा कि लोग हमें कहते हैं कि हम चीन के समर्थक हैं मगर हम तो इस द्वाउस में चुन कर चले आये मुझे पता नहीं कि उन्हें क्यों इस बात का गर्व है जो अभी उन्होंने कहा है . . . . . .

SHRI VISHWANATHA MENON I I said, "We are called"; I did not say that.

**भी सीताराम केसरी :** अर्भा मेरे दोस्त ने कहा कि फिर भी मुझे जनता द्वारा चुन कर यहां भेजा गया है। इस बात पर उन्हें बड़ा गवं है कि 1940 में भी वह कम्युनिस्ट पार्टी के मैम्बर थे। बहुत से कम्युनिस्ट पार्टी के मैम्बर 1930 और 1934 से मेरे दोस्त हैं। श्री रामावतार मास्त्री मेरे दोस्त हैं। मैं जानता हूं कि जिस तरह से उनके अन्दर राष्ट्रीय भावना कुट कुट कर भरी हुई है, किस तरह से आजादी हासिल करने के लिए अग्नि उनके अन्दर प्रज्जविलत होती रही है। हमारे मित्र कहते हैं कि उन्हें गर्ब है कि वह 1940 में कम्युनिस्ट पार्टी के मैम्बर ये। यह वह समय या जबकि अंग्रेजी राज के **खिलाफ अंग्रेजों** के खिलाफ हमने जंग लडी थी। लेकिन आपको याद होगा कि तब इन लोगों ने ही बंधेजों के साथ दोस्ती की थी। क्या अंग्रे**जों** के साथ दोस्ती करने पर इनको गर्व है ? यही मैम्बर आज चीन के समर्थक है। तब भी गर्व के साथ ये कहते हैं कि मैं चुन कर आया हूं।

मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे दोस्त यहां चुन कर आए हैं। उनके जो विचार हैं उनको रखने के लिए, उनको व्यक्त करने के लिए वह स्वतन्त्र है। यहां उनको अपने विचारों का प्रचार करने की स्वाधीनता मिली हुई है, जन मानस को प्रभावित करने के लिए वे अपने विचार जनता के सामने रख सकते हैं. इसकी उनको आजादी है। जनता पर वे अपना प्रभाव भी जमा सकते हैं। जनता द्वारा निर्वा-चित किये जाने पर वह यहां आए हैं, यह ठीक है। लेकिन क्या वह इस बत को नहीं जानते हैं हैं कि माओं का फोटो ले कर बंगाल में, कलकत्ता में, वहां की सडकों पर इनकी पार्टी के सदस्य चले हैं, माओ का फोटो स्टेज पर लगा कर उन्होंने भाषण किये हैं ? इस तरह की इजाजत इनको नहीं दी जा सकती है। इस करह की स्वाधीनता भी उनको यहां नहीं दी जा सकती है कि ट्रेंन को वे रोकें और पैसें अर्थ को कहें कि तुम यहां माओ का फोटो टागो, बर्ना ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। नक्सलबाड़ी में किसानों के यहां जाकर उनके धान को लुटने की इजाजत उनको नहीं दी जा सकती है। वहां जाकर उनको कहें कि तुम कम्यनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं होगे तो तुम्हें तंग करेंगे, इसकी अज्ञा नहीं दी जा सकती है। लोगों को वहां पर यात्नायें देने की आजादी उनको नहीं दी जा सकता है। बोलेने की आजादी अगर दी जाती है जो इसका मतलब यह भी है कि दूसरों की आजादी की भी आप रक्षा करें। जब कानून को हाथ में लिया जाता है और दूसरों की स्वाधीनता को छीनने की कोशिश की जाती है तब इस-तरह की जो चीजें हैं इन पर रोक लगाना ही इस विधेयक का उद्देश्य है--

भी कंबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मंत्री महोदय ने कहा था कि माओ के जो पोस्टर लगाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमरे पास कोई कानून नहीं है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। लेकिन कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं।

SHR! NAMBIAR (Tiruchirappalli): He did not say that. (Interruption) We dispute that; we question that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him continue.

ची चंदर साल गुप्त : अ।इंदा भी नहीं लदायेंगे, कभी नहीं लगायेंगे ?

SHRI NAMBIAR: It is being repeatedly said and it is being repeatedly denied. I again deny, on behalf of my Party, that we never put up Mao's photograph. Do you want me to repeat it hundred times? I can repeat it hundred times.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Nambiar, you should remeber that repetition never always carries conviction. (Interruption) Lot him conclude.

SHRI NAMBIAR: What can I do? It is being repeated in our very face. I can deny it any number of times.

बी सीताराम केसरी : मैं यह कह रहा या कि देश को आजादी और देश की अखंडता की बनाये रखने के लिए इस कानन की सकत जरूरत है। असली बात यह है कि माओ का फोटो अगर घर में टांगें और आप कहें कि उनके विचार, उनका उद्देश्य, उनकी नीति आपके चरित्र में रिफ्लैक्ट नहीं होती है तो इसको कोई मान नहीं सकता है। मैं आप से पूछता चाहता हुं कि आप देश को अखंडता चाहते हैं या नहीं। भारत में आपको स्वाधीनता है। जो आप चाहें बोल सकते हैं। लेकिन चीन में आपको यह स्वाधीनता नहीं मिल सकती है। वहां आप देखें क्या हो रहा है। वहां इस तरह विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता नहीं है। मैं कहंगा कि जब इनका पर्दाफाश हो तो इनको षबराना नहीं चाहिये। जो चुनौती है उसको आप स्वीकार करें। केरल में गलत प्रचार करके आप चन कर आए हैं इसलिए आप कहते हैं कि मैं चीन का समर्थक हुं और फिर भी चुन कर आया हूं, तभी आप यहां बैठे हुए हैं। हमने जनतंत्र को अपनाया है इसलिए आपको यहां बोलने का अधिकार प्राप्त है।

जो अराजक तत्व हैं, जो इस तरह के तत्व हैं जोकि दूसरे देशों क समर्थन करते हैं उन पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये, उन पर नियंत्रण लगाया जना चाहिये। देश की अखंडता खतरे में पड़ी रही है। अभी जो विधेयक हमने पास किया है, लेंगुएज बिल हमने पास किया है उसको ले कर उत्तर प्रदेश में, बिहार में तथा दूसरी जगहों पर जो घटनायें घटित हुई हैं, जो खून खराबा हुआ है, वह नहीं होना चाहिये था। अराजक तत्वों ने इन हिंसक कार्यों को करवाया है। इस तरह जब अराजक तत्व सिर उठाते हैं तो देश की अखंडता 'पर, देश की एकता पर आषात होता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थेन करता हुं।

SHRI NAMBIAR I I want to clarify

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has already made his position clear.

SHRI NAMBIAR: Our Party is being implicated; otherwise, I would not get up. He can scold me, if he wants, but I am sure that he will not want it. He can even beat me, but I know he would not like to do that. Because my Party is being implicated, I have to say this. What Mr. Menon said was that even after his being accused as a communist, a pro-China man, which was not true, he got duly elected......(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have followed his speech. He need not expalin.

Mr. Swell (Interruptions)

SHRI SWELL (Autonomous Districts): I think, I shall begin by telling the Home Minister that I have no quarrel with him in so far as the objective of this Bill is concerned, and I do not think that there is anybody in this House who has any difference with him with regard to the need to safeguard and maintain the sovereignty and integrity of this country. I do not think that he harbours in his mind an seri ous suspicion about the bona fides, about the patriotism, of any Member of this House. But I consider certain provisions of

7904

this Bill to be obnoxious, liable to abuse; they may defeat the very purpose of the Bill and may convert this Government into a machine of oppression.

Within the very limited time at my disposal, I think I should best do by posing a number of questions to the Home Minister and I would like him to satisfy me by providing answers to those questions before I make up my mind whether this Bill is worth supporting.

He has defined 'unlawful activity' as any action whether by committing an act or by words, either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise, which is intended, or supports any claim, to bring about on any ground whatsoever the cession of a part of the territory of India or the secession of a part of the territory of India from the Union of which incites any individual or group or individuals to bring about such cession or secession.

#### 17 HRS.

Sir, I would like him to satisfy me on this point: where does honest expression of opinion and mobilisation of public opinion end and where does incitement begin ? Sir, situated as we are to-day, our relationship with our neighbours, whether it is Pakistan or China or Burma, is the biggest factor for the peace and progress of this country, for the stability of this part of the world and for the peace and progress of the world as a whole. And this Government to which the Home Minister belongs, all these years, for the last 20 years, has again and again underlined this fact. When the Chinese seized Aksai Chin and built a road over that area, which we claim to be ours, we kept silent about it. When Pakistan demanded certain areas of ours we agreed to hand over Beru Bari in West Bengal to them. When Pakistan to-day sits over two-thirds of Kashmir territory which we claim to be ours, we keep silent about it and during the Indo-Pakistan conflict when we were able to recover some portions of our territory in Kashmir, when we took Haji Pir pass, under the influence of Russia and under the Tashkent agreement we agreed to withdraw from Haji Pir pass. And, to-day, when the Chinese, whether it is at Long Ju or Bara Hoti or Ladakh, are sitting over wide areas of our territory, we keep silent about it. Why?

That is because of that policy which we have pursued-peaceful settlement of our disputes with our neighbours through negotiations. That is what this Government has been doing. If to-day or tomorrow there is anybody or any section of opinion in this country which really and honestly feels that going to war with Pakistan or going to war with China, would not serve the interests of this country, would do great harm to this country, that a peaceful negotiation should be entered upon for the settlement of certain boundaries, whether with Pakistan or with China, and in a democratic country where we live it is not enough to give an opinion on a matter and if I know this Government, an honest opinion honestly expressed does not go very far with them, mass mobilisation to bring pressure to influence the opinion is necessary-if there is such a sizeable section of our people in the country to-day who come forward and try to mobilse public opinion in order to bring democratic pressure upon the Government not to go to war but to try to settle certain boundary disputes peacefully would that be an incitement or an honest expression of opinion? If you try by this Bill to curb that democratic freedom of the people of this country to mobilise public opinion, is that what you consider to be a reasonable restriction ?

Then, Sir, I strongly object to the invidious nature of this Bill. What the Government themselves have the liberty to do, they would deny that right to the other people of this country. I would invite your attention to another provision of this Bill at 13 (3) which says:

"Nothing in this section shall apply to any treaty, agreement or convention entered into between the Government of India and the Government of any other country or to any negotiations therefor carried on by any person authorised in this behalf by the Government of India."

It follows that if the Government of India today feel that certain areas of our country, should be handed over to Pakistan or to China in the interests of peace, they are free to do so; in fact, somebody in this House today has made a reference to certain remarks made by the late Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru when he referred to certain areas in the Himalayas as places

## [Shri Swell]

where no man lived and not a blade of grass grew and implied thereby that it was not worth-while for us to involve the whole country in a war with a great country like China. Again, recently there has been a lot of criticism of the action of the Prime Minister when she flew over Kashmir and Pakistan on her way to Russia and sent a message of goodwill and congratulations to President Ayub Khan over the completion of the Mangla Dam. This dam is situated in that part of our territory in Kashmir which we say is forcibly occupied by Pakistan. I appreciate her desire and honest intention to try to live in peace with Pakistan, or with China. She could do it as Prime Minister. But if I as an individual would do the same thing I would be hauled up under the provisions of this Bill. When the Prime Minister does it, it is all legal, but not when I as an individual citizen do it. I am saying again that I am not finding fault with the Prime Minister for what she did. But what I object to is this, namely the effort sought to be made in this Bill to draw un invidious distinction, to create two classes of citizens in this country, those who are in Government and who can sell away the whole country in the name of an agreement with a foreign country, in the name of conventions and in the name of negotiations and the rest of the people in the country who are deprived of the democratic right to express their honest opinions.

I would put this question to the Home Minister. If he is honest in his intention he should at least do away with this kind of distinction that he seeks to make in this Bill.

SHRI KAMAL NAYAN BAJAJ :
On a point of clarification......

SHRI SWELL: I am not yielding.

SHRI KAMAL NAYAN BAJAJ: The hon. Member has said that this is the honest opinion that there should be a peaceful settlement with China on the boundary question.....That could be an honest opinion. But is this also an honest opinion of his that China made no aggression on India. This is what I would like to know from him.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not yielding. If Shri Kamal Nayan Bajaj wants I shall give him an opportunity afterwards. Shri Swell has just been explaining a particular clause and pointing out how it would be invidious in its operation. That was his only contention. Beyond that, there was nothing else.

SHRI SWELL: Lastly, I would put this question to the Home Minister, Clause 16 of this Bill prevents the citizens of this country who has been deprived of his freedom from making an appeal to the highest court of judiciary in the country. I question the constitutionality of this provision. The Home Minister, when he moved for consideration of this Bill this morning said that it was constitutional, and he said that the exceptions to article 19 of the Constitution permitted him to bring forward this Bill. But I would question him again under article 32 of the Constitution which says:

"The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed."

This is the right given to every citizen of this country to move the Supreme Court. But the Bill here says that no proceedings under this Act can be called in question in any court.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI: The Bill is illegal.

SHRI SWELL: Whether this is constitutional, whether this is legal is the point.

Because of these obnoxious provisions, as I say, I cannot support the Bill as it is.

श्री शिव नारायण : (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि इस सरकार के पास हम ने एमरजेन्सी पावर्स दे रखी हैं, लेकिन ये उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं । आपकी एपीजमेन्ट की पासिसी का यह प्रतिफल है कि आज इतनी गासियां इस सरकार को सुननी पड़ती हैं । आज जो उपद्रव देश के चारों तरफ हो रहे हैं, वे किसी से छिपे नहीं हैं । आज जो हम ,अन-सा फुल एक्टिविटीख का बिल लाये हैं, इसका उहेश्य यही है कि इन गैरकानूनी कार्मों को

रोका जाय। मैं नहीं समझता कि इस सदन में कोई ऐसा भी सदस्य है जो यह न चाहता हो कि इन गैर कानूनी कामों को न रोका जाय। मेरे मित्र स्वेल साहब ने भी यही कहा है कि अगर इसमें थोड़ा हेर-फेर कर दिया जाय तो वे भी इस बिल का स्वागत करेंगे। विरोधी दल होने के नाते मैं उनकी इस बात से एग्रीड हूं कि विरोध में कुछ न कुछ तो कहना ही चाहिये लेकिन बिल के इस प्रिन्सिपल से वह एग्रीड हैं। आज इस मुल्क में अपनो-आमान कायम करने के लिये यह आवश्यक था कि इस विल को यहां लाया जाता। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इस हाउस को एशोरेन्स दिया हुआ है कि दिसम्बर के बाद हम एमरजेन्सी पावर्स की ड्राप कर देंगे, लेकिन आज जो नंगा नाच बंगाल में हो रहा है, जो नंगा नाच काश्मीर में हो रहा है, जिस नंगा नाच की केरल में तैयारी हो रही है, मैं होम मिनिस्टर साहब को सावधान करना चाहता हूं कि और पुरजोर शब्दों में सावधान करना चाहता हूं कि केरल यें क्या-क्या तैयारियां हो रही हैं। यह भाषा का प्रश्न नहीं है,यह राज-नीतिक प्रश्न है। विदेशी माल पर, विदेशी पैसे पर आज जो खिलवाड़ इस देश में हो रहा है, इस देश की राजनीति से, इस देश की स्वतन्त्रता के साय जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिये।

मेरे दोस्त सन् 40 से कम्युनिस्ट हैं, लेकिन वह भूल गये कि 1942 में आपने क्या कहा था—इन लोगों ने उस वक्त अंग्रेओं के साथ हाथ मिलाया था—कहा था—दिस इज पियुपिल्ज वार—आज वे लोग देशभिक्त का बड़ा दम भरते हैं। मैं उका नाम नहीं लेना वाहता हूं जिन्होंने उस जमाने में एजन्टी की थी, लेकिन आज चौहान साहव को उपदेश देते हैं, डांट बताते हैं —उनको शर्म आनी चाहिये, जो आज देश के टुकड़े करना चाहते हैं, इस देश को बेचना चाहते हैं। मैं इसी लिये होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि ओ कानून आप बतायें, उसका इस्तेमाल कीजिये—शठेशाठ्यम समचारेत्—राजनीति में रियायत

नहीं की जाती, यही पाठ हमें चाणक्य ने इस देश में पढ़ाया है। मैं श्री कृष्ण का भक्त हुं, उन्होंने गीता जैसी महान पुस्तक हम को दी है, जिस पर जर्मनी नाज करता है, जिस पर हिटलर नाज करता था । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे चह्नाण साहब कोई मामूली होम मिनिस्टर नहीं हैं, मजबूत आदमी हैं---इसी लिये आप उन को गालिया देते हो, क्यों कि वे सजग हैं। मैं चह्वाण साहब से कहना चाहता हूं कि इस देश की एकता इन्टीप्रिटि, इस की नैशनल प्रेस्टिज को रखना आपका धर्म है, अगर नहीं रखोगे, तो इतिहास में आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जायेगा, अगर बन जाओगे, तो आप की पूजा होगी। आप सरदार पटेल की जगह पर बैठे हए हो, जिसने हिन्दुस्तान की 600 रियासतों को एक जगह मिलाया था---इस-लिये मैं आपसे आशा रखता हं कि आप इस देश को एक सूत्र में बांधोगे, इस की ऊंचा उठाओंगे, इस देश के गरीबों को प्रोटेक्शन दोगे।

हम गरीब हैं, हमारी गरीब जनता पर आज बड़ा जुल्म होता है। हम यह कानून बना कर तुम्हारे हाय में अधिकार दे रहे हैं, इस से बड़ा हमारी ईमानदारी का सुबूत और क्या हो सकता है-अाप चाहें गाजियाबाद से निकलने के बाद हम को बन्द कर सकते हो, इसमें कोई रुकावट नहीं है। होम मिनिस्टर इस में कुछ भी नहीं कर सकेंगे । लेकिन आप **इन की** मिनिस्ट्री के नमुने देखिये---हम तो 20 वर्ष में करप्ट हुये, लेकिन ये लोग तो 9 महीने में ही करप्ट हो गये, देश के कोने-कोने में इनकी थ-थ हो रही है। हरियाणा में क्या हुआ आपके सामने है । मैं इनको वैलेंज करता हूं --हरियाणा के चुनाव में देख लेना, मैं भी मैदान में उत<del>रूंगा---- और आपको मालुम हो जाये</del>गा कि आप की इस मिनिस्ट्री की जनता पर क्या असर पड़ा है।

टु सेफगार्ड सर्विस एक्टिविटीज की बातें जाप करते हैं।—लेकिन कहीं से कबस जाता है, कहीं माओ का पैसा आता है, कहीं

## [श्री शिव नारायण]

माओ की तसवीर दिखाई जाती है-वड़े शर्म की बात है--मैं अगर होम मिनिस्टर होता उस दिन गोली चलवा देता . . . . . . व्यवधान . . . . . इनको इन्डोनेशिया भिजवा देता । यह वह देश है जिसके सिये भगतसिंह, राजगुरु और सुख देव ने कुर्वानी दी, इसी पालियामेंट में भगत सिंह ने बम मारा था और फिर हंसते-हंसते फासी के तखते पर चढ़ गया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी ऐसे प्रदेश से आता ह जहां चोरा-चोरी की घटना हुई थी, जहां कामल नेहरू के सिर पर लाठियां बरसाई गई थीं, जहां जवाहरलाल नेहरू 19 वर्ष तक जेल में रहे। हमारे उन घावों पर नमक न छिड़ किये। जब हम बोलत हैं, तो आपको परेशानी होने लगती है। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि आप इस देश के प्रोटेक्टर बन कर आये हैं, इस देश की रक्षा करें, जो भी कानून बनायें, उस का सही मायनों में इस्तेमाल करें।

मैं निम्बयार साहब से अपील करूंगा कि मैं आप से कम हुल्लड़बाज नहीं हूं, अगर आप एक डिस्टर्ब करेंगे तो हम चार कर सकते हैं, आप एक जगह अड्चन डालेंगे, हम पच्चीस जगह डालेंगे। इस कानून को हम देश में कम्युनिज्म को प्रिवेन्ट करने के लिये लाये हैं ताकि देश में हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े न हों। ये पोलिटी-शियन्ज जो उनकी भावनाओं का लाभ उठाकर गेम खेलते हैं। --ये जनसंघ के बड़े नेता, जिन्होंने कहा कि इस कानून में गड़बड़ी है, वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वे भी अन-ला-फुल एक्टीविटीज में हिस्सा लेते हैं इसिलये इसका विरोध कर रहे हैं। अन-ला-कृम एक्टीविटीज तो ये जितने यहां अपोजीशन में भाई लोग बैठे हैं, ये सब करते हैं, गलत काम करते हैं। कभी रेलवे उड़वा देंगे, कभी कहते हैं किसी का घर लुटवा देंगे--- उत्तर प्रदेश में कहा गया कि कांग्रेसियों के घर लुटवा देंगे हमारे प्रेजिडेन्ट कमलापति विपाठी और सी॰ बी॰ गुप्ता के लिये कहा गया कि उन का वर फुंकवा देंगे --- इस प्रकार की धमकियां

वी जा रही हैं, लेकिन मैं केरल के उस प्रोफेसर की तारीफ करता हूं जिस ने कहा है कि हम उच्चर प्रदेश को हिन्दी पढ़ायेंगे । इसका नाम है एकता लाना । मैं मद्रास भी गया थे पी०ए०सी० की मीटिंग में गया था, वहां मैंने गांव-गांव में जाकर पता लगाया--मैंने देखा कि वहां पर हिन्दी पढ़ाई जा रही है, लड़के और लड़कियां बहां पर हिन्दी सीख रहे हैं। बैनर्जी साहब ने तो अपना इन्तजाम कर लिया है, केरल के स्रोग हिन्दी पढ़ रहे हैं---मैसुर के लोग हिन्दी पढ़ रहे हैं, आन्ध्र में पढ़ रहे हैं-मैं वहां उन के तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं। किसी पर कोई दबाव नहीं डाला गया है। हम किसी पर हिन्दी लादना नहीं चाहते, जिसकी तिबयत हो पढ़े, न चाहे न पड़े । मुझे खुशी है कि हम कहीं पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के लोनों से प्रार्थना करूंगा कि यह तुम्हारी इयूटी है कि ऐसी एक्टीविटीज न कराओ कि कस जब तुम इधार और हम उधर बैठें तीजिस प्रकार की कार्यवाहियां आज तुम कर खडे हो, उस से ज्यादा हम करने लगें। आपने 9 महीने में ही अपनी प्रेस्टिज को खो दिया है। अगर आप लोगों ने इस असे में बेस्ट एक्टी-विटीज की होती तो आज जनता आफ्के साथ होती। बंगाल में डेमोक्रेसी के मुंह पर किस ने घूंसा मारा, वहां पर अन-सा-फूल एक्टीविटीज हमने नहीं की थीं, इन सोगों ने की थीं। वहां पर आज जो चीफ मिनिस्टर है, वह कांग्रेसी नहीं है, उसने कांग्रेस छोड़ कर प्रोग्रेसिव पार्टी बनाई थी। जब अमिय बोस बोल रहे थे, तब बैनर्जी साहब कूदने सगे। उनको मालूम नहीं कि वह सुभाष बाबू का भतीजा है. उसकी रगों में सुभाष बाबू का खुन घूम रहा है, ऐसी जोर का थप्पड़ मारा कि आपका दिमाग ठीक हो गया।

17·15 Hrs.

[SHRI G. S. DHELLON in the Chair]

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने अन्दर डीलेपन को मत आने दीजिये, इस कानून का सही माइनों में इस्तेमाल की जिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हं।

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : Mr. Chairman, Sir, after the very able legal arguments advanced by Mr. Sheo Narain in support of the Bill, I wish to say a few words. The gist of the Bill is this. The hon. Home Minister thinks that he has introduced this Bill in order to combat unlawful activities in this country. affecting the sovereignty and integrity of this country, but all the supporters who spoke about the Bill pointed out to a single party this side and said this Bill is intended against them. Why this kind of confusion has arisen in the party led by the Home Minister, we are not able to understand, but I leave that party aside.

In the Minutes of Dissent here, I find strong dissenting notes given by Mr. Madhu Limaye who does not belong to that party; and Mr. Prakash Vir Shastri who also does not belong to that party. Likewise the D.M.K. has opposed it. And today, I found that the Swatantra party also has objected to it. Therefore, in order to understand the true import of this, it is much better not to think about the aspect of being allergic to any particular party.

The most objectionable feature of this Bill, in my opinion, is the proviso to sub-clause (2) of clause 3, which reads as follows:

"Providing that nothing in this subsection shall require the Central Government to disclose any fact which it considers to be against the public interest to disclose."

Therefore, the huge support given to this Bill on the ground that after all there will be a tribunal composed of a high court judge and therefore one need not bother about this, falls to the ground. The Government need not disclose the grounds at all; further, because it is a tribunal appointed by the Government, we do not know whether the tribunal will be in a position to get all the information from the Government. Even there, the Government might say, "We have not disclosed the grounds, and therefore you are not entitled to ask for the grounds." Now, this tribunal itself is not

a very happy feature. As another hon. Member has said,-

SHRI Y. B. CHAVAN: If I may intervene to make a clarification. The point is that the fact may not be disclosed in the notification, but when it goes before the tribunal, the intention is not to conceal anything from the tribunal, if the tribunal wants to know about it.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: Then, I suppose it can be put clearly that the tribunal will have the power to call for the grounds which are not disclosed. Unless it is made clear, the tribunal would not have that power. Now, the tribunal in itself is not good as provided in the Bill. It is a judge chosen by the Government who will be appointed on the tribunal. You remember that in Ceylon; when the Prime Minister was murdered by somebody, and when a special tribunal was appointed by the Ceylon Government, the lawyer who appeared for the accused took the objection that that was not good and that was not legal, and that it did not satisfy any constitutional conscience. He said it must be left to the high court to appoint a judge. The judge agreed and returned the case. If a judge has got to be appointed to consider such an important matter as this, the choice must be left to the high court; they must appoint whatever judge they like in the exigencies of the work of the high court.

SHRI KAMALANAYAN BAJAJ: What was the decision of the Ceylon Government on that objection?

SHRI TENNETI VISWANATHAM:
You should have some patience. Generally
I do not intervene.

SHRI KAMALANAYAN BAJAJ: It is not a question of intervention. It is because he said that an objection was taken, I wanted to know the result of that objection.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: If he can be patient, I shall tell him. I was quoting the Ceylon case—

SHRI PILOO MODY (Godhra): Sir, he is indulging in unlawful activity!

SHRI KAMALANAYAN BAJAJ: If this is unlawful, then it was also equally unlawful!

SHRI TENNETI VISWANATHAM: I think as students of law we are entitled to look into the decisions given not only in India but in Ceylon, Austria, Italy, England and America. I was only speaking from that point of view. This is an ad hoc tribunal. It is not as if it is a standing tribunal. Suppose a gentleman A is prosecuted and the judgment does not satisfy the requirements of the Government. Next time they may appoint another judge. It gives a sort of uncasiness even in the minds of the judges, "Is it right for us to act under this law or not ?" So, it would have been all right if they have left it to the High Court to appointment whomsoever they might like.

There are certain drafting mistakes. For instance, it says:

"(f) 'unlawful activity', in relation to an individual or association, means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words...." etc.

Action by words is not a happy grammar. That can be changed.

#### Clause 3 says:

"If the Central Government is of opinion ..." It would have been proper if the draftsman at least conceded to the accused that the Goernment is "satisfied" that an association has become unlawful, etc. The word "satisfied" is deliberately omitted. What kind of opinion? There are no guidelines in the section itself, excepting the definition of unlawful activity. Then, there is a proviso that it can be declared unlawful immediately without any other formality. In one case, it may be referred to the tribunal for approval. In the other case it need not be referred to the tribunal. The language is not quite clear. Probably the Home Minister is under the impression that emergent action taken under the proviso to clause 3(3) would also be referred to the tribunal. If that is so, it must be men-It is not so. tioned. In clause 4 which deals with reference to tribunal, it is said :

"Where any association has been declared unlawful by a notification under sub-section (1) of section 3...." You do not refer to notification issued under sub-clause (3). If you want that also to go for the approval of the tribunal that must be mentioned. Otherwise, by implication it is negatived.

Another objectionable feature is that the accused is obliged to prove his case. It is easy to prove something which is positive. But to prove the negative is almost impossible. It is like asking a man to got up on his own shoulders. How can he do it ? If there is any evidence in the hands of the prosecution, they must bring it forward, leaving it to the accused to rebut it in the best way he can. But the Government can simply go with folded hands and say, "I have hauled him up." That man has to prove, "I am not this, not that...." and so on. All the philosophy of Shankaracharya "Neti, Neti, Neti...." cannot prove it. The draftsman might have been tempted by such a provision in laws like the Food Adulteration Act, etc. But there is an article caught hold of by the prosecution and the accused is asked to prove his innocence. Here there is absolutely nothing. Even the grounds need not be disclosed to him. His line of argument has to be, "The Government of India has prosecuted me. 1 am innocent of all the charges that are not disclosed to me". I believe it makes a mockery of law.

According to Government, this is a very important law and unless this is passed, they are not able to tackle the situation in India. Therefore, they want to take this extraordinary power. But it is the Government that must take the responsibility. Instead of the Government taking the responsibility of hauling up a man they want to delegate it to any officer, It will be delegated to an officer who may be of any level or any grade. It is not good. Even under the Defence of India Act unless the Minister actually sees the file and signs it, it would not be legal. The present Bill is more dangerous than even the Preventive Detention Act and provision for delegation of this power to any officer, is a very bad provision. I believe, if this Bill is to be passed it should only be with the amendment whereby the delegation of power to an officer is taken away.

There are some other things. Here it is said: "The Central Government may

by notification in the official gazette constitute when necessary a tribunal..." As I submitted it is not a standing tribunal. The judge may be changed from case to case because he may not be satisfactory to the Government. I do not think the Government will always have a poor opinion of a judge who does not decide a case in their favour. But, all the same, being a tribunal and seeing also the history of appointments and non-appointment of certain persons as tribunals it is legitimate for us to say that that kind of thing should not be perpetrated in this.

In the end, as Shri Swell has pointed out, there is that obnoxious clause, which is there in so many of the Acts passed by the Government of India not only now but for some time, that these proceedings shall not be reviewed by any court and there is no right of appeal. Of course, they say that the power given to the High Courts and the Supreme Court cannot be removed by that section. Why do you insert that section. It is a useless section. This section should not be found in the legislation passed by any democratic parliament. The presence of the section does not bar the Supreme Court or the High Courts from looking into the validity of any of these cases. But it takes away the legitimate right of appeal. Therefore, I submit, unless these obnoxious features are removed the fears expressed by all these parties, not one, may be very real fears and very innocent people may be booked and then there will be no remedy.

Once again, Sir, I endorse the other suggestion that instead of having these tribunals if the Government simply makes an amendment that if they are satisfied that a person is engaging in unlawful activities an order may be served and then he may be given the right to go to the High Court. Then it will be quite all right. But the interposition of the tribunal with limited powers and sometimes with unlimited powers is not good. They say they have got all the powers under the Civil Procedure Code and the Criminal Procedure Code. But, all the same, they may not have those powers also. If the Judge does exercise his powers against the Government he may not be appointed again. That lurking fear may be in the mind of the judge even though he may be a working judge and not a retired judge.

Therefore, what I submit is, on all those points if the Government bestows its attention, this Bill, which is a bad one, can perhaps be improved to some extent and then allay the fears of the various political parties. I am concluding with this sentence that this is not an objection raised by merely the Communist Party here. Although the entire support of the Bill from the Congress side has come as being directed against the condition in Naxalbari, in West Bengal, every other party has objected. Why ? It is because it has got such bad features which are liable to be absued. We know by experience that many laws have been and are being abused by the Executive. Therefore, Sir, I oppose this Bill.

श्री हेम राज (कांगड़ा): मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। यह जो बिल प्रवर समिति से आया है इसका मैं समर्थन करता हूं।

जो वक्ता इस विधेयक पर बोले हैं उनमें अपोजीशन पार्टीज के भी वक्ता थे और कांग्रेस पार्टी के भी थे। कुछ ऐसे वक्ता भी बोले हैं जोकि अनुअटैच्ड हैं. किसी भी पार्टी में नहीं हैं। अपोजीशन पार्टीज के वक्ताओं ने कहा है कि जो उसूल है उसको हम मानते हैं। उनके साय-साथ अनअटैच्ड जो मैम्बर बोले हैं उन्होने भी इस बात को माना है कि देश की सलामती के लिए, देश के इंटे ग्रेशन के लिए, अाज की देश की हालत को महेनजर रखते हुये यह निहायत जरूरी है कि इस बिल को स्पोर्ट किया जाए । कम्यनिस्ट भाइयों को मैं कहना चाहता हं कि यह कांग्रेस सरकार ही है जोकि आपके अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करने का मौका देती है। जहां तक चीन की सरकार का सम्बन्ध है वहां पर भी लोगों को कहा जाता तो है कि आप अपने खयालात का इजहार करें लेकिन अगर कोई आजादी से अपने खयालात का इजहार करता है तो फिर उसकी जान खतर में ही रहती है। लैट ए हंबूड फ्लावर्ज बलुम, नारा तो यह दे दिया जाता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने खया-लात का आजादाना तरीके से इजहार करता है तो उसका सफाया हो जाता है। मैं समझता हं

## [श्री हेमराज]

कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। आप चलते तो हैं गरीबों का सहारा लेकर, यह कह कर कि उनको रोटी चाहिये, कपड़ा चाहिये लेकिन आपके मन में कुछ और ही है। आपके मुंह पर तो राम राम है और बगल में धुरी है। मुंह से तो आप राम राम कहते हैं लेकिन लोगों को ठगने के लिए आगे हो जाते हैं। बगल में आप छुरी रखे हुये हैं। आप हिन्दुस्तान को चाहे चीन का और चाहे रूस का गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार ठीक मौके पर इस बिल को लाई है। जिस तरह के हालात देश में पैदा हो गए हैं उनको देखते हुये यह अजहद जरूरी हो गया है कि इस किस्म की हरकर्तों पर पाबन्दी लगाई जाए । इस प्रकार की हरकतों को ज्यादा देर तक बरदाक्त नहीं किया जा सकता है।

एतराज उठाया जाता है कि यह जो बिल है इस में अपील का राइट नहीं दिया गया है। जिस वक्त यह सवाल होम मिनिस्टर के सामने उठाया गया या उस वक्त उन्होंने यह मंजूर किया था कि किसी रिटायर्ड जज को नहीं लेंगे ताकि किसी किस्म का असर न पढ़ सके। अभी हमारे विश्वनाथन साहब भाषण कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि इसको मान सिया जाना चाहिये कि जज तीन होने चाहिये । यहां से सिर्फ हाई कोर्ट को संदेशा जाएगा और वहां पर यह चीफ जस्टिस पर मुनहसर होगा कि किस को वह भेजते हैं। उन पर कोई पाबन्दी किसी किस्म की नहीं है। बहु जिस को चाहें भेज सकते हैं। उनकी ही ओपीनियन काउंट करेगी, सैंटर की ओपिनियन काउंट नहीं करेगी। सैंट्रल गंबनमेंट चीफ जस्टिस को मजबूर नहीं कर सकती है कि फलां जज को वह भेजें। जिस जज को चाहेंगे चीफ जस्टिस भेजना उसको वह अपने आप डिसाइड करेंगे। अगर आप इस मामले में कोई शक जाहिर करते है तो इसका मतलब यह है कि ज्यूडिशरी पर आप डाउट करते हैं। अभी कहा गया है कि ज्यु किमरी पर हम को नाज है। हिन्दुस्तान की ज्यूडिशरी पर अगर आपको नाज है तो फिर एक जज हो या तीन जज हों, किसी प्रकार का सक क्यों किया जाता है। एक जज जो होना बह भी तो दुश्स्त ओपीनियन ही देगा।

अभी श्री विश्वनाथन ने तथा कुछ और भाइयों ने कहा कि यहां कोई अपील के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। इसके साय-साथ उन्होंने ऑटिंकल 32 भी कोट किया है। जिस वक्त यह बिल प्रवर समिति के पास का उस वक्त भी यह सवाल प्रवर समिति के सामने उठाया गया था। तब एटर्नी जनरल ने जवाब दिया था कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट की पावर्ज का सम्बन्ध है, जहां तक रिट का सम्बन्ध है, उसको सुप्रीम कोर्ट से लिया नहीं जा सकता है। अगर अपील का राइट न दिया जाए तब तो उनके हकूक महदूद हो जायेंगे लेकिन अगर रिट के जो हकूक हासिल हैं आर्टिकल 32 के नीचे वे हों तब उनके हकूक महदूद नहीं हो सकते हैं, इस तरह की बात जो कही जाती है, इसमें मुझे कोई वजन मालूम नहीं देता है। रिवीजन की पावर को ले लिया गया है। रिवीजन वह नहीं कर सकते हैं। रिट को जो पावर है चूंकि वह बाई इम्पिलिकेशन वहां पर मौजूद रहती है इसलिए मैं समझता हूं कि उन में किसी किस्म का किसी को सन्देह नहीं हो सकता है।

मैं समझता हूं कि प्रगर कोई व्यक्ति प्रपनी जाती राय एक्सप्रेस करता है, तो उस सूरत में वह इस कानून के नीचे हाल अप नहीं हो सकता है, इस कानून की प्रिप में नहीं भा सकता है। मैंने पहले ही धर्ज किया है कि हमारे भाई कहते एक बात हैं भीर करते दूसरी बात हैं— उन के मुंह में कुछ है भीर एक्शन में कुछ है। भगर कोई इनसाइट करता है, तो वह इस कानून की प्रिप में भा जाता है।

भव एक सवाल यह रह जाता है कि भोषी-नियन कैसे फार्म हो भौर किस मरहले पर फार्म हो—गवर्नमेंट भोषीनियन कैसे बनायेगी । मैं समझता हूं कि फैक्ट्स गवर्नमेंट के पास भायेंगे भौर उसके भाषार पर वह भपनी भोषीनियन वनावेगी । उसका प्रपना डिपार्टमेंट है, मधी-नरी है, जिस के पास फैस्ट्रस झायेंगे । कहा नया है कि इस क्लाज में शब्द "झोपीनियन" नहीं, बहिक शब्द "सेटिसफैक्शन" होना चाहिए । लेकिन में समझता हूं कि शब्द "झोपीनियन" बिल्कुस बुरुस्त रखा गया है भीर उसमें तब्दीसी की कोई जरूरत नहीं है ।

यह भी कहा गया है कि म्रोनसं माफ़ पूफ एक्यूज्ड पर रखा गया है। जो भी हाई कोर्ट का जज मुकरंर होगा, उस को इस बारे में निश्चित प्रोसीजर को फोलो करना होगा। गवर्नमेंट फैक्ट्स को धपने पास नहीं रख सकती है। जो नोटिफिकेशन जारी होगा, उस में माउंड्ज दिये जायेंगे। एक्यूज्ड को जो नोटिस कायेगा, उसमें वे दर्ज होंगे। फैक्ट्स जज के पास खकर जायेंगे भीर जब फैक्ट्स जज के पास खकर जायेंगे भीर जब फैक्ट्स जज के पास खायेंगे, तो हर एक्यूज्ड को हक है कि वह उनका मुमायना कर सकता है भीर उन का मुनासिब जवाब दे सकता है। इसलिए इस दलील में भी कोई वजन नहीं है कि एक्यूज्ड को पता नहीं लयेगा कि फैक्ट्स क्या है।

सेकिन यह जाहिर है कि जिन फ़ेक्ट्स को प्रकट करने से हमारे देश के किसी दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात पर बुरा मंसर पड़ सकता है, कम से कम उन फैक्ट्स को प्रकट नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस बारे में बिल्कुल दुरुस्त तरीका अपनाया क्या है।

जैसा कि माननीय सदस्य, श्री शिव नारायण, ने कहा है, सरकार कानून तो बना सेती है, लेकिन उन पर ठीक तरह से धमल- चरामद नहीं करती है। धगर कानूनों पर ठीक तरह से धमल- चरामद हो, तो वे कम्युनिस्ट पनप न सकें श्रीर देश का इनटेग्निटी पर भी आकात न हो। हम कानून तो बनाते हैं, लेकिन उन पर धमल करने के मामले में हिषक आते हैं। धगर सरकार मजबूती से उन पर धमल करने, जो हमारे यहां देश-विरोधी कार्यवाहियां नहीं कल सकती हैं। धगर सरकार की तरफ

से इन मामलों में कमजोरी न दिखाई जाती, तो हमारे में सब मसले हम हो जाते। इन हालात में प्रवर समिति से जो बिल हमारे सामने भाव। है, उसको हमें पास कर देना चाहिए।

जनसंघ के हुमारे माई हर रोज कहते हैं
कि जो लोग स्वतन्त्र नागालंड मौर स्वतन्त्र
मिजोलंड का नारा लगाते हैं, सरकार उनके
खिलाफ कार्यवाही नहीं करती हैं। लेकिन जब
सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने
के लिए कोई कानून लाती है, तो वे वावेला
मचा देते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि उन का
यह वावेला महज बाहरी दिलावा है। मैं मापौजीशन वालों से कहूंगा कि उन में से जो लोग
हिन्दुस्तान की एकता, एनटेब्रिटी मौर साबिरेन्टी को कायम रखना राहते हैं, उन को पूरे
जोर से इस विल का समर्बन करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विस का समर्थेन करता हूं।

भी भोंकारलाल बोहरा (चित्तोइगढ़): समापित महोदय, भावश्यकता भाविष्कार की जनती है। जब हमारे देश पर चीन का भाकमण हुमा था, तब भारत सुरक्षा कानून की भावश्यकता पड़ी थी। इसी प्रकार जब पश्चिमी बंगाल में नक्सलबाड़ी में हिंसात्मक घटनायें हुई भीर यह पता चला कि हमारे देश के ही कुछ लोग एक बाहरी देश की सहायता खे यहां पर सशस्त्र विद्रोह की स्थित उत्पन्न करना चाहते हैं, तो सरकार को यह कानून लाने की भावश्यकता पड़ी।

जैसा कि इस सदन को जात है, केवस कांग्रेस-के कार्यकर्ताओं के सिलाफ ही हिसात्मक कार्यवाहियां नहीं हुई, बल्कि एस०एस०पी० के एक प्रच्छे कार्यकर्ता, एक लेवर वकर, औं हत्या कर दी गई। मैं नहीं जानता कि उस समय एस०एस०पी० वाले किस तरह उस जहर को पी गये। शायद प्रापोजीयान में प्रपनी स्थिति को बनाए रसने के लिए वे कुछ बोले नहीं। लेकिन यह सत्य है कि नक्सनवाड़ी की घटनाओं से मार्विस्ट कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ कर [श्री बोंकारलाल बोहरा]

सभी विरोधी दलों को बड़ी चिन्ता हुई थी कि स्वतन्त्रता के बीस वर्ष बाद प्राज हिन्दुस्तान में ऐसी स्थिति मा गई है कि यहां पर इस प्रकार के हिंसात्मक प्रदर्शन और घटनायें हो रही हैं। जैसा कि मैंने कहा है, इसी के परिणामस्वरूप गृह मंत्री ने इस बिल को यहां पर उपस्थित किया है।

मैं कहना चाहता हूं कि मतीत में चाहे हम कभी एक रहे हों, लेकिन यह पहला स्वर्ण अवसर भाया है कि हम सारे हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश की सीमायें भखंड और असुण्य रहें, यदि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बन जाने के बाद हमारे देश में जो क्षेत्र बचा है, उस में किसी विदेशी शक्ति का म्रतिकमण न हो, यदि हम प्रपने देश की स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता और एकता की रक्षा करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि हम इस बिल का समर्थन करें।

हमारे कम्युनिस्ट भाई और अन्य विरोधी बन्धु भपने भपने दृष्टिकोण से इस बिल का विरोध करते हैं। मैं खास तौर से जनसंघ के माइयों से कहना चाहता हूं कि वे प्रपनी प्रति-.राष्ट्रीयता भौर उप राष्ट्रीयता में इस तथ्य को नषरभन्दाज कर देते हैं कि पाकिस्तान बन जाने के बाद भी इस देश में करोड़ों मुसलमान रह गए हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम भौर वे मिन कर रहें, यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश मंपूनः पाकिस्तानी वातावरणं या डिवि-जन का सतरा न हो, तो हमें प्रपनी राष्ट्रीयता को उपता से उतार कर उचित भीर संगत **ब्राधार पर** तय करना होगा । मैं निश्चित रूप से कहना बाहता हं कि हमारी मान्यतायें इस मामार पर निश्चित होना चाहिए कि इस देश में रहने वाले जितने भी हम भाई-बहन हैं, हम सब को मिल कर इस देश में रहना है।

बब मैं परिवमी बंगाल की घटनाओं की ओर देखता हूं, तो मुझे आस्वर्य होता है कि एक तरफ तो श्री नम्बूदरीपाद है, जो उद्योग-पितयों श्रीर कल-कारलाने लाने बालों को केरल में भाने श्रीर वहां पर अपनें उद्योग स्था-पित करने का निमंत्रण दे रहे हैं श्रीर दूसरी श्रोर उन्हीं की पार्टी के सदस्य पिष्वमी बंगाल में उद्योगों को समाप्त करने में भपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं श्राता कि माक्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी में इस तरह की दो तरह की नीति कैसे चल रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उहोंने अपनी श्रति-अन्तर्राष्ट्रीयता, एक्सट्रीम इन्टरनेशनिल्डम के कारण भारत को लो दिया है।

जो लोग समझते हैं कि बंगाल की राष्ट्रीयता कमजोर है, वे गलती पर हैं। श्री एवं एनं मुकर्जी का भाषण सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। बंगाल के लोगों ने हमें राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया। बंगाल के कान्तिकारियों और राजनीतिक नेताओं पर हम को गुमान, गर्व और भिभान है। इसलिए मुझे मब भी विश्वास है कि माक्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से माओन्से-तुंग की टीचिंग्ज का प्रवार करते थे, उस के चित्रों का प्रदर्शन करने से या वहां पर वियतनाम बनाने की धमिकयों से बंगाल की राष्ट्रीयता कमजोर नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल हमेशा की उरह लोकतंत्र और राष्ट्रीयता का प्रवल पोषक रहेगा और हिन्दुस्तान के साथ रहेगा।

श्रगर कम्युनिस्ट पार्टी, या समाजवादी दल या जनसंघ श्रपनी-श्रपनी विचार धारी का प्रचार करते हैं, तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे इस बात पर एतराज है, कि किसी भी दल या व्यक्ति की तरफ से देस की एकता और स्वतन्त्रता पर श्राचात किया नाये। मैं श्री मंघु लिमये को लास तौर से कहना चाहता हूं कि जब उन की पार्टी से एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई, तो वह और उन के साथी चुप रहे, लेकिन जब नक्सलबाड़ी में घटनायें होने लगीं, तो उन्होंनें स्थित की गम्भीरता को समझा है। मैं एस०एस०पी० की राष्ट्रीयता का कायल हूं। स्वर्गीय डा॰ लोहिया के प्रति मेरा असंड विश्वास था। उन की राष्ट्रीयता संदेह से परे थी। भ्राज हमारी राष्ट्रीयता की परीक्षा हो रही है। यह बिल भौर किसी वजह से नहीं, केवल इसी वजह से आया है कि हमारा राष्ट्र एक बना रहे भौर हमारे देश के टुकड़े न हों। मैं केवल इसी भाषार पर इस बिल का समर्थन करना चाहता हूं। मैं गृह मंत्री का भ्रीमनन्दन करता हूं कि उन्होंने समय रहते यह बहुत बड़ा काम किया है।

जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था, मावश्य-कता भ्राविष्कार की जननी है। पिछले पांच छः महीनों की घटनाग्रों से इस बिल की ग्रावश्य-कता पड़ी। हमने देखना कि कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और देश की राष्ट्रीयता का अर्थं बदलना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में धगर हम अपने देश की एकता और स्व-तन्त्रता की रक्षा के लिए इस तरह का बिल पास नहीं करते हैं तो हमारे पास कोई हथियार नहीं है कि जो माम्रोत्-से-तुंग के नारे लगें या वियत-नाम के नारे लगें तो हम उन को चेक कर सकें। कंबर लाल गुप्त जी ने कहाथा कि उन्होंने एक प्रश्न पूछा था तो उसके जवाब में यह कहा गया था कि हमारे पास इस तरह के कांडों को बन्द करके के लिए कोई हथियार नहीं है। तो इस प्रकार का कानृन देश की रक्षा के लिए राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए भीर हमारी राप्ट्रीयता के विकास के लिए बहुत अरूरी है **श्रौर इसी** श्राधार पर मैं इस बिल का जोरों से स्वागत करता हूं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विचारों की स्वतन्त्रता ग्राप को जरूर है। घ्राप श्रपने विचारों का प्रकाश करें।, जनता पर भ्रपना प्रभाव डालें लेकिन भ्राप को यह **हक** नहीं है कि राष्ट्रीयता से ऊपर उठ कर श्राप कोई श्रराष्ट्रीय हरकतें ऐसी करें जिससे कि राष्ट्र के टुकड़े हों भ्रौर राष्ट्र की शांति भंग हो। सब से ऊपर हमारी राष्ट्रीयता है। भाषा से, प्रान्त से श्रौर हमारी तमाम छोटी मोटी जो संकीर्णताएं हैं, छोटी मोटी जो मांगें हैं उन से बढ़ कर हमारी राष्ट्रीयता है। इसक्रिए

चोरबाजारी, काला-बाजारी, जमास्रो**री** इन सब के विरुद्ध उठें, मुझे कोई एतराज नहीं है, ग्राप भौर मांगें पेश करें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं मार्किसस्ट कम्यूनिस्ट पार्टी के बन्धुमों से कहुंगा कि भाप की पार्टी इसलिए म्रलोकप्रिय होती जा रही है कि माप की राष्ट्रीयता को लोग संदेह की निगाह से देखते हैं। ग्राप के विचारों के प्रति लोगों की सहानुभूति होते हुये भी लोग यह महसूस करते हैं कि ग्राप देश को बेच सकते हैं। तो क्या मैं ग्राप से मपील करूं कि जैसे 1942 के मंदर माप ने एक गलत कदम उठाया था, जैसे चीन का हमला हुमा तो म्राप ने एक म्रराष्ट्रीय नुट बनाया तो ग्राप की पार्टी को दो टुकड़ों में बंट गई इसी प्रकार माज यह स्थिति है कि ग्राप इसके विरुद्ध बात करते हैं तो लोगों को शक होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इसलिए में कहना चाहता हू कि भव वह समय चला गया कि आप भावना के म्रावेश में माकर कोई काम करें। समय आ गया है कि हम इस देश की राष्ट्रीयता को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीयता का विकास करने के लिए काम करें। मैं कहना चाहता हूं कि ग्रंभी हमारी राष्ट्रीयता के विकास का प्रारम्भ हुमा है। राष्ट्रीयता के विकास का पहला प्रध्याय शुरू हुमा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस तरह के राष्ट्र-विरोधी कांडों ग्रौर हरकतों को रोकने के लिये ऐसे बिल का समर्थन करें। हमारी राष्ट्रीयता मजबूत होगी तो हम मजबूत होंगे । यही बात में भपने डी० एम० के० के भाइयों से कहना चाहता हूं जैसे कि श्रीकांतन नायर ने कहा था कि वार हो जायगी भीर डी॰एम॰के॰ वालों ने कहा था, तो उन से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी संपूर्ण दृष्टि प्रसंड राष्ट्रीयता के विकास पर होनी चाहिए भौर हमारी प्रान्तीयता की जो संकीण मांगें हैं उन को हमें दबाना चाहिए। इसी दृष्टि से इस बिल का स्वागत करते हुये मुझे प्रसन्नता होती है।

भी रणभीर सिंह (रोहतक) : वेयरमैंत साहब, मैं होम मिनिस्टर साहब ते जो

# श्री र**ण**धीर सिंह]

विम हाउस के सामने पेश किया है उसकी मृह्क के नजरिए से, कीम के ख्याल से और मुल्क के बचाव के ख्याल से इस मौके पर एक बहुत जरूरी बिल समझता हूं। चेयरमैंन साहब आप खुद वकील हैं और मेरे बाकी दोस्त जो कानून जानते हैं वह इस बात को महसूस करेंगे कि इंडियन पीनल कोड में यह सेक्शन तो था कि कोई किंग के खिलाफ लड़ाई सब्दें तो उसको फांसी के तख्ते पर पहुंचा देते थे। कीई लड़ाई लड़े एम्पायर के खिलाफ तो उस पर मुकदमा चलता था। लेकिन अंग्रेज के जाने के बाद हम समझते यह है कि यह जो क्लाज उस पीनल कोड में था, आज हिन्दुस्तान की एकता के खिलाफ, हिन्दुस्तान की इंटीग्रिटी के खिलाफ, अपने देश की सावरेनटी के खिलाफ कोई नारे लगाए या काम करे तो उसके पनिशमेंट के लिए कोई ऐसा कानून अपने पास नहीं है। मैं अपने भाई जनसंघ वाले श्रीचंद बौयल से और बाकी जो लाइयर फड बैठे हैं उनसे जानना चाहता हुं कि ताजीरात हिन्द में या डिफेंस आफ इंडिया रूस्स में या सिक्यो-रिटी ऐक्ट में जो अब तक रहे हैं या जितने रेग्सेसंस ऐक्ट बने हैं या किमिनल अमेंडमेंट ऐक्ट में कहीं भी नजर डाल कर देखें कोई ब्राविजन ऐसा कानून में कहीं नहीं मिलेगा जो इस बिल की जगह पूरा करता हो।

17:58, hrs.

SHEEL C. K. BHATTACHARYA in the Chair.]

तो में होम मिनिस्टर साहब को मुबारक-बाद बेता हूं इसके लिए और असल बात तो यह है कि हम सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ हैं लेकिन हिन्दुस्तानी नहीं हैं। हर काम को चाहते हैं, हर राइट को चाहते हैं, हम प्रीऐम्बल का हम भरते हैं कि प्रीऐम्बल में लिखा हुआ है दिवलिटी, जटिस, लिबर्टी, फ़ैटनिटी यह सब है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उस प्रीऐम्बल में सब से पहले कोई लब्ब है तो साबरेन डेमो-बेटिक का लब्ज है और उसको हम ने कांस्टी-ट्यूट किया है। उस बदिकस्मत देम में जहां

सैकड़ों जाति बिरादरियां हैं, जहां दर्जनों मजहब हैं, जहां जाति बिरादरी के मसले पर, जहां जवान के मामले पर, छोटी छोटी बातों पर, मजहब की बात पर, जोन की बात पर प्रान्त की बात पर लोग अपने वत्तन से भी गहारी की बात सोचते हैं, मैं बड़ा आदर करता हं अपने डी॰एम०के॰ के भाइयों का, उनका बड़ा कांट्रीब्यूशन है देश में, भाई राजाराम बड़े होशियार मेम्बर हैं हमारे यहां, लेकिन परसों वह कह रहे थे कि तुम अपने आदिमियों की साउच से ले जाओ, हम अपने आदिमयों को नार्चं से बुला लेंगे। मैं कहना चाहता हं कि आखिर यह बात आती क्यों है मन में? एक पढ़े लिखें एम० पी० के दिमाग में जो लीडर हैं जनता के उनके दिमाग में यह बात आ सकती है तो वह लोग जो हैडक्वार्टर्स में काम करते हैं, जो ऐसे नाजुक रीजंस में काम करते हैं,काश्मीर जैसी जगहों में जहां मजहब का नारा शानदार अफीम का काम दे सकता है और जहर का काम दे सकता है, जो मिजोलैंड में रहते हैं नागा लैंड में रहते हैं और नागा लैंड में ऐसे ऐसे नारे चलते हैं और जहां एक नहीं, दर्जनीं नहीं, सैकड़ों औ हजारों की तादाद में इनफिर-दैटर्स आते हैं .....

समापित महोदय: अब हाफ ऐन अवर गुरू होना है....

भी रवाधीर सिंह: अच्छी बात है। आप मुझे कल मौका दें।

18 bes:

•SUPPLY OF RIVER WATERS TO WEST PAKISTAN

भी बलराज मधोक (दिलण दिल्ली) : बाध्यक्ष महोदय, में इस समय सदन के सामने एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में विचार रखना चाहता हूं। पिछले दिनों जब मंगला डैम मुकम्मिल हुआ और उस के बारे में इस सदन में बहुत सी चर्चा भी हुई, परन्तु जिस बात को नजरअन्दाज कर दिया गया वह यह कि इस

<sup>•</sup>Half-An-Hour Discussion.

मंगला डैम के बनने के बाद हिन्दुस्तान पाकि-स्तान से कोई पानी की भीख नहीं मांगता, हम अप ना अधिकार मांगते हैं, यह जो सिन्धु घाटी का पानी है इसकी समस्या क्या है? ब्यौरा क्या है? सन् 1947 में जब भारत का बटवारा हुआ सिन्धु घाटी का क्षेत्र पंजाब का बटवारा हुआ सिन्धु घाटी का क्षेत्र पंजाब का बौर सिन्ध का सिचाई की दृष्टि से सब से विकसित भाग था। इसमें दो करोड़ 60 लाख एकड़ में सिचाई होती थी। पंजाब की इन तीन नदियों से जो पाकिस्तान में हैं बीसों नहरें निकाली गई थीं और वह पंजाब की जनता ने उन नहरों को बनाया था। उन के रुपये उस में लगे थे और जो पंजाब का उस समय का नेशनल डेट था उसका अधिक रुपया इन नहरों के बनाने में लगा था।

जब बटवारा हुआ, पंजाब के क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत के लगभग भाग भारत में आया. लेकिन वहां का जो सिचित क्षेत्र था, जिसमें सिचाई होती थी, वह हमें केवल 20 प्रतिशत भी नहीं मिली। 2 करोड़ 60 लाख एवड भिम में से भारत के हिस्से केवल 50 लाख एकड सिचित इलाका आया. बाकी का 2 करोड 10 लाख एकड इलाका पाविस्तान में रह गया। वहां के जो 6 दरिया है, उन में से हमारी तरफ केवल तीन पड़े--स्रल्ज, व्यास, रावी और चिनाब, जेहलम, सिंध उधर रह गये। इन दरियाओं के पानी की स्थिति इस प्रकार है कि जो पूर्वी दरिया हमें मिले उनमें 20 प्रतिशत पानी है और जो दरिया पानि स्तान में गये. उन में 80 प्रतिशत पानी है। ऐसी स्थित में यह आवश्यक था कि जो तीन नदियां हमारे पास रह गई थीं, उनका सारा पानी हम अपने क्षेत्र की सिचाई के लिये रखते। यदि पावि स्तान हमारे साथ भाईचारे से रहता तो जो पानी इन नदियों से पाकिस्तान को जा रहा था. उसे कुछ समय के लिये देते, लेकिन पाकिस्तान ने तो पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि वह भारत के साथ भाईचारे से रहना नहीं चाहता। अगर वह रहना चाहता, तो काश्मीर पर हमला नहीं करता। उस ने किया, हमारे 35 काश्मीर पर हमला M101LSS/67-5-3-68-GIPF.

हजार वर्ग मील इलाके को दबा कर बैठ गया। जब पाकिस्तान का किरदार यह या तो यह आवश्यक था कि हम पाकिस्तान के साथ इस मामले में कोई बातचीत न करते और जो तीन नदियां हमारे पास थीं जिन पर हमारा अधि-कार था, उन को हम अपने लिये इस्तेमाल करते। लेकिन हमारी जो तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण प्रायः आज बहुत सी समस्यायें पैदा हुई हैं, उसी की बजह से हम यह मामला वर्ल्ड बैंक में ले गये। जैसे काश्मीर के मामले को हम ने प्०एन०ओ० में ले जाकर खराब किया, उसी तरह से इन नदियों के मामले को. हम विश्व बैंक के सामने ले गये और फिर उस ने यह फैसला किया कि पांच साल तक हम पाकिस्तान को पानी दें और पाकिस्तान **को** रिप्लेसमेंट नहर बनाने के लिये 50 करोड रुपया दें। यह ज्यादती थी क्योंकि पाकिस्तान की जो नहर बनी थी वह हमारे ही पैसे से बनी थी। पंजाब का जो डेट था, उस में पाकि-स्तान का हिस्सा 3000 करोड रुपये था, लेकिन पाकिस्तानने एक धेला नहीं दिया। ऐसी स्थिति में वर्ल्ड बैंक के एवार्ड को मानने का कोई कारण नहीं था। लेकिन हम ने मान लिया, पाकि-स्तान ने फिर भी नहीं माना । मामला लम्बा होने लगा। पं० नेहरू को दया आई, क्योंकि पाकिस्तान उन का नाजायज बेटा **या, भागते हये** अयब के पास गये, 1960 में एक सन्धि की । उस वक्त के समाचार पत्नों को देखिये ....

श्री प्रेम चन्द चर्मा: सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

MR. CHAIRMAN: There is no quorum. Shri Balraj Madhok may resume his seat.

The bell is being rung-

Still, there is no quorum. So, the House will now stand adjourned till 11 a.m. tomorrow.

18.06 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 19, 1967/Agrahayana 28, 1889 (Saka).